{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 18 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना मुख्य चुनावी मुद्दा

ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये मतदान प्रारम्भ होने में कुछ ही घंटे रह गये हैं और इस चरण के अंतर्गत जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां प्रचार भी थम गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभरता नज़र आ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिये निश्चित ही चिंता की बात होगी क्योंकि इस पर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस द्वारा जैसा हमला उस पर हो रहा है वह इसलिये अधिक चिंतनीय है क्योंकि ये आक्रमण सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हो रहे हैं। उन्हें इस भ्रष्टाचार का सूत्रधार बतलाया जा रहा है। चूंकि भाजपा का सारा प्रचार नरेंद्र मोदी पर ही टिका है, अगर यह मुद्दा मतदाताओं के जेहन में बैठ गया तो भाजपा का अपने दम पर 370 तथा सहयोगी दलों के साथ मिलकर बने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के 400 पार के नारे की धज्जियां उड़ जायेंगी। शायद यही कारण है कि मोदी बार-बार इस योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड्स) को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जान गया है कि उसके हाथ एक ऐसा अस्त्र लग गया है जिसके बल पर भाजपा को इस चुनाव में धूल चटाई जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक घोषित करने के साथ ही भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर आती दिख रही है। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को परिवारवाद के अलावा मोदी व भाजपा जिस मामले को लेकर सर्वाधिक कोसती थी, वह गांधी कुटुम्ब तथा उसका कथित भ्रष्टाचार ही रहा है। बाजी उस वक्त पलट गई जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र की भाजपा सरकार की इस योजना को ही भ्रष्टाचार का तरीका ठहरा कर उसे बेनकाब कर दिया।

यही कारण है कि देश के कई अखबारों व चैनलों को नरेंद्र मोदी इन दिनों साक्षात्कार दे रहे हैं जिसका प्रमुख मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही है। ऐसा नहीं कि वे केवल इसी पर बात कर रहे हों पर उनके हाल के दिये ज्यादातर इंटरव्यू में जिस प्रमुखता से वे इस पर बातें कर रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें इस मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही सफाई देनी पड़ रही है। जैसा कि कहा जाता है कि उनके ज्यादातर साक्षात्कार उन्हीं की प्रचार टीम द्वारा तैयार होते हैं, स्वाभाविकत: उनमें यह मुद्दा बहुत ही खास स्थान पा रहा है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि साक्षात्कारों की प्रश्नावली मोदी के कार्यालय या उनकी नज़रों से गुजरती ही है। जिनमें उनकी सहमति हो वे ही सवाल इसमें रखे जाते हैं। अब तमाम साक्षात्कारों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में श्री मोदी जो कह रहे हैं उनमें यह बात ज़रूर होती है कि 'जो लोग आज इसे लेकर उत्साहित हैं वे आगे जकर पछताएंगे।' वे यह भी कह रहे हैं कि 'पहली बार चुनावी चंदे का ट्रेल पता चल रहा है वरना पूर्ववर्ती सरकारों के समय तो पता भी नहीं चलता था कि किसी भी पार्टी को कहां से चंदा मिल रहा है।' हालांकि वे यह नहीं बता रहे हैं; और कोई पूरक प्रश्न पूछ भी नहीं रहा है कि अगर वे पारदर्शिता के इतने ही हिमायती हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को इस योजना के बाबत सारी जानकारी देने से क्यों आनाकानी कर रहा था। खासकर, सरकार के इशारे पर किसलिये कारोबारियों के संगठन अदालत के सामने इस गुहार के साथ पहुंचे थे कि चंदा देने वालों के नाम उजागर न किये जायें। प्रधानमंत्री मोदी तो चुनावी बॉन्ड्स के बारे में जो कह रहे हैं, वह अपनी जगह पर है परन्तु खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अब इस योजना को संशोधित स्वरूप में लाने की योजना बना रहा है- बावजूद इसके कि देश आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और मोदी सरकार केवल कार्यवाहक है। जिस सरकार व प्रधानमंत्री को शीर्ष कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई योजना पर शर्मिंदा होना चाहिये था, वे न केवल इसका शिद्दत से बचाव कर रहे हैं बल्कि इसका दूसरा संस्करण लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, वह भी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मोदी की हठधर्मिता इस कदर है कि वे कोर्ट की अवमानना की परवाह किये बिना ही इसके पक्ष में बोल रहे हैं, मीडिया में अपना पक्ष रख रहे हैं और उसे फिर से पेश करने की तैयारी भी कर रहे हैं।

दूसरी तरफ विपक्ष ने भी जान लिया है कि यह मोदी की कमजोर नब्ज़ है जो उसके हाथ लग गई है। सो वह पूरी ताकत से उसे दबा रही है। दरअसल इसके कई आयाम एक साथ उजागर हो गये। इसमें बताया गया कि भाजपा के लिये चंदा बटोरने के लिये केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया गया। जैसे-जैसे इस घोटाले की परतें खुलती गयीं यह साफ होता चला गया कि देश के समक्ष आज जो महंगाई, बेरोजगारी आदि की समस्याएं हैं उन सभी की जड़ें भी इस घोटाले से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार कोरोना काल में लोगों को लगाये गये टीके का सम्बन्ध भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे मामले सामने आये हैं जो बतलाते हैं कि इसके बल पर भाजपा सरकार ने ठेके बांटे हैं या डरा-धमकाकर कारोबारियों से चंदा लिया है। कई ऐसी कम्पनियों के नाम भी सामने आये हैं जिन्होंने अपने लाभ से कई गुना ज्यादा चंदा भाजपा को दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे हफ्ता वसूली जैसा बताया है, जिससे साफ है कि इन चुनावों में इलेक्टोरल बॉन्ड अब बड़ा मुद्दा बन गए हैं।

कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों से कुछ उम्मीदें

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

देश में सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा यूपीएससी के नतीजे मंगलवार शाम को घोषित हुए। पिछले कुछ सालों से शीर्ष स्थान लड़कियों को मिल रहा था, इस बार लड़कों को प्रथम और द्वितीय आने का मौका मिला है। संघ लोक सेवा आयोग ने 28 सौ से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया था, जिनमें से 1016 लोगों को सफलता मिली है। मतलब यह कि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को नाकामी हाथ लगी है। और अगर यूपीएससी की प्रिलिम्स और मेन्स परीक्षा के अभ्यर्थियों की बात करें तो करीब 13 लाख लोगों ने ये परीक्षाएं दी थीं। 13 लाख में केवल 28 सौ साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचे और वहां से एक हजार 16 लोग सफल होकर निकले। हालांकि नतीजे आने के बाद से शीर्ष 50 स्थान पर आने वालों की ही ज्यादा चर्चा मीडिया में है। बाकी साढ़े नौ सौ लोगों की सफलता की कहानी या तो उनके परिजन सुनाएंगे या उन्हें कोचिंग देने वाले संस्थान।

यूपीएससी में सफल होने वालों के संघर्ष की कहानियां भी अब बाहर आनी शुरु हो चुकी हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इनसे उस राह पर आगे बढ़ने वालों को प्रेरणा मिलती है कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी बारहवीं फेल, जो सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में ऐसी ही सफलता की कहानी है, जिसमें गांव की स्कूल से पढ़ा एक लड़का, बार-बार की असफलता और आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ही लेता है और साक्षात्कार में बैठे लोगों को यह बखूबी समझा देता है कि हिंदी या अंग्रेजी केवल माध्यम हैं, असल बात तो लोगों की समस्याओं और जज्बात को समझने की है। फिल्म में एक और किरदार है, जिसने साक्षात्कार पर पहुंचने के अपने सारे मौके ले लिए, लेकिन किसी तरह सफल नहीं हुआ, तो फिर अपने अनुभव से दूसरों को प्रशिक्षण देने लगा। यह किरदार रि स्टार्ट यानी फिर से शुरु करना चाहिए, जैसे गीत से प्रेरणा देता नजर आया है।

फिल्म में यह सब देखने-सुनने में अच्छा ही लगता है, क्योंकि बात दो-ढाई घंटे की होती है, हम किरदारों से खुद को जोड़ लेते हैं और उनके साथ भावनाओं में डूबने-उतरने लगते हैं। मगर हकीकत कितनी अलग होती है, इसका एक उदाहरण ट्विटर पर देखने मिला, जिसमें एक असफल अभ्यर्थी ने आंकड़े दिए कि 12 प्रयास, 7 बार मेन्स और 5 बार साक्षात्कार, फिर भी असफलता हाथ लगी, शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह केवल एक असफलता और निराशा का उदाहरण नहीं है, बल्कि यहां वो मलाल भी नजर आ रहा है जिसमें जीवन के सुनहरे बरस व्यर्थ हो गए। इस देश में लाखों लोग हर साल इसी तरह के मलाल से गुजरते हैं। उन्हें रि स्टार्ट जैसे गीतों से सांत्वना देने की जगह यह समझाने की जरूरत है कि अपनी बुद्धि और प्रतिभा का इस्तेमाल वो इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

यूपीएससी की सफल लोगों की कहानियों को भुनाते हुए कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, जहां दड़बों में ठुंसी हुई मुर्गियों की तरह छात्रों को भरा जाता है। लाखों की फीस उनके अभिभावक देते हैं, और बहुतों को ये उम्मीद रहती है कि बच्चा सफल हो जाए तो सरकारी रौब का स्वाद चखने मिले।

> **यूपीएससी की सफल लोगों की कहानियों को भुनाते हुए कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं, जहां दड़बों में ठुंसी हुई मुर्गियों की तरह छात्रों को भरा जाता है। लाखों की फीस उनके अभिभावक देते हैं, और बहुतों को ये उम्मीद रहती है कि बच्चा सफल हो जाए तो सरकारी रौब का स्वाद चखने मिले। हालांकि इस स्वाद की कल्पना और हकीकत में काफी फर्क है।**

हालांकि इस स्वाद की कल्पना और हकीकत में काफी फर्क है। कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सरकार में बड़े अधिकारी बनने वालों को सत्ता के दबाव का सामना करना पड़ता है। बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो सत्ता पर बैठे लोगों की जी हुजूरी करने से इंकार करने की हिम्मत दिखाते हैं और वही फैसले लेते हैं जो जनता या देश के हित में हों। और ऐसे अधिकारियों को अक्सर सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ता है। कभी उन्हें तबादलों की मार झेलनी पड़ती है, कभी सरेआम अपमान सहन करना पड़ता है। अब तो सत्ता के साथ-साथ पूंजी का दबाव भी मिल गया है, जिसमें अधिकारियों के लिए रीढ़ को सीधा रखना कठिन हो चला है। सत्ता के अनुचित दबाव में आने से इंकार करने वाले लोग या तो प्रताड़नाओं को सहते हुए अपनी सेवानिवृत्ति का इंतजार करते हैं या फिर समय से पहले सेवानिवृत्ति ले कर निजी संस्थानों में अपनी सेवाओं का लाभ देने लगते हैं। आजकल सेवानिवृत्ति के फौरन बाद राजनीति में आने और फिर ऊंचे पदों या आयोगों की अध्यक्षता करने का मौका भी मिलने लगा है। इसके दोहरे लाभ मिलते हैं, एक तो अधिकारी वाला रौब-दाब बना रहता है और दूसरा अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता के हित में लिए गए फैसलों की न समीक्षा होती है, न किसी कार्रवाई का डर रहता है। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे लोगों को व्यावहारिक बुद्धि वाला कहा जाता है, जो लहर के विपरीत न जाकर धारा के साथ बहना मंजूर कर लेते हैं। लेकिन फिर यहां एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या यूपीएससी की कठिन परीक्षा सत्ता की चाकरी करने के लिए उत्तीर्ण की गई या इसमें कहीं देश और जनसेवा का भाव भी था। अब जो नए अधिकारी तैयार हो रहे हैं, उनकी सफलता की कहानियां आखिर कितने दिन तक सुनाई जाएंगी, क्या उसके बाद वो भी सत्ता की सुविधा वाले सांचे में ढाल दिए जाएंगे। ये सवाल हाल की एक घटना से और भी प्रासंगिक हो जाता है।

आयरलैंड के एक अखबार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भारत के चुनावों के संदर्भ में आलोचनात्मक टिप्पणी की। जिस पर आयरलैंड में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा ने अखबार को अपनी प्रतिक्रिया भेजी और उसमें न केवल भारतीय प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए उनकी सरकार के कामकाज की तारीफ की, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस या गांधी परिवार का नाम लिखे बिना उसकी आलोचना की। अखिलेश मिश्रा ने लिखा कि भारत में एक ही वंशवादी परिवार के 55 साल के शासन, जिनमें शुरुआती 30 वर्ष महत्वपूर्ण हैं, के दौरान भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जमा चुके पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ लड़ाई श्री मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक प्रमुख वजह है। इस जवाब में अखिलेश मिश्रा ने अपनी पक्षधरता साफ जाहिर कर दी है कि वे केवल भारत सरकार का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि भाजपा का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आयरिश अखबार में भाजपा के शासनकाल में लिए जा रहे फैसलों और हालिया घटनाओं पर टिप्पणी की गई थी। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी अखिलेश मिश्रा के इस रवैये को कांग्रेस ने अपमानजनक और गैरपेशेवराना करार दिया है और उन पर कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस की शिकायत का किस तरह से संज्ञान लिया जाता है, यह अलग मसला है। लेकिन यहां सवाल वही है कि संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने, फिर प्रशिक्षण लेने के बाद जब अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में उतरते हैं, तो उनकी प्रतिबद्धताएं किसके लिए रहती हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं। अगर वे आम जनता की भलाई को सर्वोपरि रखते हुए फैसले नहीं लेते और सत्ता प्रतिष्ठान के चाकर की तरह काम करना स्वीकार करते हैं, तो फिर हर साल 20-30 लोगों के यूपीएससी में सफल होने और संघर्ष से आगे बढ़ने की जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनका क्या औचित्य रह जाता है।

मध्यप्रदेश में एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे सुदीप बनर्जी, जिन्होंने साक्षरता, कला संस्कृति इन सबके लिए कई अनूठे काम किए। बस्तर के आदिवासियों के हितों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार से भिड़ने में झिझक नहीं दिखाई। भोपाल गैस दुर्घटना के वक्त मोर्चे पर डटकर पीड़ितों की मदद की। किसी भी उद्योगपति या मंत्री के आगे दबाव में नहीं आए। सुदीप बनर्जी की संवेदनशीलता और ईमानदारी की मिसालें कई मौकों पर दी जाती रही हैं। उनकी तरह कई और आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी हुए हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन क्या वे लोग अब समाज के और यूपीएससी में अभी सफल होने वालों के आदर्श हैं, यह विचारणीय है। आखिर में कवि चंद्रकांत देवताले की कविता खुद पर निगरानी का वक्त की चंद पंक्तियां पेश हैं-

हाँफ रही कविता
कितना कर सकती है छातीकुट्टा
कह रही बार-बार निगरानी रखो
जैसी दुश्मन पर, वैसी ही खुद पर
चुटकी भर अमरता-खातिर
विश्वासघात न हो जाए।
अपनी भाषा, धरती और लोगों के साथ।

यूपीएससी में सफल होने वाले तमाम लोगों को शुभकामनाएं इस उम्मीद के साथ कि वे अपनी भाषा, धरती और लोगों के विश्वास को बनाए रखेंगे।

कर्नाटक में कांग्रेस दे रही भाजपा-जद (एस) को कड़ी टक्कर

■ कल्याणी शंकर

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं जिसके लिए 26 अप्रैल और 7 मई को सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। कांग्रेस पार्टी और भाजपा-जद(एस) गठबंधन मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का समर्थन प्राप्त है, जो लिंगायत समुदाय के बीच प्रभावशाली हैं जो राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। यह चुनाव कर्नाटक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण हैं।

कर्नाटक अतीत में कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसने आपातकाल के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया, जो इसके राजनीतिक महत्व का एक प्रमाण है। यह ऐतिहासिक महत्व इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की जीत से स्पष्ट है, दोनों ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें जीतीं।

ये चुनाव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी-जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन के बीच एक बड़ी लड़ाई है। वे कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा के दोबारा प्रवेश का प्रतीक हैं। चुनाव नीतिगत प्राथमिकताओं और शासन शैली को बदल सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। परिणामों का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और समझ महत्वपूर्ण हो जायेगी।

> **कांग्रेस सरकार ने पिछले साल किये गये पांच आवश्यक चुनावी गारंटियों को लागू कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा के लिए धन में वृद्धि और रोजगार सृजन शामिल था। ये वायदे क्षेत्र के मतदाताओं की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने और सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किये गये थे।**

भाजपा दक्षिण में अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को मजबूत करने, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति बढ़ाने और दक्षिण भारत में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आगामी कर्नाटक चुनावों में विजयी होना चाहती है। इसके विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, जद(एस) अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में जीवित रहने का प्रयास कर रहा है। संक्षेप में, जद (एस) राज्य में एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी प्रासंगिकता बनाये रखने का प्रयास कर रहा है।

कर्नाटक में भाजपा का प्रचार अभियान पीएम मोदी की उपलब्धियों और कांग्रेस की विफलताओं पर केंद्रित है। यह दो प्रभावशाली समुदायों, लिंगायत और वोक्कालिगा को लक्षित करता है, जो इसकी चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य में एक प्रमुख समुदाय होने के नाते लिंगायत पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थन करते रहे हैं।

इसके विपरीत, एक अन्य प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिगा, जद (एस) का मजबूत जनाधाररहा है। भाजपा की चुनावी सफलता के लिए इन समुदायों पर जीत हासिल करना महत्वपूर्ण है।

भाजपा को कुछ स्थानीय संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 के बाद पहली बार पार्टी में खुली बगावत हुई है। इसकी वजह भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन है, जिसे अभी तक अच्छा समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस के भी अपने बागी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस कर्नाटक में एससी, एसटी और मुसलमानों पर भरोसा रख रही है।

कांग्रेस सरकार ने पिछले साल किये गये पांच आवश्यक चुनावी गारंटियों को लागू कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा के लिए धन में वृद्धि और रोजगार सृजन शामिल था। ये वायदे क्षेत्र के मतदाताओं की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने और सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किये गये थे।

एडिना, न्यूज 18 और इंडिया टुडे ग्रुप के तीन चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कर्नाटक के आगामी चुनावों के लिए परस्पर विरोधी परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। एडिना का अनुमान है कि कांग्रेस 17 सीटें जीतेगी, और भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन को 11 सीटें मिलेंगी। न्यूज 18 का अनुमान है कि एनडीए 25 सीटें जीतेगी, कांग्रेस केवल 3 इंडिया टुडे ग्रुप का अनुमान है कि एनडीए 53फीसदी वोट शेयर के साथ 24 सीटेंजीतेगी। इंडिया गठबंधन को 42फीसदी वोट शेयर के साथ केवल चार सीटें मिलने की उम्मीद है। ये सर्वेक्षण वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। वे पाठकों को चुनाव के संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं।

2019 के चुनावों से एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है जब कांग्रेस और जद (एस) सहयोगी थे। भाजपा का लक्ष्य पुराने मैसूर में वोक्कालिगा वोटों को सुरक्षित करना और चुनाव को अपने पक्ष में झुकाना है। पुराने मैसूर क्षेत्र का एक प्रमुख समुदाय वोक्कालिगा पारंपरिक रूप से जद (एस) का समर्थन करता रहा है। इस समुदाय पर जीत हासिल करने की भाजपा की रणनीति में जाति-आधारित पहुंच, विकास के वायदे और जद (एस) सरकार की विफलताओं को उजागर करना शामिल है। सफल होने पर, यह रणनीति चुनाव परिणाम और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

भाजपा ने अपने उम्मीदवारों में एक शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ, मैसूरु शाही परिवार के सदस्य और एक पूर्व मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा है। इसने कुछ नये चेहरों को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस में कई मंत्रियों के रिश्तेदार हैं और ये उम्मीदवार नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इसने ताकतवर राजनेताओं के परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारकर जोखिम उठाया है।

2008 में जब से भाजपा ने अपनी पहली सरकार बनायी, तब से 'गिराने का खेल' जारी है। पैसा और पद अक्सर विधायकों को वफादारी बदलने के लिए लुभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है। वोट पाने के लिए दोनों पार्टियां पैसा और उपहार खर्च करने को तैयार हैं। दोनों गठबंधनों की पार्टियों के पास पैसा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी को भारी रकम चुकानी पड़ रही है। कई उम्मीदवारों को पार्टी लेबल की चिंता नहीं है। उनकी चिंता सत्ता हासिल करने की है। देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के मतदाता किस तरह अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पावन प्रसंग

मन की शांति

हमें पग पग पर सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है और हम ऐसा समझते हैं कि यदि अमुक-अमुक वस्तुएं हमें मिल जाए, तो हम बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु जैसे ही वह वस्तु हमें मिल जाती है, हम उसके सुख का अनुभव न कर उसकी रक्षा की चिंता करने में दुखी होने लगते हैं। यह डर बना रहता है कि कहीं वह चीज खो न जाए। इस प्रकार एक न एक भय आजीवन बना रहता है और साथ ही साथ एक न एक लोभ भी लगा ही रहता है। हम स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी न किसी के आगे हाथ पसारा करते हैं। अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करते हैं और जब कोई हमारी ओर पूरा-पूरा ध्यान नहीं देता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी अवहेलना हो रही है, हमारी मानहानि हो रही है। हमें प्रशंसा की भूख रहती है। हमारे अंदर लोभ और मोह व्याप्त रहते हैं। फल यह होता है कि जो शक्ति हमारे उद्धार के लिए मिली है, उसका दुरुपयोग होता है और हम दिन-रात इस शक्ति का अपव्यय कर अंत में देखते हैं, तो हाथ कुछ नहीं आता। जैसे-जैसे हम वृद्धावस्था के निकट पहुंचते हैं, तो हमारे दोषों का बोझ बढ़ता जाता है और फल यह होता है कि हम अत्यन्त मानसिक उद्वेग का अनुभव करने लगते हैं।

शक्ति के अपव्यय से बचने का उपाय होना आवश्यक है। पहले तो हम यह समझें कि संसार की क्षुद्र बातों से ऊपर उठे बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मानसिक कल्याण और बोध तभी प्राप्त हो सकता है, जब हमारे अंदर से विरक्ति की भावनाएं उठें। हम ऊपरी रूप से साधु-फकीर का वेश बनाए रह सकते हैं परंतु भीतर से मन का सहयोग विरक्ति की ओर न हो तो हमें बार-बार लोभ और मोह के झकोरों से अस्त-व्यस्त होना पड़ेगा और तब हम देखेंगे कि हमारे लिए सुख-शांति नाम की कोई चीज नहीं रही। अत: भोगों से उपराम प्राप्त करने के लिए अंदर का मन साध लेना परमावश्यक है। ऐसा कर लेने से बाकी का काम आसान हो जाएगा।

हमें संसार के कामों में लगे रहना चाहिए। हमारे जिम्मे जो भी काम आ जाए, उन्हें सहर्ष करना चाहिए। यदि सभी लोग काम छोड़ना प्रारंभ कर दें, तो फिर कैसे होगा? अत: हमें प्रवाह प्राप्त जो काम हैं, उन्हें तो करना ही है और जब उन कामों को करें तो ठीक से करें, परंतु मन की चिंतनधारा को सबल अंतर्मुखी करते जाए। ऐसा करते हुए हम बहुत कुछ आत्मकल्याण कर सकेंगे। काम करते हमारे अंदर दोष भी प्रकट होंगे, तो हमें उनको सामने आने देना चाहिए तभी दोष दूर हो सकेंगे। अपनी शक्ति का सदुपयोग हो, इसके लिए तटस्थ भाव सांसारिक कर्मों के करने की चेष्टा करें। ऐसा यदि हम करें, तो कर्म का बोझ हम पर नहीं पड़ेगा और हम संसार के होकर उसमें फंसने से बच जाएंगे। विनोबाजी कहते थे-'समुद्र के किनारे खड़े रहकर ही हम समुद्र की लहरों का दृश्य देख सकते हैं जो व्यक्ति उन लहरों में डूब रहा है, वह उस दृश्य को किस भांति देख सकेगा? उसी भांति हमें भी अभ्यास और विरक्ति के द्वारा धीरे-धीरे मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति का क्षय रोक सकेंगे। इसलिए अनुभवी संतों ने इस बात पर बार-बार जोर दिया है कि इस संसार को नश्वर समझो, अपने शरीर को नश्वर समझो, अपनी मृत्यु को सदा सामने रखो, तब तुम निश्चिंत भाव से काम कर सकोगे और संसार में फंसने से बच जाओगे।

हम जो प्रवाह प्राप्त कर्म पाएं, उसमें अपना संतोष मानें और उसको ठीक-ठीक करने का अभाव करें, उसे करते हुए अपने अंदर चिंतन करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चिंतन में आध्यात्मिकता की ही बातें बार-बार आएं यों तो मन बहुत ही चंचल है, यह हमें वहां से यहां उठाता, बिठाता और फेंकता है। अत: धीरे-धीरे ही इसको वश में किया जा सकता है। अस्तु, हमें सतत इस ओर प्रवृत्त रहने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई चीज हमारे मन के अनुकूल न हो, तो हमें उस समय क्रोध अथवा क्षोभ दिखाने की आवश्यकता नहीं।

दैनिक जीवन में सभी प्रकार की आशा-निराशा और सुख-दुख का अनुभव करना पड़ता है। कोई भी इससे बचा नहीं रह सकता है। इसलिए सुख-दुख के जीवन से ऊपर उठने की कला साध लेनी चाहिए।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

भेदभाव और सुविधाओं की कमी से प्रभावित बालिका शिक्षा

आज जब हम स्वतंत्र हैं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है इसके बावजूद कई ऐसे गांव, बस्ती और कस्बे हैं जहां भेदभाव तो कहीं बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण इस अधिकार का हनन हो रहा है। जिसका सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव किशोरियों की शिक्षा पर पड़ता है।

हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के विकास से संबंधित कई अहम निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों और नई तकनीकों पर आधारित गतिविधियों से राज्य के ग्रामीण विद्यालयों को जोड़ने में प्राथमिकता पर ज़ोर दिया है ताकि नई तकनीक पर आधारित कार्यक्रमों से गांव के विद्यार्थी भी लाभांवित हो सकें। दरअसल आज भी राजस्थान के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। हालांकि राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की औसत दर 61.4 प्रतिशत दर्शाया गया है। जिसमें सबसे अधिक गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में 66.2 प्रतिशत और सबसे कम प्रतापगढ़ में 53.2 प्रतिशत बताया गया है. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम है उसके पीछे कई कारण बताये जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख गांव से स्कूल की दूरी है जिससे सबसे अधिक किशोरियों की शिक्षा प्रभावित होती है। इस संबंध में कक्षा 9वीं की छात्रा जाह्नवी बताती है कि गांव के बच्चे और किशोरियां प्रतिदिन पैदल स्कूल जाते हैं लेकिन वहां सुविधाएं नाममात्र की हैं। क्लास रूम तो बने हुए हैं लेकिन विद्यार्थियों के लिए न तो शौचालय की सुविधा उपलब्ध है और न ही पीने के साफ़ पानी की व्यवस्था है. जो पानी उपलब्ध है वह इतना खारा है कि बच्चे उसे पीना नहीं चाहते हैं।

गांव से कम से कम 20 छात्राएं नियमित रूप से स्कूल जाती हैं. लेकिन माहवारी के समय उन्हें सुविधाओं की कमी के कारण घर पर ही रुकना पड़ता है जिससे उनकी क्लास छूट जाती है और वह सिलेबस में पीछे रह जाती हैं।जाह्नवी बताती है कि -स्कूल में केवल सुविधाओं की ही कमी नहीं है, बल्कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव भी किया जाता है। रसूलपुरा में उच्च जातियों की संख्या अधिक है और स्कूल में भी इसी जाति से संबद्ध शिक्षकों और विद्यार्थियों की बहुलता है, ऐसे में वह हमें पढ़ाने में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाते है।

जब स्कूल में उच्च जातियों के छात्र-छात्राएं हमारे साथ जातिगत भेदभाव करते हैं और जब हम इसकी शिकायत शिक्षकों से करते हैं तो वह इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब अभिभावक स्कूल आकर इसकी शिकायत करते हैं तो उस समय शिक्षक कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें डांटा जाता है कि स्कूल की बात घर पर मत बताया करो। अभिभावक हमारी सुरक्षा के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं. यही कारण है कि अब इस गांव की लड़कियों को अकेले स्कूल जाने आने नहीं दिया जाता है।

हमें कक्षा में बोलने भी नहीं देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों में किशोरियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए साथ ही स्कूल का ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां वह आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। दरअसल शिक्षा हमें जातिगत भेदभाव से दूर करती है, लेकिन सच तो यह है कि हाशिए पर खड़े समुदाय और अति पिछड़े समाज के बच्चों को आज भी इसे पाने के लिए संघर्ष करनी पड़ रहा है। उन्हें कई प्रकार के भेदभावों से गुज़रना पड़ रहा है। उनके हौसले को बढ़ाने की जगह मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है।

यशोदा गुर्जर, अजमेर राजस्थान

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव,
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

दैनिक
जलते दीप

जोधपुर, गुरुवार 18 अप्रैल 2024

चुनाव में धनबल की ताकत

चुनावों में धनबल के बढ़ते चलन को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए सरकार और भारत निर्वाचन आयोग सतत प्रयत्नशील देखे गए हैं। मगर हकीकत यही है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगने के बजाय यह हर बार कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार आम चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ भी नहीं है और अब तक चार हजार छह सौ पचास करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की जा चुकी है। यह पिछले आम चुनाव में हुई कुल तीन हजार चार सौ पचहत्तर करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती से बहुत अधिक है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मार्च से जब्ती का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक हर रोज करीब सौ करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की जा रही है। अभी तक की गई जब्ती में करीब पैंतालीस फीसद हिस्सा मादक पदार्थों का है। इसमें केवल तीन सौ पंचानबे करोड़ रुपए नगदी जब्त की गई है। चार सौ नवासी करोड़ रुपए मूल्य की शराब और दो हजार उनहत्तर करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। छिपी बात नहीं है कि चुनावों में काले धन को सफेद करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। राजनीतिक दल बहुत सारे ज्ञात-अज्ञात स्रोतों से चंदा इकट्ठा करते हैं। इसी से पार पाने के लिए चुनावी बांड का नियम बना था। मगर वह भी पारदर्शी साबित नहीं हुआ। उसमें काले धन और संदिग्ध चंदे का प्रवाह देखा गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। मगर चुनावी बांड से आए चंदे के हिसाब-किताब से यह तो पता चल गया कि कुछ राजनीतिक दलों के पास भारी मात्रा में धन जमा हो गया है। जाहिर है, जिन दलों के पास जितना अधिक धन है, वे उतना अधिक खर्च भी करेंगे। मगर चुनाव में मनमाने खर्च से समानता के अवसर का सिद्धांत बाधित होता है। इस पर अंकुश लगाना भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है। अच्छी बात है कि इस दिशा में वह प्रयास कर रहा है। मगर धनबल से जनबल को प्रभावित करने की प्रवृत्ति इस कदर बढ़ती गई है कि प्रत्याशी और पार्टियां न केवल निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा से अधिक खर्च करने, बल्कि मतदाताओं को चोरी-छिपे नगदी और शराब, मादक पदार्थ, महंगे उपहार आदि देकर प्रभावित करने की कोशिश भी करती हैं। विचित्र है कि इसमें स्थानीय प्रशासन भी उनका सहयोग करता है। इस चुनाव में पार्टियों की मदद करते एक सौ छह सरकारी अधिकारी अब तक पकड़े जा चुके हैं। इस बार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही निर्वाचन आयोग अवैध धन के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए निगरानी दलों के गठन का एलान कर दिया था। अच्छी बात है कि वे निगरानी दल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मगर केवल जब्ती से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की इस प्रवृत्ति को कहां तक रोका जा सकेगा, कहना मुश्किल है। इस तरह मादक पदार्थ और शराब बांट कर वे लोगों को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं। जब तक उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उनमें शायद ही हिचक पैदा हो। मगर निर्वाचन आयोग को एक नख-दंत विहीन शेर बना कर रखा गया है। इसलिए राजनेता और राजनीतिक दल मनमानी से बाज नहीं आते।

संवेदनहीनता के अस्पताल

आये दिन छोटे-बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में ऐसे किस्से उजागर होते हैं, जो चिकित्सा-तंत्र की संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। लेकिन लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक मरीज के साथ एक ही बैड में शव रखना वाकई परेशान करने वाली घटना है। हालांकि, पहले कहा गया कि अज्ञात मरीज का शव एक अन्य मरीज के बिस्तर पर दो घंटे से अधिक समय तक रहा, बाद में विभागीय जांच में अवधि को 37 मिनट बताया गया। बहरहाल, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में प्रशासनिक जांच के आदेश दिये गए हैं, लापरवाही की जवाबदेही तय करके कार्रवाई की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से घटना परेशान करती है। निस्संदेह, उस मरीज की मनःस्थिति को समझा जा सकता है जो शव के साथ लेटा रहा होगा। यह घटना हमारे सरकारी अस्पतालों की बदहाली को बताती है, जिसके चलते कि एक बैड पर दो-दो मरीजों को लिटाया जाता है। ऐसे में रोगियों को अन्य संक्रमण होने की भी प्रबल संभावना बनी रहती है। विडंबना ये है कि इन अस्पतालों में वे ही मरीज आते हैं, जो मजबूरी के मारे होते हैं। वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं होते। बताया जाता है कि मरने वाले मरीज को नौ अप्रैल को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी जांघ की हड्डी टूटी थी। इस अज्ञात मरीज के साथ कोई तीमारदार भी नहीं था। लगता है कि उसे समय रहते पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि बारह अप्रैल को किसी डॉक्टर ने मरीज की फाइल में नोट लिखा कि मरीज बिस्तर पर नहीं पाया गया, जबकि मरीज चलने-फिरने में सक्षम नहीं था। उसकी फाइल में कुछ और नोट्स भी हैं लेकिन लिखने वाले डॉक्टर का नाम उसमें नहीं था। चौदह अप्रैल को मरीज को दूसरे अस्पताल में रैफर किया गया, लेकिन रैफर करने वाले डॉक्टर का उसमें उल्लेख नहीं है। कालांतर 15 अप्रैल को मरीज की सुबह ग्यारह चालीस पर मौत होना बताया गया है। शव को सवा बारह बजे के बाद मोर्चरी में शिफ्ट किया जाना बताया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच शुरू की है। बहरहाल, मामले की हकीकत जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन घटना ने एक बार फिर सिविल अस्पतालों में प्रबंधन की खामियों को उजागर ही किया है। बताते हैं कि नौ अप्रैल को भर्ती अज्ञात मरीज को ग्यारह अप्रैल तक उपचार नहीं मिला। कहना कठिन है कि उस मरीज के साथ क्या हादसा हुआ जिससे उसकी जांघ की हड्डी टूटी। क्या वो कोई राहगीर था जो किसी वाहन से हुई दुर्घटना का शिकार हुआ? यदि वह स्थानीय था तो उसके तीमारदार क्यों नहीं आए? क्या वह किसी आपराधिक साजिश का शिकार हुआ? बहरहाल, एक बात तो तय है कि दुर्भाग्य का मारा अज्ञात मरीज सिविल अस्पताल में कोताही का शिकार हो गया। बहुत संभव है कि समय रहते उसे उपचार मिलता तो शायद उसकी जान बच जाती। सवाल यह है कि गरीबों की अंतिम उम्मीद बने सरकारी अस्पतालों की बदहाली सुधारने के प्रयास क्यों नहीं किये जाते? लुधियाना जैसे बड़े व समृद्ध शहरों में तमाम व्यक्ति व समाजसेवी संगठन जनसेवा हेतु सक्रिय रहते हैं, क्यों नहीं इन अस्पतालों में पर्याप्त बैड उपलब्ध कराने के प्रयास होते हैं? तमाम राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, क्यों नहीं समाज के अंतिम व्यक्ति के उपचार के लिये आखिरी आश्रय स्थल सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिये योगदान दिया जाता? हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस दिशा में पहल करते? जनता को इन अस्पतालों में जीवन रक्षा उपकरणों व बैड आदि की व्यवस्था कराने के लिये सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह भी हकीकत है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भारी दबाव है। अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ग्रांट भी उपलब्ध नहीं करायी जाती ताकि उपचार की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। विडंबना यह भी कि यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों का भी अभाव है। युवा डॉक्टर मरीजों के दबाव व आर्थिक लाभों के सम्मोहन में सरकारी सेवाओं में आने से कतराने लगे हैं।

प्रसंगतः विश्वास

एक संत अपने शिष्यों के साथ नाव से नदी पार कर रहे थे। अचानक तेज हवाएं बहने लगीं और नदी में पानी उछलने लगा। संत की नाव के साथ जो नावें चल रही थीं, वे बुरी तरह थरथराने लगीं। कुछ ही क्षणों में लहरों का पानी नाव के भीतर आने लगा। शिष्य बुरी तरह डरने लगे। नाव के एक कोने में एक शिष्य बेफिक्र सोया था। उसके साथियों ने उसे झकझोर कर जगाया। उसने पूछा, 'क्या बात है, मुझे किस कारण से जगाया है?' उसके साथियों ने तूफान के बारे में उसे बताया। उस शिष्य ने बहुत शांति से चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और कहा, 'तूफान आते ही हैं और मनुष्य का भी अंत होता ही है। इसमें ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक बात है।' सभी साथी उसका उत्तर सुनकर सन्न रह गए। भयभीत साथियों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस शिष्य ने आंखें बंद कर लीं। उसके साथी समझ रहे थे कि उसने संकट को भली-भांति पहचाना नहीं है। इसी कारण वह स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहा है। उधर अपनी मस्ती में खोए हुए उस शिष्य ने आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की। अन्य साथियों ने समझा कि यह अपना अंतिम समय निकट जानकर भगवान से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांग रहा है लेकिन शिष्य ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, 'ऐ तूफान, तुम तुरंत शांत हो जाओ ताकि हम सुरक्षित उस पार पहुंच जाएं।' तूफान तुरंत शांत हो गया। नाव का हिलना बंद हो गया। शिष्यों ने भी चैन की सांस ली। उसके साथियों ने उस शिष्य से पूछा, 'आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि इस भयंकर तूफान को शांत कर दिया।' वह सहजता से बोला 'मित्रो, विश्वास की शक्ति असीम है। तूफान विश्वास से बड़ा नहीं हो सकता। अपने विश्वास पर सदा अडिग रहना चाहिए।'

राजनीति में अनुकरण की रणनीति

राजनीति में अनुकरण रणनीति का एक रूप है। कई क्षेत्रीय खिलाड़ी मोदी की नकल मात्र हैं। स्थानीय चुनावी आख्यान शासन के वैकल्पिक रूपों के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि क्षेत्रीय नेताओं के चारों ओर घूमता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, मुख्यमंत्री और संदेशवाहक हैं। वहां वोट या तो उनके पक्ष में होगा या विरोध में। ऐसा कर्नाटक में डीके शिवकुमार और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान के पक्ष या विरोध में मतदान होगा। ऐसे अन्य क्षेत्रीय नेता बिहार में तेजस्वी यादव, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केरल में पिनराई विजयन हैं। दुखद है और अचरज की बात भी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी वैकल्पिक संदेशवाहक नहीं बन सके। सभी पार्टियों के लिए मुद्दे या तो तभी उठाने के लिए हैं, जब बहुत जरूरी हो या ध्यान भटकाना हो।

राजनीति अतिरेकों से बुनी होती है, जिसमें स्मृति और विस्मृति के डिजाइन होते हैं। दिसंबर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी तमिलनाडु में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जीके मूपनार के लिए प्रचार कर रहे थे। वे लोग दूर-दराज के एक टोले में स्थित एक झोपड़ी में गये। मूपनार ने वहां रहने वाली बूढ़ी महिला से पूछा कि क्या वह राजीव को पहचानती है। उसने तुरंत जवाब दिया- 'हां, ये इंदिरा अम्मा के बेटे हैं। आप कौन हैं?' यह जवाब कांग्रेस और अन्य दलों के व्यक्तिगत और वंशगत कुलीनता के विरोधाभास को बिंबित करता है। मतदाता प्रधानमंत्री को जानते थे, पर क्षेत्रीय नेता को नहीं। इस चुनाव के नतीजे ने यही साबित किया। विधानसभा की 234 सीटों में कांग्रेस को केवल 26 सीटें मिलीं तथा उसे 20 प्रतिशत से भी कम वोट मिले। हालांकि 2024 का साल 1989 नहीं है, पर लगभग सभी राज्यों में स्मृति का हाल वैसा ही है। पूर्व में इटानगर से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक मतदाता तुरंत सर्वव्यापी नरेंद्र मोदी से जुड़ जाते हैं। लेकिन उनमें से आधे से अधिक ने भाजपा या उसके स्थानीय प्रत्याशी को नहीं चुना है। पहली बार आम चुनाव मुद्दों की किसी एक राष्ट्रीय सूची के बिना हो रहा है। हर क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दे हैं, पर व्यक्तिगत सर्वोच्चता सामान्य बात बन गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर माध्यम, संदेश और संदेशवाहक एक ही व्यक्ति है- नरेंद्र मोदी। प्रचार अभियानों में उनके समर्थक उनकी वैचारिक अभिव्यक्तियों से कहीं अधिक उनके व्यक्तित्व, हाव-भाव और मानसिक क्षमता से प्रभावित होते हैं। इस रणनीति से उन्हें बड़े लाभ हुए हैं और शायद तीसरी बार भी उन्हें रिकॉर्ड सफलता मिले।

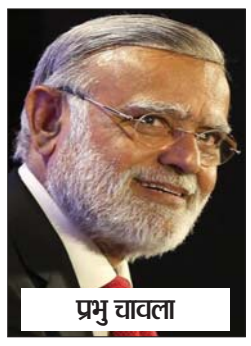
प्रभु चावला

राजनीति में अनुकरण रणनीति का एक रूप है। कई क्षेत्रीय खिलाड़ी मोदी की नकल मात्र हैं। स्थानीय चुनावी आख्यान शासन के वैकल्पिक रूपों के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि क्षेत्रीय नेताओं के चारों ओर घूमता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, मुख्यमंत्री और संदेशवाहक हैं। वहां वोट या तो उनके पक्ष में होगा या विरोध में। ऐसा कर्नाटक में डीके शिवकुमार और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान के पक्ष या विरोध में मतदान होगा। ऐसे अन्य क्षेत्रीय नेता बिहार में तेजस्वी यादव, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और केरल में पिनराई विजयन हैं। दुखद है और अचरज की बात भी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी वैकल्पिक संदेशवाहक नहीं बन सके। सभी पार्टियों के लिए मुद्दे या तो तभी उठाने के लिए हैं, जब बहुत जरूरी हो या ध्यान भटकाना हो। राजनीतिक विमर्श क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। उत्तर भारत में 'फूट डालो और राज करो' के तरीके के लिए संस्कृति, राजनीति और धर्म शिकार के मैदान हैं। लगभग 60 प्रतिशत सीटों पर मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य खिलाड़ी हैं, पर बाकी राज्यों में मोदी ही महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री केवल सांकेतिक दूसरा इंजन भर हैं।

सभी राज्यों में भाजपा विकास का कार्ड खेल रही है, पर अंततः उसका अभियान हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इसको जोड़ने वाला सूत्र मोदी का दृढ़ निश्चय है- अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर, पाकिस्तान पर लगाम और जोर-शोर के साथ गिरफ्तारियों से आतंक को कम करना। प्रधानमंत्री की सभाओं में भाजपा के मुख्यमंत्री महज कट-आउट हैं। दूसरी ओर, अखिलेश, तेजस्वी, मान, केजरीवाल, अब्दुल्ला और महबूबा अपने को मोदी के स्थानीय विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत (130 सीटें) एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां मोदी का सीधा मुकाबला ताकतवर स्थानीय क्षत्रपों से है। इसीलिए वे दक्षिणी राज्यों के अधिक दौरे करते हैं। भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने का उनका लक्ष्य पांच दक्षिणी राज्यों के नतीजों पर निर्भर करता है। भाजपा ने ऐसा कोई स्थानीय नेता नहीं तैयार किया है, जिसका जनाधार पूरे राज्य में हो। अन्नामलाई को मीडिया में खूब जगह मिली है, पर उन्हें अभी जमीन पर ठीक-ठाक स्वीकार्यता हासिल करनी है। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ी है, पर तमिल और मलयाली वोटरों की चेतना में कमल खिलना अभी बाकी है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्ना द्रमुक की सर्वाधिक लोकप्रियता है। करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद स्टालिन सबसे बड़े द्रविड़ नेता हैं। भाजपा ने कच?छतीवू का मुद्दा उठाकर द्रमुक को पीछे करने की कोशिश की, पर विफल रही। ऐसी कोशिश केरल में भाजपा ने 'द केरला स्टोरी' नामक फिल्म को प्रचारित कर की। भाजपा के स्थानीय नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया-शिवकुमार की जोड़ी की कोई बराबरी नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में लड़ाई मोदी बनाम शेष है।

पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र मोदी के जादू पर निर्भर हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की ताकत के सामने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फड़नवीस और अजीत पवार कमजोर साबित हो रहे हैं। इनके भाषणों में असली मुद्दे नहीं हैं, अधिक जोर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर है। भाजपा ने सारा दारोमदार मोदी पर छोड़ दिया है।

विजेता के निर्धारण में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पूर्वी भारत में छोटे राज्यों में भाजपा मजबूत है, पर ओडिशा में मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री पटनायक के मधुर संबंध हैं, पर पहली बार भाजपा चौथाई सदी के वर्चस्व के बाद बीजद को गंभीर चुनौती देती दिख रही है। राज्य की 21 में से 15 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजद मोदी के करिश्मे पर पटनायक के जादू को प्रभावी सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते पांच सालों में भाजपा नेताओं ने सभी राज्यों की कुल यात्रा से कहीं अधिक दौरे पश्चिम बंगाल के किये हैं। मोदी बंगाल को हिंदुत्व के चुंबक और भ्रष्टाचार विरोधी भाषणों से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसा लगता है कि यह चुनाव भारत को बेहतर बनाने और इसके लोकतांत्रिक आधार को मजबूती देने का अभियान नहीं है। यह अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने और सामने खड़े विपक्षियों को खत्म कर देने के लिए व्यक्तिगत नेताओं के बीच एक कटुतापूर्ण युद्ध है। यह आखिरी नतीजा ही तय करेगा कि क्या भारत एक ऐसा देश है, जिसे विविधता राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एकजुट करती है। यह वैश्विक स्तर पर विचारधारा के वैयक्तीकरण का दौर है। मोदी आदर्श के तौर पर भारत का संचालन कर रहे हैं और क्षेत्रीय शासक भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। **(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर है)**

चुनावी दौर में मस्क की यात्रा के यक्ष प्रश्न

- पुष्परंजन

वर्ष 1995 में धातु विज्ञान स्नातक वांग चुआनफू ने 'बीवाईडी' की स्थापना की, एक छोटी चीनी कंपनी, जो जापानी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक सस्ते में रिचार्जेबल निकल-कैडमियम बैटरी वाली कार बनाने पर केंद्रित थी। लगभग 30 साल बाद, शिएन-शान्शी और शेन्ज़ेन स्थित कंपनी 'बीवाईडी' इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की दुनिया की अग्रणी निर्माता बन गई है। टेस्ला की स्थापना 2003 में हुई थी। एलोन मस्क ने टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग जैसी कंपनियों की स्थापना की। वर्ष 2023 की आखिरी तिमाही में चीनी कंपनी 'बीवाईडी' ने प्योर-प्ले इलेक्ट्रिक कारों की वैश्विक बिक्री में अमेरिकी दिग्गज टेस्ला (टीएसएलए) को भी पीछे छोड़ दिया था। दोनों कंपनियों में रेस अब भी चल रही है। टेस्ला ने 2024 की पहली तिमाही में अपना ताज फ़िर से हासिल कर लिया है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। आम चुनाव के समय मस्क का मोदी से मिलना मानीखेज़ है।

जून, 2010 में सूचीबद्ध होने पर टेस्ला स्टॉक की कीमत 17 डॉलर प्रति शेयर थी। अब टेस्ला के शेयर 166 डॉलर पार कर चुके हैं। आज की तारीख में टेस्ला 560 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के साथ दुनिया की दिग्गज कार कंपनियों में से एक बन चुकी है। लंदन की डेटा और एनालिटिक्स कंपनी 'ग्लोबलडेटा' के बिजनेस फंडामेंटल विश्लेषक मूर्ति गांधी के अनुसार, 'जहां तक बीवाईडी का सवाल है, इसकी 81 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसे दुनिया के शीर्ष 10 वाहन निर्माताओं में से एक बनाती है। फिर भी, यह टेस्ला और टोयोटा (टीएम) और स्टेलेंटिस (एसटीएलए) जैसे अन्य कार निर्माताओं से काफी पीछे है, जो फ्रेंच पीएसए ग्रुप और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स के 2021 विलय से बना समूह है। यह समूह 14 ब्रांडों के तहत कारें बेचता है, जिनमें क्रिसलर, सिट्रोएन, जीप, मासेराती और प्यूज़ो शामिल हैं।' 2023 में, टेस्ला ने बीवाईडी की तुलना में लगभग 230,000 अधिक कारें बेचीं। फिर भी बीवाईडी की प्रतिस्पर्धी क़ीमत ने टेस्ला की महंगी कारों की लकीर छोटी कर रखी है।

बीवाईडी ने रणनीति बदली है। 4 मार्च, 2024 को अपने सबसे पॉपुलर मॉडलों में से एक, 'युआन प्लस क्रॉसओवर' का एक नया संस्करण लॉन्च किया, जिसे चीन के बाहर 'एट्टो 3' के नाम से जाना जाता है, उसकी कीमत 11 प्रतिशत घटाकर 119,800 युआन कर दी। बीवाईडी ने अपनी सबसे किफ़ायती कार, 'सीगल' को भी 5 प्रतिशत सस्ता किया। हालांकि टेस्ला ने भी पिछले साल चीन में कुछ मॉडलों की कीमतों में कटौती की थी, लेकिन वो बीवाईडी से सस्ती कारें नहीं बेच पाई।

यूके स्थित कंसल्टेंसी फर्म 'रो मोशन' के अनुसार, 'अमेरिका के बाद चीन, टेस्ला का सबसे बड़ा बाजार है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 2019 में अपने शंघाई गीगाफैक्टरी में उत्पादन शुरू किया, जहां से 947,000 कारों की डिलीवरी की। बीवाईडी अमेरिका में अपनी कारें नहीं बेचता है, हालांकि कैलिफ़ोर्निया में बीवाईडी ने बस बनाने की फैक्टरी लगा रखी है। टेस्ला और बीवाईडी दोनों अपने घरेलू बाजारों में विस्तार कर रहे हैं, साथ ही विदेशों में कारखाने लगा रहे हैं।

वर्ष 2023 में दुनियाभर में कुल 13.6 मिलियन ईवी (बीईवी और हाइब्रिड सहित) बेचे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। बीवाईडी ने 2023 में वैश्विक स्तर पर हाइब्रिड सहित लगभग 3 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। अमेरिका और कनाडा ने टेस्ला के लगभग सात लाख वाहन खरीदे, जबकि उसके छह लाख वाहन चीन में बेचे गए। यूरोपीय देशों में टेस्ला की बिक्री में लगभग चार लाख वाहन शामिल थे। बावजूद इसके, इस साल टेस्ला के शेयर 29 प्रतिशत नीचे हैं, जबकि बीवाईडी स्टॉक लगभग 6 फीसद डाउन है।

वर्ष 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2 प्रतिशत थी। मोदी सरकार 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी की हिस्सेदारी का लक्ष्य रख रही है। टेस्ला ने इस साल के अंत में भारत में निर्यात के लिए अपने जर्मन प्लांट में राइट-हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। लेकिन टेस्ला का लक्ष्य है कि उसे भारत में कार फैक्टरी लगानी है, दो अरब डॉलर का निवेश भी करना है। रोज़गार मिलते हैं, तो निश्चित रूप से श्रेय मोदी सरकार को जायेगा। मस्क ने इस सप्ताह एक्स पर कहा था, 'भारत में इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए, उतनी ही जितनी कि हर दूसरे देश में इलेक्ट्रिक कारें हैं।'

लेकिन कहानी एक कार कंपनी के विस्तार तक सीमित नहीं है। एलोन मस्क 'न्यूरालिंक' के सीईओ भी हैं, जो मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए अल्ट्रा-हाई बैंडविड्थ ब्रेन-मशीन इंटरफेस विकसित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी यह तकनीक चुनाव में किसी भी खेल को आगे बढ़ाने में सक्षम है। यूरोपीय संघ ने एलोन मस्क के इरादों को भांपकर ही उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी।

यूरोपीय संघ एलोन मस्क के स्टारलिंक उपग्रह प्रणाली के वर्चस्व पर अंकुश लगाना चाहता है। चुनांचे, यूरोपीय संघ 'आईआरआईएस' नामक संचार उपग्रहों के एक नए समूह के निर्माण और संचालन के लिए अरबों यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। एलोन मस्क यूरोपीय संघ की नज़र में अविश्वसनीय और विवादित शख्सियत हैं। ईयू ने स्पष्ट किया कि एक्स के माध्यम से एलोन मस्क ने ग़लत-सलत ख़बरें प्लांट कर, यूरोपीय देशों में चुनावों को प्रभावित करने की चेष्टा की थी। ब्राज़ील में भी कुछ ऐसा ही खेल एलोन मस्क कर चुके हैं। 1 जून, 2023 को, सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट (सीसीडीएच) ने बताया कि एक्स, जिसे पहले ट्विटर नाम दिया गया था, ग्राहकों द्वारा पोस्ट की गई 99 प्रतिशत नफरत वाले संदेशों के विरुद्ध कार्रवाई में विफल रहा है।

7 अप्रैल, 2024 को ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पर फ़र्जी सूचनाएं प्लांट करने के आरोप में एलोन मस्क को लपेटा है। जस्टिस अलेक्जेंड्रे जे मोरेस ने एक्स के बहुतेरे पॉपुलर अकाउंट्स को बंद करने के आदेश दिए। लेकिन एलोन मस्क ने स्वयं को ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझने की ताव में ताबड़तोड़ पोस्ट एक्स पर डाले- 'इस न्यायाधीश ने ब्राज़ील के संविधान और लोगों के साथ निर्लज्जतापूर्वक और बार-बार विश्वासघात किया है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, या उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए. शर्म करो ञअलेक्जेंड्रे, शर्म करो।'

सवाल यह है, एलोन मस्क चुनावी माहौल में भारत क्यों आ रहे हैं? एक्स की जो भूमिका यूरोपीय देशों और ब्राज़ील में रही, उस पर सवाल उठे हैं। क्या टेस्ला के कारोबार में लाभ के लिए सत्ताधीशों को एक्स के जरिये मदद होती है। ऐसे अनेक यक्ष प्रश्न हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

https://t.me/Allnewspaperpdf

सम्पादकीय

आचार संहिता में शिक्षा मंत्री की घोषणा और उसमें भी झोल ही झोल

शिक्षा मंत्री ने चुनाव के दौरान लगी हुई आचार संहिता के बीच पूर्व सैनिकों को शिक्षक बनाने की घोषणा कर दी। कोटा में एक चुनावी सभा के दौरान दिलावर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को बीएड का दर्जा देंगे। पहले तो आचार संहिता में इस तरह की घोषणा पर शिकायत और विवाद होना तय है। दूसरा जिस तरह की ये घोषणा है उसमें झोल ही झोल नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग ने तो इस पर एक तरह आपत्ति भी दर्ज करा दी है। फिलहाल दिलावर उस आपत्ति को मान नहीं रहे हैं लेकिन इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा इस पर संशय ही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अब बीएड डिग्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा।

कोटा के रामगंजमंडी में एक सभा के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मेरिट और आरक्षण के आधार पर शिक्षक बनाया जाएगा। सैनिकों की आकस्मिक मौत होने और शहीद होने पर वीरांगना और आश्रितों को अनुकम्पा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। रामगंजमंडी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। दिलावर ने कहा कि देश में राजस्थान शिक्षा विभाग पहली बार इसकी पहल कर रहा है। इसका प्रस्ताव जल्द तैयार कर शिक्षा विभाग सीएम भजनलाल शर्मा को भेजेगा। यहां ये उल्लेखनीय है कि कुछ पूर्व सैनिकों ने शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है।

अधिकारियों का कहना है कि पूर्व सैनिकों की शिक्षा ट्रेनिंग, शिक्षा विभाग से कम है। ऐसे में पूर्व सैनिकों को शिक्षक नहीं बनाया जा सकता हैं। लेकिन विभाग के इस तर्क को दिलावर दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने भरी सभा में कहा है कि इसको लेकर अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि रिटायर्ड सैनिकों को बीएड डिग्री के बराबर मानना पड़ेगा। ऐसे में अब पूर्व सैनिकों को मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर सरकारी टीचर बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय सैनिकों की सामान्य मौत हो जाती है या युद्ध के दौरान शहीद हो जाते है। इसके बाद परिवार के पालन पोषण में काफी समस्या आती है, लेकिन फिर भी शहीद की वीरांगनाओं को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। अब वीरांगनाओं और शहीद के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसके लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता में घोषणा का विवाद बढ़ा तो शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि इसमें नई घोषणा नहीं की है जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी जानकारी दी गई है। जो नियम है, उनके अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। कई रिटायर्ड सैनिकों ने शिक्षा विभाग में आवेदन किया, लेकिन पूर्व सैनिकों की शिक्षा ट्रेनिंग को आधार मानते हुए उन्हें विभाग में मौका नहीं मिला था। जब यह बातें सामने आई तो अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बीएड के समकक्ष रिटायर्ड फौजियों को माना जाए, उसके आधार पर वह परीक्षा दे सकेंगे और मेरिट के हिसाब से सलेक्शन होगा।

विश्व विरासत दिवस

भारत की बेमिसाल विरासत से दुनिया स्तंभित

अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ ये दो संगठन है, जो इस बात का आकलन करते हैं कि स्थल विश्व धरोहर बनने लायक है या नहीं। साल में एक बार इस विषय के लिए समिति की बैठक होती है और फिर उन जगहों का चयन करती है, उसके बाद दोनों संगठन इसकी सिफारिश विश्व धरोहर समिति से करते हैं। फिर ये फैसला लिया जाता है कि उस जगह को विश्व धरोहर बनाना है या नहीं। विश्व विरासत दिवस की इसलिए अपने आप में एक वैश्विक महत्ता है, क्योंकि इसके जरिए दुनिया में सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में सहूलियत मिल रही है। विश्व की विरासतें मानव को सतत रूप से प्रेरित करती हैं। सिर्फ किसी समाज की विरासत उसी समाज को प्रेरित नहीं करती बल्कि विश्व के दूसरे समाजों को भी विरासत अच्छी तरह से प्रेरित करती है। विरासत दिवस के चलते पर्यावरण और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है।

ललित गर्ग

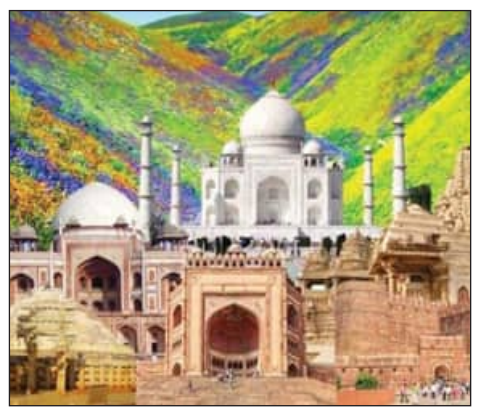

मानव सभ्यता के इतिहास और विरासत को एक साथ सम्मान देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग त्योहारों, परंपराओं और स्मारकों के माध्यम से अपनी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाते हैं। इस दिवस को मनाते हुए यूनेस्को असाधारण मूल्य के सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के साथ जुड़े एक समृद्ध इतिहास को बढ़ावा देता है। पहला विश्व धरोहर दिवस ट्यूनीशिया में मनाया गया था। विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईसीओएमओएस) ने की थी। इसके बाद 1983 में इसे 'यूनेस्को' की मंजूरी मिली। 1983 के बाद से हर साल अलग-अलग थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस दुनियाभर में मनाया जाता है। 2024 की आधिकारिक थीम हमारे वैश्विक विरासत की रक्षा करना है। यूनेस्को किसी स्मारक या स्थल को धरोहर घोषित करता है तो उसके बाद उस जगह का नाम विश्व में काफी मशहूर हो जाता है। जिससे वहां विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी काफी बढ़ जाता है, जिसका लाभ सीधा देश की अर्थव्यवस्था एवं वहां के पर्यटन व्यवसाय को मिलता है। विश्व धरोहर घोषित होने के बाद उस जगह का खास ध्यान रखा जाता है और उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। यदि ये स्मारक ऐसे देश में है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो यूनेस्को ही स्मारक की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। विभिन्न समुदायों के बीच रिश्तों को आत्मीय और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और मानवीय उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार होती हैं। यही वजह है कि विश्व विरासत को दुनियाभर के मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। विश्व विरासत दिवस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को लाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी है। यह पर्यटन को प्रोत्साहन देने का सशक्त माध्यम है। भारत की अर्थव्यवस्था पर्यटन-उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राजस्थान भारत का एक राज्य है जो विश्व विरासत का समृद्ध केन्द्र है, यह पर्यटन के लिए सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। राजस्थान की पुरातात्विक विरासत या

सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत है। यूं तो भारत के सभी राज्यों में समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी है। प्राकृतिक सुंदरता और महान इतिहास से संपन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धिशाली है। राजस्थान देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के लिए एक सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारत की सैर करने वाला हर तीसरा विदेशी सैलानी राजस्थान देखने ज़रूर आता है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हैं। इन प्रसिद्ध विरासत स्थलों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों पर्यटक आते हैं। जयपुर का हवामहल, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के धोरे काफी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथम्भोर दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। यहाँ शेखावटी की कई पुरानी हवेलियाँ भी हैं जो वर्तमान में हैरीटेज होटलें बन चुकी हैं। पर्यटन ने यहाँ आतिथ्य क्षेत्र में भी रोज़गार को बढ़ावा दिया है। यहाँ की मुख्य मिठाई 'घेवर' है। राजस्थान असंख्य पर्यटन अनुभवों, व्यंजनों और मोहक स्थलों का प्रांत है। चाहे भव्य स्मारक हों, प्राचीन मंदिर या मकबरे हों, नदी-झरने, प्राकृतिक मनोरम स्थल हो, इसके चमकीले रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाले इसके वर्तमान से अटूट संबंध है। यहां सभी प्रकार के पर्यटकों को चाहे वे साहसिक यात्रा पर हों, सांस्कृतिक यात्रा पर या वह तीर्थयात्रा करने आए हों, सबके लिए खूबसूरत जगहें हैं। यह राजस्थान पल-पल परिवर्तित, नितनूतन, बहुआयामी और इन्द्रजाल की हद तक चमत्कारी यथार्थ से परिपूर्ण समृद्ध विरासत का खजाना है। इस राजस्थान की समग्र विविधताओं, नित नवीनताओं और अंतर्विरोधों से साक्षात्कार करना सचमुच अलौकिक एवं विलक्षण अनुभव है। देश-दुनिया में हमारे पूर्वजों ने विभिन्न शिल्प-कलाओं में जो शानदार कृतियां (स्मारक, ग्रंथ, मंदिर, किले, महल या मकबरे आदि के रूप में) उकेरीं, वो आज हम सभी के सामने महान सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में मौजूद हैं। ये हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, साथ ही आर्थिक लाभ का जरिया भी बनते हैं। भारतीय संस्कृति में हरे-भरे पेड़, पवित्र नदियां, पहाड़, झरनों, पशु-पक्षियों की रक्षा करने का संदेश हमें विरासत में मिला है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से केवल स्मारक एवं स्थल हीं नहीं, प्रभु श्रीराम जैसे महानायकों का जीवन भी दुनिया के लिये प्रेरणास्रोत रहा है। स्वयं भगवान श्रीराम व माता सीता 14 वर्षों तक वन में रहकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया। ऋषि-मुनियों के हवन-यज्ञ के जरिए निकलने वाले ऑक्सीजन को अवरोध पहुंचाने वाले दैत्यों का वध करके प्रकृति की रक्षा की। जब श्रीराम ने हमें प्रकृति के साथ जुड़कर रहने का संदेश दिया है तो हम वर्तमान में क्यों प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने 550 साल पहले रामचरित मानस की रचना करके श्रीराम के चरित्र से दुनिया को श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ भाई, प्रकृति प्रेम और मर्यादा का पालन करने का संदेश दिया है। रामचरित मानस एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आपको देखकर अपना वर्तमान सुधार सकता है एवं पर्यावरण की विकराल होती समस्या का समाधान पा सकता है। प्रकृति एवं पर्यावरण के आधार नदियों एवं पहाड़ों के साथी बनना होगा, उनका संरक्षण एवं सम्मान करना होगा, तभी विश्व विरासत दिवस मनाना सार्थक होगा। भारत में विश्व धरोहरों का सम्मान इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक भारत पहले विदेशी आक्रांताओं और फिर साम्राज्यवादी लूट-खसोट का केंद्र रहा है, इसलिए पिछले लगभग 1000 सालों में भारत की सांस्कृतिक विरासत न सिर्फ बड़े पैमाने पर छिन्न-भिन्न हुई बल्कि इन विदेशी लुटेरों और साम्राज्यवादी षड़यंत्रकारियों ने लोगों के दिलोदिमाग में ऐसी हीनताबोध भी भर दिया कि आम हिंदुस्तानियों को अपने इतिहास, संस्कृति और परंपरा में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज ही नजर नहीं आती थी, जिसे सांस्कृतिक धरोहर मानकर उसके प्रति गौरवबोध का एहसास हो।

आदर्श समाज व्यवस्था का मूल आधार है प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीना। रामायण में आदर्श समाज व्यवस्था को रामराज्य के रूप में बताया गया है उसका बड़ा कारण है प्रकृति के कण-कण के प्रति संवेदनशीलता। विश्व विरासत दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि चिंतन, कार्रवाई और प्रतिबद्धता का दिन है। इस अवसर का उपयोग सभी के लाभ के लिए अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संरक्षण में योगदान देना है। यह वैश्विक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चिंतन करता है और इन अमूल्य खजानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है।

आज का इतिहास

18 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने 1612 में मुमताज से निकाह किया।
- सन 1853 में एशिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से तन्ना तक चलायी गयी।
- वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्यां तोपे को 1859 में फांसी दी गयी।
- सेन फ्रांसिस्को में 1906 में आये भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत।
- महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया।
- यांकी स्टेडियम 1923 में ब्रोंक्स में खुल गया।
- सूर्य सेन उर्फ मास्टर दा और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 62 लोगों ने 1930 में चटगांव शास्त्रागार पर धावा बोला।
- नीदरलैंड के हेग में 1948 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ।
- बांडुंग में 1955 में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- सम्राट अशोक नामक देश का पहला जंबो जेट विमान 747 सन 1971 में मुंबई में उतरा।
- प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह का 1978 में निधन।
- जिंबाब्वे ने 1980 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने की घोषणा की।
- सन 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ।
- वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ ब्रायन लारा ने 1994 में 375 रन बनाकर टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकार्ड बनाया।
- सन 2001 में भारतीय सीमा में घुस आई बांग्लादेश की सेना की गोलीबारी से भारत के 16 जवान शहीद हुए थे।
- 1973 से इटली में निवास कर रहे अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व शासक मोहम्मद जहीर शाह 2002 में काबुल लौटे।
- पाकिस्तान ने 2008 में भारतीय क़ैदी सरबजीत सिंह की फांसी की सजा को एक महीने के लिए टाला।
- भारत और मैक्सिको ने 2008 में नागरिक उड्डयन और ऊर्जा के क्षेत्र में नये समझौते किए।
- इंफोसिस टैक्नोलाजी ने 2008 में विकास एवं मरम्मत सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका की कॉनसेको के साथ पाँच वर्ष के लिए क़रार किया।
- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में जानलेवा इंजेक्शन के ज़रिये सज़ा-ए-मौत को वैध ठहराया।
- इराक की राजधानी बगदाद में 2013 में हुए बम धमाकों से 27 की मौत, 65 घायल।
- माउंट एवरेस्ट में सन 2014 में आए हिमस्खलन से नेपाल के 12 पर्वतारोहियों की मौत।

18 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- सिक्खों के नौवें गुरु गुरु तेग़ बहादुर का जन्म 1621 में हुआ।
- आधुनिक भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक और उद्धारक धोंडो केशव कर्वे का जन्म 1858 में हुआ।
- भारत के राजनीतिज्ञ चन्देश्वर प्रसाद नारायण सिंह का जन्म 1901 में हुआ।
- हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का जन्म 1916 में हुआ।
- बालीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों का जन्म 1961 में हुआ।

विशेष आलेख

क्या रघुराजन के अनुसार मोदी को विकसित भारत का सपना नहीं देखना चाहिए

रामस्वरूप रावतसरे

आरबीआई (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि चीन और साउथ एशिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत अपने युवाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उनका कहना है कि भारत को अपने लोगों की स्किल को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। मोदी सरकार की नीतियों के धुर आलोचक माने जाने वाले राजन ने कहा कि भारत में हर सेक्टर में समस्या है और यही वजह है कि कई इनोवेटर्स विदेश जाकर कंपनियां बना रहे हैं। देश में भयंकर बेरोजगारी है। हालत यह है कि पीएचडी वाले भी रेलवे में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। राजन में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को जीडीपी के सही आंकड़े बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बीच में हैं लेकिन समस्या यह है कि हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। चीन और कोरिया जब इस स्थिति में थे तो उन्होंने इसका कहीं बेहतर तरीके से फायदा उठाया था। लेकिन हम अपने युवाओं को काम नहीं दे पा रहे हैं। सवाल उठता है कि हम कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हम लोगों की क्षमताओं को बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। साथ ही रोजगार की प्रकृति भी बदली जा सकती है। हमें दोनों मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। भारत से प्रतिभाओं के पलायन के बारे में राजन ने कहा कि आज कई भारतीय इनोवेटर सिंगापुर या सिलिकॉन वैली जाकर कंपनियां बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें वहां काम करना आसान लगता है। उन्होंने कहा, हमें यह पूछना चाहिए कि उन्हें भारत के बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इनमें से कई लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं और भारत में रहकर खुश नहीं हैं। वे वैश्विक स्तर पर अपना विस्तार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत में युवाओं के वर्ग की मानसिकता विराट कोहली जैसी है। यानी हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सर्विसेज, मैन्यूफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन हर क्षेत्र में समस्या है। देश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। महिलाओं की भागीदारी तो बहुत कम है। पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। सरकारी नौकरियों के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं। पीएचडी वाले भी रेलवे में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या पिछले 10 साल में पैदा नहीं हुई है बल्कि यह समस्या कई दशक से बढ़ रही है। हमें यह देखने की जरूरत है कि गलती कहां हुई है और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। हम लंबे समय तक इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत में बेरोजगारी की समस्या बताते है लेकिन उसके समाधान में बस इतना कहते है कि यह समस्या कई दसकों से है। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका समाधान क्या हो सकता है? यहां सब कुछ गोलमाल है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कुछ समय पहले कहा था। भारत सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्यूफैक्चरिंग में बड़ा दांव खेलने जा रहा है। देश में चार सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि अगले पांच साल में भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने की रेस में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करके वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने से भी जरूरी कई काम हैं। उसके इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर फोकस करने के बजाय अपने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। रघुराम राजन ने एक नोट में कहा कि भारत सरकार हायर एजुकेशन के सालाना बजट से ज्यादा पैसा चिप मैन्यूफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी के रूप में दे रही है। यह अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से यह विकसित देश बनने का रास्ता नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों के धुर विरोधी रहे राजन ने साफ किया कि उनकी बात का यह मतलब नहीं है कि भारत को कभी भी सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज हर देश यही कर रहा है। इस रेस में पड़ने का मतलब खुद को बर्बाद करना है। भारत ने पिछले महीने तीन सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी थी। इन पर कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा जिसमें सरकार की तरफ से 48,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। राजन ने अपने नोट में कहा कि वास्तव में चिप सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी है। इसका मतलब यह है कि इसका फ्रंट से भुगतान किया जाएगा, यह प्रॉडक्शन पर आधारित नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि जल्दी ही चिप्स का प्रॉडक्शन शुरू हो जाएगा। अगर यह दावा सही है तो कैपिटल सब्सिडी जल्दी हो देनी होगी। लेकिन कोई नौसिखिया ही इस पर यकीन करेगा कि सब्सिडी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर सब सही रहा तो हमें 28 एनएम चिप्स मिलेगी। आज मॉडर्न सेल फोन पर तीन एनएम की चिप लगती है। अगर हमें फ्रंटियर में ग्लोबल चिप मैन्यूफैक्चरर बनना है तो हमें उस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ फैक्ट्रीज को सब्सिडी देनी होगी। इसकी वजह यह है कि आधुनिक चिप बनाने में ज्यादा मॉडर्न मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी यूज होती है जो ज्यादा महंगी होगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि भारत के लिए चिप मैन्यूफैक्चरिंग से भी जरूरी कई काम हैं। जैसे कॉलेजों में स्पेक्ट्रोमीटर लगाना ताकि साइंस के बेहतर छात्र पैदा कर सके। यह साफ नहीं है कि सरकार कैसे तय करती है कि किस इंडस्ट्री, सेक्यर या कंपनी को सब्सिडी चाहिए। चिप मैन्यूफैक्चरिंग में ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है जबकि इस समय रोजगार हमारी सबसे बड़ी चुनौती हैं।

हर व्यक्ति में श्रेष्ठता की सम्भावनांए है, बस तराशने की जरूरत है

रामस्वरूप रावतसरे

सुरेश परिवार की आर्थिक कमजोरी के कारण अपनी पढ़ाई के दौरान विश्वविद्यालय स्तर तक भी नहीं पहुँच सका था। उसके माता पिता ने कम उम्र में ही उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद, उसने एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। अनुभव की कमी के कारण, एक सप्ताह से भी कम समय में छात्रों नें उसे परेशान कर दिया। जब वह आँसुओं के साथ घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और कहा, ''आपको इसके बारे में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। शायद कोई और उपयुक्त नौकरी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी!'' थोड़े समय पश्चात सुरेश को एक और नौकरी मिल गई पर, जल्द ही उसकी धीमी गति के कारण उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। इस बार पत्नी ने कहा, ''इस बार आपको जहाँ मौका मिला था वहाँ कुशल और गैर कुशल दोनों तरह के लोग थे। कुछ को अपने काम का वर्षो का अनुभव था। जहाँ तक आपकी बात है, आप उस समय स्कूल में थे, इसलिए आपको इन आवश्यक कौशलों का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता था?'' इसलिए चिंता ना करें आगे सब ठीक होगा। फिर सुरेश कई नौकरियों के लिए गया पर किसी भी नौकरी में कभी भी लंबे समय तक नहीं रह सका। वह हर बार निराश होकर घर लौटता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे दिलासा देती थी और वह कभी उससे निराश या नाराज नहीं होती थी। वह जब अपनी उम्र के तीसरे दशक में था, तब उसे भाषाओं के ज्ञान में रूचि जागी। वह मूक-बधिर के एक स्कूल में सलाहकार बन गया। फिर धीरे-धीरे उसने विकलांगों के लिए अपना एक स्कूल भी खोल लिया। कुछ वर्षों बाद उसने विकलांगों के उपकरण बेचने वाले आउटलेट्स की विभिन्न शहरों और प्रांतों में, बिक्री श्रृंखला स्थापित कर ली। उसका काम चल निकला। अब वह करोड़पतियों की श्रेणी में आ गया। एक दिन सुरेश ने अपनी पत्नी से पूछा, ''जब मैं हर काम में असफल हो रहा था, तो क्या कारण था कि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास था?'' उसकी पत्नी ने उसे बहुत ही आसान सा जवाब दिया। उसने कहा, ''जब जमीन का एक टुकड़ा गेहूँ बोने के लिए उपयुक्त नहीं होता तो हम वहाँ दालें लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर दालें अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही हैं, तो हम वहाँ फल या सब्जियाँ लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि वह फसल भी किफायती साबित नहीं होती है, तो हम इसके बजाय दूसरे अनाज के बीज बिखेर सकते हैं। हो सकता है किसी कारण से ये बीज भी इस भूमि के लिए उपयुक्त नहीं हो। लेकिन निश्चित रूप से इस भूमि में किसी ना किसी प्रकार के बीज तो उपयोगी होंगे ही। उन बीजों का उपयोग करेगें तो वही बीज एक दिन इस धरती पर फूल बनकर खिलेंगे। बस हमें यह पता लगाना होगा कि इस भूमि के लिए कौन से बीज बेहतर हैं?'' पत्नी की बात सुनकर वह रोने लगा क्योंकि पत्नी के विश्वास, प्रेम, धैर्य और दृढ़ता ने उसके लिए बेहतरीन काम किया था।''इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है। हर कोई उपयोगी और श्रेष्ठ है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना वह बेहतरीन और विशिष्ट गुण खोजना होता है। जिसमें वह पारंगत है और उसकी तलाश सतत रूप से जारी रखनी होती है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। पार्टनरों का सहयोग प्राप्त होगा। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। व्यापार में अधिक लाभ होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

वृष
मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। लेन-देन में सावधानी रखें। शत्रुओं का पराभव होगा। विवाद को बढ़ावा न दें। भय रहेगा। प्रमाद न करें। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

मिथुन
छोटे भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। संचित कोष में वृद्धि होगी। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। स्थायी संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बन सकती है। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी।

कर्क
कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बेचैनी रहेगी। चोट व रोग से बचें। विवेक से कार्य करें। लाभ में वृद्धि होगी। मान-सम्मान मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं।

सिंह
वाणी पर नियंत्रण रखें। अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है।

कन्या
आय में निश्चितता रहेगी। मातहतों से अनबन हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं में इजाफा होगा। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। भागदौड़ रहेगी। दूर से बुरी खबर मिल सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। बनते कामों में बाधा हो सकती है।

तुला
भाइयों का सहयोग मिलेगा। पुराने किए गए प्रयासों का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। नौकरी में चैन रहेगा। निवेश शुभ रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा।

वृश्चिक
आय में निश्चितता रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें। लाभ बढ़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें। जल्दबाजी से हानि होगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। दूसरों के कार्य में दखल न दें। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

धनु
जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। घर-बाहर सभी अपेक्षित कार्य पूर्ण होंगे। दूसरों के कार्य की जवाबदारी न लें।

मकर
चिंता तथा तनाव रहेंगे। पार्टनरों से मतभेद संभव है। व्यवसाय ठीक चलेगा। समय नेष्ट है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। जरा सी लापरवाही से अधिक हानि हो सकती है। पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है।

कुंभ
दूसरों से अपेक्षा न करें। कुसंगति से हानि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी बड़े काम करने की योजना बनेगी। व्यवसाय लाभप्रद रहेगा।

मीन
व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। किसी के व्यवहार से स्वाभिमान को चोट पहुंच सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कोई बड़ी बाधा आ सकती है। राजभय रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। अपेक्षित कार्यों में विलंब होगा।

सुप्रीम कोर्ट की बाबा रामदेव को फटकार

पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बाबाओं का उदय हुआ है। इसके पहले भी बाबा हुआ करते थे मगर इन दिनों बाबाओं का जितना राजनैतिक और सामाजिक दबदबा है, उतना पहले शायद कभी नहीं रहा। कई बाबा अनेक तरह के काले कामों में लिप्त भी पाए गए हैं मगर उनकी दैवीय छवि के चलते उनके अपराधों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर उनके आश्रम के एक कर्मी शंकर रमण की हत्या का आरोप था। सत्यसाईं बाबा के प्रशांति निलयम में भी एक हत्या हुई थी। गुरमीत राम रहीम के कुकर्मों को उजागर करने के लिए पत्रकार छत्रपति रामचंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंततः राम रहीम कानून के पंजे में फँस गया और इन दिनों जेल में है। यह अलग बात है कि वो अधिकांश समय पैरोल पर बाहर रहता है। आसाराम बापू लम्बे समय तक कानून की पकड़ से दूर रहा मगर अब वह सीखचों के पीछे है। इस समय बागेश्वर धाम नामक एक बाबा काफी लोकप्रिय है। ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। देश में असंख्य बाबा हैं जो अपने-अपने अंधभक्तों की भीड़ से घिरे रहते हैं। उनकी रईसी देखते ही बनती है। दो अन्य बाबाओं का जिक्र जरूरी है। एक हैं श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने अपने उत्सव के लिए यमुना को बर्बाद कर दिया था। वे अन्ना हजारे के आरएसएस-समर्थित आन्दोलन से भी जुड़े हुए थे। फिर बाबा रामदेव हैं। रामदेव ने अपने करियर की शुरुआत योग गुरु के रूप में की थी। लेकिन बाद में उन्होंने पतंजलि ब्रांड नेम से व्यापार शुरू कर दिया। आयुर्वेदिक उत्पादों को बनाने और बेचने वाली इस कंपनी ने बाबा रामदेव को अरबपतियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है और उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। या कम से कम अब तक तो नहीं था। उनके आयुर्वेदिक उत्पादों का जबरदस्त प्रचार-प्रसार हुआ और मीडिया का एक बड़ा तबका उनका गुणगान करने लगा। बाबा और आचार्य की शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बहुत नहीं जानते। इस समय देश में कई आयुर्वेदिक कॉलेज हैं मगर इन दोनों के पास शायद आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं है। पड़ताल से बचने के लिए रामदेव ने देशभक्ति का लबादा ओढ़ लिया और यह कहते रहे कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं। असली खेल शुरू हुआ कोविड-19 महामारी के दौरान। एक ओर सरकार ने पुणे स्थित भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का विकास और उत्पादन करने हेतु भारी आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई वहीं बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि उनकी कंपनी ने कोविड-19 के इलाज और उससे बचाव के लिए एक दवाई विकसित की है जिसका नाम है कोरोनिल। हमें यह भी बताया गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमोदन प्राप्त है। जब आयुष मंत्रालय ने इस दावे को चुनौती दी तो पतंजलि की ओर से यह कहा गया कि कोरोनिल 'डब्ल्यूएचओ के मार्गनिर्देशों के अनुरूप है। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के बारे में दावों को सत्यापित करने से इंकार कर दिया। इसके बाद भी कोरोनिल के कांबो पैक को बड़ी धूमधाम से दो केबिनेट मंत्रियों- डॉ. हर्षवर्धन और नितिन गडकरी, की उपस्थिति में जारी किया गया। हर्षवर्धन स्वयं एलोपैथिक डाक्टर हैं। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से यह जाहिर है कि वे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के कितने अंधभक्त हैं। बाबा ने दावा किया कि कोरोनिल का परीक्षण मामूली से लेकर मध्यम श्रेणी के कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों पर किया गया और कोरोनिल का सेवन करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका कोविड टेस्ट निगेटिव हो गया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किसी भी नई दवा को सामान्य उपयोग के लिए जारी करने के पहले उसका जैव रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, पशुओं पर उसका परीक्षण किया जाता है और फिर समुचित आकार के नमूनों पर उसकी डबल ब्लाइंड ट्रायल की जाती है। कोरोनिल के मामले में इनमें से कुछ भी नहीं किया गया। अपनी व्यवसायिक सफलता से गदगद बाबा रामदेव ने गोदी मीडिया की प्रशंसा को कबूल किया। इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एलोपैथी को एक बेवकूफाना विज्ञान बताना शुरू कर दिया। इससे व्यथित होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने रामदेव के खिलाफ प्रकरण दायर किया जिसकी सुनवाई हाल में हुई। रामदेव ने अदालत में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अपमान करने के लिए आईएमए से क्षमायाचना की। वहां पाठकों को यह याद दिलाना श्रेयस्कर होगा कि बाबा रामदेव ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी तब उन्होंने यह दावा किया था कि योग के कारण उनका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वे लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं। मगर उपवास प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी हालत इतनी पतली हो गई कि उन्हें एक एलोपैथिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी तरह करीब एक वर्ष पहले जब आचार्य बालकृष्ण बीमार पड़े तो वे एक एलोपैथिक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गए। उच्चतम न्यायालय की चेतावनियों के बाद भी बाबा की कंपनी भ्रामक विज्ञापन जारी करती रही। अदालत ने उन्हें बुलाया और बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। मगर अदालत ने उनकी माफी मंजूर नहीं की। अदालत में चल रहे प्रकरण का नतीजा चाहे जो हो सवाल यह है कि देसी चिकित्सा पद्धतियों और आस्था पर आधारित ज्ञान के आधार पर कोई भला किस तरह आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मखौल बना सकता है? यह मानने से किसी को इंकार नहीं है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ही नहीं बल्कि दादी मां के नुस्खों में भी कुछ ज्ञान हो सकता है। मगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति साक्ष्य और साथी चिकित्सकों व वैज्ञानिकों की समीक्षा पर आधारित होती है। हर दावे को हर तरह की समीक्षा और समालोचना का सामना करना पड़ता है। और इसके नतीजे में ही ऐसी चीजें विकसित होती हैं जो मानवता के लिए उपयोगी साबित होती हैं। इसके विपरीत आस्था पर आधारित ज्ञान और उससे जुड़ी चिकित्सा प्रणालियों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। हर बाबा अपनी तरह से रोगों का इलाज करता है। चिकित्सा प्रणालियों के प्रोटोकाल में लगातार सुधार इसलिए होता रहता है क्योंकि उसकी समीक्षा करने का अधिकार सभी को होता है। इसके विपरीत रामदेव जैसे लोग अपने दैवीय दर्जे का लाभ उठाते हुए मनमाने दावे करते हैं और उन्हें न तो कोई चुनौती देता है और न कोई उनकी आलोचना करता है। बाबा ने यह दावा भी किया था कि वे कैंसर और एड्स का इलाज भी कर सकते हैं। वे तो समलैंगिकता को भी एक रोग मानते हैं और उनका दावा है कि वे इलाज से उसे ठीक कर सकते हैं। अब तक उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और इसी के चलते वे इतने अहंकारी हो गए थे कि वे एलोपैथी का मजाक बनाते थे और 'अपनी प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। बाबा लोग इतने मजे में क्यों हैं? इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में धर्म के नाम पर राजनीति का बोलबाला बढ़ा है। इसके साथ ही प्राचीन ज्ञान का भी महिमामंडन किया जा रहा है। वैज्ञानिकता और तार्किकता में विश्वास करने वाले लोग चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा जाए।

आरती कुमारी

पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है सनातन हिंदू धर्म

पूरे विश्व में आज विभिन्न देशों के नागरिकों में शांति का अभाव दिखाई दे रहा है एवं परिवार के सदस्यों के बीच भी भाईचारे की कमी दिखाई दे रही है। शादी के तुरंत बाद तलाक लेना तो जैसे आम बात हो गई है, आज कई विकसित देशों में तलाक की दर 60 प्रतिशत से भी अधिक है। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाला उनका अपना कोई साथ नहीं है। अमेरिका में तो लगभग 10 लाख बुजुर्ग नागरिक खुले में रहते हुए अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इन देशों में तो जैसे सामाजिक तानाबाना ही छिन्न भिन्न हो गया है। इसी प्रकार के अन्य कई कारणों के चलते आज सनातन हिंदू धर्म के प्रति विदेशी लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का अपना एक अलग ही महत्व है। सनातन हिंदू धर्म में कुटुंब के प्रति वफादारी बचपन से ही सिखाई जाती है। भारत में आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में हैं, जिससे बच्चे अपने बचपन में ही अपने माता पिता की सेवा करने के संस्कार सीखते हैं और उन्हें पूरे जीवन भर अपने साथ रखने का संकल्प लेते हैं। विश्व में कुछ अन्य धर्मों में बच्चों को बचपन में ही कट्टरता सिखाई जाती है एवं केवल अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में पेश किया जाता है। इससे इन बच्चों में अन्य धर्मों के प्रति सद्भावना विकसित नहीं हो पाती है। कई बार तो अन्य धर्म को मानने वाले नागरिकों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें अपना धर्म मानने को मजबूर भी किया जाता है। इसके ठीक विपरीत सनातन हिंदू धर्म किसी अन्य मजहब को मानने वाले व्यक्ति पर कभी भी कोई दबाव नहीं डालता है। सनातन हिंदू संस्कृति अन्य धर्मों के नागरिकों को किसी प्रकार का धर्म मानने की खुली स्वतंत्रता प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था तब इस धरा पर निवास करने वाले लोग केवल सनातन हिंदू धर्म का ही पालन करते थे। सनातन हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा संयमित धर्म है जो किसी अन्य धर्म की ना तो उपेक्षा करता है और न ही वह अपने धर्म के वर्चस्व को सबके सामने रखने का प्रयास करता है। इसी कारण से कट्टरता के इस माहौल में आज पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था एवं रुचि बढ़ रही है। सनातन हिंदू धर्म आज विश्व में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और भारत में अधिकतर लोग इस धर्म को मानते हैं। एक अनुमान के अनुसार सनातन हिंदू धर्म इस पृथ्वी पर 10,000 वर्षों से हैं। लेकिन यदि वेदों और उपनिषदों में लिखी बातों को माने तो सनातन हिंदू धर्म की उत्पति लाखों वर्ष पहिले हुई थी उस समय ये सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते थे। इस धर्म को बहुत प्रभावशाली माना गया है। अन्य कुछ धर्मों के संस्थापक रहे हैं, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में प्रभु यीशू को माना जाता है तथा इस्लाम धर्म के लिए मोहम्मद साहिब को संस्थापक माना जाता है और बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध को संस्थापक जाना जाता है। परंतु, हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि कुछ संतों एवं महापुरूषों ने एक

होकर जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने का तरीका विकसित किया था। सनातन हिंदू संस्कृति को, धर्म नहीं बल्कि यह, जीवन जीने का एक तरीका भी माना जाता था। सनातन हिंदू धर्म का यह मानना है कि प्रभु परमात्मा ने इस धरा पर सबको खुलकर हंसने, उत्सव मनाने और मनोरंजन करने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सनातन हिंदू धर्म में सबसे अधिक त्यौहार और संस्कार होते हैं। उत्सव, जीवन में सकारात्मक संदेश लेकर आते हैं और हमारे संस्कार मिलन सरिता को दर्शाते हैं। सनातन हिंदू धर्म की यही प्रक्रिया दुनिया पसंद करती है। तभी तो ब्रिज की होली और कुम्भ के मेले का अवलोकन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग भारत में आते हैं। यही एक कारण है कि आज पूरी दुनिया के कोने कोने में लोग हिंदू धर्म में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार, आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदूओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हिंदू वहां राजनैतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा, कोरोना महामारी के बाद से पूरे अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों में योग और ध्यान की ओर लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। योग और ध्यान पूरे विश्व को सनातन हिंदू धर्म की ही देन है। सनातन हिंदू धर्म बिलकुल ही कट्टरपंथी धर्म नहीं है। अन्य धर्मों की तरह इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं हैं। इस धर्म में धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है जैसा कि कुछ अन्य धर्मों में होता है। हिंदू धर्म मानता है कि शिक्षा सभी तरह की होनी चाहिए केवल धार्मिक आधार पर शिक्षा देना उचित नहीं है। किसी भी बच्चे की शिक्षा में अगर संस्कार जुड़ जाए तो वह बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और वह एक अच्छा इंसान बनता है। सनातन हिंदू धर्म में परोपकार की भावना होती है। अन्य धर्मों की तरह यह केवल अपने वर्चस्व के बारे में नहीं सोचता है। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बहुल देश हैं वहां पर सनातन हिंदू धर्म से जुड़े संस्कार आज भी पाए जाते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह देश हिंदू धर्म से कितना प्रभावित रहा है। मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद हिंदू धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव यहां आज भी दिखाई देता है। मुस्लिम लोग भी अपना नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखना पसंद करते हैं। सनातन हिंदू धर्म कभी भी किसी नागरिक पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालता है। सनातन हिंदू धर्म कभी भी किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है। परंतु, आज प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में बहुत से लोग अन्य धर्मों को छोड़कर स्वप्रेरणा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म में स्त्रियों को जितना सम्मान दिया जाता है उतना किसी भी अन्य धर्म में नहीं दिया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में स्त्रियों की पूजा की जाती है। सनातन हिंदू धर्म में आस्था का मतलब है कि जीवन में उमंग, उत्साह, उल्लास और मानवता की ओर झुकाव।

जहां भारत में सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की नाकाम कोशिश की जाती है वहीं रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, घाना, सुरीनाम जैसे देशों में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है। कई देशों में तो आज सनातन हिंदू संस्कारों का अनुपालन करते हुए विशेष गांव स्थापित किए जा रहे हैं। आयरलैंड में 22 एकड़ का एक हिंदू आइलैंड बन गया है। इसे हरे कृष्णा आइलैंड का नाम दिया गया है। यहां निवासरत समस्त नागरिकों द्वारा सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन रीति रिवाजों का पालन बहुत ही सहजता के साथ किया जाता है। सनातन हिंदू धर्म के वैदिक नियमों को सदा सदा के लिए जीवित रखने के लिए यहां पर रहने वाले सनातनी हिंदू, मांस का परित्याग का शाकाहारी भोजन गृहण करते हैं। नशीले पदार्थों, शराब एवं सिगरेट आदि पदार्थों से भी दूर रहते हैं। सुबह एवं शाम मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहता है तथा कृषि एवं गाय पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती है एवं पुरुष धोती कुर्ता धारण करते हैं। इसी प्रकार के गांव जहां हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन किया जाता है अन्य कई देशों यथा घाना, फीजी एवं अन्य कई अफ्रीकी देशों, सुदूर अमेरिका, यूरोप के देशों, आदि में भी तेजी से फैलते जा रहे हैं। इसी प्रकार, कजाकिस्तान एक मुस्लिम देश है क्योंकि यहां की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी इस्लाम को मानने वाले लोगों की है। परंतु, हाल ही के समय में यहां भी एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है और यहां नागरिक सनातन हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। यहां सनातन हिंदू धर्म की लहर इतनी तेजी से उठी है कि हर तरफ हिंदू धर्म की आस्था एवं आध्यात्म का फैलाव दिखाई दे रहा है। यहां के युवा विशेष रूप से भगवत गीता पढ़ने की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हिंदू धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक कजाकिस्तानी महिला मारीना टारगाकोवा की भगवत गीता को पढ़कर हिंदू धर्म के प्रति रुचि इतनी बढ़ी है कि अब उसने जैसे बीड़ा ही उठा लिया है कि वह कजाकिस्तान में सनातन हिंदू धर्म को फैलाने का प्रयास लगातार करती नजर आ रही है।

विवाह की बढ़ती उम्र से जूझता युवा वर्ग, समाज की खामोशी पर सवालियाँ निशान !

अशोक भाटिया

आज हर वर्गों एक चिंताजनक दौर साफ़ नजर आ रहा है; अधिक उम्र तक युवक-युवतियों की शादी न होना। इसको लेकर आज सभी समाज काफी चिंताग्रस्त है। लड़के की उम्र 30 के पार जाने लगी है परन्तु शादी की बात करे तो इस उम्र तक उनकी शादी न होना एक सामाजिक समस्या बनकर उभर रही है। यह समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि लड़के एवं लड़कियों की उम्र 30-35 पार करने पर भी वे कुँवारे बैठे है; यही कारण है कि लड़के-लड़कियों में एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इसका एक मुख्य कारणों में तेजी से समाज में परम्पराओं का बदलता दौर शामिल है। हर माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर अपने पैर पर खड़ा करने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते है, बेटा-बेटी को अच्छी शिक्षा-दीक्षा देने के लिए हर संभव कोशिश करता है। यह सब उपक्रम बच्चों की कवलियत हो बढ़ा रहा है परन्तु कावलियत और सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में सभी युवा वर्ग इस तरह दौड़ लगा रहा है कि उनके जीवन के सुन्हेरे पल की कुर्बानी देकर यह लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत सी सामाजिक परम्पराओं को आड़े हाथ लेने से नहीं चूकते। सरकारी नौकरी वाले वर की चाहत- आज मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर उच्च वर्गीय परिवारों में ऐसी होड़ सी लग गई है जिसमे सब अपनी बेटियों को सरकारी नौकरी पेशा के घर शादी करना चाहते है। किसी सरकारी नौकरी के लड़के को देखकर उसके घर लड़की देने की जैसे होड़ लग जाती है सरकारी नौकरी नहीं उसके पास अलादीन का चिराग हो जो हर आदेश पर आपने आका की मन मुराद इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बैठा हो। सरकारी नौकरी वाले लड़के-लडकियाँ वाले भी सरकारी नौकरी रुपी मैजिक छड़ी से अपने आपको दूसरे से अलग छबी एवं दायरा बना लिए है। क्या कम पढ़ा लिखा होना, या किसी प्रकार का निजी व्यवसाय, निजी संस्थानों में जॉब करने वालो की जीवन शैली सरकारी नौकरी वाले से हमेशा कम होती है ? पता नहीं लोगो के मन में क्या चल रहा है !"हर राजा जनक अपनी अपनी बेटी को दसरथ जैसे महान वैभवशाली राजा के घर राम जैसे वर के साथ विवाह करवाना चाहते है। परन्तु मेरी समझ में इस वैभव का उस समय कोई मूल्य नहीं होता जब किस्मत में वनवास ही लिखा हो। स्थिति एवं परिस्थिति विपरीत होने पर मनुष्य के धन, वैभव, प्रतिष्ठा, पद ये कुछ काम नहीं आते।" बढती उम्र में शादी न होना एक अवसाद की स्थिति – कहने का अभिप्राय एकदम सीधा है अच्छे से जीवन जीवन-यापन करने का कौशल एवं प्रतिभाशाली लड़के को अपनी कन्या का जीवन साथी चुन सकते है, रही बात उनकी जीवन शैली में परिवर्तन लाना; आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि जिस बेटी को आपने अच्छी शिक्षा-दीक्षा दी है वह अपने इस कौशल से अपने जीवन को सवारने की शक्ति रखती है। बढती उम्र तक बेटियों की शादी न होना उसमें सामाजिक रूप से सभी को एक मत होकर सोचना होगा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ को समय पर पूर्ण करना एक सामाजिक धर्म है। आज की परिस्थितियों को देखकर यह स्पष्ट नजर आने लगा है कि लड़के-लड़कियों के जवां होते सपनों पर न तो किसी समाज के कर्ता-धर्ताओं की नजर है और न ही किसी रिश्तेदार और सगे संबंधियों की। हमारी सोच एवं मानसिकता; हमें क्या मतलब है में; उलझ कर रह गई है। निसंदेह यह सच किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन हर समाज की हकीकत यही है। यह बात से सभी बाकिफ है कि पूर्ण मानसिक रूप से परिपक्यता 25-30 वर्ष तक लड़कियों में आ जाती है, लड़कियों में 18-25 के बीच का दौर ससुराल के वातावरण, परिस्थिति, रिश्ते-नाते एवं सम्रद्धि की सोच विकसित करने का दौर होता है, उसे यहाँ कई जिम्मेदारियों एवं अवसर को सीखने का मौका मिलता है जो जीवन को खुशहाल एवं जीवन शैली को परिपक्यता लाने में मददगार होता है; वही इस उम्र तक शादी न होना इस पक्ष को कमजोर बनता है एवं अधिक उम्र में शादी ससुराल में सामंजस को संघर्षमय बनाता है; क्योंकि उनकी आदतें पक्की और मजबूत हो जाती हैं अब उन्हें मोड़ा या झुकाया नहीं जा सकता जिस कारण घर में बहस, वाद विवाद, तलाक जैसे परिस्थिति हो जाती है, जिससे लड़का-लड़की में अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव – आधुनिक जीवन शैली एवं अधिक शिक्षा-दीक्षा के चलते अभी सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल का करने का फैसला लिया है। यहाँ तक ठीक है कि शादी कम से कम 21-22 वर्ष तक हो जानी चाहिए। यह लड़के के लिए भी लागू हो कि उनकी शादी 25 तक हो ही जाये वह अपने जीवन का लक्ष्य इसके बाद भी पूरा कर सकते है। ससुराल के लोग बहु को बेटी जैसी सुविधायें एवं अधिकार दे, शादी के बाद भी उसकी शिक्षा एवं अवसर को हासिल करने का मौका प्रदान करें तो यह चुनौती कभी चिंता नहीं बनेगी। एक समय था जब संयुक्त परिवार के चलते सभी परिजन अपने ही किसी रिश्तेदार व परिचितों से शादी संबंध बालिग होते ही करा देते थे। मगर बढ़ते एकल परिवारों ने इस परेशानी को और गंभीर बना दिया है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एकल परिवार प्रथा ने आपसी प्रेम व्यवहार ही खत्म सा कर दिया है। अब तो शादी के लिए जांच पड़ताल में और कोई तो नकारात्मक करें या न करें अपनी ही खास सगे संबंधी नकारात्मक विचार से संबंध खराब कर देते है। उच्च शिक्षा एवं रोजगार के चलते बढती उम्र – वैसे हम सब को भलीभांति ज्ञात है कि शिक्षा शुरू से ही मनुष्य के लिए एक मूल आवश्यकता रही है, इसके वदौलत ही हमें अपने जीवन को निखारने के नये आयाम मिलते है लेकिन पिछले दो दशक से इस आवश्यकता को उच्च शिक्षा एवं भरण-पोषण वाली डिग्री के तरफ बढ़ते अंधाधुंध प्रभाव देखा जा सकता है। इस कारण से लगभग सभी लड़के-लड़कियों की उम्र 25 पार हो रही है, 25 के बाद 2-3 साल जॉब, बिजनेस करने के बाद शादी की बात का नम्बर लगता है। इसके चलते लड़के-लड़कियों की उम्र 30 के आसपास हो जाती है, इस समय तक रिश्ता हो गया तो ठीक नहीं तो इसके बाद लोगो का नजरिया बदल जाता है और अधिक उम्र के लड़के-लड़कियों से रिश्ता ज़माने में कई सबाल उठने लगते है। अरमानों और सपनो की चाहत – हर परिवार अपने और अपनी लड़की की चाहत का ख्याल रखते हुए जीवन साथी की तलाश में जुटे होते है।बेटी के ससुराल में जीवन के विलासिता से जुडी सारी सुविधायें खोजते-खोजते लड़की की बढती उम्र का भान भी नहीं रहता। लड़के पक्ष की तगड़ी कमाई एवं सपने पूरे करने का हर समान का होना; जैसे शादी की मुख्य शर्त हो, कई बार उसके कौशल एवं संस्कार को परे रखकर हैसियत पर आकर बात अटक जाती है। परन्तु जिस चीज को हम लड़के में एवं उसके परिवार में खोजते फिरते है; क्या इस चीज के लिए अपना स्वयं का बेटा पूर्ण करने में समर्थ है या दूसरे की बेटी लाने के लिए यह शर्त पर हम स्वयं खरे उतरते है; आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। शायद ही कोई परिवार होगा जो आदिकाल से अमीर रहा हो, सभी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे है। जब हम एक अच्छा मुकाम तक पहुच गए है, संघर्ष से डरने की क्या बात! अपने कौशल से सभी अपने लक्ष्य तक पहुँचे है, इसके लिए हमें अपने बेटा-बेटी को तैयार करने की आवश्यकता है। एकांकीपन से हटकर मिडएटर बनना होगा – उम्र का इस पड़ाव में आने के बाद न केवल लड़का-लड़की बल्कि उनके माता-पिता, भाई-बहिन, घर परिवार और सगे सम्बंधियो की चिंता बढ़ता है वल्कि सभी की तमाम कोशिशे भी असफल हो जाती है, यदि कभी इन कोशिशों से बात जम भी गई तो यह बात कहना मुश्किल है कि यह रिश्ता कितना सफल होगा। हम सभी जानते है कि शादी-विवाह के लिए किसी न किसी मिडएटर की जरुरत पड़ती है परन्तु इस उम्र में कोई मिडएटर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। परन्तु रिश्ता ज़माने में मिडएटर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है; इसलिए सभी को निःस्वार्थ यह दायित्व निभाने के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। यदि हम किसी के लिए मिडएटर नहीं बनेंगे तो हमारे लिए कौन मिडएटर बनेगा? यह भी देखा गया है कि बड़ी उम्र में शादी न जुड़ने की वजह से कई परिवार को अपनी मनोकामना के लिए मंदिर, पूजा -पाठ, भगवान को मनाने के लिए दान दक्षिणा में उलझ जाते है और अपना पैसा व समय बर्वाद करते है। बगैर मिडएटर के कोई मेट्रोमोनी व बायोडाटा से सम्बन्ध होना मुश्किल ही होता है। मिडएटर का सामाजिकता से हटकर एकांकीवाद का शिकार होते जा रहे है।युवा मन की उलझन – इस उम्र में अपनी व्यथा सुनाने के लिए कहाँ जाए युवा मन? बस युवा अपने भाग्य के भरोसे अपने आपको ठगा सा महसूस करने लगता है। अपने उम्र के किसी लड़का या लड़की को अपने जीवन साथी के साथ देखकर उसके मन में अपने-आपके प्रति आपमान का महसूस करने लगता है। ऐसे समय में युवा मन आपनी आत्मग्लानी से परिपूर्ण होने लगता है, मन में अवसर का कडवा घूट पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति में कई बार लड़के-लडकियाँ गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाते है जिसका एक सभ्य समाज कल्पना भी नहीं करता। समाज को आगे आना होगा – हर वर्ग बेटा-बेटियों की शादी के लिए जूझते हुए देखा जा सकता है; हर परिवार किसी न किसी प्रकार से इस समस्या का सामना कर रहा है। लोग आज समाजसेवा के लिए व समाज में नाम कमाने के लिए लाखो रूपये खर्च करने से नहीं कतराते है लेकिन अवसाद यह है कि हर समाज में बढती उम्र में शादी के विषय में चर्चा करने के लिए समय ही नहीं है। "जिसका दोना ढरकेगा वही रुखा खायेगा" इससे समाज को क्या लेना-लेना। यह भावना बहुत चिंताजनक है। समाज की ऐसी सोच से समाज विकास संभव नहीं है उन्हें अपने दायित्वों से दूर न होकर इस और अपना ध्यान आकर्षण कर इस चिंता से निलकने के विषय में घोर चिंतन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस मुद्दे में बहुत से सामाजिक संस्थाओं ने काम किया भी होगा; परन्तु यह मिशन के रूप में सभी समाज में चलाने की आवश्यकता है जिससे इस मुद्दे का एक सकारात्मक समाधान नजर आयें। हम सब को एक मंच में आकर सकारात्मक सोच के साथ ऐसे लडको-लड़कियों व परिवार की सोच को बदलने हेतु सभी को मजबूत पहल के साथ लड़का-लड़कियों की यथासंभव रिश्ता करवाने का प्रयास करे। यह छोटी सी पहल एक बड़ी चिंता एवं चुनौती से मुक्त करने के लिए एक उज्वल कदम साबित हो सकता है।

मेष राशिः आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आया है। आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जायेगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप परिवार के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृष राशि : आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं।

मिथुन राशि : आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए है, लेकिन पढाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क रहेंगे।

कर्क राशि : आज महा अष्टमी के दिन आपके सभी कार्य सफल होंगे। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नयी बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवनसाथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रो के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हें मेहमान के आगमन का योग बन रहा है।

सिंह राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेस मैन आज कोई जरुरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा, आपकी टेंशन ख़त्म होंगी। आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते। आपको मातापिता का पूरा सहयोग मिलेगा।

कन्या राशि : आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। आज किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आज आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभायेंगे।

तुला राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को आगें बढाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। परिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगो को आज बड़ा मुनाफा होगा। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी।

वृश्चिक राशि : आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। माता महागौरी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग बैंक में कार्य करते हैं वह आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगें। पिता से आज आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा। आज कोई ऐसी पुरानी चीज आपके हाथ लग सकती है, जिसे पा कर आपको खुशी महसूस होगी। आज दोस्तों के साथ फोन पर बात कर के समय बिताएंगे।

धनु राशि : आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका मन घरेलू काम-काज में लगेगा। आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं। डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिए नयी खुशियां लेकर आया है। आपके दोस्त आपसे मदद की गुहार करेंगे, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे। आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आज आप किसी जरुरी मीटिंग में शामिल होंगे। पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफी मदद मिलेगी।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। परिवार के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी मे जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा। आज कोई नई स्किल सीखने का विचार कर सकते है जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आज आप नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए ख़ास रहने वाला है। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा। आज अपको किसी करीबी से कोई ऐसी सलाह मिलेगी, जिससे आपको काफी फायदा होगा। आप आर्थिक मामलो मे किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, यह सलाह मददगार साबित होगी। आज माता महागौरी को मिठाई का भोग लगाएं, आपका दिन बेहतर रहेगा।

सूर्य तिलकका सुख

पूरे देश और विदेशोंमें जहां भारतीय हैं, वहां बुधवारको रामनवमीका महापर्व पूरे धूमधामसे मनाया गया लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेशके अयोध्यामें रामनवमीका उत्सव विलक्षण ही रहा। लगभग पांच शताब्दीकी लम्बी प्रतीक्षाके बाद विगत २२ जनवरीको बालक रामललाकी प्राण-प्रतिष्ठाके उपरान्त बुधवारको पहली रामनवमीपर लाखों श्रद्धालुओंने भगवान रामका दर्शन और पूजन-अर्चन किया। सबसे महत्वपूर्ण और विलक्षण दृश्य दोपहर बारह बजे अभिजीत मुहूर्तमें रामललाका पहला सूर्य तिलक रहा। तीन मिनटतक रामललाके मस्तकपर सूर्यकी नीली किरणें पड़ीं और इसीके साथ रामललाका जन्म हुआ। इसके पूर्व जगद्गुरु राघवाचार्यने ५१ कलशोंसे भगवान रामललाका अभिषेक किया। मन्दिरके कपाट 'भोरमें साढ़े तीन बजे' ही खुल गये थे और २० घण्टेतक दर्शनकी व्यवस्था भी सराहनीय रही। श्रद्धालुओंका तांता अनवरत लगा रहा। सूर्य तिलकके लिए वैज्ञानिकोंने एक अलग परियोजना तैयार की थी। वैज्ञानिकोंकी टीमने अष्टधातुके २० पाइपसे ६५ फुट लम्बा सिस्टम बनाया था। चार लेंस और चार मिररके माध्यमसे गर्भगृहतक रामललाके मस्तकतक सूर्यकी किरण पहुंचायी गयी थी। इस परियोजनाकी तैयारी पहलेसे ही की जा रही थी और मंगलवारको वैज्ञानिकोंने इसका परीक्षण भी किया। अयोध्यामें श्रद्धालुओंने सूर्य तिलकका जो सौभाग्य प्राप्त किया, वह वर्णनातीत है। सभी श्रद्धालु हर्षित और आह्लादित थे। अयोध्याके दस हजार मन्दिरोंमें जन्मोत्सवके बाद 'भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला...' की अनुगूंजसे पूरी अयोध्या भक्ति भावमें डूब गयी। अयोध्याके सभी मन्दिरोंमें भव्य और दिव्य सजावट की गयी थी। जगद्गुरु राघवाचार्यका कहना है कि भगवान रामका अवतार लोक-कल्याणके लिए हुआ है। यहां दर्शन-पूजनसे विशेष लाभकी प्राप्ति होती है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने भी रामनवमीपर अपनी भावनाओंको व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पहली रामनवमीपर अपनी भावनाओंको व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पहली रामनवमी है जब अयोध्यामें भव्य और दिव्य मन्दिरमें हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या एक अप्रतिम आनन्दमें है। पांच शताब्दियोंकी प्रतीक्षाके बाद इस तरहसे रामनवमी मनानेका देशवासियोंको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुलाबी वस्त्रमें फूलोंसे बने दिव्य हार धारण किये रामललाकी छवि अत्यन्त मनोहारी रही। रामललाको सोनेका मुकुट पहनाया गया है, जिसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। पूरा दृश्य परम सुखदायी रहा।

नक्सलियोंपर कहर

छत्तीसगढ़में २९ नक्सलियोंका मारा जाना लोकसभा चुनावसे पहले सुरक्षाबलोंकी बड़ी कामयाबी है। राज्यके नक्सल प्रभावित कांकेर जिलेके हापाटोला जंगलमें मंगलवारको सुरक्षाबलोंने नक्सलियोंके खिलाफ एक बड़े आपरेशनको अंजाम दिया। यह राज्यमें अबतककी सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें २९ नक्सली मार गिराये गये। इस मुठभेड़में २५-२५ लाख रुपयेके इनामी दुर्दान्त शंकर राव और ललिता माडवीका मारा जाना राहतकी बात है। इससे पहले साल २०१८ में महाराष्ट्रके गढ़चिरौलीमें ३७ नक्सली मारे गये थे। इस तरह देशमें यह दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है। इसमें हमारे तीन जवान भी घायल हुए हैं। मारे गये कई नक्सलियोंकी अभीतक पहचान नहीं हुई है लेकिन घटनास्थलसे जो हथियार बरामद हुए हैं, उससे पता चलता है कि कई बड़े नक्सली मारे गये हैं। इस वर्ष कांकेर सहित बस्तरके सात जिलोंमें सुरक्षाबलोंने अबतक ७९ नक्सलियोंको मार गिराया है जो नक्सल विरोधी अभियानकी सफलताको रेखांकित करता है। नक्सलवाद विकास, शान्ति और युवाओंके भविष्यका सबसे बड़ा दुश्मन है जिसे जड़-मूलसे उखाड़ फेंकनेकी जरूरत है। इस सम्बन्धमें स्वराष्ट्रमंत्रीका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें सरकार देशको नक्सलवादके दंशसे मुक्त करनेके लिए दृढ़ संकल्पित है। लोकसभा चुनावके प्रथम चरणके मतदानसे तीन दिन पहले इतनी बड़ी संख्यामें नक्सलियोंका सफाया उन अराजक तत्वोंके लिए बड़ा सबक है जो चुनावमें खलल डालनेके फिराकमें हैं। चुनावके दौरान इस तरहके अभियान उचित और प्रशंसनीय हैं। निर्भीक और शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करानेके लिए जिला प्रशासनको इस तरहके सतत अभियान चलानेकी जरूरत है। इससे विध्वंसक साजिशकर्ताओं और अराजक तत्वोंमें प्रभावकारी सन्देश जायगा जो देश और समाजके हितमें है।

लोक संवाद

मौतके कुएं

महोदय,-भूमिगत सीवर सिस्टमने भले ही समूची व्यवस्थाका प्रारूप बदलकर रख दिया हो लेकिन सफाईके लिए अत्याधुनिक संयंत्र प्रयोग करनेके मामलेमें देश आज भी काफी पिछड़ा नजर आता है। सुरक्षाके लिहाजसे सीवर सफाई कर्मियोंको आवश्यक उपकरणतक उपलब्ध नहीं है। यही कोताही अकसर जानलेवा सिद्ध होती है। बीते दिनों, गुरदासपुरके चावा गांवमें सीवरेज साफ करते समय विषैली गैस चढ़नेसे एक मजदूरकी जान चली गयी जबकि अन्य दो मूर्छित हो गये। देशके विभिन्न भागोंमें औसतन प्रतिदिन दो सफाईकर्मी जिन्दगी गंवा बैठते हैं। विचारणीय है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, २०१३ के तहत किसी भी व्यक्तिको सीवरमें भेजना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि विषम परिस्थितिमें कोई व्यक्ति सीवरके अंदर भेजा जाता है तो इसके लिए २७ प्रकारके नियमोंका पालन करना जरूरी है। भूमिगत सफाईसे पूर्व कर्मचारियोंको आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सरकारी अध्यादेश, २००८ के अंतर्गत कानूनी प्रावधानोंमें शुमार होता है, बावजूद इसके ठेकेदारों द्वारा नियमित सफाई कर्मियोंके अतिरिक्त संविदा एवं ठेकेपर भर्ती मजदूर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्थाके मैनहोलमें उतारना एक आम बात है। गत वर्ष अक्तूबर माहमें सर्वोच्च न्यायालयने सीवर सफाईके दौरान सफाई कर्मीकी मौत होनेपर मिलने वाला मुआवजा बढ़ाकर ३० लाख रुपये करनेका आदेश दिया था। स्थायी दिव्यांगता होनेपर न्यूनतम २० लाख रुपये तथा अन्य प्रकारकी दिव्यांगतामें सरकारी अधिकारियों द्वारा पीड़ित पक्षको दस लाख रुपये अदा करनेकी बात भी कही। प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम, २०१३ इस कुप्रथाके उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है किन्तु केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून, २०२३ में जारी आंकड़े बताते हैं, ७६६ में से मात्र ५०८ जिले स्वयंको हाथसे मैला ढोनेकी प्रथासे मुक्त घोषित कर पाये। निश्चय ही यह विसंगति प्रथाकी वास्तविक स्थिति एवं सरकारी प्रयासोंकी प्रभावशीलताको लेकर चिन्ता उत्पन्न करती है। आर्थिक सुदृढ़ताकी ओर कदम बढ़ाते भारतवर्षमें अधिकांश नगरपालिकाओंके पास सीवेज सिस्टमकी सफाई हेतु नवीनतम संयंत्र उपलब्ध न होना आश्चर्यजनक है। ऐसी घटनाएं मजदूर कल्याण योजनाओंको धत्ता बताती प्रतीत होती हैं। कम पैसेमें कार्य निबटानेकी स्वार्थी सोच भी इस कुप्रथाको मिटने ही नहीं देती। समुचित निवेश द्वारा आधुनिक शौचालयों, सीवेज उपचार संयंत्रों तथा कुशल अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणालियोंके निर्माण सहित स्वच्छताके बुनियादी ढांचेमें सुधार लाया जाय तो निःसंदेह अपशिष्ट निबटानके लिए सुरक्षित विकल्प मिल जायंगे। पहलके तौरपर सरकारी-गैरसरकारी संघटन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गम्भीरतापूर्वक प्रयास करें तो सीवर सफाई कर्मियोंके जीवनकी दिशा एवं दशा बदल सकती है। जीवन अनमोल है। मुआवजा भले ही आर्थिक संबल दे किन्तु किसी पारिवारिक सदस्यके बिछोहसे उपजने वाली पीड़ा कदापि कम नहीं कर सकता। देशके हर नागरिकका जीवन सुरक्षित बनाये रखना सरकारों एवं प्रशासनका सर्वोपरि दायित्व है। नियम कानून होनेपर भी यदि इनकी सरेआम धज्जियां उड़ती हैं तो इसे तंत्रकी सबसे बड़ी विफलता कहेंगे। जीवन-सुरक्षाके प्रति लापरवाही दर्शाना अथवा घटित घटनाओंको गम्भीरतापूर्वक न लेना जहां संवेदनशून्यताका प्रतीक है, वहीं व्यवस्थाकी कार्यशैलीपर भी प्रश्नचिह्न अंकित करता है। मुआवजा देने भरसे हालात नहीं सुधरा करते। स्थितियां तो अनुकूल तभी बनती हैं जब जवाबदेह व्यक्ति योंध् अधिकारियोंके विरुद्ध बनती काररवाई हो। चंद पैसे बचानेके लालचमें गरीब मजदूरोंको मौतके कुंओंमें धकेलने वाले लोग कानूनसे बचकर, खुलेआम अप्रिय घटनाओंके दोहरावको मौका देनेका सबब बनते रहें तो देशके लिए इससे बड़ी विडंबना भला क्या होगी। **-दीपिका अरोड़ा, वाया ईमेल।**

दल-बदलकी प्रवृत्तिसे घटती साख

दल-बदल भारतीय राजनीतिका मानो एक रिवाज-सा बन गया है। इस बार भी आम चुनावोंके समय नेताओंका एक दल छोड़कर दूसरे दलमें जानेका खेल जारी है। चुनावोंमें आचार संहिताके चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन दल-बदलका दौर चुनावोंमें ही सबसे ज्यादा होता है। सत्ताके स्वादसे कोई भी दल अछूता नहीं रहता।

❒ राजेश माहेश्वरी

आजकल दल-बदलनेका दौर खूब हो रहा है। यह बात दूसरी है कि ज्यादातर नेताओंमें भाजपाका दामन थामनेकी होड़ मची है। दल-बदलकी प्रवृत्ति राजनीतिक चकाचौंधके वर्तमान माहौलमें पिछले तीन दशकसे काफी तेजीसे बढ़ती आयी है। दल बदलुओंको अपना मंच देकर राजनीतिक दल आम आदमीके मनमें निराशा पैदा करते हैं। ईमानदार, अच्छी सोचवाले दूरदर्शी नेता लुप्त होते जा रहे हैं। सभी सेलिब्रिटी आखिर सत्ताकी तरफ ही क्यों भागते हैं। पूर्व न्यायाधीश हों, पूर्व अधिकारी अथवा अभिनेता और खिलाड़ी वे राजनीतिमें आयें इससे कोई इनकार नहीं करेगा। यदि भाजपाकी विचारधारा विजेंदर या उन जैसे लोगोंको अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले पांच सालतक वे कांग्रेसमें क्यों रहे। ऐसेमें अहम सवाल यह है कि क्या ऐसा करके राजनीतिक दल और उनके नेता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाके मूल मंत्र और चुनाव-व्यवस्था और संविधानकी मूल भावनाके साथ खिलवाड़ नहीं करते। राजनीतिक दलों और नेताओंको लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें वे कुछ गलत, अनैतिक देखते ही नहीं एक दिन पहले भाजपापर निशाना साधनेवाले मुक्केबाज विजेंदरने कांग्रेससे नाता तोड़ भाजपाका दामन थाम लिया। महज चौबीस घण्टेमें विजेंदरका दिल क्यों बदल गया, इसका जवाब तो उनको ही देना चाहिए था, लेकिन घर वापसी और अपने दलमें दम घुटनेका बहाना ही नेताओंके पास रहने लगा है। ऐसे नेताओंकी भी कमी नहीं है जो गत वर्षके अंतमें हुए विधानसभा चुनावोंमें एक पार्टीके चुनाव चिह्नपर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टीका चुनाव चिह्न लेकर मैदानमें उतरते दिख रहे हैं। ऐसे नेता फिर किसी नयी पार्टीमें नहीं जायंगे इसकी क्या गारंटी है। अच्छे लोग राजनीतिमें यदि सिर्फ पद पानेके लिए ही आये तो उसे क्या माना जाय। ऐसी जानी-मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहां और कल वहांके उदाहरण पेश कर चुकी हैं। ऐसी सेलिब्रिटीको पार्टीमें शामिल होते ही टिकटसे पुरस्कृत कर दिया जाता है। राजनीतिक दलोंको इस बातपर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन, किस इरादेसे पार्टीमें आ रहा है।

देशमें लम्बे समयसे चुनाव सुधारोंपर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इसपर भी होनी चाहिए कि टिकट किसे और क्यों दिया जाय। पार्टीके निष्ठावान कार्यकर्ताओंकी अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टीमें शामिल होनेवालेको टिकट देना कहांतक उचित है। दलोंको विचार करना ही होगा कि राजनीतिके मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधाराके लिए समर्पित कार्यकर्ताओंको मौका देकर राजनीतिको स्वस्थ रखना चाहते हैं। वर्तमानमें दलबदल कानूनका प्रभाव न के बराबर है। इस कानूनको हर बार टंगड़ी मार दी जाती है और शोर भी नहीं होता।

आखिर इसे क्यों उचित माना जाता है। यह उचित इसलिए नहीं है कि दल विशिष्ट राजनीतिक विचारधाराके आधारपर बनते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहांपर सरकारें चुनावोंके माध्यमसे चुनी जाती हैं। सत्ता हासिल करनेके लिए नेता दल बदलनेमें देर नहीं लगाते हैं। बिना सिद्धांतके दूसरी पार्टीमें ऐसे जम जाते हैं, जैसे वे शुरूसे इसी पार्टीमें हों। नेताओंका लक्ष्य सिर्फ सत्ताप्राप्ति है। उनके लिए न तो कोई लोकमतका महत्व है, न ही जनतंत्र का। उनके न कोई मूल्य हैं और न ही सिद्धांत। वे सत्ताकी चाहमें साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाते हैं। नेताओंको चुनावके लिए टिकटका न मिलना दलबदलका प्रमुख कारण है। जब किसी दलके किसी सदस्यको या उसके साथीको पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो वह उस दलको छोड़ देता है। नेता अपने स्वार्थके लिए दल बदलते है। उन्हें सत्ताकी ताकत और पैसोंकी चमक ऐसा करनेके लिए प्रेरित करती है। जिनको सचमें समाज या देशकी सेवा करनी होती है, वे दलबदलपर ध्यान नहीं देते। इस हमाममें सब नंगे हैं। साम, दाम, दंड, भेदसे सत्ता हथियानेकी इच्छासे कोई दल अछूता नहीं है। वर्तमानमें राजनीति धन अर्जित करनेका सबसे सरल और सुरक्षित साधन है। हमारे देशके ज्यादातर नेताओंका कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है और सिद्धांत विहीन राजनेता ही अपनी सुविधाके अनुसार दल बदलते रहते हैं। यह भी कटु सत्य है कि आज बहुत सारे नेता जनसेवाके बहाने तरह-तरहके कारोबारमें लिप्त हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके सारे व्यापार नियमानुकूल और साफ-सुथरे हैं। अवैध-धंधों और नियम.विरुद्ध काम करनेके लिए कई नेता कुख्यात हैं। वे कानूनकी पकड़से बचनेके लिए हर समय सत्तापक्षमें रहना चाहते हैं। इसलिए जो दल सत्तामें आये, उसके साथ हो जाते हैं। देशमें लगातार दल बदलकी घटनाओंके साथ नेताओंके व्यक्तिगत हितकी चर्चा भी व्यापक तौरपर होती हैं असर विभिन्न स्तरके चुनावमें वोटिंग परसेंटेजमें गिरावटके तौर देखा जा सकता है। निस्संदेह, यह घटनाक्रम भारतीय राजनीतिमें नैतिक मूल्योंके पराभवका चित्र भी उकेरता है। जो बताता है कि सत्तामें आनेकी बेचैनी जन-प्रतिनिधियोंको किसी भी हदतक ले जा सकती है। फार्म हाउसों और गेस्ट हाउसोंमें घेर कर ले जाये जाते विधायक इस दयनीय स्थितिको ही उजागर करते हैं। जो राजनीतिक पंडितोंके लिए अध्ययनका विषय होना चाहिए कि विपक्षमें बैठनेमें विधायकोंमें बेचैनी क्यों होती है और वे स्वार्थोंके लिए जनताके विश्वाससे छल क्यों करते हैं। नेताओंके बीच दलबदल जितना सहज और सरल हो गया है, वोटरके लिए नेता उतना ही अविश्वसनीय होता जा रहा है। यद्यपि आजादीके बादसे ही नेताओंकी छविपर सवाल खड़े होते रहे हैं। जनसेवाका भाव ही नेताओंके एजेंडेसे गायब होता जा रहा है। किसी भी स्तरका चुनाव जीतनेके बाद नेताओंके रहन-सहनमें जो बदलाव लाता है, वह वोटरकी निगाहसे बच नहीं पाता। देशमें लगातार दल-बदलकी घटनाओंके साथ नेताओंके व्यक्तिगत हितकी चर्चा भी व्यापक तौरपर होती है। असर विभिन्न स्तरके चुनावमें वोटिंग परसेंटेजमें गिरावटके तौर देखा जा सकता है।

ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं कि नामी-गिरामी लोगोंने राजनीतिमें प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। उसके बाद जनतासे जुड़ ही नहीं पाये और अगले चुनावमें इनका टिकट कट गया। देशमें लम्बे समयसे चुनाव सुधारोंपर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इसपर भी होनी चाहिए कि टिकट किसे और क्यों दिया जाय। पार्टीके निष्ठावान कार्यकर्ताओंकी अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टीमें शामिल होनेवालेको टिकट देना कहांतक उचित है। दलोंको विचार करना ही होगा कि राजनीतिके मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधाराके लिए समर्पित कार्यकर्ताओंको मौका देकर राजनीतिको स्वस्थ रखना चाहते हैं। वर्तमानमें दलबदल कानूनका प्रभाव न के बराबर है। इस कानूनको हर बार टंगड़ी मार दी जाती है और शोर भी नहीं होता। इस कानूनकी खामियां भी कई बार सामने आती हैं, जिसे दूर किया जाना भी बहुत जरूरी है। यह कानून थोक दलबदलको मान्यता देता हैं, अयोग्यताका फैसला स्पीकर लेता है, जो काफी विवादास्पद है। दल बदल कानूनमें पुनः संशोधन होना चाहिए।

कठिन संघर्षके बाद स्वर्णिम अवसर

अयोध्यामें राम मंदिरकी प्राण-प्रतिष्ठाके बाद ९ अप्रैलको पहली बार पांच सौ वर्षों बाद श्रीराम ललाने अपने घरमें जन्मदिन मनाया। ये स्वर्णिम अवसर कड़े संघर्षसे हासिल हुआ है। इसमें ७० से अधिक बारका संघर्ष शामिल है।

❒ आशीष वशिष्ठ

हमारे मंदिरोंपर हमलेका रक्तरंजित इतिहास शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ादायक पिछले ७५ वर्ष रहे। स्वतंत्रताप्राप्तिके बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूने तुष्टीकरणकी राजनीतिको सिर माथेसे लगाया और हिन्दू आस्थाओं और भावनाओंको कुचलनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। नेहरूसे लेकर मनमोहन सिंहकी सरकारतकने राम मंदिरकी राहमें रोड़े अटकानेका काम किया। भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीने एक बार संसदमें कहा था कि राम मंदिरका निर्माण राष्ट्रीय स्वाभिमानका मुद्दा है। उनका वह वक्तव्य सही मायनेमें एक संदेश था, जिसमें राजनीति नहीं थी। सच तो ये है कि राम मंदिरका विरोध करनेवालोंने ही इसे वोट बैंककी राजनीतिका हिस्सा बना दिया। कांग्रेस और अन्य कुछ दल मुस्लिम मतोंके कारण इस मुद्देपर हिन्दुओंके न्यायोचित दावोंकी अनदेखी करते रहे। प्रतिक्रिया स्वरूप इस मामलेने दूसरा मोड़ ले लिया। दुर्भाग्य है कि देशकी बहुसंख्यक आबादीके आराध्य श्रीरामकी जन्मभूमिको अवैध कब्जेसे मुक्त करवानेका कार्य न्यायालयके निर्णयसे संभव हो सका और वह प्रक्रिया भी वर्षों नहीं दशकोंतक चली। सबसे बड़ी बात कि बाबरी ढांचेकी तरफदारी धर्मनिरपेक्षताके झंडाबरदार बने हिन्दू नेतागण भी करते रहे। सोमनाथ मंदिरको अंतिम बार औरंगजेबने यह कहकर तोड़वाया था कि इस बार इसे पूरी तरह नेस्तानाबूद कर दो कि मंदिरका कहीं कोई निशानतक दिखाई न दे। सोमनाथपर मस्जिद और कब्रिस्तानको सरदार पटेलने इतिहासकी विकृतिका चिह्न और राष्ट्रीय अपमान बताकर कहा था कि राष्ट्रके गौरवकी पुनर्प्रतिष्ठाके लिए सोमनाथ मंदिरका पुनर्निर्माण आवश्यक है। गांधी जी भी इससे सहमत थे। हिन्दू बहुल देशमें प्रभु श्रीरामकी जन्मस्थलीको मुक्त करवानेमें जिस तरहके अवरोध उत्पन्न किये गये वे अकल्पनीय रहे। यदि सोमनाथके साथ ही राम जन्मभूमिका मसला भी तत्कालीन नेहरू सरकार सुलझा लेती तब शायद इसे लेकर राजनीति करनेका किसीको अवसर नहीं मिलता।

वर्तमानमें देशमें रामनाम की प्रचंड लहरके चलते अब कांग्रेस नेता, समर्थक यह साबित करनेमें जुटा है कि राम मंदिरमें कांग्रेसका भी योगदान है, जबकि जमीनी सचाई यह है कि कांग्रेसने रामके नामपर घिनौनी राजनीतिका प्रदर्शन किया है। एक ऐसी राजनीति जिसने राम मंदिर मुद्देको उलझानेका काम किया। राम मंदिर केसमें कपिल सिब्बलने सुप्रीम कोर्टसे आग्रह किया था कि अयोध्या मामलेकी जांचको कोर्ट २०१९ के आम चुनावतक टाल दे। २००८ में तत्कालीन यूपीए सरकारने इस मामलेमें हलफनामा दाखिल कर सेतु समुद्रम परियोजनाके लिए राम सेतुको तोड़कर तय वर्तमान मार्गसे ही लागू किये जानेपर जोर देते हुए कहा था कि भगवान रामके अस्तित्वमें होनेके बारेमें कोई पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। ये भी कहा था कि रामायण महज कल्पित कथा है। आजादीके बाद प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूकी सरकारने पहली लोकसभामें १९५५-५६ में हिन्दू कोड बिल्स पास किये। इस बिलको लेकर डा. राजेन्द्र प्रसाद और पंडित जवाहर लाल नेहरूके बीच राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसकी एक बड़ी वजह दोनोंका धर्मको लेकर रवैया था। वर्ष १९७६ में इंदिराने देशमें आपातकालके दौरान प्रस्तावनामें संशोधन किया, जिसमें सेक्युलर शब्द शामिल किया गया था। जिसका मतलब था कि भारत हिन्दू देश होते हुए भी हिन्दू देश नहीं कहा जा सकता। १९९१ में लागू किया गया यह प्लेस आफ वर्शिप एक्ट कहता है कि १५ अगस्त, १९४७ से पहले अस्तित्वमें आये किसी भी धर्मके पूजा स्थलको किसी दूसरे धर्मके पूजा स्थलमें नहीं बदला जा सकता। यह कानून तब लाया गया जब राम मंदिर आन्दोलन अपने चरमपर था। इस कानूनकी परिधिसे अयोध्याकी राम जन्मभूमिको अलग रखा गया है। कांग्रेसके बनाये कानूनोंके चलते ही वर्तमानमें ज्ञानवापी, भोजशाला और मथुरा आदि हिन्दू आस्थाके स्थलोंको वापस पाने लिए हिन्दू समाज कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।

कांग्रेस और इंडी गठबंधनमें शामिल घटक दलोंके कई नेता राम मंदिर और सनातन धर्मपर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। वास्तवमें सोमनाथसे अयोध्यातक कांग्रेसका चरित्र बिल्कुल भी बदला नहीं है। १८वीं लोकसभाके गठनके लिए आम चुनाव हो रहे हैं। रामललाकी प्राण-प्रतिष्ठा समारोहमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षके तमाम दल और नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठाके शुभ अवसरको भाजपा और आरएसएसको इवेंट बताती रही। लेकिन जमीन सचाई यह है कि कांग्रेस समेत विपक्षने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोहसे दूरी बनाकर वही गलती की है, जो गलती कभी पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरूने की थी। उस वक्त नेहरू सोमनाथ मंदिरके उद्घाटनमें नहीं गये थे। असलमें मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेसके एजेंडेमें प्रथम स्थानपर है। उसके एजेंडेमें न सोमनाथ था और न ही अयोध्या है। राममंदिर किसीकी आस्थापर आक्रमण नहीं, भारतकी अस्मितासे जुड़े प्रश्नोंका उत्तर है। राम मंदिरके निर्माणसे सम्पूर्ण विश्वमें रचता बसता हिन्दू समाज आह्लादित है। न्यायालयके निर्णयके बाद भव्य राम मंदिर निर्माणके लिए हिन्दू समाजने दिल खोलकर सहयोग किया। यह ऐतिहासिक सहयोग इस बातका साक्षात प्रतीक है कि हिन्दू समाज इस घड़ीके लिए चिर प्रतीक्षित था। आज अयोध्यामें जो भव्य राम मंदिर संसारकी शोभा बढ़ा रहा है, वह संसारभरके हिन्दुओंकी आस्था, एकता, अखण्डता, श्रद्धा, मान्यता और संकल्पका सर्वोच्च पवित्र प्रतीक है। इस रामनवमीको हिन्दू समाज अपने आराध्य भगवान श्रीरामके पूजन वंदनके समय अपने पूर्वजोंके संघर्ष और बलिदानको भी अवश्य स्मरण करना चाहिए। इसी दिनके लिए तो निहत्थे राम भक्तोंने अपने सीनेपर गोलियां खाई थी। जिस सरयूमें आज हम और आप स्नान ध्यान और आचमन कर रहे हैं, उसका जल किसी समय राम भक्तोंके रक्तसे लाल हुआ था। इसी दिनके लिए तो हमारे पूर्वजोंने धैर्यपूर्वक हिन्दू विरोधी सरकारोंसे राजनीतिक लड़ाई लड़ी। न्यायालयमें अपना पक्ष तथ्यों और साक्ष्योंके साथ प्रस्तुत किया। किसी भी स्तरपर उतावलापन, उत्तेजना और अधीरताका प्रदर्शन नहीं किया। इस घमंड या अहंकारमें भी नहीं आये कि हम बहुसंख्यक हैं। वास्तवमें राम मंदिरके लिए संघर्ष संपूर्ण हिन्दू समाजकी सहनशीलताए धैर्य और कानूनके प्रति आदरके उच्च भावको दर्शाता है। वह अपने संकल्पोंपर अडिग रहता है। बड़ीसे बड़ी बाधाको वह कानून और नैतिकताके सीमामें रहकर ही पार करता है। इस रामनवमीपर दीपक उन सभी नाम अनाम शहीद कार सेवकों और राम भक्तोंके नामका भी प्रज्ज्वलित हुए, जिन्होंने राम मंदिर आन्दोलनमें अपने प्राणोंको न्यौछावर किया। उन्हीं महान बलिदानियोंके त्यागके कारण आज बालक राम भव्य मंदिरमें प्रतिष्ठित हो पाये हैं। रामनवमीके शुभ अवसरपर भगवान सूर्य अपने प्रकाशसे बालक रामका तिलक किया। साथ ही अखिल विश्वको यह संदेश दिया कि लाखों षड्यंत्रों, अन्याय और अत्याचारोंके बावजूद सनातन धर्मका मस्तक झुकाया नहीं जा सका और रामलला अपने घरमें विराजमान हुए।

आत्मबोध

शाश्वत सत्ता

❒ यशपाल कुमार

राम शब्दका मनमें स्मरण करते ही मन प्रफुल्लित और सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता है। मनमें आनन्द, दिव्यता, पवित्रताका संचार होने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी मनमें बैठे असुर समूह प्रभु श्रीरामके नामके हृदयमें आते ही ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदयके होते ही अंधकारके अस्तित्वका पता ही नहीं लगता। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाशकी सत्ताकी अनुभूति होती है। जो चराचर जगतमें सदा सर्वदा एक रस विद्यमान है, योगी, ऋषि, भक्त जिस तत्व एवं स्वरूपमें रमण कर आत्यांतिक सुखकी अनुभूति करते हुए आनन्दके समुद्रमें गोते लगाते हैं, परम शान्तिका लाभ प्राप्त करते हैं वह तत्व 'श्रीराम' हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल तत्व, इनसे भी सूक्ष्म प्राण तत्व, प्राण तत्व से भी परे महत्यतत्व, का भी जो कारण है, नियन्ता है एवं जिसका स्वयंका कोई कारण और नियन्ता नहीं, वह अनादि पुराण पुरुष भगवान श्रीराम है। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश जिनमें सदा प्रतिष्ठित है, जो दुर्गम है, दुराधर्ष हैं वे ही सगुण साकार कौशल्या नन्दन भक्त वत्सल अयोध्यापति भगवान श्रीराम हैं। भगवान श्रीराम हर्ष विषाद, मायासे रहित, निर्विकार और दीन-दुखियोंके लिए पुष्पसे भी कोमलसे भी अति कोमल हैं। बुद्धि मन और बाणीको जिस सत्तासे निश्चय मनन एवं बोलनेकी शक्ति प्राप्त होती है वह सत्ता ही श्रीराम हैं। केनोपिनिषदमें श्रुति भगवती कहती है-जो वाणी द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है, बल्कि जिसकी शक्तिसे वक्तामें बोलनेकी सामर्थ्य है, जिसको कोई भी मनसे नहीं समझ सकता, बल्कि जिससे मनको मनन करनेकी शक्ति प्राप्त होती है, जिसको चक्षुके द्वारा कोई नहीं देख सकता, बल्कि जिससे चक्षुको देखनेकी शक्ति प्राप्त होती है, जिसको कोई भी श्रोतके द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे श्रोत इन्द्रियको सुननेकी शक्ति प्राप्त होती है, जो प्राणोंके द्वारा चेष्टायुक्त नहीं होता, बल्कि जिससे प्राण चेष्टायुक्त होते हैं वह तत्व सबमें रमा हुआ है जिसे श्रुति ब्रह्म कहती है वह ब्रह्म तत्व ही श्रीराम हैं। भगवान श्रीरामने वनवास कालमें जड़, चेतन, पशु-पक्षी, कोल भील वंचित सभीको अपने चिन्मय सौन्दर्य माधुर्यसे आप्लावित कर दिया। संत तुलसी कहते हैं- जगत् गुरुम् च शाश्वतम्। तुरीयमेव केवलम् हे राम! आप चराचर जगतके ईश्वर, व्यापक जगतगुरु, शाश्वत, तीनो गुणों(सत् राज तम) से सर्वथा परे अपने स्वरूपमें सदा स्थित हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमहिं तुमहिं होई जाई॥ तुम्हरी ही कृपा तुमहि रघुनन्दन जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥ नर तन धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत्त राजा॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे॥

सहकारी बैंक जमाकर्ताओंके हित असुरक्षित

❒ सत्यपाल वशिष्ठ

भारतमें सहकारी आन्दोलनकी शुरुआत १९०४ में सहकारी समिति अधिनियमके पारित होनेके साथ शुरू हुई। इसका उद्देश्य किसानों, कारीगरों और समाजके अन्य वर्गोंके लोगोंके विकासमें मदद करने तथा बचतको प्रोत्साहन देनेका था। देशके सहकारी ढांचेका विस्तार और विकास छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनामें हुआ। सहकारी बैंक एवं समितियां शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रोंमें छोटे व्यवसायोंको ऋणकी सुविधा प्रदान करती हैं। सहकारी बैंक, सहकारी समिति अधिनियमके तहत पंजीकृत होते हैं। वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम १९४९ और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) १९५५ द्वारा शासित होते हैं। आरबीआईकी इनपर निगरानी रहती है। सहकारी समितियोंपर उनके सदस्योंका स्वामित्व होता है। इनका नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूपसे निदेशक मंडलका चुनाव करते हैं। ये सहकारी समिति अधिनियमके तहत पंजीकृत किये जाते हैं। ये सहकारी संस्थाएं हैं और इनको सहकारी समितियोंके रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमोंके अधीन संचालित किया जाता है। आरबीआईके दिशा-निर्देश इनपर लागू नहीं होते। ये आम नागरिकोंको साहूकारों और बिचौलियोंसे मुक्त करते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्योंको सस्ती दरोंपर ऋण देती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्योंको अच्छी सेवाएं देना है। सहकारी वित्तीय संस्थाओंने ही देशके गांवों और कस्बोंमें आम लोगोंको बैंकिंगसे जोड़कर अर्थव्यवस्थाके विकासमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी वित्तीय संस्थाओंके संचालनमें कमियोंके कारण ये ग्रामीण लोगोंके लिए इतनी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुईं। ये छोटे किसानोंकी जरूरतोंको पूरा करनेमें असफल रहीं। देशके सभी राज्योंमें सहकारी बैंकों एवं समितियोंमें आम तौरपर घोटाले होते रहते हैं। इन घोटालोंके कारण हैं- राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रबंधनमें अक्षमता, रेगुलर ऑडिटका अभाव, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांचका अभाव, बैंकके कर्मचारियों द्वारा ही घोटाले, गलत तरीकेसे ऋण देना, बैंक सदस्योंको सीमासे अधिक तथा लम्बी अबधिके ऋण देना तथा डिफाल्टरको दोबारा ऋण देना आदि। देशमें सहकारी बैंकोंके बड़े घोटालोंमें पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक भी था। इसपर काररवाई करते हुए आरबीआईने उसे अगले छह महीनेतक किसी भी प्रकारका कार्य न करनेका आदेश दिया था तथा साथमें आरबीआईने पीएमसी बैंकके ग्राहकोंके लिए पैसे निकालनेकी सीमा भी निर्धारित की थी। इस बैंककी जमा राशि ११६१७ करोड़ रुपये थी। यह सभी सहकारी बैंकोंसे बड़ा बैंक था। देशका सबसे बड़ा बैंक जिस प्रकार संकटका सामना कर रहा है, यह देशकी सहकारी बैंककी प्रणाली हेतु चिन्ताका विषय है। अभी हाल ही में हिमाचलके सोलन जिलेमें एक अर्बन सहकारी समितिकी प्रबंध कमेटीके सदस्योंने १८ करोड़ रुपयेका घोटाला किया। कमेटीने अपने नजदीकी रिश्तेदारोंको सीमासे अधिक ऋण दिया। हालांकि ये पहले भी कई बार ऋण न चुकानेके दोषी थे। इससे सहकारी सभाके २८०० जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी वापस लेनेके लिए दर-दरकी ठोकरें खा रहे हैं। इनमें बहुत-सी औरतें हैं। एक जमाकर्ता जो सेनासे सेवानिवृत्त है, उसने १३ लाख रुपये निवेश किये थे। उसकी पत्नी कैंसरसे पीड़ित है। उसने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवनकी पूंजी निवेश की थी, उसको वापस लेनेकी जंग हार गया हूं, हालांकि मैंने १९६२, १९६५ और १९७१ की लड़ाइयां जीती हैं। इस घोटालेका पता ऑडिटमें लगा। इसी तरहका घोटाला मंडीके एक अर्बन बैंकमें भी हुआ था। उसमें भी प्रबंधन कमेटीने नियमोंको ताकपर रखकर ऋण जारी किये थे। एक और घोटाला है जिसमें एक सहकारी बैंकके पूर्व चेयरमैनको प्रवर्तन निदेशालयने २५० करोड़ रुपयेके घोटालेमें पकड़ा था। उसने नियमोंका उल्लंघन कर ऋण अपंजीकृत कम्पनीको जारी किया था। सहकारी समितियोंमें तो ये घोटाले आम हैं। सहकारी बैंकोंमें हो रहे घोटालोंको ध्यानमें रखते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्टमें संशोधन किया गया। सहकारी बैंकोंके प्रबंधन, पूंजी, ऑडिट और लिक्विडेशनको आरबीआईके रेगुलेटरी दायरेमें शामिल किया गया है। वित्तमंत्रीने जमाकर्ताओंके हितोंकी रक्षा करनेके लिए इस बिलको लाया है। उन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकके संकटका उल्लेख किया। सहकारी बैंकोंको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट १९४९ के कई प्रावधानोंसे छूट थी। परन्तु अब २०२० का बिल सहकारी बैंकोंपर वाणिज्यिक बैंकोंकी तरह ही लागू होगा। जब सहकारी बैंको एवं समितियोंमें घोटाला होता है तो जमाकर्ताओंको अपने पैसेके लिए ही इंतजार और तड़पना पड़ता है। इस समस्याका समाधान बहुत जरूरी है ताकि जमाकर्ताओंको परेशानीका सामना न करना पड़े। इसके लिए सहकारी बैंककी एवं सहकारी समितियां आरबीआई द्वारा विनियमित एवं शासित होनी चाहिए। राज्य सरकारें आरबीआईके दिशा-निर्देशोंके अनुसार काम करें। सरकार द्वारा पुनः पूंजीकरणके लिए आरबीआईको दी गयी राशिका उपयोग, संकटमें आये इन सहकारी बैंकों एवं समितियोंपर भी करना चाहिए। सहकारी बैंकों एवं समितियोंमें हो रहे घोटालोंको देखते हुए यह भी आवश्यक है कि इनके ढांचे एवं संचालनमें बुनियादी परिवर्तन किये जायं। डिपाजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआईसीजीसी) एक्टमें सरकारने जो बदलाव किया है, उसमें जमाकर्ताको बैंक डूबनेकी स्थितिमें बहुत बड़ी राहत मिली है। यही एक्ट सहकारी समितियोंपर भी लागू हो। पांच लाख रुपये तककी जमा राशिकी जगह पूरी जमा राशि इंश्योरड-सुरक्षित होनी चाहिए। इन उपायोंसे ही सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियोंमें लोगोंका विश्वास बन पायगा। तभी उनका सही संचालन होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है।
-सर्वपल्ली राधाकृष्णन

ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के पूर्ण मिलान की मांग को लेकर शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण की शुरुआत से ऐन पहले जो टिप्पणियां की हैं, वे सभी आशंकाओं पर विराम लगा देने वाली हैं। इन टिप्पणियों के बाद अनावश्यक चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप समाप्त हो जाने चाहिए।

अब बहस खत्म हो

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की पर्चियों के पूर्ण मिलान की मांग के संदर्भ में, शीर्ष अदालत की पीठ ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण की शुरुआत से ऐन पहले जो टिप्पणियां की हैं, वे महत्वपूर्ण होने के साथ सभी आशंकाओं पर विराम लगाने वाली भी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से ईवीएम में हेरफेर से जुड़ी आशंकाएं जताई जाती रही हैं, जिनके समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने कई कदम भी उठाए हैं, जिनमें वीवीपैट व्यवस्था और इसमें लाए गए सुधार भी शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर जिसे वोट दिया गया है, उसका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है। ईवीएम में लगे शीशे की स्क्रीन पर यह पर्ची कुछ सेकंड तक दिखती है। यह पूरी व्यवस्था दरअसल इसलिए की गई है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से किन्हीं पांच ईवीएम और वीवीपैट में पड़े वोटों की जांच की जाती है। गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए या तो पूरे चुनाव मतपत्रों के जरिये हों या फिर ईवीएम में पड़े वोटों व वीवीपैट की पर्चियों का सौ फीसदी मिलान किया जाए। अदालत ने भी कहा है कि करीब 97 करोड़ मतदाताओं वाले भारत में ऐसी मांग अव्यावहारिक है, तो इसकी वजह स्पष्ट है। एक तो इससे चुनावों के नतीजों की घोषणा में विलंब होगा और दूसरे, इससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे गलतियों की आशंका बढ़ेगी। याचिकाकर्ता पूर्ण पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसे की बात कर रहे हैं, जो जायज भी है, लेकिन इनके नाम पर बूथ कैप्चरिंग वाले दौर की ओर तो लौटा नहीं जा सकता, जिसका स्मरण शीर्ष अदालत ने भी कराया है, और जिससे

अब भी देश के कुछ राज्य पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके हैं। तथ्य यह है कि वीवीपैट व्यवस्था में अब तक किसी बड़ी गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी अगर कोई संशय है, तो संकीर्ण अंतर से जीत मिलने वाली सीटों में पुनर्गणना के नमूने को बढ़ाने या पुनः मतगणना का आग्रह तो समझ आता है, पर इस तरह ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों में सौ-फीसदी मिलान की मांग अतिशयोक्ति ही है, जो संपूर्ण व्यवस्था में भरोसे की कमी को दिखाती है। मामले में अंतिम फैसला कुछ भी हो, उम्मीद है कि शीर्ष अदालत की इन टिप्पणियों के बाद अनावश्यक चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप समाप्त हो सकेंगे।

जीवन धारा

महर्षि अरविंद

शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहां भक्ति-भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है।

अंतर्ज्ञान की शक्ति से परमात्मा के दर्शन

संसार के समस्त पदार्थों में जो 'सत्य' पाया गया, वह समस्त हमारे भीतर आ जाए, और हमारा शरीर भी उसी से भर उठे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा अंतर्ज्ञान पहले मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। पर यदि वह इसी स्थान पर बना रहे, तो जब तक हम ऊपर रहेंगे, तभी तक वह काम देगा। जैसे ही हम नीचे के स्तर पर आए, उसका संबंध टूट जाएगा। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने समाधि पर इतना जोर दिया था। इस उपाय से वे इस ज्ञान शक्ति को मनोमय क्षेत्र में ले आते थे। वहीं पर सूक्ष्म इंद्रियों की सृष्टि होती है। ये सूक्ष्म इंद्रियां बाहर की इंद्रियों की सहायता के बिना भी दर्शन, स्पर्शन करने में समर्थ होती हैं। जब तक शरीर का रूपांतर नहीं होगा (इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर और सुख का स्वरूप बदल जाएगा), तब तक हमें अपनी विजय पूर्ण और सारयुक्त नहीं समझनी चाहिए। पर ऐसा होने पर शरीर की कार्य-शक्ति में अंतर आ जाएगा। तब शरीर अमृतमय हो जाएगा, रोग और बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सब इंद्रियां सृष्टि के गूढ़ और वास्तविक तत्व को ग्रहण करने लगेंगी। यह अंतरंग ज्ञान की शक्ति मानव इंद्रियों को प्राप्त हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। वैदिक युग के ऋषि समस्त चैतन्य और ज्ञान-शक्ति को सार रूप करके उद्दीप्त करते थे। उस समय वैज्ञानिक यंत्र तो थे नहीं। इसलिए ज्ञानी जन भीतरी ज्ञान के जरिये ही सृष्टि के रहस्यों का पता लगाते थे। ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने गायें चराते-चराते ही अनंत प्रकृति के स्वरूप को समझ लिया था। उनको पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि से ज्ञान मिला था। यही सनातन ज्ञान पथ है और यही ज्ञान की मुक्त प्रणाली है। पर आजकल की वैज्ञानिक धारणा के अनुसार, अनुभव के साथ पदार्थ का मिलान करना ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हम जो कुछ देखते-सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना ही ज्ञान हम सत्य मानते हैं, उसके सिवाय और कुछ हम नहीं जानते, न मानते हैं। पर अब विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ नवीन विचारक मान रहे हैं कि अंतर्ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहां भक्ति-भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है। यह सत्य है कि भक्ति होने से भगवान का कार्य करने में शक्ति का अभाव नहीं रहेगा, पर इससे ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त न होने से वृहत सृष्टि में प्रवेश असंभव है। ज्ञान द्वारा ही भगवान के अनंत स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। अनंत विचित्रताओं-भेदों में ऐक्यता स्थापित किए बिना हमें क्षुद्र सृष्टि में रहना पड़ेगा और ऐसी क्षुद्रता भगवान की इच्छा के विरुद्ध होती है। इसलिए सबको वृहत होना चाहिए और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान का ही अनुगामी समता का भाव है और समता ही वृहत सृष्टि का बीज मंत्र है। सिर्फ कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान का प्रकाश सृष्टि का सर्वोच्च अंग है।

बिना ज्ञान कुछ नहीं...

सूत्र

सबको वृहत होना चाहिए और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान का ही अनुगामी समता का भाव है और समता ही वृहत सृष्टि का बीज मंत्र है। सिर्फ कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान का प्रकाश सृष्टि का सर्वोच्च अंग है। जब शक्ति और भक्ति के सम्मिश्रण से ज्ञान रूप धारण करेगा, तभी समस्त सृष्टि सार्थक होगी।

चुनावों में चुनौती बन रहा चीन

चीन मतदाताओं को सबसे ज्यादा किस चीज से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान कराने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मतभेद पैदा हो सकें। आशंका है कि वह भारत में लोकसभा चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है।

हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी और राजनीति का जुड़ाव तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत के लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य चुनावों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का दुरुपयोग कर सकता है। यह लेख इस मुद्दे के बहुआयामी आयामों को रेखांकित करता है और तकनीकी, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थों की खोज करता है। ताइवान के अनुभवों के जरिये इसकी भी पड़ताल की गई है कि इनसे निपटने में सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशांत माली

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई गई राजनीतिक सामग्री वितरित करेगा, जो 'इन हाई-प्रोफाइल चुनावों में उसके हितों को लाभ पहुंचा सकता है', क्योंकि एआई से तेजी से मीम्स, वीडियो और ऑडियो सामग्रियां बन रही हैं। कंपनी ने जून, 2023 से चीन और उत्तर कोरिया में 'कुछ उल्लेखनीय साइबर रुझान देखे हैं, जो न केवल अपने परिचित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक जटिल प्रभावी तकनीकों का उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं।' माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीनी साइबर हमलावरों ने तीन लक्ष्य क्षेत्रों को चुना है- दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के देश, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके क्षेत्रीय विरोधी और अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार। चीनी अभियान एआई-जेनरेटेड या एआई-समर्थित सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखते हैं। इन अभियानों के पीछे के खिलाड़ियों ने एआई-जनरेटेड मीडिया को बढ़ाने की इच्छा दर्शाई है, जो उनके रणनीतिक आख्यानों को लाभ पहुंचाता है, साथ ही वे वीडियो, मीम्स और ऑडियो सामग्री भी बनाते हैं।

चीन, मतदाताओं को सबसे ज्यादा किस चीज से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान कराने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मतभेद पैदा हो सकें। वह संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को भी अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य लक्ष्यों और गुप्तचर जानकारी संग्रह को वित्तपोषित करने और आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरंसी लूट और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने वाले हमलों को बढ़ा दिया है। इसने अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए एआई का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है।

सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने चीन द्वारा एआई का इस्तेमाल कर भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में चुनावों को बाधित करने की आशंका से संबंधित जो चेतावनी जारी की है, वह चिंताजनक है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार, चीन आगामी प्रमुख चुनावों में विशेष रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एआई द्वारा बनाई गई सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर (एमटीएसी) की रिपोर्ट इस आसन्न खतरे को रेखांकित करती है कि 'इस साल दुनिया भर में होने वाले प्रमुख चुनावों को देखते हुए, खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में, चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई जनरेटेड सामग्री बनाएगा और उसका प्रचार करेगा।'

माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चीन के कथित ट्रायल रन की खबरों के बाद आई है, जहां उसने जनवरी में एआई द्वारा बनाई सामग्री के जरिये दुष्प्रचार का प्रयास किया था। रिपोर्ट में स्टॉर्म 1376 नामक एक बीजिंग समर्थित समूह का उल्लेख है, जिसे स्पैमोफ्लाज या ड्रैगनब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो ताइवानी चुनाव के दौरान अत्यधिक सक्रिय था। यह राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले का अध्ययन करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तकनीकी हस्तक्षेप की क्षमता को रेखांकित करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाई गई सामग्री जनमत को प्रभावित करने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। माइक्रो टार्गेटिंग और भावनात्मक संदेश जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, एआई एल्गोरिदम इको चैंबर्स बना सकता है, जो मौजूदा विश्वासों को मजबूत करता है और समाज को ध्रुवीकृत करता है। इसके अलावा, 'डीपफेक' तकनीक का उदय सूचना के पारंपरिक स्रोतों में विश्वास को कम करते हुए, तथ्य और कल्पना के बीच की बारीक रेखा को धुंधला कर एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।

सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एआई सामग्री के दुरुपयोग को रोकने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को जटिल बनाती है, जिससे दुर्भावनापूर्ण लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बिना किसी दंड के काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी नवाचार की तीव्र गति विनियामक प्रयासों से आगे निकल जाती है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए उभरते खतरों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, एआई सामग्री निर्माण और प्रसार का विकेंद्रीकृत स्वरूप पारंपरिक प्रवर्तन रणनीतियों में बाधा डालता है, जिसके लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

डिजिटल युग में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा एआई-जनरेटेड सामग्री के संभावित उपयोग से प्रौद्योगिकी और राजनीति के बीच जटिलता स्पष्ट होती है। ताइवान जैसे अन्य देशों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि तकनीकी हस्तक्षेप दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को मजबूत विनियामक ढांचा विकसित करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और चुनावों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करेगी और नागरिकों का अपने राजनीतिक संस्थानों पर भरोसा कम हो सकता है।

-लेखक साइबर कानून विशेषज्ञ और बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील हैं।

दूसरा पहलू

अफ्रीकी महाद्वीप ने अपने यहां मौजूद कार्बन से कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है।

दुनिया में कार्बन को संतुलित करता अफ्रीका

एक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले एक दशक में अफ्रीकी महाद्वीप ने अपने यहां मौजूद कार्बन से कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा जमा कार्बन की कुल मात्रा एक तंत्र के भीतर कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से अधिक हो जाती है, तो इसे कार्बन सिंक कहा जाता है। लेकिन जैसे-जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए बदला जा रहा है, कार्बन भंडारण क्षमता कम हो रही है और उत्सर्जन दर बढ़ रही है। हम अफ्रीकी महाद्वीप में उत्सर्जित होने वाली और अवशोषित की जा रही कुल ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा का पता लगाना चाहते थे। इससे हम यह समझ पाए कि कैसे यह महाद्वीप वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर रहा है। इस अध्ययन का लक्ष्य महाद्वीपों (या बड़े देशों) और बड़े क्षेत्रों के लिए एक उन्नत ग्रीनहाउस बजट तैयार करना है। ऐसी जानकारी नीति निर्माण के लिए बहुत महत्व रखती है। यदि वैज्ञानिकों, भूमि प्रबंधकों और एनजीओ को यह पता हो कि किन गतिविधियों से ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, तो वे इसे कम करने के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं के साथ काम कर सकते हैं। अफ्रीका के मामले में हमारा आकलन है कि जब लोग जमीन का उपयोग खेती या दूसरे कामों के लिए करने लगते हैं, तो आग से उत्सर्जन भले कम हो जाता है, पर शाकाहारी जीवों से मीथेन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी हैं, जो कार्बन और ग्रीनहाउस गैसों को जमीन की सतह की ओर वापस खींचती हैं। अफ्रीका का पिछला कार्बन बजट (1985 से 2009) बताता है कि अफ्रीका में कार्बन खींचने की प्रक्रियाएं, प्राकृतिक उत्सर्जन और मानवजनित उत्सर्जन के मुकाबले ज्यादा थीं। यह महाद्वीप कार्बन सिंक था, भले ही यह मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा था, पर अफ्रीका पूरे विश्व को जलवायु सेवा प्रदान कर रहा था। अफ्रीकी भूमि की कार्बन शोषण क्षमता लगभग 0.8 गीगाटन कार्बन सालाना है, जो दुनिया की कुल कार्बन शोषण का लगभग 20 प्रतिशत है। इसकी कार्बन शोषण क्षमता में कमी नहीं हुई है। अफ्रीका को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए तरीके खोजना एक बड़ी चुनौती है। कार्बन-तटस्थ ऊर्जा स्रोतों में निवेश और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी से इसकी शुरुआत की जा सकेगी। *(द कन्वर्सेशन)*

-साथ में सैली आर्किबैल्ड

योलैंडी अर्न्स्ट

जब लोग जमीन का उपयोग खेती या दूसरे कामों के लिए करने लगते हैं, तो आग से उत्सर्जन भले कम हो जाता है, पर शाकाहारी जीवों से मीथेन का उत्सर्जन बढ़ जाता है।

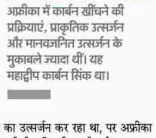

अफ्रीका में कार्बन खींचने की प्रक्रियाएं, प्राकृतिक उत्सर्जन और मानवजनित उत्सर्जन के मुकाबले ज्यादा थीं। यह महाद्वीप कार्बन सिंक था।

आंकड़े

शीर्ष नाशपाती उत्पादक

वैश्विक स्तर पर नाशपाती के उत्पादन में कोस्टारिका अव्वल है, जबकि हमारा देश शीर्ष सात उत्पादकों में शामिल है।

कोस्टारिका	10.26%
इंडोनेशिया	10.08%
फिलीपीन	9.98%
ब्राजील	8.09%
चीन	6.63%

स्रोत : FAO

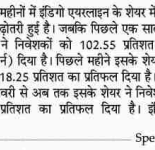

जिंदगी में हमें बहुत-सी चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें लालच में न फंसकर सही राह चुननी चाहिए।

दिव्य पुष्प

अंतर्यात्रा
संकलित

एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था। एक दिन जब वह पानी लेने गया, तो उसने तालाब में एक अद्भुत पुष्प देखा। उसने अपनी पत्नी को भी बुलाकर दिखाया। उन दोनों ने सोचा कि अगर यह पुष्प राजा को दे दिया जाए, तो वह इनाम देगा।

वह पुष्प लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसने पूछा कि यह पुष्प लेकर कहां जा रहे हो? उसने बताया कि मैं राजा के पास जा रहा हूं। इसे राजा को भेंट करके उनसे इनाम लूंगा। व्यापारी ने कहा कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब व्यापारी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को मना कर दिया। राजा ने जब वह दिव्य पुष्प देखा, तो अचंभित हो गए। राजा 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था। तभी उसके मन में एक अजीब-सी चेतना आई। वह राजा को पुष्प न देकर सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए कहा, मैं समझ गया हूं कि आपकी शरण में आने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा।

आज का इतिहास

आजादी के मायने समझाने वाले तात्या टोपे का बलिदान दिवस

देश में आजादी का बिगुल फूंकने वाले कई बड़े नामों में एक और नाम तात्या टोपे का भी है, जिन्होंने देश में न सिर्फ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, बल्कि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया और गुलामी को अपना भाग्य मान चुकी पूरे देश की जनता को यह बताया कि आजादी क्या होती है और उसे हासिल करना कितना जरूरी है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र रघुनाथ टोपे था। अंग्रेजों ने 1857 की आजादी की पहली क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा देश और दुनिया के इतिहास में 18 अप्रैल के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें जाने-माने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन शामिल है।

हवाइयां उड़ातीं हवाई टिकट की कीमतें

बड़ी संख्या में विमानों का परिचालन रद्द होने से हवाई टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरतमंद यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।

सतीश सिंह | विमानन

भारत की इंडिगो एयरलाइन 1.47 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी विमानन कंपनी बन गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, यात्रियों की संख्या के हिसाब से भारत के विमानन क्षेत्र में इंडिगो एयरलाइन की 60.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि दूसरे स्थान पर एयर इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत है।

विगत छह महीनों में इंडिगो एयरलाइन के शेयर में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि पिछले एक साल में इसके शेयरों ने निवेशकों को 102.55 प्रतिशत का प्रतिफल (रिटर्न) दिया है। पिछले महीने इसके शेयर ने निवेशकों को 18.25 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है। इस साल एक जनवरी से अब तक इसके शेयर ने निवेशकों को 27.78 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है। इंडिगो

एयरलाइन ने दो फरवरी, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा की थी, जिसके अनुसार इंडिगो का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 110.7 प्रतिशत बढ़कर 2,998 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में इसने 1,422.6 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तिमाही में भी इंडिगो ने 188.9 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। विगत पांच वर्षों में पहली बार किसी भारतीय विमानन कंपनी ने किसी भी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया है, क्योंकि दूसरी तिमाही विमानन उद्योग के लिए कमजोर मांग वाला सीजन माना जाता है। इंडिगो का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बनना निश्चित रूप से हर्ष एवं गौरव का विषय हो सकता है। यह शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि इसके शेयर में निवेश करके निवेशकों ने काफी कमाई की है, लेकिन यह जरूरतमंद यात्रियों के लिए खुशी की बात कतई नहीं हो सकती है। मौज-मस्ती के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयर टिकट की कीमत ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन किसी बीमार का इलाज के लिए सफर करने या नौकरी में योगदान देने, जरूरी मीटिंग में शामिल होने, आदि के लिए यात्रा करने वालों के लिए लगातार एयर टिकट की कीमत में इजाफा परेशानी का कारण बन गया है। यात्रा वेबसाइट इक्सिगो के विश्लेषण से पता चला है कि एक से सात मार्च की तुलना में एक से सात अप्रैल की अवधि में कुछ हवाई मार्गों पर किराया 39 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इस अवधि में दिल्ली से बंगलूरू के बीच के उड़ानों के लिए एक तरफ का किराया 39 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि दिल्ली से श्रीनगर के हवाई किराये में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइन के पास 320 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है, जो हर दिन 1,900 से ज्यादा फेरे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शहरों में लगाते हैं। वर्ष 2024 में 150 नए विमानों को घरेलू उड़ान हेतु बेड़े में जोड़ा गया है। फिर भी यह घरेलू मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। घरेलू यात्रियों की संख्या में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 24 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। 2023 में घरेलू यात्रियों की संख्या 15.2 करोड़ से अधिक हो गई है। विमानन उद्योग मांग के अनुरूप क्षमता बढ़ाने में कई चुनौतियों से जूझ रहा है। घरेलू मार्गों पर भी बड़े विमानों का उपयोग हो रहा है। बावजूद इसके, मांग और आपूर्ति के बीच खाई बनी हुई है। इंडिगो को छोड़ दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें गाहे-बगाहे रद्द होने और यात्री मांग में मजबूती के कारण हवाई किराये में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। गर्मियों में घरेलू उड़ानों में यात्रियों को टिकट के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। सभी एयरलाइंस के टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। गर्मी की छुट्टियों में इसमें बढ़ोतरी का अंदेशा है। हालांकि, 18 से 24 महीने पहले भारत में एयर टिकट की कीमत काफी सस्ती थी। एयर टिकट की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है। वैसे, विमानन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संसदीय स्थायी समिति ने भी छुट्टियों और त्योहारों के दौरान एयर टिकट की कीमत वृद्धि पर रोक लगाने पर जोर दिया है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 62 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम्।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते।

भावार्थ : इस चराचर जगत में जो कर्म शास्त्रविधान से नियत किया हुआ हो तथा कर्तापन के अभिमान से रहित हो। साथ ही फल की इच्छा किए बिना किसी मनुष्य द्वारा बिना राग-द्वेष के किया हुआ कार्य हो, वह सात्त्विक कहा जाता है।

समान संहिता की जमीन

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस संहिता को स्वीकार किया, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर सहमति बनेगी। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए यह अवश्य कहा था कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका यह आशय कदापि न था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा की जाएगी। सच यह है कि संविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रीय सत्ता ने समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। उलटे जब भी किसी दल और यहां तक कि उच्चतर न्यायपालिका ने इसकी आवश्यकता जताई तो वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया गया। यह काम अब भी किया जा रहा है। बीते दिनों ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं। इस संहिता का विरोध संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के अनदेखी भी है। आखिर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार आदि के कानून एक जैसे हों?

समान नागरिक संहिता का निर्माण भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है। चूंकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को पूरे कर चुकी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे। घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के निर्माण की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतीय समाज की आवश्यकता भी, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे, लोगों में यह आवश्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारतवासी एक जैसे कानून से संचालित हैं। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही, पंथ-मजहब की विभाजनकारी राजनीति पर भी लगाम लगाएगी। समान नागरिक संहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर झूठ के सहारे वैसा दुष्प्रचार न होने पाए, जैसा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया गया।

नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता

प्रदेश में तीन चरणों के अंतर्गत हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनजातीय संस्कृति, आदिवासी समाज, कला-संस्कृति की विविधता वाले इस वनांचल में लोकतंत्र पर कम हमले नहीं हुए हैं। नक्सलवाद यहां जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाता रहा है, सरकारी प्रतीकों पर हमला करता रहा है। यही नहीं, वह लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोड़ा अटकाता रहा है। विकास की राह में नक्सलवादी खंदक खोदते रहे हैं। देश विरोधी इन तत्वों ने सदैव से ही लोकतंत्र को निशाना बनाया है, इसलिए संसदीय क्षेत्र के कई हिस्सों में चुनाव कराना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मतदान दलों की सुरक्षा, आम मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना यहां चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए आयोग ने यहां चुनाव की व्यापक तैयारियां की हैं। जागरूकता अभियान के जरिए मतदान बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। आम मतदाताओं में विश्वास बहाली के लिए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों ने भी गांव-गांव, गलियों-मोहल्लों तक जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी लगातार इलाके में लोकतंत्र की लौ जलाकर रखी है। अब बस्तर में प्रचार खत्म हो गया है। मतदाताओं को अपना नया सांसद चुनना है। वे जिसे भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनेंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उनकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में जोर-शोर से उठाए। उनकी तकलीफों, समस्याओं को अपनी आवाज दे। उनके निराकरण में अपनी भूमिका निभाए। क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करे। अब जब मतदान शुरू होने के लिए कुछ घंटों का ही समय बाकी है, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बस्तर में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो-जो उपाय किए जा सकते हैं, वे करने चाहिए।

> अब जब मतदान शुरू होने के लिए कुछ घंटों का ही समय बाकी है, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बस्तर में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो-जो उपाय किए जा सकते हैं, वे करने चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

नईदुनिया जनमत

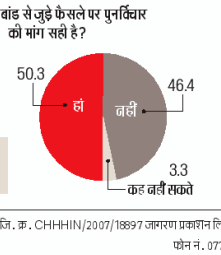

कल का परिणाम

क्या चुनावी बांड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की मांग सही है?

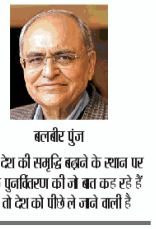

आज का सवाल
क्या रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई से अन्य नेता सबक लेंगे?

परिणाम इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राहुल गांधी के सपनों का भारत

बलबीर पुंज

राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की जो बात कह रहे हैं वह तो देश को पीछे ले जाने वाली है

लोकसभा चुनाव की गहमागहमी चरम पर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे मुखर आलोचक बनकर उभरे हैं। मोदी का विरोध उनकी पार्टी और व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इसकी झलक उनके कुछ हालिया बयानों और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से मिल जाती है। बीते दिनों तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि 'हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे से पता लगाएंगे कि देश का धन किसके और कौन से वर्ग के हाथ में है, जो आपका हक बनता है, वह हम आपको देने का काम करेंगे।' इसके जरिये राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की बात कह रहे हैं। यह नीति कोई नई नहीं है। वास्तव में यह राहुल का मौलिक राजनीतिक-वैचारिक चिंतन भी नहीं। वह उस उधार के दर्शन का प्रतिबिंब है, जिसे 1969-71 में उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वामपंथियों से राजनीतिक समझौते के अंतर्गत आउटसोर्स किया था। उस समय के भारत में भुखमरी और महंगाई के साथ टेलीफोन, सीमेंट, इस्पात, कार-स्कूटर से लेकर दूध-चीनी, तेल-अनाज आदि खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी और उसके लिए लगने वाली लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखती थीं। गरीबी हटाने और समानता लाने हेतु देश में 97.7 प्रतिशत तक आयकर था। इस मार्क्स-लेनिन-स्टालिन प्रेरित समाजवादी व्यवस्था से देश में कालाधन, भ्रष्टाचार, गरीबी और कपट कई गुना बढ़ गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि 1991 में देश को अपनी देनदारियों को पूरा करने हेतु विदेशी बैंकों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। इस अभिशाप रूपी वाम-विचारधारा से तब भारत ही ग्रस्त नहीं था। चीन में माओ (1949-76) और कंबोडिया में पोल पाट का शासनकाल (1975-79) भी इसी चिंतन का भयावह परिणाम देख चुका है। वहां भी सामाजिक-आर्थिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निजी संपत्ति-स्वामित्व और धन-संपदा को समाप्त कर दिया था। ऐसे अव्यावहारिक उपायों से न केवल मानवाधिकारों का भीषण हनन हुआ, अपितु करोड़ों लोगों की मौत तक हो गई।

आज चीन इसीलिए चमक रहा है, क्योंकि चीनी सत्ता अधिष्ठान समय को भांपते हुए अपनी विशुद्ध वाम-नीतियों को दशकों पहले तिलांजलि दे चुका है। वर्तमान भारत भी पिछली सदी के अंतिम दशकों तक जारी नीतियों से उपजी लचर स्थिति से बाहर निकलकर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कालबाह्य वामपंथी जुमले अब भारतीय जनमानस को आकर्षित नहीं करते। आज का युवा आकांक्षावान है। वह समृद्धि और आर्थिक विकास को लांछित नहीं, अपितु अपनाना चाहता है। इस आमूलचूल परिवर्तन में नीतिगत सुधारों के साथ भारतीय उद्यम क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे एक समय पनपने नहीं दिया गया।

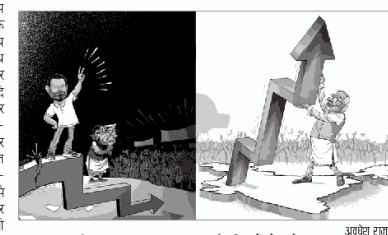

अवधेश राजपूत

करीब 50 वर्ष पहले जिन अपशब्दों से वामपंथी-पश्चिमी समूह टाटा-बिरला जैसे औद्योगिक समूहों को निशाने पर रखते थे, वही अब अंबानी-अदाणी समूह के लिए उपयोग होते हैं। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी भारतीय औद्योगिक घरानों को तो कोसते है, परंतु विदेशी कंपनियों के खिलाफ वैसी मुखरता नहीं दिखाते। भीषण कोरोना काल में स्वदेशी कोविड टीके के बजाय विदेशी वैक्सीन पर राहुल का अधिक विश्वास इसका एक प्रमाण है। इसका कारण क्या है? क्या राहुल औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं?

राहुल गांधी भारत को राष्ट्र के बजाय 'राज्यों का संघ' बता चुके हैं। यह विचार उन्हीं विदेशी विचारधाराओं के अनुरूप है, जिसमें देश के मूल सनातन दर्शन, संस्कृति, पहचान और इतिहास के प्रति हीन-भावना और भारत को 'राष्ट्र' नहीं मानने का चिंतन है। जब राहुल के सहयोगी दल द्रमुक के नेताओं ने खुलकर 'सनातन को मिटाने' का आह्वान किया, तब वह न केवल चुप रहे, अपितु उनकी पार्टी के कार्ति चिदंबरम और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे इसका समर्थन करते नजर आए। राहुल को भारत की पहचान श्रीराम के जन्मभूमि मंदिर जाना भी स्वीकार नहीं। उनके लिए बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिकता के पर्याय हैं, परंतु वह 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरित तत्वों के खिलाफ अक्सर मौन रहते हैं। इसी प्रकार उनके 'जितनी आबादी, उतना हक' सरीखे विचार में राष्ट्रीय पहचान 'भारतीयता' गौण होकर जाति प्रमुख हो जाती है। इससे हिंदू समाज में जाति विभाजन की खाई और गहरी होगी। यह राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होगा।

इधर राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर जिस संविधान के बदलने-खत्म करने का खौफ दिखा रहे हैं, उसकी पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि भारतीय संविधान में सौ से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस ने ही किए हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राहुल गांधी ने 2013 में अपनी सरकार के एक अध्यादेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था। असल में राहुल 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं कि केवल उन्हें ही कोई भी विचार रखने और अपने अनुकूल 'लोक' (जनमानस) और 'तंत्र' (मीडिया-न्यायालय सहित) चलाने का 'दैवीय अधिकार' है। अब राहुल को मोदी का विकल्प बनना, उनसे वैचारिक-राजनीतिक रूप से अलग दिखना है। इस होड़ में वह जो वादे और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भारत कैसा होगा? क्या लोकलुभावन नीतियों के नाम पर सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज की वापसी होगी, जिसमें अतीत के दौर की तरह रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी के साथ कालाबाजारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार चरम पर था? क्या उनके विचारों पर चलने वाली सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी या उस स्थिति में पहुंचा देगी, जब देश की आर्थिकी तबाह हो गई थी? क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में बदहाली का कारण इसी प्रकार की राजनीति नहीं रही? इस पर विचार करते हैं कि अगले पांच वर्षों में भारत की तस्वीर कैसी होगी? क्या वह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप बनेगी, जिसमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप स्थापित करने का लक्ष्य है या फिर वैसी जिसका तानाबाना राहुल गांधी बुन रहे हैं? इसका उत्तर मतदाताओं के विवेक पर निर्भर है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे हैं

लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आइआइएम-अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आइआइटी-मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है। जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है। इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है।

क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजरायल ने भी यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है।

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच बढ़े ● फाइल

अनुसंधान एवं विकास ही बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई। सवाल यह उठता है कि शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू नवप्रवर्तन क्यों पैदा करता है? शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य देशों ने दिया। जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 प्रतिशत है और विश्व औसत 1.8 प्रतिशत से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है।

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे। इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

ऊर्जा

सांसारिक सुख

विकास के दो पथ हैं-बाहरी और आंतरिक। आज बाहरी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक सोच ने विकास की रफ्तार को अकल्पनीय गति दी है। विकास की हर दौड़ में वह आगे बढ़ता जा रहा है। आज बाह्य विकास इतना हुआ है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना की आनन-फानन में अवगति हो जाती है, लेकिन स्वयं के भीतर घटित होने वाली घटना का कुछ अता-पता भी नहीं है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। बाहर तो उजाला फैलता जा रहा है और भीतर गहन अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अंधकार को हटाए बिना उजाला कैसे मिल सकता है? उजाले के बिना सुख, शांति और तृप्ति कहां है?

मनुष्य की जिस ऊर्जा का उपयोग अंधकार को हटाने के लिए होना चाहिए था, वह निरर्थक कार्यों में बह रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग चेतना के रूपांतरण एवं ऊर्ध्वारोहण के लिए होना चाहिए था, वह बाहरी संचालन में खप रही है, क्योंकि आज आदमी केवल देह की परिधि में ही जी रहा है। वह संसार के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। उसकी समग्र दृष्टि बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस बाह्य दौड़ को ही वह पूर्णता की कसौटी समझ रहा है। वह इस सच्चाई को भूल रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो सुखानुभूति वह कर रहा है, उसे केवल सुखाभास या मृगतृष्णा ही कहा जा सकता है। मनुष्य को सुखाभास की अनुभूति से स्वयं को ऊपर उठाकर आनंद एवं तृप्ति की अनुभूति में प्रविष्ट होना है।

आनंद आत्मा का स्वभाव है और सुख-दुख शरीर का स्वभाव है। इसलिए निजानंद में प्रवेश करना अपेक्षित है। स्वयं के भीतर डुबकी लगाकर ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसने सर्वस्व पा लिया। सांसारिक सुखों की मृगमरीचिका से बाहर निकलकर अपने ही अंतस की गहराई में उतर जाना श्रेयस्कर है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

letter@naidunia.com

अपने-अपने राम

प्रवीन लखेड़ा का आलेख 'जन-जन तक पहुंचे श्रीराम का संदेश' सचमुच में विचारणीय है। वर्तमान भारत की स्वतंत्रता के अमृतकाल की सांप्रतिक पीढ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे अपने जीवनकाल में अयोध्या में सदियों बाद भगवान राम के मंदिर की सुखबर ने आह्लादित किया है। अब इस पीढ़ी का दायित्व है कि रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए वह अपने-अपने मर्यादित राम का अनुसरण करे और अपने दायित्वों का इस प्रकार निर्वहन करे कि उनमें स्वार्थ की कोई झलक न हो। कोई भी समाज अथवा राष्ट्र उसके व्यक्तियों के प्रयासों से ही श्रेष्ठ बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रत्येक आचरण हमें संजीवनी देता है। उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़कर और उसे जीवन में उतारकर ही हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। ऐसा भारत जिसमें कोई ऊंच-नीच न हो, समाज में कोई कलह न हो, समस्याओं की नहीं अपितु समाधान की बात हो, केवल अधिकारों की नहीं, अपितु कर्तव्यों की आवाज उभरे। ऐसा भारत जिसमें कोई भूखा न सोए, लोग सदाचार के बल पर आगे आएं, प्रकृति से कोई खिलवाड़ न हो। ऐसा भारत जहां हर ओर खुशहाली हो, एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो, हर वर्ग केवल राष्ट्रोत्थान की बात करे।

yograj62@gmail.com

यह तो संविधान के विरुद्ध घोषणा है

तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बंगाल की मुख्यमंत्री की इस पार्टी ने वादा किया है कि बंगाल में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगे। टीएमसी का यह वादा संविधान की मूल अवधारणा और संघीय ढांचे की अवहेलना करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई पार्टी खुले तौर पर संविधान की इस तरह धज्जियां उड़ा रही है। साफ है कि टीएमसी किस वर्ग को लुभाना चाह रही है। वह अवैध घुसपैठियों की हिमायत करके राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भी खुले आम खतरे में डालने का प्रयास कर रही है। इस मामले में जहां चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, वहीं जनता को भी ऐसे असंवैधानिक और देशविरोधी बातें करने वाले दलों को सबक सिखाना चाहिए।

-**समरथ पाटीदार**, रांकोदा, रतलाम

कांच का घर और दूसरों पर पत्थर!

समाचार : राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल 22 से 25 लोगों की है।

टिप्पणी : कमाल की बात तो यह है कि यह बात उस कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जहां देश ने पूरी कांग्रेस ही केवल दो लोगों की देखी है। एक सोनिया गांधी और दूसरे राहुल गांधी। हालांकि इसके पहले भी यह गांधी परिवार के पास ही रही।

- **डा. अनिल अग्रवाल**, अग्रवाल नगर, इंदौर

सहनशक्ति का होना जरूरी

लोगों में सहनशक्ति का अभाव है। सड़कों पर देखिए, किसी को जरा-सा भी धक्का लग जाए तो वह विवाद करने लगता है। झगड़ा इतना अधिक बढ़ जाता है कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कल की ही बात है। एक बाइक सवार एक ई-रिक्शा वाले को गालियां बक रहा था। यह देखकर कुछ लोगों ने कहा कि बाइक वाले को टक्कर भी नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ई-रिक्शा वाला दुर्घटना बचाते हुए बगल से निकल गया, फिर भी बाइक वाला झगड़ा करने पर उतारू है। अगर ई-रिक्शा वाला ही भारी पड़ गया तो? जितना हो सके, विवाद टालना चाहिए। अगर आप सुरक्षित हैं, कोई घटना होते-होते टल गई तो झगड़ा मोल मत लीजिए। सामने वाले को प्रेम से समझा सकते हैं कि सावधानी से चलिए। भीड़भाड़ में कुछ लोग जानबूझकर धक्का मारते हैं, वाहन चढ़ा देते हैं, वहीं कुछ लोग सावधान होने के बावजूद कहीं टकरा जाते हैं तो उनसे विवाद न करके स्थिति को समझना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ा करने का बहाना खोजते रहते हैं। गलती खुद करेंगे और दोषी सामने वाले को बताएंगे। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत-से लोगों को देखा है कि वे नियमों के प्रति बेहद लापरवाह हैं।

- **गोकुल शर्मा**, रायपुर

X पोस्ट

हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्रीराम का सूर्यतिलक का दृश्य देख सके।

मि. सिन्हा@MrSinha_

दूसरे की जाति से घृणा करना और उन्हें बेवजह नीचा दिखाना ही असली जातिवाद है। कौन किस जाति में पैदा होगा, यह हमारे हाथ में नहीं तो फिर क्यों किसी से जाति या धर्म की वजह से नफरत करें?

रोहिणी@RohiniGhavari11

भारत की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवा में मुस्लिम वर्ग के 51 अभ्यर्थी चुने गए। जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं को ऐसे समान अवसर उपलब्ध नहीं। उलटे वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जबरन मतांतरण कराया जाता है। इसके बावजूद वामपंथी इस्लामिस्ट तबके की दृष्टि में भारत असहिष्णु है।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नंबर दो हो गई हैं। सुनीता जी का स्थान पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया से भी ऊपर है। फिर अन्य सांसदों का नीचे रहना स्वाभाविक है। अरविंद जी तो राजनीति बदलने आए थे।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2007/18897 जागरण प्रकाशन लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संजय शुक्ला द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के प्रेस प्लॉट नं. 47/3, भनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर से मुद्रित एवं तीसरी मंजिल, कृष्णा ग्लोरी कॉम्पलेक्स, सांई नगर, होटल वेबीलॉन इन के पीछे, जेल रोड, रायपुर से प्रकाशित
फोन नं. 0771-4711000 फैक्स : 0771-4711024 इंटरनेट संस्करण : http://www.naidunia.com संपादक : सद्गुरु शरण* *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।
****

संपादकीय

महंगाई के सवाल पर यह कैसा विरोधाभास है!

खुदरा महंगाई दस माह के सबसे निचले स्तर 4.85% पर आ गई लेकिन खाद्य महंगाई आज भी (मात्र 0.14% घटकर) पांच माह के उच्चतम स्तर 8.52% पर टिकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई गर्मी के समानुपाती है। औसत खुदरा महंगाई के कम होने का कारण पेट्रोलियम के वैश्विक मूल्य में गिरावट है। लेकिन चिंता यह है कि तापमान जैसे-जैसे बढ़ेगा दूध और सब्जियां महंगी होंगी। भारत दुनिया में सब्जी और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन हरी सब्जियों का एक बड़ा प्रतिशत गांव से शहर आने में बर्बाद हो जाता है क्योंकि देश में कोल्ड स्टोरेज या उचित ट्रांसपोर्ट साधनों का अभाव है। आज भी दूध संगठित क्षेत्र में मात्र 22 प्रतिशत है जबकि 233 मिलियन टन के सालाना उत्पादन के साथ भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी आजादी के समय से चार गुना बढ़कर 505 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति दिन है। लेकिन क्या एक आम गृहस्थ अपने बच्चों को रोजाना एक गिलास दूध दे पाता है? सरकार के आंकड़ों और भोगे हुए यथार्थ में यही बड़ा अंतर है। अभिजात्य वर्ग खुश होता है कि खुदरा महंगाई नीचे है क्योंकि उसकी आय का बड़ा हिस्सा बेहतर जीवन शैली पर खर्च होता है, जबकि निम्न, निम्न मध्यम व मध्यम वर्ग की आय का क्रमशः 70, 50 और 40 फीसदी खाद्य पदार्थों पर। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम काबू करना जरूरी है।

प्रेरणा

हर पत्थर की कथा एक पर्वत की ओर जाती है।
-विलियम स्टैनले मर्विन

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

हमारा काम प्रयास करना है, परिणाम ऊपर वाला देगा

एक बहुत प्यारी पंक्ति है, जिसे शिव जी ने बोला है। 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा'। 'जो कुछ राम ने रचा है, वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए'। ये पंक्ति एक तरह का आश्वासन है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, जो होकर रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य हो जाएं, दुर्भाग्य ही मान लें। इसका अर्थ है, अपने प्रयास करते रहिए, परिणाम के प्रति विचलित न हों। कब तक तकदीर से लड़ेंगे, लोग पनघट पर प्यासे खड़े हैं। भरपूर मिठाई खरीद सकने वाले को डायबिटीज है। जिन्होंने मनौती मांग-मांग कर संतान प्राप्त की, वो अपने ही बच्चों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं, जिनकी योग्यता के अनुसार आय नहीं हो रही। शरीर को खूब स्वस्थ रखने वालों को भी कैंसर हो जाता है। जब जीवन में इतना विपरीत हो तो अशांति आना ही है। और जब अशांति आ जाए तो बचने के जितने तरीके हैं, उसमें से एक सरल तरीका है। हमारा काम प्रयास करना है, परिणाम ऊपर वाला देगा। अपने कर्म में भरपूर ऊर्जा लगाएं पर उसके परिणाम देने में हस्तक्षेप न करें।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • विविधता के बावजूद कुछ पैटर्न भी हैं

भारत के मतदाता किस तरह से वोट डालते हैं?

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

भारत के लोग जटिल होते हैं। इसका कारण हमारे यहां पाई जाने वाली संस्कृति, भाषा, धर्म, विचारधारा और आस्था की विविधताएं है। यही कारण है कि भारत के लोग किस तरह से वोट देते हैं, इसे मालूम करने का कोई सीधा-सरल मानदंड तय करना लगभग असंभव है। लेकिन 1.4 अरब की आबादी वाले विविधतापूर्ण देश में भी कुछ पैटर्न उभरकर सामने आ सकते हैं। चूंकि चुनावी मौसम चरम पर है, और हम सभी 4 जून को घोषित होने वाले परिणामों को जानने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए क्यों न यह विश्लेषण करने का प्रयास करें कि भारतीय मतदाताओं के मन में क्या है। इसे जानने के मुख्य मानदंड इस प्रकार हो सकते हैं :

फिक्स्ड वोटर : भारतीय परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक ही पार्टी को वोट देता आ रहा होता है। ऐसा उस पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व या पीढ़ीगत रूप से उसके प्रति जुड़ाव के कारण हो सकता है। तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन-सा उम्मीदवार उतारा है या उसके घोषणा-पत्र में क्या है। इस तरह के फिक्स्ड वोट को बदलने के लिए कड़ी मुहिम चलाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाहे कितने ही वॉट्सएप फॉरवर्ड क्यों न देख लें, इस तरह के वोटर अमूमन अपना मन नहीं बदलते। इसके बावजूद पार्टियां अपने फिक्स्ड वोटरों को हलके में नहीं ले सकतीं। उन्हें उनकी न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहना ही पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है, 'कभी भी अपने समर्थक-आधार को नाराज न करें।'

मजबूत नेता : यह लोकसभा चुनाव है, जो प्रधानमंत्री के चयन का भी माध्यम है। इसलिए इसमें प्रधानमंत्री पद के लिए एक निश्चित चेहरा बहुत मायने रखता है। यकीनन, केवल चेहरा होना ही काफी नहीं है। चेहरा एक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुछ अपेक्षित गुण भी होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा गुण है मजबूती। भारत के लोग (और दुनिया के भी) एक मजबूत नेता को पसंद करते हैं। इसका आकलन ठोस और साहसिक निर्णय लेने की उसकी क्षमता से किया जाता है। भारत दशकों तक धीमे क्रियान्वयन के दौर से गुजरा है और उसने शीर्ष नेतृत्व में विश्लेषण-क्षमता के अभाव का भी सामना किया है। इससे भारतीयों में एक मजबूत नेता के प्रति चाहत और बढ़ गई है। किसी नेता के अपनी विचारधारा और पहचान पर मजबूती से टिके रहने से भी उसकी ताकत का प्रदर्शन होता है, फिर भले ही यह सभी नागरिकों को और विशेषकर बुद्धिजीवियों को पसंद न आए। एक मजबूत नेता सुरक्षा और व्यवस्था की भावना भी देता है और सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता अकसर दूसरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है।

जनता से जुड़ाव : मजबूती के अलावा एक और गुण जो भारतीयों को पसंद आता है, वह है आम लोगों से जुड़ने की किसी नेता की क्षमता। लोग यह पसंद करते हैं कि कोई नेता मजबूत होने के बावजूद उनके स्तर तक कैसे आ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, जो उनके त्योहार मना सकता हो, उनके जैसा खाना खा सकता हो और उन्हीं के लहजे में बात कर सकता हो। मजबूती और जनसम्पर्क का यह कॉम्बो एक बड़ी संख्या में वोटरों को अपनी ओर खींचने में सफल रहता है।

पहचान के आधार पर वोट देने वाले : यह वर्ग मुख्य रूप से जाति और धर्म के आधार पर वोट करता है। उसके पास इस बात के अपने ठोस कारण होते हैं कि वे इस तरह से मतदान क्यों करते हैं (खासकर यदि वे वंचित जातियों या अल्पसंख्यक तबके से हों तो)। उनके लिए ऊपर बताए गए दूसरे क्राइटेरिया भी तभी

एक मजबूत नेता सुरक्षा और व्यवस्था की भावना देता है और सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता अकसर दूसरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। भारतीयों को किसी नेता की आम लोगों से जुड़ने की क्षमता भी पसंद आती है।

मायने रखते हैं, जब कोई पार्टी उनके जाति/धर्म के मानदंडों को पूरा करने में सक्षम हो।

नीतियों के आधार पर वोट देने वाले : इस तरह के वोटर नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर मतदान करते हैं। यह कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं जैसे मुफ्त या सब्सिडी वाली वस्तुएं। या यह महंगाई, टैक्स, बुनियादी ढांचा, रोजगार, हेल्थकेयर, शिक्षा आदि से सम्बंधित सरकार के निर्णय हो सकते हैं। इस तरह के मतदाता स्विंग भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान में रखकर पार्टियां बेहतर घोषणा-पत्रों, योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती हैं या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखती हैं। भले ही इस तरह के मतदाताओं का प्रतिशत कम हो, लेकिन स्विंग-वोटर होने के कारण वे नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है। आप सभी को चुनावी-मौसम की शुभकामनाएं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

विशेष • चिकित्सा-व्यवस्था चरमराई, मरीज मर रहे हैं

गाजा में युद्ध-क्षेत्र का सबसे भयावह रूप प्रकट हुआ है

डेविड नॉट
लंदन के सेंट मेरी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट-सर्जन

पिछले 30 सालों में मैंने दुनियाभर के युद्ध-क्षेत्रों में एक शल्य-चिकित्सक के रूप में काम किया है। मैंने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान और इराक में विभिन्न संघर्षों के परिणामस्वरूप हताहत होने वाले लोगों का इलाज किया है। युद्ध के घावों, विस्फोट से होने वाली चोटों और बंदूक की गोली से हुए जख्मों के इलाज के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। कभी-कभी युद्धों में बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। मैंने 30 से अधिक युद्ध-क्षेत्रों में जिन रोगियों को देखा है, उनमें से कुछ को तो इतनी गंभीर चोटें लगी थीं कि दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थकेयर यूनिट्स के लिए भी उनका इलाज करना टेढ़ी खीर होता। हालांकि अधिकांश चोटें ऐसी होती हैं, जिनका मामूली संसाधनों से भी उपचार किया जा सकता है। उन युद्ध-क्षेत्रों में अधिकांश रोगियों को निश्चित समय-सीमा के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जिससे उनके इलाज के लिए सर्वोत्तम सर्जिकल-निर्णय समय रहते लिए जा सके।

लेकिन गाजा के जैसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाल ही में मैंने गाजा के राफा शहर में एक महीने तक काम किया। गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर स्थित इस शहर के रास्ते पर मीलों तक सहायता-सामग्री ले जाने वाले ट्रक खड़े हुए थे। उनके चक्के जाम थे। राफा से बीच-रोड तक की सड़क पर अधिकांश एनजीओ का ठिकाना था, लेकिन उसे देखकर झटका लगता था। मैंने सीरिया और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में काम किया है, जहां व्यवस्थित रूप से एक-दूसरे से सुरक्षित दूरी पर तम्बू बनाए गए थे, लेकिन यहां मैंने एक छोटी-सी जगह में हजारों-हजार लोगों को ठसे हुए देखा। वहां पूरे के पूरे परिवार ऐसे थे जिनके सिर पर छत के नाम पर सिर्फ एक पॉलिथीन थी। जो भाग्यशाली थे, वो तम्बू में रह रहे थे। लेकिन इन तम्बुओं में भी बच्चों सहित छह या सात लोग रह रहे थे और वहां बैठने के लिए भी बामुश्किल ही कोई जगह होती थी- सोने की तो बात ही छोड़िए। वहां टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं थी। मीलों तक यही दृश्य दिखाई देता था।

गाजा में मेरा मिशन बंदूक की गोलियों और बम विस्फोटों की चोटों की मरम्मत के लिए अग्रिम पंक्ति में एक सर्जन के रूप में काम करना नहीं था। वहां मुझे हजारों लोगों की सर्जिकल-जटिलताओं से निपटने के लिए दूसरी पंक्ति में रहना था। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक बदतर था। मैं राफा के एकमात्र कार्यरत अस्पताल में काम कर रहा था। इसमें लगभग 40 बिस्तर और दो ऑपरेटिंग थिएटर थे। लेकिन जब मैं पहुंचा, तब वहां पहले ही 2,000 से अधिक मरीज वार्डों, गलियारों और हर उस जगह पर लेटे थे, जो खाली थी। एक कमरे में अक्सर छह से आठ मरीज होते थे। कई मरीजों के ऑपरेशन हुए थे और एक-दूसरे से सटे हुए होने के कारण उनमें संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया था। कई लोगों के घाव ऐसे थे, जो सिल दिए जाने के बावजूद खुल गए थे, और उन पर मवाद जमा था। सभी कुपोषित थे, जिससे उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी।

एक समाज अपने लोगों को जैसी चिकित्सा-देखभाल मुहैया कराता है, वह यहां पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। यमन या सीरिया में भयानक युद्धों के दौरान भी लोगों को कम से कम बुनियादी जीवनरक्षक दवाएं तो दी ही जा सकती थीं। लेकिन गाजा में ऐसा नहीं था। यहां सभी फार्मेसियां बंद हो चुकी थीं और दवाइयों का टोटा था। डायबिटीज के अलावा कार्डियोलॉजिकल, रीनल, ऑन्कोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल रोगों से पीड़ित लोगों के लिए रोजमर्रा

एक समाज अपने लोगों को जैसी चिकित्सा-देखभाल मुहैया कराता है, वह गाजा में ध्वस्त हो चुकी है। यमन- सीरिया में भयानक युद्धों के दौरान भी लोगों को कम से कम जीवनरक्षक दवाएं तो दी ही जा सकी थीं। गाजा में ऐसा नहीं है।

की दवाएं तक हमें उपलब्ध नहीं थीं। अस्पताल में 12 रीनल डायलिसिस मशीनें थीं, जिनमें से दस खराब हो गई थीं। छाती में संक्रमण या अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बीमारियों के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं थीं।

अराजकता के इस माहौल में हजारों लोग अपने भाग्य के भरोसे थे। संक्रामक रोगों का कहर साफ देखा जा सकता था। छोटे बच्चों में संक्रमण इतना बढ़ गया था कि उनके फेफड़े मवाद से भर गए थे और वे सांस नहीं ले पा रहे थे। यह अवस्था एम्पायेमा कहलाती है और अभी तक मैंने इसके बारे में किताबों में ही पढ़ा था। यह व्याधि 19वीं सदी में हुआ करती थी। लैब नहीं होने के कारण मरीजों को पैथोलॉजिकल परामर्श नहीं दिया जा सकता था। इमरजेंसी विभाग खचाखच भरा था और मरीज फर्श पर लेटे थे। जब मैं वहां पर था, तब राफा के उत्तर में मौजूद खान-यूसुफ शहर पर बमबारी हो रही थी और उसमें जख्मी होने वाले लोग 12 घंटे तक कोई उपचार नहीं पा सके थे। उनमें से अधिकतर अगले दिन का सूरज नहीं देख पाए।

(द इकोनॉमिस्ट से)

https://t.me/AllNewsPaperPdf

हेल्थ & वेलनेस

वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को • 38% भारतीयों को फैटी लिवर की समस्या, 35% बच्चे भी शिकार

माता-पिता, भाई-बहन के खर्राटे और आपका कॉलर साइज भी बताता है कि लिवर में फैट हो सकता है

डॉ. एस.के. सरीन
डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलिरी साइंस, दिल्ली

शरीर को डिटॉक्स करने, फैट घटाने और इम्युनिटी को मजबूत करने जैसे 500 से भी ज्यादा काम करने वाले लिवर पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स) दिल्ली ने पिछले साल एक अध्ययन में पाया कि लगभग 38% भारतीयों को फैटी लिवर से जुड़ी समस्या है। चिंताजनक यह है कि लगभग 35% बच्चे भी इसके शिकार हैं। फैटी लिवर वह स्थिति है जिसमें लिवर के ऊपर अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता घटने लगती है। वैसे तो यह समस्या मुख्य रूप से शराब पीने के कारण होती है, लेकिन बिगड़ी जीवनशैली और खराब खानपान की वजह से भी फैटी लिवर हो रहा है। इसे मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज (एमएएफएलडी) नाम दिया गया है। लिवर की सेहत के प्रति जागरूकता के लिए 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। **आज जानिए लिवर की सेहत से जुड़े कुछ संकेतों और उपायों के बारे में।**

चार संकेत जो बताते हैं कि आपका लिवर फैटी हो सकता है

1. कमर का साइज ज्यादा हो

महिला की कमर 32 सेमी और पुरुष की 36 सेमी से ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि लिवर में फैट है। दरअसल कमर का अधिक होना यह बताता है कि कमर में विसरल फैट यानी एक्स्ट्रा चर्बी जमा है। कमर की चर्बी सीधे लिवर पर एकत्रित होती है।

2. पुरुष का कॉलर साइज 37 और महिला का 33 सेंटीमीटर से ज्यादा हो

पुरुषों का कॉलर साइज 37 सेमी और महिलाओं का 33 सेमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल गले के पास कुछ मांसपेशियां होती हैं जब लिवर में फैट अधिक होता है तो यह इन मांसपेशियों में भी जमा होता है, जिससे गर्दन मोटी होने लगती है।

3. माता-पिता, भाई-बहन को शुगर, हार्ट की बीमारी

यदि दादा-दादी, माता-पिता या भाई-बहन खर्राटे लेते हैं तो उन्हें फैटी लिवर हो सकता है। चूंकि इसके जेनेटिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी में आने की आशंका होती है, इसलिए आपको भी खतरा हो सकता है। उन्हें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, हार्ट या किडनी की बीमारी होने पर भी आपमें लिवर की समस्या हो सकती है।

4. अगर वेस्ट-हिप रेशो मानक से अधिक हो

महिलाओं और पुरुषों में वेस्ट और हिप का अनुपात भी लिवर की सेहत बताता है। महिला का वेस्ट-हिप का अनुपात 0.7 और पुरुष का 0.9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह लिवर में फैट का संकेत हो सकता है। इसे जानने के लिए कमर की चौड़ाई में कूल्हे की चौड़ाई से भाग दे दें। जैसे यदि महिला की कमर 32 इंच है तो कूल्हे का साइज लगभग 45 हो।

ये तीन फॉर्मूले कारगर हैं

वजन : आदर्श स्थिति से थोड़ा कम

अक्सर आदर्श वजन ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका थोड़ा कम होना बेहतर है। सही वजन के लिए पुरुष अपनी लंबाई (सेमी में) में 100 और महिलाएं 105 घटाएं। यदि माता-पिता को या आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो 5 और घटा लें।

डाइट : 50% भोजन बिना पका हो

सही डाइट का फॉर्मूला यह है कि थाली में भोजन का 50 प्रतिशत हिस्सा बिना पका हुआ होना चाहिए। जैसे कि सलाद, फल, स्प्राउट्स आदि। यह न केवल पाचन बेहतर करता है बल्कि लिवर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है। याद रखें मीठे फलों में भी शुगर काफी होती है। उसकी मात्रा को भी रोजाना की शुगर में शामिल करें।

व्यायाम : पसीना आने के बाद 30 मिनट

एक्सरसाइज का फायदा शरीर को तब मिलता है जब शरीर से पसीना निकलने के बाद 30 से 45 मिनट तक की जाए। दरअसल पसीना निकलने के पहले तक किए गए प्रयास वार्मअप होते हैं। इसके बाद की एक्सरसाइज से ही शरीर के ऑर्गन पूरी क्षमता के साथ एक्टिव होकर लाभ ले पाते हैं।

स्ट्रेस • शरीर की खुश रहने की प्रवृत्ति घटाता है

सिरदर्द के अलावा पेट दर्द व सर्दी भी तनाव के लक्षण हो सकते हैं

डॉ. पंकज सिंघई,
मणिपाल हॉस्पिटल, बेंगलुरु

सामान्य तनाव हमें बदलाव करने और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अधिक तनाव शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। नशा करने वालों में लत का खतरा बढ़ जाता है।

नशे की लत को यूं बढ़ाता है तनाव

तनाव शरीर की अच्छा महसूस करने और संतुलित रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। आप दुखी महसूस करने लगते हैं। स्मोकिंग या शराब कुछ समय के लिए फीलगुड अहसास कराते हैं, लेकिन तनाव फिर वापस आ जाता है। लगातार नशे से शरीर की तनाव मैनेज करने की क्षमता घट जाती है। फिर नशा लत बन जाता है।

इसे डीप ब्रीदिंग से मैनेज करें

लगातार बना रहने वाला तनाव कई संकेत देता है। जैसे- हृदय गति तेज होना, पेट दर्द, सिरदर्द, सर्दी, गर्दन और कंधों में अकड़न आदि। तनाव के कारण जब इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगें तो उन्हें दूर करने के लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। डाइट में न्यूट्रिशन बढ़ाएं।

रिसर्च • मेकअप से व्यायाम के दौरान त्वचा को नुकसान

मेकअप करके एक्सरसाइज करना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अमेरिका की टेक्सास एएंडएम यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता 'सुको ली' ने शोध में पाया कि यदि चेहरे पर फाउंडेशन लगाकर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यह त्वचा के छिद्रों के आकार में बदलाव कर सकता है, जिससे उनके निकलने वाले तैलीय पदार्थ की मात्रा प्रभावित हो सकती है। यह पदार्थ त्वचा को न केवल हाइड्रेड रखता है बल्कि उसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसे सीबम कहते हैं। हालांकि सीबम की मात्रा व्यक्ति की त्वचा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। क्योंकि इसकी अधिक मात्रा से मुंहासे हो सकते हैं जबकि कम मात्रा से त्वचा में जलन होती है।

सेहत का विज्ञान • भोजन में फाइबर की पर्याप्त मात्रा लंबे समय तक भूख को रोके रखती है, अधिक पानी वाले फल तरबूज, खरबूजे गर्मियों में बेहद फायदेमंद

दिनभर का भोजन 10 घंटे में और रोज 3 लीटर लिक्विड, ऐसे 5 उपायों से घटेगा 5 किलो तक वजन

रेणु खत्रेजा
न्यूट्रिशनिस्ट एवं हेल्थ कोच
@consciouslivingtips

गर्मियों का मौसम वजन घटाने के लिए बेहद अनुकूल है। लंबे दिन होने की वजह से बाहरी एक्टिविटी आसान हो जाती है। हालांकि कैलोरी बर्न करने के साथ ही वजन घटने के विज्ञान को समझ लें तो बदलाव ज्यादा कारगर होते हैं। जब बर्न की जाने वाली कैलोरी की तुलना में कम कैलोरी ग्रहण करते हैं तब वजन घटना शुरू होता है। इसे कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। खानपान में बदलाव और एक्टिविटी बढ़ाकर इसे कर सकते हैं। गर्मियों में इन 5 तरीकों से आप भी वजन घटा सकते हैं।

1. दिन में लिक्विड अधिक लें

रोजाना की डाइट में आसान बदलाव लाएं

गर्मियों में कम से कम 3 लीटर तरल पदार्थ जरूर लें। इसमें पतला सत्तू, नमकीन नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी को भी शामिल कर सकते हैं। ये न केवल पानी की कमी पूरा करते हैं बल्कि टॉक्सिन को भी बाहर निकालते हैं। साथ ही शुगरी फूड घटाएं। बार-बार खाने की आदत को सीमित करें। भोजन में प्रोटीन बढ़ाएं। इससे लंबे समय तक तृप्ति का अहसास रहता है।

मास्टर टिप : सत्तू या छाछ नाश्ते और लंच के बीच जबकि नमकीन नींबू पानी अथवा नारियल पानी लंच और डिनर के बीच लें।

2. अधिक पानी वाले फल-सब्जी खाएं

इनमें कैलोरी कम होती है पोषण अधिक मिलता है

खीरा (96% पानी), टमाटर (95%), तरबूज (92%), खरबूजे (91%) और संतरा (86%) ये कुछ ऐसे फल हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ये न केवल ताजगी प्रदान करते हैं बल्कि पोषण भी अधिक देते हैं जबकि इनमें कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है। ये हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं। जूस की जगह साबुत फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है।

मास्टर टिप : दोपहर के भोजन की शुरुआत एक मध्यम आकार के खीरे के सेवन से करें।

3. 10 घंटे की समय सीमा में ही करें दिनभर का भोजन

इससे शरीर में जमा फैट तेजी से कम होने लगता है

मुख्य भोजन को 10 घंटे की समय सीमा में बांट लें। यानी नाश्ता यदि सुबह 10 बजे कर रहे हैं तो दिन का बाकी भोजन रात 8 बजे तक कर लें। हालांकि मेडिकल कंडीशन होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

मास्टर टिप: बाकी समय ब्लैक टी, ग्रीन टी, नमकीन नींबू पानी व ब्लैक कॉफी पीएं।

4. अलसी, लोबिया, पत्ता गोभी खाएं

इनसे भोजन में घुलनशील फाइबर की मात्रा बढ़ती है

भोजन में फाइबर की पर्याप्त मात्रा न केवल लंबे समय तक तृप्ति का अहसास देती है बल्कि कमर के आसपास बढ़ने वाली चर्बी को भी घटाती है। खासकर घुलनशील फाइबर। इसके लिए अलसी, चिया सीड्स, बीन्स, लोबिया, चना, शकरकंद और गोभी आदि को डाइट में शामिल करें।

मास्टर टिप : अलसी को पीसकर डाइट में शामिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे आटे में मिला सकते हैं। इसके लिए आटे को गर्म पानी से गूंधें।

5. रोज 8000 कदम चलें

इससे आपकी ओवरऑल सेहत में सुधार होता है

नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल कैलोरी बर्न करने के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ऐसे में रोज 7 से 8 हजार कदम चलने का लक्ष्य बनाएं। सुबह या फिर शाम ढलने के बाद वॉक करना ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि इस दौरान तापमान कम होता है, जिससे शरीर को फायदा ज्यादा मिलता है।

मास्टर टिप : फोन पर बात करते समय टहलने, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने जैसे तरीके अपनाकर कदमों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 18 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

हथियार छोड़ने का समय

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलवादियों को मौत की नींद सुला दिया। सरकार की दृष्टि से सुरक्षा बलों का यह कारनामा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि एक तो इसमें बड़ी संख्या में नक्सलवादियों को मारा गया है, और दूसरे, मारे गए नक्सलियों में उनके नामी गिरामी ईनामी कमांडर भी शामिल हैं। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान से पूर्व सुरक्षा बलों की इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में नक्सलियों का सफाया करने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार देश को नक्सलवाद की बुराई से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे विचारधारात्मक धरातल पर एक बड़ी त्रासदी ही कहा जाएगा कि जो आंदोलन भारत के दबे-कुचले मानवीय समूहों को उनका हक तथा

गरिमापूर्ण जीवन दिलाने के लिए पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद को सशस्त्र संघर्ष के बल पर उखाड़ फेंक देना चाहता था और शोषित-वंचित तबकों को जल, जंगल और जमीन और खनिज संपदा का आधिपत्य दिलाना चाहता था, अब वह अपनी समाप्ति की घड़ियां गिन रहा है। नक्सलवाद की आरंभिक सोच यही थी कि जिस तरह से सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और उसके बाद जिस तरह से माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष के बल पर चीन में साम्यवादी सत्ता स्थापित हुई, उसी तरह भारत में भी की जा सकती है। इसी विचार को आधार बिंदु मानकर उन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट समूहों में उग्र मतभेदों, टूट-फूट और विभाजनों के बावजूद देश के उन हिस्सों में जहां राज्य की भुजा आसानी से पहुंचने में सक्षम नहीं थी, वहां अपना प्रभाव भी बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब देश के दस राज्यों के 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित घोषित किए गए लेकिन नक्सलवादी नेतृत्व कभी भी ठीक प्रकार से यह नहीं समझ सका कि सोवियत संघ और चीन में जैसी आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों के बीच कम्युनिस्ट संघर्ष को सफलता मिली थी, भारत में वैसी परिस्थितियां नहीं थीं। भारत का समाज जाति, धर्म, क्षेत्र आदि जैसे विभाजनों से ग्रस्त था, उसमें इस विचारधारा के आगे पनपने की कोई गुंजाइश नहीं थी और परिणाम सामने है। बेहतर होगा कि नक्सलवादी अपने संघर्ष सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर करें ताकि जनता जागरूक हो सके और लोकतंत्र के भीतर ही जनता सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर पाए।

चुनौतीपूर्ण है आर्थिक संकट

कार्यस्थल पर कोई भी निर्णय लेते समय देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों के समूह से मुलाकात के दौरान कहा। आर्थिक संकेतक प्रगति के उपयोगी मापदंड माने जाते हैं, इसलिए सरकारी नीतियों को प्रभावी और उपयोगी बनाने में अर्थशास्त्रियों की भूमिका को उन्होंने बहुत उपयोगी बताया। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उन्हें आने वाले समय में अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित कर उनका उपयोग करने के असंख्य अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर नीतिगत सुझाव देते समय या निर्णय लेते हुए देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान रखें। आर्थिक विश्लेषण और विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही संसाधन वितरण प्रणाली और योजनाओं के मूल्यांकन के लिए उचित सलाह प्रदान करने की बात

भी उन्होंने की। 2022-2023 के बैच के आईईएस अधिकारियों में 60% महिलाओं के होने की बात की और इससे महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का आग्रह भी किया। ऐसे दौर में जब आर्थिक विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, राष्ट्रपति द्वारा अधिकारियों को यह सलाह देना देशवासियों के प्रति उनके मानवतावादी रवैये का द्योतक है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गईं सरकारी नीतियां जब तक प्रभावी नहीं होंगी, तब तक उनइनका लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचना मुश्किल है। देखने में आता है कि सरकारें योजनाएं बना कर उन्हें बिसरा देती हैं। उच्चाधिकारियों के हाथ में है कि वे इनका क्रियान्वयन सुबीते से करें। निःसंदेह इस तरह की नौकरियों में देश के हर वर्ग और हर प्रांत के अधिकारियों का चयन होता है, इसलिए उन्हें बुनियादी समस्याओं और संकटों का भान होता है। स्वयं राष्ट्रपति ऐसे समुदाय और वर्ग से निकल कर सबसे बड़े पद तक पहुंची हैं कि उन्हें देशवासियों की समस्याओं का न केवल अहसास है, बल्कि गरीबों और महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों को भी उन्होंने करीब से देखा है। किसी भी समाज की प्रगति तभी नजर आती है, जब उसका सर्वांगीण विकास हो रहा हो। कहना न होगा कि आर्थिक असंतुलन ने हमारे संकटों को बढ़ाया है। यह चुनौती है, जिससे निपटना बेहद जरूरी है।

कटाक्ष/ सहीराम

अपने-अपने पत्र

एक जमाना था जी, जब सभी पार्टियों के चुनाव घोषणापत्रों का घोषणापत्र ही नाम होता था। लेकिन अब अच्छी बात यह हुई है कि सब पार्टियों के चुनाव घोषणापत्रों का नाम अलग-अलग होने लगा है। यह बिल्कुल वैसे ही होने लगा है जैसे पहले हर नेता सफेद कुर्ते-पाजामे या कुर्ता-धोती में ही होता था, लेकिन अब सब अलग-अलग डिजाइनर कपड़ों में होते हैं। अब घोषणापत्रों के नाम ही अलग-अलग नहीं होने लगे हैं, बल्कि खूब कैची भी होने लगे हैं। बेशक, अंदर से तो हर घोषणापत्र एक जैसा होता है, वैसे ही जैसे अंदर से हर नेता काइयां ही होता है। पहले कोई पहचान ही नहीं होती थी कि घोषणापत्र डल सा मामला होता था। एक बार प्रेस के समक्ष रीलीज करने के बाद गोदाम में रख दो भैया। कबाड़ी के यहां तो सबको एक ही भाव जाना है। लेकिन अब तो इन अलग-अलग नामों से आ रहे घोषणापत्रों को प्रेस वालों को भी भाव देना पड़ रहा है। नाम बदलने का सिलसिला अब शहरों और जिलों तक ही महदूद नहीं रह गया है। वैसे तो जब से चीन ने हमारे अरुणाचल के स्थानों के नाम बदले हैं, तब से इस फिमोमिना को अंतरराष्ट्रीय भी कहा जा सकता है। लेकिन घोषणापत्रों तक तो यह सिलसिला जरूर ही आ लिया है।

खैर, अगर कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र, न्याय पत्र के नाम से आया है, तो भाजपा का चुनाव घोषणापत्र, संकल्प पत्र के नाम से आया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा का चुनाव घोषणापत्र, मोदी की गारंटी के नाम से आया है। वैसे तो जब पार्टी का नाम ही मोदी की पार्टी हो गया है, और सरकार का नाम ही मोदी सरकार हो गया है तो घोषणापत्र का नाम भी अगर मोदी की गारंटी है, तो क्या गलत है। जब भाजपा को वोट ही मोदी के नाम पर पड़ना है, तो घोषणापत्र भी तो उन्हीं के नाम का चलेगा न। उसके लिए तो मोदी का चित्र ही अपने आप में घोषणापत्र होता। ज्यादा से ज्यादा एक दो नारों से काम चल जाता। जैसे पिछले दो चुनावों में चला। किसने घोषणापत्र पढ़ा, सबने नारे ही तो सुने और फिदा हो गए। बस एक थोड़ा सा पंगा अमित शाह ने यह कहकर जरूर कर दिया कि काले धन के पंद्रह लाख हर खाते में आने की बात तो चुनावी जुमला था। लगता है उसके बाद से संकल्प पत्र जरूरी हो गया ताकि अब कोई जुमला जुमला न लगे।

अनमोल वचन

कोई भी गुस्सा हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है, और यह आसान नहीं है -सुकरात

सावधानी ही बचाव है

साइबर अपराध

सतीश सिंह

अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल में 'विश्व साइबर अपराध सूचकांक' तैयार किया है। इसके अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया है। साइबर अपराध के मामले में रूस शीर्ष पर है, जबकि यूक्रेन दूसरे, चीन तीसरे, अमेरिका चौथे, नाइजीरिया पांचवे, रोमानिया छठे और उत्तर कोरिया सातवे स्थान पर है।

भारत में कई तरह के साइबर अपराध होते हैं। हाल के वर्षों में कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए साइबर अपराध करने की घटनाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा देती हैं, जिसके तहत कॉल एवं एसएमएस को फॉरवर्ड किया जाता है। उपभोक्ताओं को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा नंबर पर यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा को एक्टिवेट करने पर मिलती है। यूएसएसडी कोड का इस्तेमाल आम तौर पर बैलेंस या फोन का आईएमईआई नंबर जानने के लिए किया जाता है। यह ऐसा फीचर है, जिसकी मदद से एक कोड डायल करके सेवाओं को शुरू या बंद करवाया जा सकता है। कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए स्कैमर कॉल करके उपभोक्ताओं को कहता है, 'हम आपकी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी से बोल रहे हैं। हमने नोटिस किया है कि आपके नंबर पर नेटवर्क की समस्या है। समस्या को दूर करने के लिए आपको 'स्टार 401 हैशटैग' नंबर डायल करना होगा।' यह नंबर डायल करने के बाद उपभोक्ता को अंजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही, उपभोक्ता कॉल करता है, उसके सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं, जिनमें बैंक और क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले लेन-देन के ओटीपी भी शामिल होते हैं। कॉल और ओटीपी का इस्तेमाल स्कैमर उपभोक्ता के बैंक खाते से पैसे निकालने, सोशल मीडिया में एक्सेस करने और नया सिम जारी करवाने में करते हैं।

कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए किए जा रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार ने 15 अप्रैल, 2024 से यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा बंद कर दी है। इसलिए स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को कहा गया है कि अपने मोबाइल फोन की सेटिंग की जांच करें और 'स्टार 401 हैशटैग' नंबर डायल करने पर कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा चालू दिखती है, तो उसे तुरंत बंद कर दें।

विगत वर्षों में डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ साइबर अपराध में तेज वृद्धि हुई है। अब तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ठगी के साधन बन गए हैं। गूगल सर्च इंजन पर लोग अपने हर प्रश्न का जबाव ढूंढ रहे हैं। ऐसे मनोविज्ञान को दृष्टिगत कर ठग नामचीन भुगतान एप्स जैसे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर

सहेज रहे हैं, जिसके कारण खुद से लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं। अब तो ब्राउजर एक्सटेंशन की डाउनलोडिंग के जरिए भी साइबर अपराध किए जा रहे हैं। यह काम वायरस के जरिए किया जाता है। सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल एवं लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं। क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिए किए गए ऑनलाइन लेन-देन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अज्ञानतावश लोग ऐसा नहीं करते और इसका फायदा साइबर ठगों को मिल जाता है। इसलिए जरूरी है कि बैंकिंग डिजिटल उत्पादों जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड आदि के उपयोग में विशेष सावधानी बरती जाए क्योंकि इनके उपयोग में बरती गई असावधानी आपकी जेब को खाली कर सकती है।

फिशिंग के तहत किसी बड़ी या नामचीन कंपनी या यूजर की कंपनी की फर्जी बेवसाइट, जिसका स्वरूप असली बेवसाइट जैसा होता है, बना कर लुभावने मेल किए जाते हैं, जिनमें मुफ्त में महंगी चीजें देने की बात कही गई होती है। मोबाइल का चलन बढ़ने के बाद हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं, जिनमें मैलवेयरयुक्त हाइपर लिंक दिया हुआ होता है। मैलवेयर, कंप्यूटर या मोबाइल या टैब में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ यूजर की वित्तीय जानकारी जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण, उनके पासवर्ड, ओटीपी, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता नंबर, जन्मतिथि आदि चुरा लेता है। यह यूजर की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से दूसरे को फर्जी ईमेल भी भेज सकता है, और इसके जरिए ठगी करने के साथ-साथ संवेदनशील जानकारी अवांछित लोगों को बेची भी जा सकती है। इसकी मदद से किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा सकता है। आजकल साइबर अपराधी फोन कॉल्स या एसएमएस द्वारा लोगों को बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बता कर उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं। लोन रिकवरी एजेंट धमकी देते हैं, आपने हमसे कर्ज लिया है और अगर दो-तीन दिनों में पैसे वापस नहीं करेंगे तो आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी।

यूजर पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़; आज सभी साइबर अपराध के शिकार बन रहे हैं। ऑनलाइन ठगी से न तो शहरी क्षेत्र के लोग बच पा रहे हैं, और न ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग। बड़े अधिकारी, बैंक अधिकारी, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस सभी इसके शिकार हो रहे हैं। बैंक के डिजिटल उत्पाद साइबर अपराध का जरिया बन गए हैं। फिर भी, सजग और जागरूक रह कर डिजिटल उत्पादों से किए जा रहे साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। लोग ब्राउजिंग सेशन के दौरान संदेहास्पद पॉप अप से सतर्क रहें, https://पैड लॉक सिंबल वाला URL है या नहीं को सुनिश्चित करें, वेबसाइट्स या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करें, अनजान नंबर या ईमेल आईडी से आए अटैचमेंट को तुरंत डिलीट कर दें और ऑनलाइन लॉटरी, कैसिनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की उपेक्षा करें तो फिशिंग मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड होने वाले संदेहास्पद हाइपर लिंक के जाल से बचा जा सकता है। मामले में सावधानी ही बचाव है। लालच नहीं करें। यह सभी समस्याओं की जड़ है। मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आएं। धमकी मिलने पर पुलिस की मदद लेने से नहीं हिचकें। निडर बनें। तभी साइबर अपराध का शिकार बनने से बचा जा सकता है।

> यूजर पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़; आज सभी साइबर अपराध के शिकार बन रहे हैं। ऑनलाइन ठगी से न तो शहरी क्षेत्र के लोग बच पा रहे हैं, और न ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग। बड़े अधिकारी, बैंक अधिकारी, जज, विधायक, सांसद, मंत्री, पुलिस सभी इसके शिकार हो रहे हैं। बैंक के डिजिटल उत्पाद साइबर अपराध का जरिया बन गए हैं। फिर भी, सजग और जागरूक रह कर डिजिटल उत्पादों से किए जा रहे साइबर अपराधों से बचा जा सकता है

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में इजाफा

- भारतीय निर्यातकों ने 2023 में यूरोपीय और लातिन अमेरिकी देशों को निर्यात में 2.1 फीसद की अच्छी वृद्धि दर्ज की
- रोमानिया, चेक गणराज्य, फिनलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया. क्यूबा, उरुग्वे, पैराग्वे, गुयाना, पेरू, मेक्सिको और ग्वाटेमाला में खास तौर पर भारतीय उत्पादों की मांग में स्वस्थ वृद्धि हुई
- यूरोप में मौजूदा अनिश्चितताओं और मंदी के बावजूद भारत के निर्यात में वृद्धि भारत का व्यापारिक जुझारूपन दर्शाती है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

सदमे से कम नहीं है कि प्रधानमंत्री अभी भी सार्वजनिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड (ईबी) की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इन्हें अवैध और असंवैधानिक करार दे चुका है। पीएम को ईबी इतने अच्छे लगते हैं तो उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो इन्हें बनाए रखने के लिए नया कानून लाएगी।

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

किताबों में बदलने लगा इतिहास

एनसीईआरटी

प्रमोद भार्गव

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों में पढ़ाए जाने वाले भारत के इतिहास में आर्य अब आक्रामणकारी नहीं, बल्कि भारतीय मूल के रूप में दर्शाए गए हैं। 21 वर्ष की खींचतान और दुनिया भर में हुए अध्ययनों के बाद तय हो गया कि 'आर्य सभ्यता' भारतीय ही थी। राखीगढ़ी के उत्खनन से निकले इस सच को देश के पाठ्यक्रमों में शामिल करने का श्रेय 'राखीगढ़ीमैन' के नाम से प्रसिद्ध प्राध्यापक वसंत शिंदे को जाता है। एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब में बदलाव किया गया है। इतिहास की पुस्तक में 'ईंट, मोती और हड्डियां : हड़प्पा सभ्यता' पाठ में आर्यों को मूल भारतीय बताया गया है। कक्षा 7, 8, 10 व 11 की इतिहास व समाजशास्त्र की पुस्तकों में भी बदलाव किया गया है।

इतिहास तथ्य और घटना के सत्य पर आधारित होता है। इसलिए इसकी साहित्य की तरह व्याख्या संभव नहीं है। विचारधारा के चश्मे से इतिहास को देखना उसके मूल से खिलवाड़ है परंतु अब आर्यों के भारतीय होने संबंधी एक के बाद एक शोध आने के बाद इतिहास बदला जाने लगा है। इस सिलसिले में पहला शोध स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के टॉमस कीवी शील्ड ने किया था। 2003 में 'अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स' में प्रकाशित इस शोध-पत्र में सबसे पुरानी जाति और जनजाति के वंशाणु (जीन) के आधार पर आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया गया था। हालांकि 2009 में वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. लालजी सिंह और प्रो. थंगराज ने भी आनुवांशिक परीक्षण के बाद आर्यों को मूल भारतीय बताया था। 2019 में प्रो. वसंत शिंदे द्वारा राखीगढ़ी उत्खनन से मिले 4000 साल पुराने वंशाणु की जांच में सबसे बड़ा सच सामने आया। शोध में पाया गया कि राखीगढ़ी से मिला जीन वर्तमान के प्रत्येक भारतीय व्यक्ति में उपलब्ध है। एनसीआरईटी की इतिहास पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के अध्यक्ष बनने पर प्रो. शिंदे ने इस तथ्य के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन कराए हैं।

इसी पुस्तक में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ छत्रपति और महाराज जोड़ा गया है। कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम से सांप्रदायिक

दंगों के चित्र हटाए गए हैं। इतिहास की पुस्तकों में यह बदलाव सिनौली-राखीगढ़ी में हुए उत्खननों में मिले साक्ष्यों के आधार पर संभव हुआ है। गोया, अब यह अवधारणा पलट गई है कि आर्य न तो विदेशी थे और न ही उन्होंने भारत पर आक्रमण किया।

हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में पुरातत्वीय खुदाई में 5000 साल पुराने मिले दो मानव कंकालों के डीएनए अध्ययन के निष्कर्ष से यह धारणा सामने आई है। इन कंकालों में एक पुरुष और एक स्त्री का था। इनके कई नमूने लेकर उनका आनुवांशिक अध्ययन पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, भारत सरकार, डेक्कन विश्वविद्यालय पुणे, सीसीएमबी, हैदराबाद और हार्वड स्कूल ऑफ मेडिसन बोस्टन, यूएसए ने किया है। डीएनए विश्लेषण में यह भी स्पष्ट हो गया है कि आर्य और द्रविड़ मूल भारतीय हैं। आर्य हमलावर के रूप में विदेश से आए होते और नरसंहार किया होता तो मानव कंकालों के शरीर पर घावों के निशान होते। भारतीय संस्कृति और भाषाएं नष्ट हो गई होतीं। ऐसा होता तो आक्रमण की बात सिद्ध होती। व्यापार, पर्यटन आदि के लिए भारत में विदेशी आते रहे और भारतीय भी विदेश जाते रहे, इन कारणों से जीन में मिलावट होती रही हैं।

प्रो. शिंदे ने राखीगढ़ी के उत्खनन के समय बताया था कि अलग-अलग खुदाई में 106 से भी ज्यादा नर-कंकाल मिले। भिन्न आकार-आकृति के हवन-कुंड और कोयले के अवशेष भी मिले हैं। तय है कि भारत में 5000 साल पहले हवन होते थे। यहीं सरस्वती और इसकी सहायक दृश्यवंती नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के निशान मिले हैं। ये लोग सरस्वती की पूजा करते थे। आनुवांशिक अनुसंधान ऐतिहासिक-अवधारणाओं को बदलने के ये आधार बने हैं। 'आर्यों' के ऊपर 'आनुवांशिकी' के आधार पर पहले भी एक शोध सामने आया है। उससे तय हुआ है कि भारतीयों की कोशिकाओं का जो आनुवांशिकी ढांचा है, वह बहुत पुराना है। डीएनए के आधार पर एक महत्त्वपूर्ण खोज से साबित हुआ है कि भारत के बहुसंख्यक लोगों के दक्षिण भारतीय दो आदिवासी समुदाय पूर्वज हैं। गंगा घाटी से आयरलैंड तक की भाषाएं आर्य परिवार की आर्य भाषाएं हैं। इसी कारण इन भाषाओं में लिपि एवं उच्चारण की भिन्नता होने के बावजूद अपभ्रंशी समरूपता है, और इन भाषाओं का उद्गम स्रोत संस्कृत है। बंगाली इतिहासकार एसी दास इस स्थान अथवा मूल भारतीयों का निवास स्थल 'सप्त सिंधु' मानते हैं, जो पंजाब में था। अब आर्यों के मूल भारतीय होने की अवधारणा को मान्यता मिल रही है। तब इतिहास के इस तथ्य के बदलाव को केवल शालेय पुस्तकों में परिवर्तन तक सीमित न रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बदलाव जरूरी हैं।

दृष्ट-अदृष्ट **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, 'हे आचार्य, इस सेना में बड़े-बड़े धनुर्धर शूरवीर योद्धा अर्जुन, भीम, सात्यकि, विराट्, महारथी राजा द्रुपद हैं। इसके अतिरिक्त, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, पुरुषश्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु एवं बलवान उत्तममौजा, शुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और उसी प्रकार द्रोपदी के पांच पुत्र! ये सभी महारथी ही हैं।' इस प्रकार दुर्योधन 18 पांडव सेना के महारथियों की गणना द्रोणाचार्य के समक्ष करता है। एक तरफ भीम और अर्जुन जैसे शूरवीर महायोद्धाओं के नाम सर्वप्रथम लेकर द्रोणाचार्य को संदेश देता है कि 'अब ढील नहीं चलेगी !' दूसरी तरफ वह अभिमन्यु और द्रोपदी के पांचों पुत्रों का समावेश कर कहना चाहता है 'पांडवों की नई पीढ़ी में भी कई शूरवीर योद्धा हैं।' दुर्योधन की नजर में छोटे-बड़े सभी नाम हैं। युद्ध की दिशा बदल दे ऐसे अभिमन्यु जैसे युवा शूरवीर योद्धा की भी गणना उसने कर ली है। परंतु उसकी नजर में रणवीर एवं युद्ध-निर्णायक श्रीकृष्ण भगवान ही नहीं हैं! न ही उस सूची में युधिष्ठिर का नाम है! यही उसकी मायिक और लौकिक दृष्टि है! उसने बाह्य दृष्टि से श्रीकृष्ण भगवान को देखा तो था ही, परंतु मात्र एक सारथि की तरह! उसने सोचा होगा कि जिसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की हो उस सारथि की भला युद्ध में क्या भूमिका? उसी प्रकार युधिष्ठिर को भी सीधे, सरल और भोले जानकार उन्हें नगण्य समझ लिया। प्रायः हम सभी इसी लौकिक दृष्टि से ग्रस्त हैं। लौकिक तर्क, लौकिक मापदंड और केवल 'मैं जो देखता हूं, मैं जो मानता हूं, वही सत्य है' के लौकिक गणित में जीने वाले हम भूल जाते हैं कि इस दृष्ट से परे भी एक अदृष्ट है जो अधिक शक्तिशाली है। जी हां, लौकिक बाह्य दृष्टि से तो यहां श्रीकृष्ण केवल सारथि थे। किन्तु अंतर्दृष्टि वाले जानते थे कि श्रीकृष्ण तो साक्षात हरि का अवतार हैं। उसी प्रकार युधिष्ठिर सत्य, धर्म, और नियम का प्रतीक है, जिसकी अवगणना से न तो धर्मयुद्ध जीत सकते हैं, और न ही जीवनयुद्ध! महंत स्वामी महाराज कहते हैं, 'जहां भगवान और भक्त हैं, वहीं विजय है। वहीं शाश्वत यश एवं कीर्ति हैं। भगवान शस्त्र उठाएं या न उठाएं, सारथि के रूप में हों या सेवक के रूप में हों, उपस्थित हों या अनुपस्थित हों, कर्ता-हर्ता वे ही हैं।'

रीडर्स मेल

अच्छा कार्य सबकी जिम्मेदारी

अभी एक तरफ देश भर में चुनावी वातावरण बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति की आराधना का पर्व मनाया जा रहा है। कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहा है तो कोई इस बात के लिए आश्वस्त दिख रहा है कि भगवान की शक्ति के सहारे इस बार भी सत्ता उन्हें ही मिलेगी। वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल सामुदायिक या जातीय गणित लगा कर समाज की सामूहिक शक्ति को छिन्न-भिन्न करने का उपक्रम कर रहे हैं। खैर, जो भी हो देश की राजनीति उच्च विचारों वाली होनी चाहिए। सभी दलों को प्रयास करना चाहिए लेकिन हम प्रायः एक गलती कर देते हैं कि अच्छा काम करने के लिए केवल सरकार से अपेक्षा करते हैं, जबकि अच्छा कार्य करने की जिम्मेदारी सब की है। जब सभी सामूहिक रूप से शक्ति की प्रतीक भारत माता की आराधना करेंगे तो निश्चित ही भारत देश शक्ति संपन्न होने की दिशा में और आगे बढ़ेगा।

सुरेश हिन्दुस्तानी, ग्वालियर, मप्र

परम सत्ता हैं राम

'राम' ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण मात्र से मन में शांति, सुख, संतुष्टि का बोध होता है। ऐसा किसी अन्य शब्द में नहीं है क्योंकि राम दशरथनंदन श्रीराम ही नहीं हैं अपितु 'राम' उस परमात्मा का नाम भी है, जिनकी साधना स्वयं रामचंद्र जी भी करते हैं यानी राम परम सत्ता हैं तो एक आदर्श का प्रतिरूप भी हैं। तभी तो 'राम' हर किसी के रोम-रोम में बसा है। सबुरी राममय हुई तो 'राम', सबुरी के हो गए और सबुरी के झूठे बेर तक खा लिए। आज सबुरी जैसी आस्था कम ही देखने को मिलती है। 'राम' का मन्दिर बन गया है, यह उत्साह हर उस व्यक्ति में है जिसके घट में 'राम' है। राम मन्दिर मुद्दा कानून की चौखट से होते हुए कानून की ही बदौलत निर्माण के लक्ष्य तक आ गया है। राम मन्दिर जितना बड़ा और भव्य बना है, उतना ही राम के भक्तों में हर्ष की अनुभूति हो रही है बशर्ते इसे राजनीतिक रंग देने से बचाया जा सके। आवश्यक यह है कि हम राम का आदर्श स्थापित करें।

डॉ. श्रीगोपाल नारसन, रुड़की, उत्तराखंड

प्रवक्ता ने 'ज्ञान चक्षु' खोले

'आप' के एक प्रवक्ता ने एक चुनावी चर्चा में बेरोजगारी पर आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में 45 करोड़ लोग रोजगारयुक्त थे किन्तु 2014 में मोदी सरकार आने से लेकर अब तक रोजगार घट कर 41 करोड़ रह गए। उन्होंने आगे कहा कि इस समय देश में 114 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। सच में बलिहारी होने को मन करता है ऐसे प्रवक्ताओं के ज्ञान पर। अब जरा उन प्रवक्ता के आंकड़ों का विश्लेषण कर लें। देश की अनुमानित जनसंख्या है-140 करोड़। यदि नवजात शिशु से लेकर मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए वृद्ध तक को भी रोजगार दिया जाए तो देश में 140 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे और 'आप' के प्रवक्ता के अनुसार 41 करोड़ रोजगार+114 करोड़ बेरोजगारों को मिला दिया जाए तो देश की जनसंख्या होनी चाहिए 155 करोड़। बेरोजगारी की तो कोई समस्या है ही नहीं। विपक्षियों द्वारा ऐसे ही अनेक तथ्यहीन बयान जनता को परोसे जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को अपने उपहास बनने की भी चिंता नहीं होती।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 244
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

कल्पमेधा

उस साहस को जानने का अभ्यास करो, जिसमें सचाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है। समस्त विश्व में उसका कोई हनन नहीं कर सकता।

-विवेकानंद

नक्सली चुनौती

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में उनतीस नक्सलियों को मार गिराया। निस्संदेह यह बड़ी कामयाबी है। इस वर्ष इस घटना सहित अब तक करीब अस्सी नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। जल्दी ही उन पर पूरी तरह नकेल कसी जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे दावे बहुत समय से करती आ रही हैं, मगर हकीकत यह है कि अनेक उपायों, रणनीतियों और प्रयासों के बावजूद वहां माओवादी हिंसा पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। थोड़े-थोड़े समय पर नक्सली सक्रिय हो उठते और घात लगा कर सुरक्षाबलों पर हमला कर देते हैं। अगर सचमुच नक्सलियों को कुछ इलाकों तक समेट दिया गया होता और उनके संगठन कमजोर हो गए होते, तो उनके पास अत्याधुनिक हथियारों की पहुंच संभव न होती, सुरक्षाबलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनके पास कारगर संचार प्रणाली न होती। छत्तीसगढ़ में करीब चालीस वर्ष से माओवादी हिंसा का दौर चल रहा है। इस बीच अनेक रणनीतियां अपनाई गईं, मगर वे कारगर नहीं हो पाईं हैं। चुनाव के माहौल में सुरक्षाबलों की ताजा कामयाबी से नक्सली उपद्रवियों का मनोबल जरूर कमजोर होगा, पर इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यावहारिक कदम की अपेक्षा अब भी बनी हुई है।

दरअसल, आदिवासी इलाकों में माओवादी हिंसा की कई परतें हैं। आदिवासियों को लगता है कि सरकार उनके जंगल और जमीन छीन कर उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है। वे इसका विरोध करते रहे हैं। शुरू में इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई, मगर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। फिर बंदूक के जरिए उन पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। फिर आदिवासियों और समर्पण करने वाले नक्सलियों को ही बंदूक देकर नक्सली संगठनों के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति अपनाई गई। उसमें काफी खून-खराबा हुआ, मगर नक्सली समस्या को समाप्त कर पाना संभव न हो सका। हेलीकाप्टर, ड्रोन और अत्याधुनिक संचार तकनीकी के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी, पर उसमें भी बहुत कामयाबी नहीं मिल सकी। नक्सली कई मौकों पर सुरक्षाबलों को अपने जाल में फंसा कर हमला करते भी देखे जा चुके हैं। दो साल पहले इसी तरह उन्होंने बीजापुर में बाईस सुरक्षाबलों को मार गिराया था।

नक्सली समस्या से पार पाने के लिए दो तरह के विचार काम करते रहे हैं, जिसमें आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके इलाकों में विकास कार्यक्रमों पर बल देने की सिफारिश की जाती रही है। इसके तहत पिछली सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई थी, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। दूसरा विचार बंदूक के बल पर नक्सलियों के सफाए का रहा है। मगर हकीकत यह है कि उनसे निपटने के लिए कोई व्यावहारिक नीति आज तक नहीं बन सकी है। हजारों निरपराध आदिवासी जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। पांच-छह साल पहले एक नीति बनाने पर जरूर जोर दिया गया था, जिसमें उनसे बातचीत का प्रस्ताव भी था, मगर वह नीति बन नहीं सकी। सबसे जरूरी है, स्थानीय आदिवासियों में यह भरोसा पैदा करना कि सरकार उनके जीवन में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। उनके जल, जंगल, जमीन के मसले पर संजीदगी से बात हो, तो शायद वे हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाएं।

बीमारी का विस्तार

बदलती जीवन-शैली, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में विषाक्तता आदि के चलते बीमारियों का विस्तार हो रहा है। नई-नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। कैंसर भी इन्हीं स्थितियों के चलते लगातार अपने पांव पसार रहा है। हालांकि अब इस समस्या से पार पाने के लिए चिकित्सा विज्ञान ने कई आसान और कारगर उपाय तलाश लिए हैं, इसकी दवाओं की उपलब्धता बढ़ी है। मगर यह अब एक आम बीमारी बन गया है। 'लैंसेट' के ताजा अध्ययन में बताया गया है कि अगले पंद्रह-सोलह वर्षों तक हर वर्ष केवल स्तन कैंसर से दस लाख मौतें हो सकती हैं। स्तन कैंसर अब एक आम बीमारी बन चुका है। स्वाभाविक ही इसे लेकर दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। बेशक इस रोग से पार पाना आसान हो गया है, पर असल समस्या हर किसी तक इसके इलाज की पहुंच संभव न हो पाना है। भारत जैसे समाजों में गरीबी, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कम होने तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभावपूर्ण नजरिया व्याप्त होने की वजह से इस समस्या पर काबू पाना और कठिन हो जाता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल में मुश्किलें इसलिए भी आती हैं कि महिलाएं खुद इसे लेकर बहुत सजग नहीं होती हैं। शहरी इलाकों में जरूर महिला स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता देखी जाती है, मगर ग्रामीण और समाज के निचले कहे जाने वाले तबकों में इसका घोर अभाव नजर आता है। फिर, कैंसर को लेकर जैसी जागरूकता होनी चाहिए, वह भी संतोषजनक नहीं है। इसका इलाज अब भी सामान्य आयवर्ग की क्षमता से बाहर है। इसलिए बहुत सारी महिलाओं में स्तन कैंसर की समय पर पहचान नहीं हो पाती और जिनकी हो भी पाती है, उसमें बहुत देर हो चुकी होती है और उनके लिए इलाज कराना कठिन होता है। 'लैंसेट' के अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि इसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को किसी न किसी रूप में संचार कौशल प्रशिक्षण देने की पहल करनी और रोगियों से संपर्क बनाना चाहिए। इस बीमारी को रोकने में सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी हैं, जिनमें परिवार, समुदाय और चिकित्सा पेशेवरों का परस्पर जुड़ाव हो।

ग्रामीण उपभोक्ता मांग और चुनौतियां

ग्रामीण उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के कई कारक हैं, जिनमें ग्रामीण आय में वृद्धि प्रमुख है। विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकारों ने इसके लिए बहुत से प्रयास किए हैं।

अजय जोशी

हाल में हुए 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआइई) के ताजा सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग तेजी से बढ़ी है। यहां टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी आदि की मांग 2019 के कोरोना काल के बाद 25.82 फीसद बढ़ी है। अप्रैल 2020 में सिर्फ 2.03 फीसद ग्रामीण उपभोक्ता मान रहे थे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे, ट्रैक्टर, दुपहिया वाहन आदि खरीदने का उनके लिए यह सबसे अच्छा समय है, लेकिन अब 27.85 फीसद ग्रामीण उपभोक्ता मानते हैं कि वर्तमान समय इसके लिए सबसे बेहतर है। लोकसभा चुनाव के दौर में धन के प्रवाह को भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। इसी वर्ष जनवरी में ग्रामीण उपभोक्ता मांग का सूचकांक कम हो गया था, मगर चुनाव की घोषणा के बाद मार्च में तेजी आने लगी। रपट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण उपभोक्ता मानते हैं कि अगले पांच साल उनकी वित्तीय स्थिति और अच्छी बनी रहेगी।

अप्रैल 2019 में 29.74 फीसद ग्रामीण मानते थे कि आर्थिक हालात बेहतर हैं, लेकिन मई 2021 में ऐसा मानने वाले सिर्फ 2.93 फीसद रह गए थे। चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद मार्च 2024 में बढ़कर यह संख्या 31.60 फीसद हो गई है। वाहन उद्योग में भी ग्रामीण उपभोक्ता मांग में तेजी आई है। कुछ दिनों पहले आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया था कि वित्तवर्ष 2020-23 की दूसरी तिमाही में दुपहिया वाहनों की 30.3 फीसद और ट्रैक्टर की बिक्री 16.1 फीसद बढ़ी है। ग्रामीण वित्त विशेषज्ञों का मानना है अगले पांच वर्षों में ग्रामीण उपभोक्ता मांग में और तेजी आने की संभावना है।

ग्रामीण उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के कई कारक हैं, जिनमें ग्रामीण आय में वृद्धि प्रमुख है। विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकारों ने इसके लिए बहुत से प्रयास किए हैं। इनमें गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इसके लिए कई लक्षित कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अंब्रेला कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम-किसान के तहत फंड ट्रांसफर, पीएम फसल बीमा योजना का दावा भुगतान, उर्वरक सब्सिडी, डेयरी सहकारी समितियों और कृषि-बुनियादी ढांचे के लिए ब्याज छूट, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड उपलब्ध कराना आदि प्रमुख हैं।

ग्रामीण उपभोक्ता आय में वृद्धि की दृष्टि से डीबीटी योजना सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें जिन योजनाओं के अंतर्गत नकद भुगतान की व्यवस्था है, उनमें धन को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। फिलहाल इस व्यवस्था में सरकार के 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएं

शामिल हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन आदि के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ शामिल हैं।

> भारत दुनिया की सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। इसमें 87.8 करोड़ ग्रामीण निवासी हैं, जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। तेज शहरीकरण के बावजूद वर्ष 2040 तक देश की आधे से अधिक जनसंख्या का निवास गांवों में ही होगा। इस दृष्टि से ग्रामीण उपभोक्ता मांग बढ़ाना देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ये सब देश की जीडीपी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान करने और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में सहायक होंगे।

इन योजनाओं से जुड़ी समस्याएं भी कम नहीं हैं। इनमें नामांकन केंद्रों का दूर-दूर होना, नामांकन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या संचालकों का नियमित उपस्थित न होना, योजनाओं के बारे में जन साधारण को जानकारी न होना आदि शामिल हैं। अभी भी देश के कई ग्रामीण और आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा और सड़क संपर्क नहीं है, लोगों में वित्तीय साक्षरता की भी कमी है। लाभार्थियों के नाम में वर्तनी की त्रुटियां, लंबित केवाईसी, बंद या निष्क्रिय बैंक खाते, आधार और बैंक खाते के विवरण में असमानता आदि के कारण डीबीटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि डीबीटी से सीधे लाभार्थी के खाते में पूरी धन राशि पहुंच जाती है, लेकिन खाते में डालने से पहले अपना कमीशन आदि नकद में ले लेना, कागजी कार्रवाई के दौरान ही कमीशन आदि के रूप में धन वसूल लेने जैसी जमीनी स्तर की समस्याएं बनी रहती हैं।

अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण या शहरी परिवार को आवश्यक न्यूनतम राशि निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता और उसके आधार पर जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत करता है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2020 के मध्य लगभग 7.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंदर आए। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या लगभग पांच करोड़ है। बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा के नीचे रहने के कारणों में वर्ष 2017 से 2020 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था में आई मंदी की स्थिति, वर्ष 2017-18 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार इस अवधि में गत 45 वर्षों में बेरोजगारी के उच्चतम स्तर, वास्तविक मजदूरी में कमी, कोविड महामारी जैसे कारण बताए जाते हैं।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग नब्बे फीसद लोगों की आजीविका का माध्यम खेती है। मछली पालन, पशु पालन, हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण जैसी कुछ गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़ी सामान्य आजीविकाएं हैं, लेकिन ये सभी मौसमी हैं, जिनमें आय की अनियमितता बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। ये सभी कारक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता मांग को प्रभावित करते हैं।

भारत दुनिया की सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है। इसमें 87.8 करोड़ ग्रामीण निवासी हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। तेज शहरीकरण के बावजूद वर्ष 2040 तक देश की आधे से अधिक जनसंख्या का निवास गांवों में ही होगा। इस दृष्टि से ग्रामीण उपभोक्ता मांग बढ़ाना देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ये सब देश की जीडीपी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान करने और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में सहायक होंगे।

उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि ग्रामीण उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और स्कूलों की स्थापना सहित सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी है। साथ ही, पेयजल, बिजली, ग्रामीण सड़कें और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं में सुधार तथा विस्तार भी जरूरी है। कृषि आय बढ़ाने, अधिकाधिक वैकल्पिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उनके सुदृढ़ विपणन की व्यवस्था करने जैसे कुछ प्रभावी उपाय जरूरी हैं, तभी ग्रामीण आय और उपभोक्ता मांग में और बढ़ोतरी हो सकेगी।

जागरूकता की जरूरत

रितुप्रिया शर्मा

समाज में समस्याएं अनेक हैं, निवारण कम। ज्यादातर लोग अपने आप में गुम अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, मगर उसके कारणों पर विचार करना या तो जरूरी नहीं समझते या फिर उन्हें इस ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। कई बार जब समस्याओं या मूल मुद्दों के हल के लिए उसके कारणों की पड़ताल की दिशा मुखर होना शुरू होती है तो कुछ ऐसे मुद्दे सतह पर तैरने लगते हैं, जिसे देखने-सुनने में लोग उलझ जाते हैं और असली मुद्दों और उसके कारणों से उनका ध्यान बंट जाता है। इस तरह के हालात बार-बार पैदा होते हैं या किए जाते हैं और इसके समांतर समस्याएं न जाने कब से अपने स्वरूप में बनी हुई रहती हैं।

विडंबना यह है कि समस्याओं के स्रोत की पहचान लोग कर सकते हैं, मगर कई बार सुविधा का जीवन जीने वाला तबका साधारण लोगों को राजनीति से निरपेक्ष होने की सलाह देता है। जबकि समाज अगर किसी समस्या से दो-चार है तो उसका स्रोत व्यवस्था में छिपा हो सकता है। इन बातों को लेकर समाज और राजनीति परस्पर जुड़े हुए हैं। समाज एक अति शक्तिशाली संस्था है। राजनीति समाज से निकला एक अंग है जो समाज की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। समाज के बिना राजनीति का न कोई अस्तित्व है और न ही कोई भविष्य। व्यक्तिगत तौर पर भी जो समस्या हमारे समक्ष आती है, उनका हल कहीं न कहीं हमारी सामाजिक बुनियाद को प्रभावित करने में सक्षम है। आज समाज में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा आदि अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। समाज चाहता है कि वह उन समस्याओं से निकलकर एक परिपक्व समाज बने, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह जाती है। कारण है राजनीति का व्यक्तिगत स्वार्थों से ओत-प्रोत होना। सत्ता का नशा जिसके ऊपर चढ़ा, वह फिर किसी बात या मुद्दे की कोई परवाह नहीं करता है।

दुनिया मेरे आगे

> विडंबना यह है कि समस्याओं के स्रोत की पहचान लोग कर सकते हैं, मगर कई बार सुविधा का जीवन जीने वाला तबका साधारण लोगों को राजनीति से निरपेक्ष होने की सलाह देता है। जबकि समाज अगर किसी समस्या से दो-चार है तो उसका स्रोत व्यवस्था में छिपा हो सकता है।

समाज के बीच जाकर वोट मांगने वाले जब जीत के बाद हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो चुनाव के बाद अपने सारे वादों को भूल बैठते हैं। अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करने और लोगों को भरोसा देने में तो ये अग्रणी रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में जाकर काम करने में काफी पिछड़ते हुए नजर आते हैं। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि अब मुद्दाविहीन राजनीति का दौर आ गया लगता है। इसमें किसी भी दल के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा दिखता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से खुद को बचाकर एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले इस दौर में समाज केवल एक तमाशबीन बनकर रह गया है।

ऐसा नहीं कि इसके लिए समाज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल, समाज भी अपने-अपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर सक्रिय है। एक व्यक्ति के तौर पर किस-किस ने क्या-क्या संघर्ष किया है या मौजूदा समाज में किस तरह की सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्या आ रही है, वह इसकी ओर मुंह मोड़कर खड़ा है। लोग केवल वोट वाले दिन सक्रिय होते हैं और फिर वोट डालते हैं। इसके बाद घर की ओर लौट जाते हैं। कौन-सा राजनीतिक दल, किस मुद्दे या उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ रहा है, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। तात्कालिक मुद्दों का गुबार हावी होता है और वह वास्तविक मुद्दों पर छा जाता है। कभी परिवार वालों के मत से, कभी राजनीतिक लहर के प्रभाव में, कभी किसी नेता के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण हमारा समाज अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर अपने आप को लोकतंत्रवादी साबित करता रहता है।

लोग समझते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन मुद्दाविहीन राजनीति क्या सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करना ही लोकतंत्र की पहचान बनती जा रही है। समाज इन सबसे कटा हुआ है। किसने, किसको और कैसे ठगा है, वह मुद्दा भूल गया है। पहले लाखों के गबन होते थे। यह बात अब अरबों तक पहुंच गई है जो कि इस दौर के लिए समाज में पैदा हुई सामान्य-सी बात है। अगर राजनीतिक मुद्दों के बिना बात की जाती है तो उन मुद्दों का निराकरण भी नहीं हो पाता है। समाज को चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सवाल-जवाब करे, उनकी समस्या निवारण में जो भी भूमिका हो सकती है, उसके निर्धारण के लिए कोई योजना भी राजनीतिक दलों के समक्ष लाई जाए। वे ऐसा करने से इनकार करें तो फिर उन पर विश्वास न करके उन्हें अपना प्रतिनिधि न बनाएं, बल्कि किसी नए व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुने, जो वाकई समाज से जुड़ा हो और मुद्दों पर कार्य करना चाहता हो। हम ही समाज हैं तो ये सारी बातें हमारे ऊपर उतरती भी है।

लोकतांत्रिक जागृति गांव-कस्बों तक पहुंचे, यह हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो यह मुद्दाविहीन, लक्ष्यहीन राजनीति हमारी सामाजिक आधारशिला, उन्नति और आर्थिक व्यवस्था को क्षीण कर देगी। राजनीति और समाज को एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में चलाना चाहिए। व्यक्ति का मूल्य समझना व्यक्तिवादी सोच का द्योतक नहीं है। व्यक्ति का मूल्य समाज की तरक्की और दिशा निर्धारण का उत्तम तरीका है। राजनीति को मुद्दाविहीन न बनने दिया जाए। दलों को स्वार्थपरता से दूर रखते हुए उन्हें समाज की समस्याओं से अवगत कराते रहना चाहिए। निवारण के लिए प्रेरित कर लोकतंत्र का असली स्वरूप हम सामने ला सकते हैं। अन्यथा लक्ष्यहीन, मुद्दाविहीन राजनीति हमारे समाज को कहीं न कहीं, कोई न कोई नुकसान पहुंचाएगी और भविष्य में कहीं लेकर नहीं जाएगी। इसलिए समाज को इस पर गौर करके पहल करनी चाहिए, ताकि यह सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो।

निवेश का चक्रव्यूह

पिछले पांच वर्षों में सेंसेक्स दो गुना हो गया, जिससे कई लोगों ने अच्छा-खासा पैसा कमाया। इस सुनहरे पक्ष के पीछे छिपा हुआ सच दब कर रह जाता है। हर वर्ष कई नए आइपीओ जारी किए जाते हैं जो शुरुआत में तो अच्छा दम भरते हैं, मगर उनमें से लगभग पच्चीस से तीस फीसद मात्र दस या शून्य फीसद तक पर आ जाते हैं, जिसमें निवेशकों का, विशेष तौर से छोटे निवेशकों का अच्छा-खासा पैसा डूब जाता है। इसलिए इनको जारी करने वाली कपनियों से वित्त मंत्रालय को सख्त कार्रवाई करके जनता का कम से कम मूलधन तो वापस लौटाना ही चाहिए। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर इन दिनों रातों-रात मालामाल होने का दावा करने वाले विज्ञापनों की बाढ़-सी आ गई है, जो कि शुरू में मुनाफा देकर फिर अपने खाते में निवेशक का पैसा डलवा कर गायब हो जाते हैं। इन पर भी कोई नियंत्रण नहीं दिखता है। नए खिलाड़ी इनके चक्रव्यूह में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। वित्त मंत्रालय को देश में और सोशल मीडिया पर निवेशकों को ठगने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखनी होगी। निवेशकों को भी विश्वसनीय संस्थाओं के माध्यम से ही व्यापार करना चाहिए!

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

लगाम जरूरी

चुनाव के दौरान एक दूसरे दलों के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भाषा मर्यादित भी हो, ताकि उन्हें ही फिर अनावश्यक सफाई में यह न कहना पड़े कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया है। ज्यादातर सियासी दल और उनके नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ बदजुबानी करने में संकोच नहीं किया है, जबकि सभी पार्टियों में महिलाएं हैं, वे महिलाओं का हित करने के नारे के साथ वोट मांगते हैं। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के बाद तो उम्मीद थी कि यह सब बंद हो जाएगा, मगर हकीकत कुछ और है। दरअसल, महिलाओं का मजाक उड़ाने या सम्मान को चोट पहुंचाने वाले कुंठाग्रस्त लोग होते हैं। शब्दों के चुनाव और लहजे पर लगाम जरूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर प्रतिद्वंद्वी हैं, तो विचारधारा, सिद्धांत और नीति का विरोध गरिमामय शब्दों से भी हो सकता है। कानूनी कार्रवाई सख्त हो, मगर इससे बेहतर हो कि राजनीति से जुड़े लोग खुद ही सुधरें और पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व भी उन्हें सुधारें।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

प्रदूषण की ध्वनि

'कानों में कहर बरपाती आवाजें' (लेख, 13 अप्रैल) पढ़ा। ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों और अन्य जीवों को प्रभावित करता है। यह न केवल जमीन पर रहने वाले जानवरों को प्रभावित करता है, बल्कि समुद्र में रहने वाले जनवरों के लिए भी एक बढ़ती समस्या है। सरकार और आम लोगों के संयुक्त प्रयास से ध्वनि और शोर की तीव्रता को कम कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सड़क किनारे पौधरोपण कर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को दस से पंद्रह डीबी तक कम कर सकते हैं। इस छिपे हुए प्रदूषण की अनदेखी करके जो लोग लगातार तेज ध्वनि के बीच रहते हैं या कानों में ईयरफोन लगा कर ऊंचे स्वर में गीत सुनते रहते हैं, उनके कान धीरे-धीरे कब बेकाम हो जाते हैं, उन्हें पता भी तब चलता है जब एक दिन उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है।

- पूजा सिंगार, इंदौर

सेहत की फिक्र

'जानलेवा बनती बिगड़ती हवा' (लेख, 15 अप्रैल) में वायु प्रदूषण की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित किया गया है। अब तक हम समझते थे कि जहरीली हवा केवल बड़े-बड़े शहरों में ही लोगों के दम घुटने की वजह बन रही है, मगर अब इसका दायरा तेजी से फैलता जा रहा है। यहां तक कि उसका असर ग्रामीण इलाकों में देखा जाने लगा है। इसकी अनदेखी भारी पड़ सकती है और इसके बचाव के लिए हमें तत्काल उपाय करने होंगे। हमें नए पौधे लगाने चाहिए, जिससे प्राणवायु में बढ़ोतरी हो। वाहनों का उपयोग करने के मामले में साझेदारी करनी चाहिए और मिलजुल कर काम चलाना चाहिए। अपने-अपने निजी वाहन जरूरत कम, दिखावा ज्यादा होते हैं। जिस तरह हम अपने घर, परिवार की चिंता करते हैं, उसी के समान हमें स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

- इंदु मणि, राजसमंद

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

सुखद पूर्वानुमान
अधिक बरसात

भारतीय मौसम विभाग-आईएमडी ने दशक में पहली बार पूरे देश में सामान्य से अधिक बरसात का पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमान से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। एक दशक में पहली बार उसने पूरे देश में औसत से अधिक बरसात का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण है जिनमें कृषि व जल संसाधन प्रबंधन के साथ अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। नीति निर्माता और किसान इस खबर का स्वागत करेंगे, हालांकि आम लोगों को भी हमेशा की तुलना में ज्यादा मानसून से तालमेल बनाना होगा। यह सभी किसानों के लिए वास्तव में राहत की सांस होगी। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और वह समय पर व समुचित बरसात पर अत्यधिक निर्भर है। समुचित बरसात फसलें उगाने तथा अन्य कृषि गतिविधियां जारी रखने के लिए जरूरी है। बरसात में अधिकता के पूर्वानुमान के साथ ही किसान मिट्टी में ज्यादा नमी की उम्मीद कर सकते हैं जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पूर्वानुमान उनको फसल चक्र की बेहतर योजना बनाने तथा कृषि उत्पादन अधिकतम करने का अवसर भी देता है। भारत के जल संसाधन गहन रूप से मानसून पैटर्न से जुड़े हैं। इसे देखते हुए सामान्य से अधिक बरसात जल भंडारों, झीलों तथा भूमिगत जल भंडारों को भरने के लिए अच्छी होगी। इससे जल का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसकी खासकर जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है। उपयुक्त बरसात से जल संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव घटेगा तथा घरेलू, औद्योगिक व कृषि क्षेत्र के लिए सप्लाई में सुधार आएगा। अच्छे मानसून से पनबिजली उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा।

लेकिन अभी सामान्य या सामान्य से अधिक मानसून का उत्सव मनाना उचित नहीं होगा। मौसम के पूर्वानुमान अपनी प्रकृति से ही अनुमानों पर आधारित होते हैं। देश भर में अच्छा मानसून एक विरल चीज रहा है। जहां सामान्य से अधिक बरसात से अनेक लाभ होते हैं, वहीं इससे कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। ज्यादा बरसात के कारण खासकर निचले तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। बाढ़ से न केवल संपत्ति व ढांचागत संरचनाओं को नुकसान होता है, बल्कि इससे मानव जीवन भी खतरे में पड़ता है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को ढांचागत संरचनायें मजबूत करने, जल निकासी व्यवस्थाओं में सुधार करने तथा प्रभावी बाढ़ प्रबंधन रणनीतियां बनाने की दिशा में पूर्वानुमान के आधार पर कदम उठाने चाहिए। भारी बरसात से मृदा क्षरण तथा भूस्खलन का खतरा खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ जाता है। इसलिए संकटग्रस्त परिस्थितिकी तंत्रों को बचाने तथा संकट कम करने के लिए उपयुक्त मृदा संरक्षण उपाय व पुनर्वनीकरण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त जल प्रबंधन व्यवहार अपना कर पानी की बरबादी रोकने तथा जल संसाधनों को अधिकतम करने के प्रयास करने चाहिए। भारतीय मौसम विभाग- आईएमडी की भविष्यवाणी किसानों के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की बेहतर संभावनायें लाई है। वह अधिकारियों के लिए पानी की कमी से निपटने में सहायक हो सकती है। तैयारी, संरक्षण तथा टिकाऊ व्यवहारों के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर भारत को प्रचुर बरसात का लाभ उठाने की तैयारी करनी चाहिए। इससे वह अधिक बरसात के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से बच सकता है। इससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण का मार्ग खुलेगा।

ईरानी हमले से स्थायित्व को खतरा

इज़राइल पर ईरानी हमला अपनी प्रकृति से प्रतीकात्मक है, पर इससे क्षेत्र में बढ़ते तनाव का संकेत मिलता है। हालांकि, अमेरिका ने शक्ति संतुलन बनाए रखने का वादा किया है।

नीलांत इलांगमुवा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ईरानी हमला अपनी प्रकृति से प्रतीकात्मक है, पर इससे क्षेत्र में तनाव का संकेत मिलता है। हालांकि, अमेरिका ने शक्ति संतुलन बनाए रखने का वादा किया है। हालांकि, इज़राइल ने विश्व नेताओं के अनुरोध पर संयम बरता है, पर उसने ईरान के खिलाफ बदला लेने की असाधारण कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रकट की है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ईरान अपने मुहरों-हमास, हिजबुल्ला व हूती के माध्यम से न केवल इज़राइल पर हमले करता है, बल्कि वह इस पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व भी कायम करना चाहता है। ऐसे समय जब दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया में अनेक देश परंपरागत नव वर्ष मना रहे थे, पश्चिम एशिया के दूसरे सबसे बड़े देश ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इज़राइल पर अनेक मिसाइलों से निशाना लगाया। जार्डन और सऊदी अरब ने इज़राइल का समर्थन करते हुए ईरान द्वारा दागी अधिकांश मिसाइलों को गिरा दिया। यह हमला प्रतीकात्मक लगता है क्योंकि इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में हमास, यमन में हौती तथा ईराक और लेबेनान में ईरान-समर्थक हिजबुल्ला का हौसला बढ़ाने के लिए है। इन सबने पश्चिम एशिया में इज़राइल के खिलाफ युद्ध का समर्थन किया है।

इस हमले ने उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया। हमले के फौरन बाद हमास ने 'कैरो समझौता' अस्वीकार कर दिया जो शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों-सीआईए व मोसाद के बीच वार्ताओं के माध्यम से हुआ था। मिस्र ने इसमें सहायता की थी और इसका उद्देश्य इज़राइली बंधकों को रिहा कराना था। हालांकि, अनेक देशों ने इज़राइल को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित किया, पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यदि ईरान के खिलाफ हमले किए गए तो वे उनका समर्थन नहीं करेंगे। सच्चाई यह है कि अमेरिकी प्रशासन इस समय एक और युद्ध के लिए इज़राइल की सहायता नहीं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि बहुत खराब है और बाइडेन की राजनीतिक शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे में यदि अमेरिका कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय करता है ता उसे जल्द ही अभूतपूर्व नतीजों का सामना करना पड़ेगा। इलोन मस्क ने हाल में कहा है कि अमेरिका को एक और '11 सितंबर' जैसे हमले का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे टकरावों का असर न केवल वाशिंगटन या न्यूयार्क पर होगा, बल्कि इससे दुनिया भर में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर संकट पैदा हो सकता है। इतिहास ने सिद्ध किया है कि महाशक्तियां अंततः ध्वस्त हो जाती हैं। अपने जीवनकाल को देखते हुए मानव सभ्यता के दृष्टिकोण से अमेरिका महान साम्राज्यों के पतन की तुलना में युवा महाशक्ति है।

इतिहास पर गौर करें तो शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ है। इनमें रोमन साम्राज्य, आटोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य तथा ब्रिटिश साम्राज्य शामिल हैं। 16वीं से 20वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक दबावों तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों का सामना करना पड़ा और अंततः यह आंतरिक कमजोरियों तथा बाहरी दबावों के सामने ध्वस्त हो गया। राजनीतिक, सैनिक तथा सामाजिक-आर्थिक तत्वों के कारण इन साम्राज्यों के ध्वस्त होने से दुनिया को नया स्वरूप मिला। इससे सत्ता का परिवर्तनशील चरित्र तथा आधुनिक भू-राजनीति व सभ्यता पर इतिहास का स्थाई प्रभाव स्पष्ट होता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के 'डीप स्टेट' ने निश्चित रूप से अनेक अन्य देशों की तुलना में विश्व इतिहास को बेहतर ढंग से समझा है। इसी कारण अमेरिका की मूल रणनीति शांति की बात करते हुए नये युद्धों का सृजन करना है और अनिश्चितताओं पर नियंत्रण के लिए इन युद्धों को दीर्घकालीन त्रासदियों में बदलना है। इस रणनीति से वह अपने विरोधियों को कमजोर करते हुए अपनी सत्ता लगातार बनाए रखने में सफल रहता है। अनेक टकरावों को उनके राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में देखने पर इन टकरावों के बारे में बेहतर समझदारी पैदा होती है।

इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार प्रचारित विचारधारा एक राय या इज़राइल की प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन रणनीति है जिसमें तथ्यों व लक्ष्यों को अमेरिका के साथ मिल कर सावधानी से तय किया जाता है। दूसरी ओर वह इन देशों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगवा कर वहां आंतरिक संकट पैदा करता है। यह रणनीति पश्चिम का स्थाई व्यवहार बन गई है। यह तथ्य भुलाया नहीं जाना चाहिए कि ईरान का हमला बदले की कार्रवाई है। यह सीरिया में ईरानी कौंसुलेट पर इज़राइल के उकसावे भरे हमले की प्रतिक्रिया है। उसकी कार्रवाई वियेना सम्मेलन का घोर उल्लंघन थी जिसमें ईरानी क्रांतिकारी गार्ड कार्पर्स की मौतें हुई थीं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, ईरान ने सोचा था कि यदि वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो इज़राइल उसे और पीछे धकेलने तथा क्षेत्र में प्रतिरोध को कमजोर करने का प्रयास करेगा। लेकिन यह अनुमान लगाना उचित नहीं होगा कि इज़राइल ने सीरिया में ईरानी राजनयिक ठिकाने पर अपने हमले के परिणामों का अनुमान नहीं लगाया होगा।

इज़राइल की खुफिया एजेंसी ने सीरिया में हिजबुल्ला व आईआरजीसी में अच्छी घुसपैठ की है और इन नेटवर्कों को इज़राइली हमलों के लिए आसान बना दिया है। ईरान को अपने सहयोगियों में अपना सम्मान बनाए रखना है तथा आंतरिक राजनीतिक संकट से प्रभावी ढंग से निपटना है। इसलिए अपने मुहरों के माध्यम से वह हमलों को प्राथमिकता देता है, भले ही कभी-कभी दोनों पक्षों के बीच सीधे टकराव हो जाता हो। इसके साथ ही ईरान सरकार की घरेलू नीतियों के कारण तनाव बना हुआ है।

ईरान में कुछ राजनेता और अधिकारी खुलेआम ईरान की अंतर्निहित कमजोरियों का उल्लेख करते हैं। वे ईरान सरकार के समक्ष मौजूद अनेक संकटों को उजागर कर चेतावनी दे रहे हैं कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किए बिना इज़राइल से सीधे टकराव न मोल ले क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने व्यावहारिक प्रशासन तथा प्रभावी संकट प्रबंधन पर जोर दिया है तथा वे व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए वर्तमान संकट का समाधान खोजने पर जोर दे रहे हैं। समाज में आर्थिक चुनौतियां तथा मनोवैज्ञानिक अस्थिरता ऐसे तात्कालिक मुद्दे हैं जिनको तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर वे दुश्मनों को फलने-फूलने का उपजाऊ मैदान देते हैं। ईरान के अनेक राजनेताओं ने तनाव घटाने के लिए सुलह-समझौते वाली नीतियां अपनाने तथा ईरानी समाज में सद्भावना व संवेदनशीलता बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार की दमनकारी घरेलू नीतियां, खासकर अनिवार्य 'हिजाब अभियान' ने समाज में व्यापक निराशा और गुस्सा पैदा किया है जिससे सरकार की वैधता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हालिया इज़राइल-विरोधी कार्रवाइयों, जैसे एक मालवाहक जहाज पर कब्जे ने ईरानी बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ईरानी राष्ट्रीय मुद्रा में ऐसी कार्रवाइयों के कारण रिकार्ड गिरावट आई है। बड़ी संख्या में ईरानियों द्वारा आर्थिक संकट का सामना करने के कारण राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी की कटु आलोचना हुई है और उन्होंने इनसे निपटने के लिए कैबिनेट में परिवर्तन का निर्णय किया है।

पिछले वर्षों में इज़राइल ने ईरानी नाभिकीय वैज्ञानिकों और उसकी नाभिकीय ढांचागत संरचना पर हमला करने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 'स्टक्सनेट साइबर हमले' ने ईरान की नाभिकीय महत्वाकांक्षाओं को गहरा झटका दिया है। इससे सिद्ध होता है कि घरेलू राजनीतिक मुद्दों के कारण राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं किया जाता है। ईरानी नाभिकीय क्षमताओं पर 'स्टक्सनेट' हमला एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे साइबर-युद्ध का नया युग शुरू हो गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य भू-राजनीतिक परिदृश्य को पुनः बदलने के लिए सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। 'स्टक्सनेट' का प्रभाव सारी दुनिया में दिखाई पड़ा क्योंकि इससे युद्धों की बदलती प्रकृति तथा आधुनिक युद्धों में तकनीक का महत्व उजागर होता है। ऐसी स्थिति में ईरान लगातार मौन नहीं रह सकता है। इसलिए ईरान का हालिया हमला इज़राइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा न होकर अपनी इज्जत बचाने का एक कदम है।

उत्तराखंड में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका

शीतल आर्या
(लेखिका, शोधकर्ता हैं)

उत्तराखंड में महिलाएं अपनी असाधारण लचीलेपन और कड़ी मेहनत के लिए प्रसिद्ध हैं, ये विशेषताएं उनकी हिमालयी विरासत में गहराई से निहित हैं। इस बीहड़ इलाके में जीवन की चुनौतियों से जूझने के बावजूद, उत्तराखंड की महिलाएं लगातार सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में सबसे आगे रही हैं, जो चिपको आंदोलन की गौरा देवी और शराब विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली टिंचरी माई (दीपा नौटियाल) जैसी शख्सियतों का प्रतीक हैं। आंदोलन। इन महिलाओं ने उत्तराखंड की भावना को मूर्त रूप देते हुए निडर होकर अन्याय का सामना किया है। यह लेख उत्तराखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को रेखांकित करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

उत्तराखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को दो प्राथमिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है- पहला, महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व की स्थिति संभाल रही हैं और दूसरा, महिलाएं मतदाता के रूप में अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं।

राज्य की स्थापना के बाद से, विधान सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीरे-धीरे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। पहली विधानसभा में चार महिला सदस्यों से, 2022 के चुनावों में संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो एक सराहनीय प्रगति है। हालाँकि, इस प्रगति के बावजूद, महिलाएं विधानसभा में अल्पसंख्यक बनी हुई हैं, जो कुल सदस्यों का केवल एक अंश है। वर्तमान में, विधान सभा में तीन दलित महिलाओं सहित आठ महिला सदस्य हैं, जो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। विशेष रूप से, श्रीमती. रितु खंडूरी वक्ता के रूप में कार्य करती हैं, जबकि श्रीमती। रेखा आर्य कैबिनेट में अकेली महिला मंत्री हैं. इन प्रगतियों के बावजूद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता बनी हुई है, जो राजनीतिक सत्ता तक पहुँचने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है।

जबकि संसदीय क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, आठ में से केवल दो महिला सांसद हैं, महिला आबादी (49 प्रतिशत) और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच विसंगति स्पष्ट है। जमीनी स्तर के आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी के बावजूद, औपचारिक राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति अनुपातहीन रूप से कम है। उत्तराखंड में महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो प्रवासन, पर्यावरणीय गिरावट और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों से जूझ रही हैं। हालांकि, सामाजिक मानदंड और आर्थिक बाधाएँ अक्सर उनकी राजनीतिक भागीदारी को रोकती हैं। इसके अलावा, राजनीतिक दलों की महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की अनिच्छा इस असमानता को और बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने किसी भी महिला उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया है, जबकि भाजपा ने केवल एक, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह को नामांकित किया है। फिर भी, उत्तराखंड में महिला मतदाता हाल के चुनावों में पुरुषों से आगे निकल कर एक ताकतवर ताकत के रूप में उभरी हैं। उनकी बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, उनके जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से प्रेरित, उच्च साक्षरता दर और आरक्षण कोटा जैसी सरकारी पहलों ने उनकी भागीदारी को प्रेरित किया है। सरकारी नौकरियों में 30त्न क्षैतिज आरक्षण और पंचायतों में 50त्न आरक्षण जैसी नीतियों ने महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को मजबूत किया है, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया गया है।

2024 के संसदीय चुनावों से पहले, दोनों प्रमुख पार्टियाँ विभिन्न रणनीतियों को अपनाते हुए महिलाओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। कांग्रेस ने महिला सुरक्षा और न्याय पर जोर देते हुए महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और नौकरी में आरक्षण का वादा किया है। इसके विपरीत, भाजपा जमीनी स्तर पर लामबंदी के प्रयासों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर के रूप में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर प्रकाश डालती है।

महिला मतदाताओं के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उनके जमीनी स्तर के जुड़ाव और महिला आरक्षण विधेयक जैसी पहल के कारण, भाजपा की चुनावी संभावनाओं को और मजबूत करती है। मोदी फैक्टर उत्तराखंड की महिलाओं में प्रतिध्वनित हुआ है, जिसने 2017 से भाजपा के निरंतर प्रभुत्व में योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए पर्याप्त लैंगिक बजट आवंटित किया है, जो लैंगिक असमानताओं को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात करना और गर्भवती महिलाओं को मतदान केंद्रों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना जैसे उपाय समावेशी शासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्षतः, डॉ. अम्बेडकर का यह कथन कि किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की उन्नति पर निर्भर है, उत्तराखंड के लिए सत्य है। जबकि महिलाएं ऐतिहासिक रूप से सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, औपचारिक राजनीति में उनका कम प्रतिनिधित्व एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। जैसा कि उत्तराखंड आगामी चुनाव कौथिग के लिए तैयार है, जिसमें 48.1 प्रतिशत मतदाता हैं, उनकी बढ़ी हुई भागीदारी राज्य में लोकतंत्र की जीत का अग्रदूत होने का वादा करती है।

आप की बात

ईरान की धमकी

ईरान द्वारा इजरायल पर भारी ड्रोन व मिसाइल हमले के बाद उसके मंत्री चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान इजरायल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा और ऐसे नए अस्त्रों का प्रयोग करेगा जो अब तक किसी ने प्रयोग नहीं किए हैं। यह एक चौंकाने वाला बयान है। इससे लगता है कि ईरान ने कोई ऐसी नई तकनीक विकसित कर ली है जो विश्व में किसी अन्य देश के पास नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई के नए चमत्कारों को देखते हुए ईरान की धमकी पर गंभीरता से गौर करना जरूरी है। ईरान एक तानाशाह व कट्टरपंथी इस्लामवादी देश है जो दूसरे देशों में इस्लामी क्रांति का निर्यात करने का प्रयास कर रहा है। ईरान में सैकड़ों महिलाओं को केवल हिजाब न पहनने के कारण अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा है और कई को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं। ईरान घोषित रूप से इज़राइल को दुनिया के मानचित्र से समाप्त करने की धमकी भी देता रहा है। ऐसे में ईरान पर लगाम लगाना उन इस्लामी देशों के भी हित में है जो दुनिया के अन्य धर्मानुयाइयों की तरह मुस्लिम नौजवानों व नवयुवतियों को समान अधिकारों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों से लैस करना चाहते हैं। ईरानी सत्ता में बार-बार कट्टरपंथियों का हावी होना चिन्ता का विषय है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

न्यायालय पर दबाव

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश-सीजेआई को पूर्व में दो बार वकील लोग सुप्रीमकोर्ट पर दबाव बनाने के प्रयास के विरोध में पत्र लिख चुके हैं। अब देश के 21 भूतपूर्व न्यायाधीशों ने फिर से एक पत्र लिखकर न्यायालय पर राजनीतिक दबाव बनाने के प्रयासों को लेकर चिंता जाहिर की है। हमारा प्रजातंत्र जिन चार स्तंभों पर टिका है उनमें से एक स्तंभ न्यायालय भी है। देश की कई विकट समस्याओं के समाधान में न्यायालय ने अपनी भूमिका बखूबी निभाकर लोगों में न्याय के प्रति आस्था बनाए रखी है। कई बार न्यायालय ने कई मामलों का स्वतः संज्ञान भी लिया है। केंद्र में प्रबल बहुमत वाली वर्तमान सरकार ने भी सुप्रीमकोर्ट के हर आदेश को शिरोधार्य कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। पूर्व न्यायाधीशों और इसके पहले वकीलों द्वारा सार्वजनिक रूप से सीजेआई को लिखे पत्रों से न्यायपालिका में राजनीतिक उठापटक के संकेत मिलते हैं। कई बार मनमाफिक फैसला न मिलने पर कुछ बड़े वकील न्यायपालिका या सीजेआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगते हैं। इस प्रवृत्ति को सही नहीं कहा जा सकता है। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यपालिका व विधायिका की है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

बेहतर सरकार

इन दिनों देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसी कई शिकायतें हैं। लेकिन इन सारी शिकायतों के बावजूद भी ज्यादातर लोग यह भी कहते हैं कि भाजपा सरकार बेहतर है एवं अच्छा कार्य भी कर रही है। अतः इसे एक बार और अवसर देना ठीक होगा। आज देश चलाने के लिए मोदी से बेहतर कोई और नेता नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में वर्तमान मोदी सरकार ने काफी काम किए हैं। पिछली सरकारों के किसी भी कालखंड के दस साल में इतना काम कभी नहीं हुआ है। आज लोगों को यह भी विश्वास है कि मोदी सरकार अगले 5 सालों में अवश्य ही देश से गरीबी एवं महंगाई कम करने का प्रयास करेगी। आज पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, जबकि भारत ने उस पर काफी लगाम लगाई है। पड़ोसी पाकिस्तान या विकसित अमेरिका को देखें तो वहां महंगाई आसमान छू रही है। भारत ने 80 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना चलाई है जो दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी योजना है। इसका पांच साल और विस्तार किया गया है। मोदी सरकार इसलिए भी दूसरों की तुलना में बेहतर है कि उसने देश की समस्याओं को स्थाई ढंग से हल करने की नीति बनाई है। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

खतरनाक खेल

ड्रीम 11 बहुत ही खरतनाक बीमारी के तौर पर उबर रहा है। इस खेल पर समय रहते रोक लगानी होगी क्योंकि यह अनेक लोगों के लिए वित्तीय जोखिम के साथ-साथ मानसिक बीमारी का कारण बनने लगा है। ड्रीम 11 ऐसा खेल है जो 39 व 59 रूपये में युवाओं को रातोंरात करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहा है। कभी जीतने पर एक करोड़, कभी दो करोड़ और आजकल 4 करोड़ की राशि दी जा रही है। लाखों युवाओं को इस खेल की लत लगी हुई है और वे अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई को यूंही जाया करने में लगे हुए हैं। सरकारी क्षेत्र में तैनात कर्मचारी भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। ड्रीम 11 का विज्ञापन व्यापक रूप से किया जा रहा है और कई बड़े सितारे इसका प्रचार करते देखे जाते हैं। हालांकि, विज्ञापन में वित्तीय जोखिम है और इसकी लत लगने की बात कहीं जाती है, पर यह केवल खानापूरी है। देश में सट्टेबाजी, लाटरी, घुड़दौड़ की सट्टेबाजी या ऐसी ही अचानक अमीर बनाने वाले तरीकों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि आधुनिकता की चकाचौंध में इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

– **भूपेंद्र सिंह,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राजमार्गों का विस्तार

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में बीते वित्त वर्ष की तुलना में पांच से आठ प्रतिशत अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की संभावना है. पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में इन सड़कों के विस्तार की दर लगभग 20 प्रतिशत रही थी. यह बढ़ोतरी इसलिए भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल की पहली छमाही में देश के अनेक क्षेत्रों में मानसून की अवधि अपेक्षाकृत अधिक रही थी, जिसके कारण निर्माण कार्यों में अवरोध उत्पन्न हुआ था. निर्माण कार्य में तेजी सितंबर 2023 के बाद ही आ सकी थी. इस तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 2022-23 की दूसरी छमाही की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक सड़क निर्माण हुआ था. इसकी एक वजह पहली छमाही की कमी को पूरा करना था और दूसरा कारण यह रहा कि आम चुनाव को देखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया गया. क्रेडिट एजेंसी आइसीआरए की ताजा रिपोर्ट में आकलन किया है कि इस वित्त वर्ष में 12,500 से 13,000 किलोमीटर लंबे नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जायेंगे. इस विस्तार को परियोजनाओं पर ध्यान, अधिक आवंटन और सरकार की प्राथमिकता से आधार मिल रहा है. मार्च 2024 तक 45 हजार किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है. यदि भारतमाला परियोजना के पहले चरण के खर्च के संशोधित आकलनों को स्वीकृति देने में केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कुछ देरी नहीं हुई होती, तो मंजूर परियोजनाओं का आकार और बड़ा हो सकता था. बीते वित्त वर्ष में 2022-23 की तुलना में आवंटित परियोजनाओं की सड़क लंबाई में 31 प्रतिशत की कमी आयी थी, जिसकी इस वर्ष भरपाई भी हो सकती है और अधिक निर्माण भी संभावित है. राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इन मार्गों से बेहतर जुड़ाव के लिए अपने सड़कों के निर्माण पर ध्यान दे रही हैं. इससे न केवल आवागमन बढ़ाने में मदद मिली है, बल्कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की ढुलाई की मात्रा एवं गति भी बढ़ी है. केंद्र सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कई योजनाओं को राजमार्गों के निर्माण से जोड़ा गया है. सड़कों के किनारे भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, गोदाम आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ है. साथ ही, बाजार, होटल, रेस्तरां, मैकेनिक एवं रिपेयर सेंटर आदि भी बढ़े हैं. सड़कों के निर्माण और विस्तार से घरेलू बाजार में आपूर्ति बेहतर हुई है. इससे निर्यात को भी बड़ी मदद मिली है, जिसमें हर साल कीर्तिमान बन रहा है. सड़कों की लंबाई ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी निरंतर सुधार हो रहा है. इससे घरेलू पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिला है. राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार से विकास की नयी गाथा लिखी जा रही है.

मार्च 2024 तक 45 हजार किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के निर्माण की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है.

युद्ध की आशंका से बढ़ती आर्थिक चिंता

अजीत रानाडे
अर्थशास्त्री
editor@thebillionpress.org

मध्य-पूर्व में तनाव और अनिश्चितता केवल हथियार कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. बाकी के लिए यह आर्थिक तौर पर बुरी खबर है. चीन और रूस (दोनों सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं) ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की है. गाजा में इस्राइली हमलों को रोकने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर अमेरिका ने लगातार वीटो किया है. सात अक्तूबर के हमास के आतंकी हमले के जवाब में इस्राइल की कार्रवाई का स्तर बहुत अधिक रहा है, जिसमें 30 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

तैंतीस वर्षों में पहली बार किसी देश ने 13 अप्रैल को इस्राइल पर हमला किया. पिछली बार 1991 में इराक ने इस्राइल पर स्कड मिसाइलें दागी थीं. अब ईरान ने 360 मिसाइलों और ड्रोनों से इस्राइल के विभिन्न स्थानों पर हमला किया है. इनमें धीमी गति के ड्रोन भी थे, जिन्हें इस्राइल पहुंचने में छह घंटे से अधिक लगे, तो तेज गति की मिसाइलें भी थीं. ईरान के विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों को इस हमले के बारे में 72 घंटे पहले बता दिया था. इस्राइल लगभग 99 प्रतिशत मिसाइलों और ड्रोनों को गिराने में सफल रहा, इसलिए उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ. ऐसा उन्नत मिसाइल-रोधी रक्षा प्रणाली- आयरन डोम- के कारण संभव हो सका, जिसे इस्राइल ने अमेरिकी और ब्रिटिश मदद से तैयार किया है. इस बार इस प्रणाली को जॉर्डन की धरती पर भी तैनात किया गया था. कुछ घंटों की इस रक्षा का अनुमानित खर्च लगभग 1.1 अरब डॉलर था. इस तरह की प्रणालियों को तैनात करने से रक्षा कंपनियों, मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों, को लाभ होने की आशा है. दो साल से अधिक समय से यूक्रेन में चल रहे युद्ध से भी अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों को पहले ही बहुत फायदा हो चुका है. इन हमलों के लिए ईरान को भी संभवतः एक अरब डॉलर के आसपास की राशि खर्च करनी पड़ी है.

सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक अप्रैल को अपने दूतावास पर हुए इस्राइली हमले के बदले में ईरान ने इन हमलों को अंजाम दिया है. उस हमले में ईरान के दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गये थे. आखिर इस्राइल या उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वैसे हमले की अनुमति क्यों दी, जो एक कूटनीतिक निशाने पर था और ईरान ने पहले ऐसा कोई हमला भी नहीं किया था? क्या इस्राइल हमास के साथ चल रही लड़ाई का दायरा बढ़ाना तथा दूसरों को इसमें खींचना चाहता है? क्या उसे पता नहीं था कि ऐसी कोई कार्रवाई जवाबी हमले का कारण बन सकती है? या उसे ईरान से ऐसे ठोस हमले का अंदेशा नहीं था? इस्राइल के समर्थक तर्क देंगे कि दमिश्क का हमला बिना उकसावे के नहीं किया गया था. यह उनको दंडित करने के लिए था, जो हमास की सहायता कर रहे हैं. इस्राइल में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह और यमन में हूथियों को ईरान का परोक्ष समर्थन जगजाहिर है. इस्राइल पहले भी उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के इरादे से और हमास एवं हिज्बुल्लाह के समर्थन के विरोध में ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों पर हमले कर चुका है. ईरान भी परमाणु हथियार क्षमता बढ़ाने में तेजी से जुटा हुआ है. इस्राइल भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है. कुछ टीवी और सोशल मीडिया चैनलों पर ईरान के हमलों को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया गया. स्टॉक मार्केट में हलचल मच गयी. ईरानी कार्रवाई की आशंका में शुक्रवार को ही न्यूयॉर्क का डाऊ सूचकांक 2.4 प्रतिशत गिर गया था. दुनियाभर में शेयर बाजारों में गिरावट का रुख है. सोने का भाव अभूतपूर्व स्तर पर है. जल्दी ही भारत में इसका प्रति दस ग्राम दाम 80 हजार रुपये से अधिक हो जायेगा. सोने की बड़ी मांग इंगित करती है कि जोखिम से बचने वाले निवेशकों को डर है कि बाकी परिसंपत्तियों के दाम बहुत घट सकते हैं. चूंकि यह संघर्ष मध्य-पूर्व से आपूर्ति को बाधित करेगा, तो तेल के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे. समुद्र और हवाई मार्गों से ढुलाई के बीमा का खर्च भी बढ़ेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के खर्च में बढ़ोतरी होगी.

ऐसे में भारत पर तिहरा दबाव होगा. विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगी, व्यापार घाटा बढ़ेगा और मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा तथा तेल महंगा होने से मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है. बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में वृद्धि की गति धीमी पड़ी है और इस अवधि में जीडीपी वृद्धि दर लगभग छह प्रतिशत रहने की आशा है. बिगड़ते माहौल में यह और कम हो सकती है, हालांकि चुनावी खर्च से जीडीपी को मदद मिलती है. वस्तु निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. लाल सागर में हूथी हमलों से समुद्री व्यापार महंगा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नकारात्मक है. खुदरा मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है और तेल के दाम उसे और बिगाड़ सकते हैं. इसीलिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की है, जिससे आवास और वाहन ऋण में मदद मिल सकती थी. रोजगार के क्षेत्र में भी स्थिति ठीक नहीं है. हाल में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में युवा बेरोजगारी, कौशल का अभाव और श्रम बल में कम महिला भागीदारी को लेकर निराशाजनक तस्वीर पेश की गयी है. भारत में महिला भागीदारी और पुरुषों की अपेक्षा कम मेहनताना की स्थिति 2005 से ही बिगड़ रही है, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में यह खाई कम हो रही है. अनुमान है कि कोविड के बाद पांच करोड़ कामगार खेती में लौटे हैं, जहां उत्पादकता कम है, गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं है और कमतर रोजगार भी है. रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा ही हो सकता है. इसके लिए निवेशकों में भरोसा होना चाहिए तथा नये उपक्रमों, कारोबारों और उद्यमों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है. केवल सरकारी खर्च से व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन संभव नहीं है.

मध्य-पूर्व में तनाव और अनिश्चितता केवल हथियार कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है. बाकी के लिए यह आर्थिक तौर पर बुरी खबर है. चीन और रूस (दोनों सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं) ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की है. गाजा में इस्राइली हमलों को रोकने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर अमेरिका ने लगातार वीटो किया है. सात अक्तूबर के हमास के आतंकी हमले के जवाब में इस्राइल की कार्रवाई का स्तर बहुत अधिक रहा है, जिसमें 30 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चों एवं महिलाओं समेत अधिकतर नागरिक हैं. न तो गाजा में और न ही यूक्रेन में हमले थमने के आसार हैं. युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं और युद्ध उन्मादियों की आवाज शांति का निवेदन करने वालों से अधिक तेज है. नेता असफल साबित हुए हैं. यह सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, जो पहले से ही मुद्रास्फीति, ठिठके निजी निवेश, उच्च युवा बेरोजगारी और बढ़ती विषमता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भारत में साइबर अपराध का बढ़ता दायरा

सतीश सिंह
साइबर-अपराध संबंधी विषयों के जानकार
singhsatish@sbi.co.in

आजकल साइबर अपराधी कॉल या मैसेज से लोगों को बिना कर्ज लिये ही कर्जदार बताकर वसूली कर रहे हैं. ऐसी ब्लैकमेलिंग छोटी राशि के लिए ज्यादा की जा रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पुलिस में शिकायत नहीं करें. यूजर पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, आज सभी साइबर अपराध के शिकार बन रहे हैं.

अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल में 'विश्व साइबर अपराध सूचकांक' तैयार किया है, जिसके अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है. इस सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया है. ऐसे अपराधों के मामले में रूस शीर्ष पर है और फिर यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया और उत्तर कोरिया हैं. भारत में कई तरह के साइबर अपराध होते हैं. हाल के वर्षों में कॉल फॉरवर्डिंग के जरिये अपराध करने की घटनाओं में तेजी आयी है. कॉल फॉरवर्डिंग एक ऐसा फीचर है, जिसकी मदद से एक कोड डायल कर सेवा शुरू या बंद की जा सकती है. कॉल फॉरवर्डिंग के जरिये स्कैमर कॉल कर उपभोक्ता को कहता है कि हम आपकी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी से बोल रहे हैं. हमने नोटिस किया है कि आपके नंबर पर नेटवर्क की समस्या है. इसे दूर करने के लिए आपको 'स्टार 401 हैशटैग' डायल करना होगा. इसके बाद उपभोक्ता को अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है. जैसे ही उपभोक्ता कॉल करता है, उसके सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें बैंक और क्रेडिट कार्ड से हुए लेन-देन के ओटीपी भी शामिल होते हैं. इनका इस्तेमाल स्कैमर उपभोक्ता के खाते से पैसे निकालने, सोशल मीडिया में एक्सेस करने और नया सिम जारी करवाने में करते हैं. ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने 15 अप्रैल से यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा बंद कर दी है. उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने को कहा है.

विगत वर्षों में डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ साइबर अपराध में तेज वृद्धि हुई है. सोशल मीडिया भी ठगी के साधन बन गये हैं, जहां फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसा किया जा रहा है. गूगल सर्च इंजन पर लोग अपने हर प्रश्न का जवाब ढूंढने लगे हैं. ठग नामचीन भुगतान एप, जैसे- गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि, के नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर सहेज रहे हैं, जिसके कारण लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं. अब तो ब्राउजर एक्सटेंशन के डाउनलोडिंग के जरिये भी साइबर अपराध किये जा रहे हैं. यह काम वायरस के सहारे किया जाता है. सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल एवं लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं. क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिये हुए ऑनलाइन लेन-देन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अमूमन लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसका फायदा साइबर ठगों को मिल जाता है. इसलिए बैंकिंग डिजिटल उत्पादों के उपयोग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. फिशिंग के तहत किसी बड़ी या नामचीन कंपनी या फिर यूजर की कंपनी की फर्जी बेवसाइट बनाकर, जिसका स्वरूप असली बेवसाइट जैसा होता है, उससे लुभावने मेल किये जाते हैं. मोबाइल का चलन बढ़ने के बाद हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये भी ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं, जिसमें संक्रमित लिंक होता है. मैलवेयर कंप्यूटर या मोबाइल या टैब के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ यूजर की वित्तीय जानकारी चुरा लेता है. यह फर्जी ईमेल भी भेज सकता है और इसके जरिये ठगी के साथ-साथ संवेदनशील जानकारी अवांछित लोगों को बेची भी जा सकती है तथा किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की जा सकती है.

आजकल साइबर अपराधी कॉल या मैसेज से लोगों को बिना कर्ज लिये ही कर्जदार बताकर वसूली कर रहे हैं. ऐसी ब्लैकमेलिंग छोटी राशि के लिए ज्यादा की जा रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पुलिस में शिकायत नहीं करें. यूजर पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, आज सभी साइबर अपराध के शिकार बन रहे हैं. बैंक के डिजिटल उत्पाद साइबर अपराध का जरिया बन गये हैं. फिर भी, सजग, सतर्क और जागरूक रहकर डिजिटल उत्पादों से किये जा रहे साइबर अपराध से बचा जा सकता है. अगर लोग ब्राउजिंग सेशन के दौरान सतर्क रहें, वेबसाइट या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करें, अनजान नंबर या ईमेल आईडी से आये अटैचमेंट को तुरंत डिलीट कर दें और ऑनलाइन लॉटरी, कैसीनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की उपेक्षा करें, तो फिशिंग मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये फॉरवर्ड होने वाले संदेहास्पद लिंक के जाल से बचा जा सकता है.

मोबाइल एप से लोन लेना सूदखोर, महाजन, साहूकार से भी ज्यादा खतरनाक है. कई बार लोन रिकवरी एजेंट लोगों से सिर्फ पैसे ही नहीं ठगते हैं, समाज में उन्हें बदनाम भी कर देते हैं. सूदखोर, महाजन, साहूकार मोटे तौर पर गांव व कस्बे तक सीमित थे, पर लोन रिकवरी एजेंट की व्यापकता देश-काल से परे है. अधिकांश मोबाइल चीन में निर्मित हैं और उनका सर्वर भारत से बाहर होता है. इसी कारण अधिकांश रिकवरी एजेंट चीन, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका आदि से ठगी का कारोबार कर रहे हैं. इसलिए पुलिस में शिकायत करने के बावजूद ठगों को पकड़ना आसान नहीं है. यहां सावधानी ही बचाव है. लालच नहीं करें. मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आयें. धमकी मिलने पर पुलिस की मदद लें. निडर बनें, तभी साइबर अपराध का शिकार बनने से बचा जा सकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

देश छोड़ने से पहले विचार करना जरूरी

इस वर्ष की शुरुआत में, कनाडा में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले नेपाली छात्रों की खबरें सुर्खियां बनीं, क्योंकि रहने का खर्च बढ़ने के कारण उनके लिए भोजन और आवास का प्रबंध करना मुश्किल हो चला था. कनाडा द्वारा अपनी वीजा नीतियों को लचीला बनाने के साथ, विशेषकर महामारी के बाद की अवधि में, अपना घर छोड़ने को अधीर छात्रों के लिए यह एक पसंदीदा गंतव्य बन गया. इसमें शैक्षिक परामर्शदाताओं द्वारा छात्रों को कनाडाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के लिए राजी करने और उन्हें स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आसान विकल्पों का लालच देने का भी योगदान रहा. पर जब नेपाली छात्र कनाडा पहुंचे, तो उन्हें अलग वास्तविकता का सामना करना पड़ा, वहां रहने की लागत अधिक थी, और उनके लिए नौकरियां भी नहीं थीं. यह अकेले नेपाली छात्रों की समस्या नहीं थी- हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्र, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल थे, को बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ा. अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अक्सर कनाडाई कॉलेजों में पढ़ने के लिए घरेलू छात्रों की तुलना में तीन गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है. हालांकि उच्च शैक्षिक शुल्क के कारण उन्हें वहां रहने में मुश्किल आती है. कनाडा में नेपाली छात्रों के फंसे होने की समस्या आंशिक रूप से इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि नेपाल सरकार अपने नागरिकों की संरक्षक बनने में विफल रही. देश में अवसरों की कमी ने नेपालियों को स्थायी रूप से बाहर बसने को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है. प्रतीत होता है कि नेपाल सरकार की एकमात्र रुचि विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक नेपालियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र वितरित करने में है, बिना इस बात पर विचार किये कि उनके पास अपनी शैक्षिक शुल्क का भुगतान करने के लिए कोई ठोस योजना है. जब तक सरकार अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की अच्छाई, बुराई के बारे में जागरूकता अभियान नहीं चलाती, नेपाली छात्र ठगे जाते रहेंगे.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

बोधि वृक्ष

सांसों का निवेश

जब हम समझदारी से अपनी सांसों की पूंजी परमेश्वर की ओर निवेश करते हैं, तो हम एक सच्चा निवेश कर रहे हैं, जिसका हमें भविष्य में अद्भुत लाभ मिलेगा. पर यह न जानते हुए कि सांसों की अनमोल पूंजी हमें केवल परमेश्वर को पाने के लिए मिली है, हम उसे बाहर की दुनिया में व्यर्थ गंवा देते हैं. अपनी सांसों की पूंजी को हम दुनिया के सारे कर्तव्य पूरा करते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान देने में भी निवेश करें. यह निवेश एक ऐसी मिठास का अहसास लाता है जो दुनिया की किसी भी वस्तु में नहीं मिल सकती है. यह वह मिठास है जो हमेशा बनी रहती है. प्रभु में अपना समय निवेश करने का मतलब है कि हम अपना ध्यान सही दिशा में केंद्रित कर रहे हैं और अपने समय का उपयोग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब यहां इस दुनिया में आये हैं. जो अपने आपको जानना और परमेश्वर को पाना है. जिसे हम केवल ध्यान-अभ्यास द्वारा ही पा सकते हैं. जैसे ही हम अंतर में ध्यान टिकाते हैं और उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, तब हमारी आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है और प्रभु प्रेम, खुशी व आनंद पा लेती है. जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी. यदि हम आत्मा का वैभव और चमक देखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान-अभ्यास में बिताने से हमें अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है. प्रतिदिन कुछ समय ध्यान-अभ्यास में बैठने से पायेंगे कि हम अपने समय का उपयोग हमेशा आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे हैं. आध्यात्मिक जागृति के साथ प्रभु के लिए हमारा प्रेम गहरा हो जाता है, जिससे हम भीतर से परिवर्तित होते हैं. हम प्रभु के प्रेम से ओत-प्रोत हो जाते हैं, आत्मा पर चढ़े मन-माया और जड़ता के पर्दे हटते हैं. हमारा मन बाहरी दुनिया से हटकर ध्यान-अभ्यास की विधि पर लगना शुरू हो जाता है. आइए! ध्यान-अभ्यास और निरंतर परमात्मा को याद करके अपनी सांसों की पूंजी का समझदारी से निवेश करें. इससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा के पास जाने का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं.

-संत राजिंदर सिंह जी महाराज

कुछ अलग

ऊंटों का संरक्षण जरूरी

सुधीर कुमार
टिप्पणीकार
sudhirphd@bhu.ac.in

संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को 'अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष' घोषित किया है. ऊंट जिस प्रजाति समूह का हिस्सा हैं, उन्हें आमतौर पर कैमलिड्स के नाम से जाना जाता है. कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने में कैमलिड्स की भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा उनके संरक्षण का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है. ऊंट खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के साथ-साथ दुनियाभर के समुदायों के लिए मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखते हैं. ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

ऊंट बहुउद्देशीय पशु है, जिसका उपयोग दूध, मांस, जैविक उर्वरक के उत्पादन में होता है. विभिन्न त्योहारों व पर्यटन की दृष्टि से भी इनका व्यापक महत्व है. रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्रों में सवारी करने और सामान ढोने के लिए परिवहन के साधन के रूप में तथा विभिन्न कृषि कार्यों जैसे जुताई व पानी ढोने या निकालने में ऊंट का प्रयोग किया जाता है. ये ऐसी जलवायविक दशाओं में भी शान से जीते हैं, जहां अन्य जीवों का जीवन यापन मुश्किल होता है. ये अपने कूबड़ में जमा वसा को ऊर्जा में बदल लंबे समय तक बिना भोजन-पानी के जीवित रह सकते हैं. इसी के चलते सीमित पानी और वनस्पति वाले क्षेत्रों में भी ये बहुतायत में पाये जाते हैं. दूसरी खासियत यह है कि ऊंट गर्म और ठंडे दोनों तरह के चरम वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं. ये दुनिया के 90 से अधिक देशों में पाये जाते हैं. बैक्ट्रियन (पीठ पर दो कूबड़ वाले ऊंट), ड्रोमेडरी (एक कूबड़ वाले ऊंट), लामा, अल्पाका, गुआनाको और विकुना, ऊंट के विभिन्न प्रकार हैं. जंगली ऊंट- कैमलस फेरस- को 2008 में आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की 'लाल सूची' में शामिल किया गया था.

भारत में ऊंटों की तादाद लगातार कम हो रही है. देश के लगभग 84 प्रतिशत ऊंट राजस्थान में रहते हैं. उन्नीसवीं पशुधन गणना (2012) की तुलना में 20वीं पशुधन गणना (2019) में ऊंट की कुल आबादी चार लाख से घटकर ढाई लाख रह गयी है. केंद्रीय पशुपालन विभाग के अनुसार ऊंटों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के चलते ऊंट की उपयोगिता, परिवहन के आधुनिक साधनों और सड़क मार्ग के विकास से ऊंट की मांग, चारागाह भूमि तथा ऊंट पालन में कमी आना है. राजस्थान सरकार ने ऊंट को अपना 'राज्य पशु' घोषित किया है और उनके संरक्षण के लिए ठोस कानून बनाये हैं. ऊंटों के संवर्धन और संरक्षण के लिए ठोस प्रयास की दरकार है.

आपके पत्र

बढ़ती सड़क दुर्घटना चिंताजनक

सड़क दुघर्टनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यह समस्या न केवल मनुष्य जीवन को खतरे में डालती है, बल्कि समाज के विकास को भी प्रभावित करती हैं. जो चिंताजनक है. दुर्घटना होने के कारणों में अव्यवस्थित यातायात, रोड डिजाइन का सही न होना, तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, सख्त कार्रवाई का अभाव आदि शामिल हैं. इस समस्या से बचने के लिए हमें सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर होना होगा और सड़कों पर वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी होगी.

गामित दर्शना बेन, रांची

भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन

आज जनसंचार के कई माध्यम उपलब्ध हैं. माना जाता है कि सबका लक्ष्य समाज का कल्याण है. पर सच्चाई इसके उलट है. जनसंचार के एक सशक्त माध्यम विज्ञापन की बात करें, तो जहां एक तरफ यह लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाता है, वहीं भ्रमित भी करता है. यह हमें नये उत्पाद से परिचित भी कराता है, वहीं गुणवत्ता का अभाव होते हुए भी शुद्धता का दावा कर भ्रमित भी करता है. विज्ञापनदाताओं को चाहिए कि वे भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण न करें. लोग भी विज्ञापन पर आंखें मूंदकर विश्वास न करें.

निखिल रस्तोगी, लखनऊ

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 53

मजबूत निगरानी जरूरी

देसी आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। मॉन्डलीज जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वाणिज्य मंत्रालय के एक आदेश के बाद बाजार संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर सभी पेय पदार्थों को 'स्वास्थ्यवर्द्धक पेय' की श्रेणी में रखना बंद कर देना चाहिए। यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) की एक वर्ष तक चली जांच के बाद आया है। आयोग ने मॉन्डलीज के 78 वर्ष पुराने ब्रांड बॉर्नविटा को लेकर यह जांच की थी। यह सलाह तब आई है जब खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से हाल ही में अनुरोध किया था कि वे डेरी, अनाज या माल्ट आधारित पेय पदार्थ को 'स्वास्थ्यवर्द्धक पेय' या 'ऊर्जा बढ़ाने वाले पेय' के रूप में वर्गीकृत न करें। उसने कहा कि ऐसा वर्गीकरण ग्राहकों को भ्रमित करता है। ऐसा दावा करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों को हटाना भी आवश्यक था। ताजा नोटिस शायद अन्य लोकप्रिय पेय पदार्थों पर भी लागू हो जो उपभोक्ताओं को पोषण देने का दावा करते हैं। हालांकि, मुख्य आपत्ति आर्थिक हैः एनसीपीसीआर ने पाया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 'स्वास्थ्यवर्द्धक पेय' की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। यह बात भी शामिल की जानी चाहिए कि इन ब्रांडों ने अपने उत्पाद के पैकेट पर स्वास्थ्यवर्द्धक उत्पाद नहीं लिखा है।

परंतु यह घटना उस बढ़ती चिंता की ओर भी इशारा करती है जो स्वास्थ्यवर्द्धक पेशेवरों के मन में उन तमाम खाद्य और पेय पदार्थों के विज्ञापन को लेकर है जो भारत में बच्चों को लक्षित करते हैं। देसी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह रणनीति अपनाती हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने 'स्वास्थ्यवर्द्धक पेय' को लेकर जो नोटिस जारी किया है उसकी जड़ें एक वर्ष पुराने विवाद से जुड़ी हैं। उस समय पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की समीक्षा करने वाले रेवंत हिम्मतसिंगका नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बॉर्नविटा में बहुत अधिक मात्रा में चीनी होने और उसके बच्चों पर असर होने की बात कही थी। मॉन्डलीज ने उन्हें एक नोटिस भेजकर कहा था कि वह उस वीडियो को डिलीट कर दें। हिम्मतसिंगका के पास एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से लड़ने के लिए संसाधन नहीं थे इसलिए उन्होंने माफी मांग ली। कंपनी ने भी स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि बॉर्नविटा में चीनी की मात्रा दैनिक उपयोग की तय मात्रा से काफी कम है। परंतु वह वीडियो वायरल हो चुका था और एनसीपीसीआर के पास भी इसकी शिकायत पहुंची। उसने कंपनी को निर्देश दिया कि बॉर्नविटा के भ्रामक विज्ञापन, पैकेजिंग और लेबल सभी हटाए जाएं। कंपनी के दावों के उलट एनसीपीसीआर ने कहा कि बॉर्नविटा ने 'माल्टॉडेक्स्ट्रिन' और 'लिक्विड ग्लूकोज' जैसे लेबल का इस्तेमाल करके चीनी की सीमा को कम करके दिखाया। एफएसएसएआई के लेबलिंग और डिस्प्ले नियमन 2020 के मुताबिक इन्हें भी चीनी के लेबल के अंतर्गत ही दिखाया जाना चाहिए था। दिसंबर में कंपनी ने बॉर्नविटा में मिश्रित चीनी की मात्रा को कम कर दिया।

एनसीपीसीआर और वाणिज्य मंत्रालय दोनों के कदम असाधारण हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि उपभोक्ता कल्याण से जुड़े सार्वजनिक संस्थान पहले क्यों नहीं सक्रिय हुए। 'स्वास्थ्यवर्द्धक पेय' की श्रेणी कई वर्षों से चलन में है लेकिन सरकार को कदम उठाने के लिए एक इन्फ्लुएंसर के अभियान का इंतजार करना पड़ा। इसके साथ ही सैकड़ों और इन्फ्लुएंसर बिना नियामकीय जांच परख के संदिग्ध खाद्य और पेय पदार्थों की तारीफ करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पतंजलि आयुर्वेद का जो मामला था वह भी ऐसी ही कमी को उजागर करता है। इसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा लाया गया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। चूंकि वैकल्पिक दवाओं और पैकेट बंद भोजन का बाजार (खासकर बच्चों पर केंद्रित) तेजी से बढ़ रहा है इसलिए उपभोक्ता कल्याण के लिए अधिक मजबूत निगरानी संस्था की जरूरत है।

अजय मोहंती

राजनीतिक कारोबारी चक्र के अलग-अलग मार्ग

राजनीतिक कारोबारी चक्र का विचार चुनाव पूर्व और बाद में नीतिगत स्तर पर एक खास तरह की नीति की परिकल्पना करता है। यह देश की वृहद आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। बता रहे हैं अजय शाह

चुनावी साल में वृहद आर्थिकी को लेकर हमारे विचार किस तरह बदलते हैं? सार्वजनिक चयन सिद्धांत कहता है कि राज्य लोगों से मिलकर बनता है और उनके हितों को अधिकतम तौर पर पूरा करने का प्रयास करता है। चुनाव राजनेताओं के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। 'राजनीतिक कारोबारी चक्र' का विचार चुनाव के पहले और बाद में एक खास तरह की नीति की परिकल्पना करता है और वृहद अर्थव्यवस्था को लेकर विशिष्ट भावनाओं को जन्म देता है। इस अवधारणा को समझने की हमारी क्षमता आर्थिक हालात और घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करती है।

वृहद अर्थव्यवस्था, राजकोषीय और मौद्रिक नीति राजनीतिक कारोबारी चक्र के बारे में विचार के प्रारंभिक बिंदु हैं। विकसित देशों में इस प्रकृति के रुझान को देखा जा चुका है। पुराने दिनों में केंद्रीय बैंक चुनाव के पहले दरों में कटौती करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मतदाताओं को आर्थिक गतिविधियों में मामूली तेजी लाकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऐसे में मुद्रास्फीति में उभार आने में थोड़ा वक्त लगता था। इसी प्रकार चुनाव के पहले व्यय बढ़ाने को लेकर भी तमाम प्रोत्साहन हैं।

ऐसे व्यवहार से जुड़े अवसर बाजार तथा संस्थागत विकास के द्वारा सीमित होते हैं। विकसित देशों में सरकारों को यह डर होता है कि कहीं उन्हें बॉन्ड बाजार की नाराजगी न झेलनी पड़े। भारी घाटे की स्थिति में उच्च ब्याज दर के रूप में तत्काल दंड सामने आता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसा करके ऐसे व्यवहार के प्रति आकर्षण को रोका जाता है। मौद्रिक नीति की बात करें तो राजनीतिक कारोबारी चक्र की दलील के साथ पुरानी शैली की मौद्रिक नीति का अंत किया गया जहां केंद्रीय बैंकिंग का एक रहस्य था और वहां के कर्मचारियों के पास विवेकाधीन शक्तियां थीं। जब तक समुचित मौद्रिक नीति के साथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाया जा रहा है तब तक इस चिंता को संबोधित किया जा सकता है। विकासशील देशों में यह अलग ढंग से होता है। संस्थागत गुणवत्ता के कमजोर होने के कारण इस बात का खतरा अधिक होता है कि आर्थिक नीति संबंधी निर्णय दोबारा सरकार में आने की बात को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। परंतु एक अलग किस्म की बाधाएं भी हैं। वित्तीय तंगी के हालात में राजकोषीय नीति इस बात पर विचार नहीं करती कि बॉन्ड बाजार क्या सोचता है। परंतु अच्छे या बुरे दिनों में राजकोषीय नीति में छेड़छाड़ की बहुत कम गुंजाइश है। महामारी के समय विकसित देश बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रतिक्रिया दे सके क्योंकि उनके पास वित्तीय लचीलापन था। राजकोषीय नीति की रणनीति की दिक्कत को देखते हुए विकासशील देशों के पास इस क्षेत्र में सीमित लचीलापन होता है। फिर चाहे महामारी हो या चुनाव।

अधिकांश देशों के पास अब मुद्रास्फीति को लक्षित करने का औपचारिक तरीका है लेकिन कई विकासशील देशों में यह संस्थागत व्यवस्था अभी तक अच्छी तरह स्थापित नहीं है और केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों के पास कुछ शक्ति है ताकि वे चुनावी लक्ष्यों पर विचार कर सकें। वे सत्ताधारी दल की मदद के चार तरीकों के बीच उलझे हैं। क्या मुद्रास्फीति को लक्षित करके विदेशी निवेशकों को स्थिर रखना सबसे बेहतर है? या महंगाई कम करके मतदाताओं को प्रभावित करना बेहतर है? क्या ब्याज दरों को कम रखना और कमजोर विनिमय दर की मदद से निर्यात की मांग को बढ़ावा देना उचित होगा? या फिर उच्च ब्याज दरें और उच्च विनिमय दर बेहतर होगी? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।

अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में जब करीब 1,000 कर्मचारियों वाली परियोजना शुरू होती है तो यह विस्तारवादी होती है और जब परियोजना पूरी होती है तो इन 1,000 कर्मचारियों का रोजगार चला जाता है। सामान्य तौर पर परियोजना निर्माण का आरंभ और अंत कोई निश्चित घटना नहीं हैं। अक्सर ही कोई न कोई परियोजना पूरी होती रहती है और नई परियोजना शुरू होती रहती है। इसका अर्थव्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय असर दिखाई नहीं देता।

परियोजना के पूरा होने के राजनीतिक कारोबारी चक्र की संभावना पर विचार कीजिए। मान लीजिए कई परियोजनाएं चुनाव से एक वर्ष पहले पूरी हो जाती हैं। इस मामले में परियोजनाओं के पूरा होने के कारण बड़ी तादाद में निर्माण श्रमिकों की आजीविका छिन जाती है। इससे आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है।

यदि ऐसा व्यवहार मौजूद है तो यह एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिसकी मदद से राजनीतिक कारोबारी चक्र का उदय हो सकता है। यदि ऐसी बात है तो चुनावी साल तथा उसके बाद वाला वर्ष मांग के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा क्योंकि कई परियोजनाएं पूरी होंगी।

राजनीतिक कारोबारी चक्र का दूसरा मार्ग आर्थिक नीति की अनिश्चितता में निहित हो सकता है। ऐसे कई उद्योग हैं जहां सरकार का समर्थन कारोबारी योजना या निवेश के लिए अहम है। सत्ताधारी प्रतिष्ठान में बदलाव, कैबिनेट मंत्रियों का बदलना या वरिष्ठ अधिकारियों का बदलना नीतिगत परिवर्तन ला सकता है या फिर निजी व्यक्तियों के साथ व्यवहार में बदलाव आ सकता है। यदि कई कंपनियों या उद्योगों को लगता है कि उनके सामने ऐसा जोखिम है तो वे चुनाव के पहले की अवधि में निवेश को लेकर धीमा रुख रखेंगे। बागो और अल्ताफ का 2022 का शोध 2009, 2014 और 2019 के लोक सभा चुनाव के हवाले से इसे सही ठहराता है। परियोजनों के पूरा होने और कंपनियों के ऊपर पड़ने वाला असर पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है लेकिन अगर यह 10 से 20 फीसदी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है तो इससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। ये सीधे प्रभाव कई स्तरों पर असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर रोजगार गंवाने वाले श्रमिक कम कपड़े खरीदते हैं।

मुख्य धारा का आर्थिक साहित्य मौद्रिक और राजकोषीय नीति पर जोर देता है। वर्तमान साहित्य में राजनीतिक कारोबारी चक्र को लेकर कुछ दिलचस्प विचार शामिल हैं। उदाहरण के लिए कर्ज माफी। इस आलेख में हमें आश्चर्य है कि राजनीतिक अनिश्चितता का पुराना विचार और परियोजना क्रियान्वयन का नया विचार मायने रखता है। ये दोनों ही विचार वृहद आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं। इन्हें समझना और उपयुक्त कदम उठाना 2024 में भारत की वृहद अर्थव्यवस्था को लेकर विचार बनाने में हमारी मदद करेगा।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

जलवायु परिवर्तन पर न्यायिक सक्रियता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया जिससे यह चेतावनी मिल रही है कि इस साल अच्छी गर्मियां पड़ने वाली हैं। ऐसे में दो न्यायिक फैसले जलवायु परिवर्तन को लेकर नया दृष्टिकोण देते हैं।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च के एक आदेश का विस्तृत निर्णय अपलोड कर दिया है। इसमें पहली बार जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से बचाव को एक विशिष्ट अधिकार बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 14 तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 इस अधिकार का अहम स्रोत हैं।

यहां से करीब 6,000 किलोमीटर दूर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने 2,000 से अधिक स्विस महिलाओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर निर्णय दिया। ये सभी महिलाएं वरिष्ठ नागरिक थीं। यह फैसला जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकार से जोड़ने के मामले में एक वैश्विक नजीर पेश करता हुआ प्रतीत होता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि स्विस सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है और इस प्रकार उसने अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किया है। जलवायु से जुड़े कदमों को लेकर दिए गए इस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।

दोनों निर्णयों में समानता नजर आती है लेकिन यह समानता सतही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक वाणिज्यिक पहलू का समाधान करता है। यह मामला राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (एक विशालकाय पक्षी जिसे जीआईबी कहा जाता है) के संरक्षण और सौर ऊर्जा डेवलपरों के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अधिकार से संबंधित था। ताजा निर्णय जीवाश्म ईंधन के बजाय लोगों के स्वच्छ ऊर्जा के अधिकार को रेखांकित करता है और सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के एक निर्णय को पलटता है जिसमें कहा गया था कि सभी ओवरहेड (ऊपर से गुजरने वाली) ज्यादा और कम वोल्टेज वाली बिजली की लाइनों को भूमिगत किया जाए ताकि उस क्षेत्र में उड़ने वाले जीआईबी प्रभावित न हों।

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। वास्तविकता यह है कि बिजली की लाइन को जमीन के नीचे से ले जाने से सौर डेवलपरों की लागत बढ़ जाती। गत वर्ष विशेषज्ञ समिति ने कहा कि डेवलपरों को इन पक्षियों की बसाहट वाले इलाकों में चिड़ियों को भगाने वाले या एलईडी आधारित चेतावनी वाली डिस्क लगानी चाहिए। यद्यपि यह कम लागत वाला उपाय है लेकिन इनकी स्थापना के लिए मंजूरी हासिल करने में दिक्कत हो सकती है और इन उपकरणों के लिए सक्षम विक्रेताओं की भी कमी हो सकती है। गत वर्ष नवंबर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक आवेदन किया कि सौर ऊर्जा की लाइन को अनिवार्य तौर पर भूमिगत करने की व्यवस्था से देश का कार्बन उत्सर्जन प्रभावित होगा।

इस तर्क में दम है लेकिन उन पक्षियों का क्या जो एक संरक्षित प्रजाति से हैं? यह कहा जा सकता है कि चूंकि खुले वनों में केवल 200 जीआईबी बचे हैं इसलिए उन्हें संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। परंतु कल्पना कीजिए कि अगर प्रोजेक्ट टाइगर के पहले जब केवल 2,000 बाघ बचे थे, तब भी यही दलील दी जाती तो क्या होता? यहां अगर वैश्विक तापवृद्धि का व्यापक प्रश्न सामने रखें तो किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है और इसके ऐसे नुकसानदेह परिणाम हो सकते हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के मामले इसलिए बढ़े कि छिपकलियों और चिड़ियों की आबादी कम होने से मच्छर बढ़े जिन्हें वे खाती हैं। इसकी वजह से हमें अधिक नुकसानदेह रासायनिक पदार्थों की मदद से मच्छर भगाने पड़ते हैं। इससे वैश्विक ताप बजट में भी इजाफा होता है।

पर्यावरण से जुड़ा कोई भी उपाय अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है लेकिन सरकार जोखिम को संतुलित कर सकती है। हम प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं लेकिन इसके कारण आबादी का जो विस्थापन हुआ उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ वन्य जीव अभयारण्य मसलन कान्हा और कॉर्बेट में जमीन गंवाने वाले स्थानीय लोगों को गाइड या ट्रैकर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। सौर ऊर्जा डेवलपरों की दुविधा से कोई नया हल निकाला जा सकता था जहां सरकार व्यय में साझेदारी करती और स्वच्छ ऊर्जा तथा पक्षियों के संरक्षण के रूप में दोनों काम हो जाते।

प्रश्न यह है कि सबसे बड़ी अदालत का ताजा निर्णय जो संवैधानिक मूल्यों के साथ विकास के मुद्दे को रेखांकित करता है, वह जलवायु न्याय तक नागरिकों की पहुंच में कितना इजाफा करेगा? यह निर्णय 1980 के दशक के न्यायशास्त्र पर आधारित है। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार का प्रसिद्ध मामला भी इसका हिस्सा है जिसके तहत कहा गया था कि प्रदूषण रहित माहौल में जीवन बिताना अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हिस्सा है। इसके बावजूद भारत के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में प्रमुखता से नजर आते हैं। यह निर्णय ये सवाल भी खड़ा करता है कि सरकार बढ़ती गर्मी और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाली बाढ़ से होने वाली मौतों को कैसे रोकेगी। यह वैश्विक तापवृद्धि का सबसे अहम संकेत है।

ग्लेशियरों का पिघलना ही वह वजह थी जिससे स्विस महिलाओं के समूह ने मानवाधिकार न्यायालय का रुख किया था। उनका कहना था कि स्विस सरकार ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में कामयाब नहीं रही। वहां की सरकार ने कहा था कि वह 2030 तक उत्सर्जन को 1990 के स्तर के 50 फीसदी तक कम करेगी लेकिन जनमतसंग्रह करके कड़े उपायों को नकार दिया गया। यह मामला गत गर्मियों में लगे जलवायु लॉकडाउन की वजह से अदालत में गया क्योंकि इससे कई बुजुर्ग महिलाओं को घरों में कैद रहना पड़ा।

इस फैसले का वास्तविक असर स्पष्ट नहीं है। कुछ टीकाकारों का मानना है कि इसके बाद राष्ट्रीय अदालतों में वाद और वित्तीय जुर्माना लग सकता है। इसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पेरू और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। नॉर्वे में तेल और गैस खनन अधिकारों को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। दिलचस्प बात है कि स्ट्रासबर्ग की अदालत ने छह पुर्तगाली युवाओं द्वारा 32 यूरोपीय सरकारों के खिलाफ लाए गए मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारों का कार्बन उत्सर्जन देशों की सीमाओं के परे लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन इसके चलते कई जगहों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायालय सही हो सकता है लेकिन युवाओं ने मुद्दे की सही पहचान की। जलवायु परिवर्तन संबंधी कदम केवल किसी एक देश की चिंता का विषय नहीं हो सकते, इनके लिए वैश्विक सहयोग और कदमों की जरूरत है। जैसा कि ये फैसले बताते हैं जलवायु परिवर्तन के मामले में कीमत युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, बेजुबानों और जीव-जंतुओं को चुकानी पड़ रही है।

आपका पक्ष

ग्रामोदय से ही बदलेगा भारत

देश के विकास में ग्रामों के विकास की भागीदारी की संकल्पना, वास्तविक और सच्चाई से युक्त जमीनी हकीकत है। गांवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना करना, देश तथा समाज को झूठी दिलासा दिलाना है। ग्रामोदय से ही भारत के विकास की यात्रा तय होगी। देश का चहुंमुखी विकास तभी संभव हो सकेगा जब गांव में सड़क, बिजली, पानी, संचार साधन, अस्पताल, हर घर में शौचालय, अच्छे स्कूल और बाजार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। लोग अपनी माटी में रहकर अपनी रोजी-रोटी कमाकर अपने बच्चों का लालन-पालन करते हुए खुद की विकास-गाथा स्वयं लिख सकेंगे। इस हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ग्रामीणजनों की जरूरत के हिसाब से विकास संबंधी योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करने की जरूरत है। अगर ग्रामवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो गए तो समझें गांव का समुचित विकास हो गया और तभी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो पाएगा। देश के नीति निर्माताओं को भी यह देखना होगा कि गांवों और शहरों के विकास की गहरी खाई के अंतर को कैसे कम किया जाए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

देश का चहुंमुखी विकास तभी संभव हो सकेगा जब गांव में सड़क, बिजली, पानी, संचार साधन, अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों

सशक्त केंद्र सरकार से ही विकास और समृद्धि संभव

लेख 'प्रभावी प्रदर्शन के लिए जरूरी नहीं मजबूत केंद्रीकृत शासन' भारत के परिप्रेक्ष्य में विदेशी शासन व्यवस्थाओं पर गंभीर चर्चा करता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक, साम्यवादी, समाजवादी अथवा तानाशाही से शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनकी सफलताओं और विफलताओं के साथ जनमानस की आर्थिक असमानताओं, क्षेत्रीय और शैक्षिक असमानताओं, वैश्विक व्यापार, मानवाधिकारों, श्रमिकों के वेतन और कल्याण, कर और राजस्व एवं प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाओं, कॉरपोरेट कानूनों की वैश्विक स्तर पर अनुकूलता पर भी विचार करना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के जो शोधकर्ता देश के शासन और आर्थिक तंत्र से संबंध नहीं रखते और केवल आंकड़ों के विश्लेषणों से सिद्धांतों और सुझावों से अर्थव्यवस्था चलाना चाहते हैं, संभवतः उनके निर्णय और समाधान अधूरे और असामयिक होते हैं। सौभाग्य से भारत में पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहुत योग्य अर्थशास्त्री हैं जिनके मार्गदर्शन में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार समृद्धि की ओर अग्रसर हुई है। हमारे राष्ट्र, संस्कृति, लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था का आधार ही समृद्धि और संसाधनों की प्रचुरता है। गरीबी तो विदेशी आक्रांताओं के एक हजार वर्षों के भारत पर शासन और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करने और शोषण से हमें विरासत में मिली है। भारत की अर्थव्यवस्था में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है क्योंकि सभी बड़े निर्णय जैसे राजस्व संग्रह, मौद्रिक नीति, देश की सुरक्षा आदि केंद्र के नियंत्रण में हैं। अतः देश में मजबूत और दूरगामी निर्णय लेने में सक्षम केंद्र सरकार चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

संयुक्त अरब अमीरात में मंगलवार को आई भीषण बाढ़ के कारण दुबई की सड़कों पर वाहन डूब गए। बाढ़ के कारण हवाई अड्डों से विमानों का परिचालन भी बाधित हुआ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 18 अप्रैल 2024

माओवादियों को झटका

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को माओवादियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी सामान्य नहीं है। मारे जाने वाले माओवादियों की बड़ी संख्या इसका सिर्फ एक पहलू है। जिस तरह से सुरक्षा बलों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना हासिल की, अलग-अलग सूत्रों से उसकी पुष्टि कराई, जिस तरह से ऑपरेशन की योजना तैयार की, जिस कुशलता से उसे अंजाम दिया और इस दौरान केंद्र से लेकर राज्य और जिला स्तर तक जिस तालमेल के साथ उस टीम को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं- वह सब गौर करने लायक है।

सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई

सबसे बड़ा अभियान | स्थानीय प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि बस्तर संभाग में यह माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। इस पूरे क्षेत्र के नजरिए से देखा जाए तो भी यह हाल के वर्षों के बड़े अभियानों में आता है। लेकिन इसकी अहमियत इस मामले में भी है कि कई ऐसे नाम एक साथ पुलिस कार्रवाई की जद में आ गए जो इस क्षेत्र में माओवादी अभियानों की अगुआई करने के लिए जाने जाते रहे थे। इस लिहाज से यह सुरक्षा बलों की ओर से इस क्षेत्र में वामपंथी अतिवाद को दिया गया एक जोरदार झटका है।

बरसों की तैयारी | फिर भी इस उपलब्धि को प्रशासन की तात्कालिक तैयारियों का ही नतीजा नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कई वर्षों से किए जा रहे प्रयासों की भी भूमिका है। इस बीच न केवल माओवाद प्रभावित कई दुर्गम इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है बल्कि खास तौर पर पिछले पांच-सात वर्षों में सुदूर इलाकों में पुलिस कैंप लगाए गए हैं। यह अहम साबित हुआ है। इससे सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को मौके पर पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ती। लिहाजा वे जल्दी पहुंच जाती हैं और माओवादियों को तैयारी करने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता।

बढ़ी हुई आक्रामकता | इस संदर्भ में ध्यान देने लायक बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक हुआ है। यह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या से भी स्पष्ट होता है। साल 2024 के इन साढ़े तीन महीनों में ही छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथों 79 माओवादी मारे जा चुके हैं जबकि 2023 में पूरे साल के दौरान यह संख्या महज 22 थी।

कमर टूटी | पहले भी माओवादियों के खिलाफ बड़े अभियान हुए हैं। लेकिन एक बड़ा फर्क यह दिखता है कि माओवादियों की तरफ से वैसी जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही जैसी पहले हुआ करती थी। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि माओवादियों की कमर टूट चुकी है। अगर सच है तो भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वह दोबारा मजबूती न हासिल कर ले। और, इसके लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई काफी नहीं है। इसके साथ-साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच भी बढ़ानी होगी।

साड्डी दिल्ली

नज़रें नॉर्थ-ईस्ट पर

विवेक शुक्ला

दो दिन पहले आर. जेम्स कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में अपने नॉर्थ-ईस्ट (NE) के दोस्तों से गपशप के लिए जा रहे थे। मिलने की वजह महत्वपूर्ण थी। उन्हें चर्चा करनी थी NE में 19 और 26 अप्रैल फिर 9 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों पर। अपने घर से हजारों मील दूर रहने पर भी अपने राज्य के चुनावी माहौल में दिलचस्पी तो रहती ही है। पेशे से सिविल इंजीनियर जेम्स कहते हैं, अब दिल्ली-NCR अपना लगता है। मैं यहीं 25 मई को अपना वोट डालूंगा। हमारे साथ नस्लीय हिंसा और भेदभाव की घटनाएं अब गुजरे दौर की बातें हो चुकी हैं। जेम्स की टिप्पणी से भरोसा जगता है, मगर अरुणाचल के नौजवान निडो तानिया के साथ जो हुआ था, वह भी तो भुलाया नहीं जाता। 2014 में लाजपत नगर में नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई थी।

टी. वांगमू नोरबू दार्जिलिंग से हैं। कहती हैं- दिल्ली पुलिस ने NE, दार्जिलिंग और लद्दाख के नागरिकों से जुड़े मसलों को देखने के लिए अलग यूनिट बनाकर ठोस पहल की थी। इसका नानकपुरा में दफ्तर है। इसमें सब अधिकारी और स्टाफ NE से हैं। पर्वतारोही वांगमू नोरबू को अब रात को किसी पार्टी से अपने वसंत कुंज वाले घर वापस आते डर नहीं लगता। वजह दिल्ली पुलिस का पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर अब अधिक सेंसिटिव होना है। खैर, इस यूनिट के कामकाज को खुद गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में NDA की सरकार बनी, तब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य एम.पी. बेजबरुआ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति का एक सुझाव यह भी था कि दिल्ली पुलिस में एक डेडिकेटिड यूनिट NE के नागरिकों के मसलों को सुलझाने के लिए बने। सरकार ने इस सिफारिश को माना और इससे दिल्ली पुलिस का समावेशी चेहरा सामने आया। आज दिल्ली पुलिस में NE के सैकड़ों महिला-पुरुष काम कर रहे हैं।

बहरहाल, चुनावी सरगर्मियों के बीच राजधानी में कोविड के कारण 2020 से स्थगित NE फुटबॉल चैंपियनशिप को फिर से शुरू करने की मांग हो रही है। उसमें यहां बसे हुए NE के खेल प्रेमी आंबेडकर स्टेडियम में भारी तादाद में पहुंचते थे। इसे 2007 में नगा सोसायटी ने शुरू किया था। इस बीच, बीते बीसेक सालों से यहां पत्रकारिता पढ़ा रहीं मनपाह कोनियक कहती हैं कि हम अपने राज्यों से हिंदी पढ़कर आते हैं। इसलिए हमें यहां सेटल होने में दिक्कत नहीं होती। उनके गृह राज्य में भी 19 अप्रैल को मतदान है। जाहिर है, वह भी नगालैंड में मतदान पर नजर रखेंगी। राजधानी में रहने वाले नगालैंड के ईसाई नागरिक आर.के.पुरम की एक चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं। हालांकि NE के ईसाई भी अलग-अलग जनजातियों से आते हैं। इसलिए वे एक धर्म से होते हुए भी कई स्तरों पर बहुत अलग हैं, मनपाह कोनियक बताती हैं। यही अनेकता में एकता तो भारत की ताकत है।

एकदा

गांधीजी का आत्मबल

घटना जून, 1935 की है। एक दिन सेवाग्राम में कुछ घुमक्कड़ पहलवान आ पहुंचे और गांधीजी से कसरत के अपने दो-चार खेल दिखाने का आग्रह करने लगे। गांधीजी ने कहा, 'एक तो मेरे पास समय नहीं है, दूसरे जो चीज देश के काम नहीं आती, उसे देखने में मेरा मन नहीं लगता। फिर तुम्हें इनाम चाहिए होगा, वह मैं कहां से दूंगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है।' लेकिन पहलवानों ने गांधीजी की एक बात नहीं मानी और अपने करतब दिखाने लगे। उन्होंने एक मुक्के में पत्थर को तोड़कर दिखा दिया। वे पहलवान रुपये इकट्ठा कर जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता जाना चाहते थे।

Subrata Dhar

गांधीजी बोले, 'मैं तो तुम्हें लाचार नहीं मानता। तुम्हारे शरीर में तो इतना अधिक बल है कि एक मुक्का मारकर पत्थर तोड़ सकते हो। यदि मैं ऐसा करना चाहूं तो मेरा तो हाथ ही टूट जाए।' गांधीजी की बात सुनकर उनमें से एक बोला, 'पर आपके पास तो एक दूसरा ही उच्च प्रकार का बल है।' गांधीजी ने कहा, 'वह बल तो तुम्हारे अंदर भी है।' पहलवान बोले, 'जी नहीं। हमारे अंदर वह बल होता तो हम आज गांव-गांव भीख मांगते न फिरते।' उनकी बातें सुनकर गांधीजी ने कहा, 'वह बल जितना मेरे पास है, उतना ही तुम्हारे पास भी है। अंतर केवल इतना है कि वह आत्मबल तुम्हारे अंदर सो रहा है और मेरे अंदर जागृत है। जब मैंने उसको विकसित किया है, तो हर व्यक्ति उसको विकसित कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति पहलवान नहीं बन सकता। तुम अपने शरीर के बल को सेवा के लिए प्रयोग कर अपना आत्मबल जागृत कर सकते हो। इससे धीरे-धीरे तुम अपनी आजीविका भी चला सकते हो।' गांधीजी की बातें पहलवानों की समझ में आ गईं। वे बोले, 'बापू, आपने आज हमें सही राह दिखाकर हमारा जीवन सफल बना दिया है।'

संकलन : रेनू सैनी

इस्राइल अलग-थलग पड़ता जा रहा था, अब सहयोगी देशों के साथ वह नई पहलकदमी कर सकता है

Israel

ईरान के हमले ने नेतन्याहू को दिया मौका

Netanyahu

हर्ष वी. पंत

मध्य पूर्व एक बार फिर अनिश्चितता से जूझ रहा है। यहां सर्वव्यापी युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। कम ही देश है, जो इसे रोकने के ठोस उपाय करने की स्थिति में हैं। एकमात्र बड़ी ताकत अमेरिका ही है, जो अभी जमीन पर बिगड़ते हालात को कुछ हद तक संभाल सकता है। लेकिन वह भी असमंजस में दिख रहा है।

अमेरिका का रुख | अमेरिका ने अपने सहयोगी इस्राइल का साथ देने की घोषणा की है, लेकिन वह उन शक्तियों को भी आश्वस्त कर रहा है, जो क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ने देना चाहते। मध्य पूर्व की राजनीति हालांकि कभी भी कमजोर दिल वालों के अनुकूल नहीं रही है। लेकिन आज की तारीख में जब वैश्विक अस्थिरता चरम पर है, तो इन देशों के आपसी मतभेद अभूतपूर्व रूप में बाहर आने को तैयार हैं।

बदले की धमकी | मध्य पूर्व में हालिया दौर की अस्थिरता की पृष्ठभूमि तब तैयार हुई, जब दो हफ्ते पहले इस्राइल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास परिसर पर हमला किया। उसमें ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के दो सीनियर कमांडर और उनके सहयोगी मारे गए। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसका बदला लिया जाएगा।

ईरान का शक्ति प्रदर्शन | लंबे समय तक इस्राइल का ध्यान ईरान की ओर से छद्मयुद्ध (प्रॉक्सी वॉर) लड़ रहे समूहों पर ही लगा हुआ था। वह ईरान को निशाना बनाए बगैर हिज्बुल्लाह जैसे संगठनों पर अंकुश लगाने की कोशिश करता रहा। हाल के गाजा संकट के दौरान भी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्राइल पर निशाना साधते रहे हैं। मगर दूतावास पर हमले के बाद पिछले हफ्ते ईरान ने अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन करते हुए इस्राइल पर लगभग 300 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि इस्राइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन की मदद से तकरीबन उन सबको नाकाम कर दिया। इसमें इस्राइल का तीन स्तरीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम अहम साबित हुआ।

हमले से बदले हालात
- इस्राइल ने अटैक को नाकाम किया
- अब नजरें इस्राइल के जवाब पर टिकीं
- सबकी सहानुभूति इस्राइल के साथ

इस्राइल की दुविधा | इस्राइल के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान को अपनी शक्ति का अहसास कैसे कराए। खासकर उस स्थिति में जब ईरानी हमले से निपटने में सहयोग देने वाले उसके तमाम मित्र राष्ट्र उससे संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। बाइडन प्रशासन ने इस्राइल को दो टूक बता दिया है कि अमेरिका, ईरान के विरुद्ध किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल नहीं होने वाला।

ब्रिटेन, फ्रांस का रुख | ब्रिटेन तनाव कम करने के उपायों पर जरूर सहयोगी देशों के साथ सक्रिय है, लेकिन उसकी भी कोशिश यही है कि इन उपायों से युद्धविराम हो और गाजा में राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी तनाव कम करने की जरूरत बताने वालों के सुर में सुर मिलाया है।

AI Image

क्षेत्रीय ताकतों की चाहत | इस पूरे प्रकरण में जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय ताकतों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से इस्राइल की मदद की है। अब वे चाहेंगे कि तेल अवीव उनके हितों का भी ध्यान रखे।

इस्राइल पर दबाव | इस बीच, बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार पर समर्थकों की ओर से दबाव बढ़ रहा है कि वह ईरान को जवाब दे। इस्राइल का कहना है कि ईरान से संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर ईरान धमकी दे रहा है कि अगर इस्राइल ने बदला लेने की कोशिश की तो उसे और कड़ा जवाब दिया जाएगा।

ईरान का संदेश | इस्राइल पर हमले के बाद ईरान ने तेजी दिखाते हुए यह संदेश दिया कि उसकी कार्रवाई बेहद कारगर और कामयाब रही है। इसलिए अब इस समय कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ईरान के सैन्य प्रमुख ने कहा, 'अल्लाह का शुक्र है, हम इस मिशन को कारगर ढंग से अंजाम देने में कामयाब रहे। जो कुछ हम हासिल करना चाहते थे, कर चुके हैं। इसलिए अब इसे और आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं समझते।' दूसरी ओर, इस्राइल कह रहा है कि वह इस सबकी कीमत जरूर वसूलेगा, लेकिन इसका समय और स्थान दोनों अपनी मर्जी से तय करेगा।

असुरक्षा बोध | पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की अगुआई में हुए हमले के बाद असुरक्षा की भावना से जूझता इस्राइल नेतन्याहू के निष्प्रभावी नेतृत्व में चलता हुआ कहीं पहुंचता नहीं दिख रहा था। नेतन्याहू किसी भी रूप में इस्राइली नागरिकों के मन में घर कर चुके असुरक्षा बोध को दूर नहीं कर पा रहे थे।

अंतहीन युद्ध | गाजा की लड़ाई का कोई अंत तो नहीं ही दिख रहा, इस्राइल दुनिया में अलग-थलग भी पड़ता जा रहा था। ऐसे में देखा जाए तो ईरानी हमले ने उसे एक मौका मुहैया कराया है। इससे निपटने में मिली कामयाबी का इस्तेमाल करते हुए इस्राइल अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ सही तालमेल बिठाकर इस क्षेत्र में नए समीकरण को आकार देने की कोशिश कर सकता है।

भारत की अपील | हालांकि दुनिया इस बीच दम साधे इस बात का इंतजार कर रही है कि मध्य पूर्व में चल रहे खतरनाक खेल में अगली चाल क्या होने वाली है। इस्राइल से संबंधित व्यापारिक जहाज MSC एरीज में फंसे 17 नागरिकों के कारण भारत भी इस प्रकरण के लपेटे में आ गया है। इस जहाज को पिछले हफ्ते ईरान ने कब्जे में लिया था। भारत ने 'तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति की राह पर वापस लौटने' की अपील की है। लेकिन अनिश्चितता और अस्थिरता से ग्रस्त इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में संभावित नुकसान को कम करने के लिए भारतीय कूटनीति को अपने पूरे रंग में आना पड़ेगा।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

चुनाव में कायदे से क्यों नहीं होती शिक्षा की बात

रामानन्द

आम चुनाव 2024 के लिए लगभग सभी पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र आ गए हैं। कोई महंगाई का मुद्दा उठा रहा है तो कोई बेरोजगारी का और कोई भ्रष्टाचार का। शिक्षा एक ऐसा विषय है, जो हर व्यक्ति से संबंधित है। आज हर व्यक्ति अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छी से शिक्षा चाहता है। शिक्षा को लेकर आम जनमानस में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। मगर शिक्षा का यह महत्व चुनावी घोषणापत्रों में उस प्रकार से नहीं दिखता, जिस तरह से बाकी चुनावी मुद्दे दिखते हैं।

वोटरों की समझ | 2014 आम चुनाव में BJP ने शिक्षा पर कुछ चर्चा की थी। 2019 आम चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। मगर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में जिन उपलब्धियों पर बात की थी, उन पर BJP और कांग्रेस दोनों ने न केवल सवाल खड़े किए, बल्कि अपने विकल्प की योजना भी प्रस्तुत की। इस चुनाव में अभी तक शिक्षा को उतनी प्रमुखता नहीं मिली है। इसका कारण कहीं न कहीं मतदाताओं की आकांक्षाओं को समझने में राजनीतिक दलों की नाकामी भी है।

घोषणापत्र की बात | अभी तक कांग्रेस, BJP सहित लगभग सभी पार्टियों के घोषणापत्र आ चुके हैं। BJP के घोषणापत्र में राष्ट्रीय शिक्षा में सुधारों को और वृहद स्तर पर लागू करने की बात है। BJP के मेनिफेस्टो में 'गुणवत्ता शिक्षा' के नाम से शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा है। कांग्रेस के घोषणापत्र में शिक्षा से जुड़े तमाम विषयों को उठाने की बात कही गई है। दोनों पार्टियों के घोषणापत्र से एक बात साफ है कि उन्होंने शिक्षा को एक समान स्थान दिया है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक पार्टियां शिक्षा के मुद्दों से अपने को सार्वजनिक रूप से जोड़कर देखना चाहती हैं, मगर शिक्षा से जुड़े विषयों पर वैसा विमर्श नहीं करती हैं, जैसा वे बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर करती हैं।

कोई आगे, कोई पीछे | शिक्षा का विषय है भी काफी जटिल। जैसे, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसकी व्यवस्था का जिम्मा राज्य और केंद्र दोनों के पास है। यही कारण है कि शिक्षा पर नीतियां बनाते समय अनेक विरोधाभासों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस बार के BJP और कांग्रेस के घोषणापत्रों को ही देख लीजिए। BJP राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करके इसके लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर देती है, तो कांग्रेस इस पर पुनर्विचार और संशोधन की बात करती है।

AI Image

कॉमन रूम

विदेश पलायन | गौर से देखें तो शिक्षा के कारण ही समाज में बहुत सारे मुद्दे पनपते हैं, जो आगे जाकर चुनावी/सामाजिक मुद्दे बनते हैं। इस स्थिति में राजनीतिक पार्टियों को शिक्षा पर न केवल ज्यादा बात करनी चाहिए, बल्कि मतदाताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। यह विडंबना है कि भारत से लगभग 20 लाख छात्र शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं, जिनके साथ करोड़ों रुपये भी जा रहे हैं, मगर यहां शिक्षा एक मुख्य राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

सवाल का डर | राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर उन्हीं मुद्दों को प्रमुखता देती है, जो तात्कालिक हो या तुरंत व्यक्ति के मनोभावों को प्रभावित करते हों। इन पार्टियों को लगता है कि रेवड़ी बांटकर चुनाव जीतना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि मतदाताओं को शिक्षित और सशक्त बनाया जाए। एक शिक्षित और सशक्त मतदाता, रेवड़ी के लिए वित्तीय प्रावधानों और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में पूछेगा, जबकि शिक्षा के अभाव में समाज तात्कालिक सहायता से ज्यादा प्रभावित होगा।

फटाफट सरकार | लगातार बढ़ती बेरोजगारी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन का मुकाबला करने के लिए लोगों को तकनीक और कौशल से शिक्षित करना होगा। उसके लिए आधुनिक स्कूल, कॉलेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी हम सब भविष्य की चुनौतियों से निपट पाएंगे। यह तभी होगा जब शिक्षा को मुख्य मुद्दा समझा जाएगा। इस चुनाव में उठाए गए मुद्दों को देखकर लगता है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां या तो मतदाताओं की समझ को तात्कालिकता से आगे जाकर नहीं देख पातीं, या उन्हें मतदाताओं की आर्थिक और वैश्विक समझ के बारे में कम ज्ञान है।

(लेखक सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस के निदेशक हैं)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है हमारी ताकत

सीताराम गुप्ता

एक बार एक किसान अपने फार्म हाउस पर काम कर रहा था। उसका बेटा एक गाड़ी में कुछ सामान लेकर आया। जैसे ही वह पहुंचा, एक गड्ढे के पास उसकी गाड़ी पलट गई और वह कीचड़ में गाड़ी के नीचे दब गया। यह देखते ही किसान वहां पहुंच गया और गाड़ी उलटकर उसने अपने बेटे को सकुशल बाहर निकाल लिया। यह एक असंभव काम था। यह देखकर वहां काम करने वाले लोगों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने यह असंभव काम कैसे कर डाला? किसान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह असंभव काम है। मैं तो बस अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे-समझे गाड़ी को उलटने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।

आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ऐसा संभव है? असल में हम जो सोचते हैं, उससे कहीं अधिक बड़ा काम करने में हम काबिल होते हैं। सचाई तो यह है कि हमारी सोच से कहीं अधिक हमारी कूवत होती है। लेकिन फिर भी हम हर काम क्यों नहीं कर पाते? बात यह है कि हम संभव और असंभव की उधेड़बुन में फंसे रहते हैं। हर काम करने से पहले हम सोचने लगते हैं कि यह काम हमसे हो पाएगा या नहीं? इस काम को करने की कूवत मेरे अंदर है या नहीं। फिर आत्मविश्वास बनता ही नहीं है। ऊपर से आसपास के लोग सही सुझाव नहीं देते। वे उदाहरण पेश करने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर बोलता है। लोग समाधान न बताकर उस काम में आने वाली दिक्कतों के बारे में बताने लगते हैं। इससे काम करने वालों का मनोबल टूट जाता है, और अंत में वह काम करने का विचार ही छोड़ देता है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो नाकामयाबी का डर सताता रहता है।

कई बार देखा गया है, जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के थोड़े-से सहयोग से वह काम होता है। उसके बाद वह काम हमें सहज लगने लगता है। देखने में आता है कि कई मजदूर जब कोई भारी वस्तु उठाने या सरकाने की कोशिश करते हैं तो वह वस्तु टस से मस नहीं होती। पर जब उनका लीडर आता है और कुछ वाक्यों या नारों से उन्हें जोश दिलाता है तो चमत्कार-सा होता है और मजदूर उसे आसानी से उसे उठाने या सरकाने में सफल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम अपनी क्षमता के विषय में जितना सोचते हैं, हमारी कूवत उससे अधिक ही होती है। वक्त आने पर कभी-कभी हमें पता भी चल जाता है। लगता था कि फलां काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी वह काम हो गया। इसे स्थायी बनाने के लिए लगातार रियाज से इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

हमारे मन में एक सूची होती है जिसके मुताबिक हम कुछ काम कर सकते हैं और कुछ काम कतई नहीं कर सकते। यह लिस्ट खुद के अनुभव पर आधारित होती है लेकिन इसका अधिकतर काम परखा हुआ नहीं होता है। इस सूची को चेंज करने की जरूरत है। इस लिस्ट के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़ी-सी अधिक कोशिश करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त प्रयास कैसे करें? इसका सबसे सरल तरीका यही है कि हम इस भरोसे के साथ काम करें कि हम इसे कर सकते हैं, और खुद को एकाग्र करके धीरे-धीरे ताकत लगाना शुरू कर दें। काम में अगर सफलता नहीं मिलेगी, तो भी हमें उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि अपनी क्षमता को परखने का तो मौका मिलेगा।

बुंदेला दोस्ती की मिसाल है यह ताजमहल

सुविज्ञा जैन

मध्य प्रदेश के ओरछा में ताजमहल से भी पहले बनी एक भव्य इमारत है, जिसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस महल का निर्माण जहांगीर ने नहीं, अपने समय के सबसे यशस्वी बुंदेला राजा ने कराया था। दुनिया में जिस तरह ताजमहल मोहब्बत की निशानी है, उसी तरह से जहांगीर महल एक मुगल शहजादे और बुंदेला राजकुमार की दोस्ती की मिसाल है। मुगल शहजादे सलीम यानी जहांगीर और बुंदेला राजकुमार वीर सिंह देव।

सबसे सुंदर इमारत | अद्भुत शिल्पकला और नायाब नक्काशी से सजे जहांगीर महल को ओरछा की सभी ऐतिहासिक इमारतों में सबसे सुंदर माना जाता है। 1592 में ओरछा के राजा मधुकर शाह की मौत के बाद उनके बड़े बेटे रामचंद को ओरछा का राजसिंहासन मिला। उस समय मधुकर शाह के छोटे बेटे वीर सिंह देव की ख्याति अपने शौर्य और वीरता के लिए चारों तरफ थी। वीर सिंह को दतिया में बरौनी की जागीर मिली, जो उन्हें अपनी योग्यता के मुताबिक नहीं लगी। इसीलिए वीर सिंह ने भाई रामचंद के खिलाफ बगावत कर दी।

टाइम मशीन

इलाहाबाद में मुलाकात | यह वही समय था जब मुगलिया सल्तनत में शहंशाह अकबर और उनके बेटे जहांगीर के बीच दूरियां बढ़ रही थीं। जहांगीर ने इसकी वजह अकबर के बेहद करीबी और नवरत्नों में एक अबुल फजल को बताया। जहांगीर और अकबर के बीच एक समय दूरी इतनी बढ़ गई कि जहांगीर ने बगावत कर दी और इलाहाबाद में अलग दरबार बना लिया। इसी बीच 1599 में जहांगीर की मुलाकात वीर सिंह बुंदेला से हुई। इससे पहले रामचंद 1592 से 1599 के बीच कई बार मुगल सेना की मदद लेकर वीर सिंह पर हमला कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे थे।

दोस्त से मांगी मदद | अबुल फजल को जहांगीर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उन्हें लगने लगा था कि अबुल फजल के रहते वह शायद कभी अपने पिता के पास लौट नहीं पाएंगे। 1602 में जहांगीर को खबर मिली कि एक दौरे पर गए अबुल फजल दक्षिण से आगरा की तरफ लौटने वाले हैं और उनका काफिला बुंदेलखंड से होकर गुजरेगा। जहांगीर ने दोस्त वीर सिंह से मदद मांगी।

अबुल फजल पर हमला | दक्षिण से लौटते हुए अबुल फजल के काफिले पर ग्वालियर के पास वीर सिंह और उनके साथियों ने हमला बोल दिया। अबुल फजल की मौत हो गई। यह खबर सुन अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीर सिंह को पकड़ने के लिए सेना रवाना कर दी। लेकिन, जहांगीर ने अपने दोस्त को सचेत कर दिया था। हालांकि वीर सिंह के लश्कर को अकबर की सेना ने हरा दिया, फिर भी वीर सिंह पकड़ में नहीं आए। उन्होंने पहले एरच के किले में शरण ली, लेकिन जब उसे भी घेर लिया गया तो वह दतिया पहुंच गए। वहां उनका इंतजार खुद जहांगीर कर रहे थे।

ओरछा का राजा | इन घटनाओं के बाद सलीम यानी जहांगीर अपने पिता अकबर के पास लौट आए। धीरे-धीरे दोनों के रिश्तों में सुधार आया। 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद जहांगीर ने गद्दी संभाली। उन्होंने दोस्त वीर सिंह को कई सूबों की जागीर दी और उन्हें ओरछा का राजा घोषित कर दिया।

सफल राजा | वीर सिंह देव के राज में बुंदेला राजवंश ने खूब तरक्की की। उन्हें कई ऐतिहासिक धरोहरों के निर्माण के लिए याद किया जाता है। झांसी का किला, दतिया का महल, मथुरा में केशवराय मंदिर, ओरछा के फूल बाग जैसी कई धरोहरें वीर सिंह देव की बनवाई हुई हैं। जल भंडारण के लिए ओरछा में वीर सागर, कुंडार में सिंह सागर और दिनारा में देव सागर जैसे जलाशयों का निर्माण भी वीर सिंह देव ने ही कराया। वह अपने समय के सबसे समृद्ध राजपूत राजा थे, जिन्हें 1623 में महाराजा की उपाधि से नवाजा गया।

जहांगीर महल | ओरछा स्टेट गजेटियर के मुताबिक, वीर सिंह देव ने सिर्फ एक साल, 1628 में ही 52 इमारतों का शिलान्यास किया। इन्हीं में से एक है जहांगीर महल। यह तब बना था, जब जहांगीर ओरछा आने वाले थे। शाही अमले के ठहरने के लिए दो सौ से ज्यादा कमरे बनाए गए। बेतवा नदी के किनारे महल के झरोखों से ओरछा की कुदरती खूबसूरती दिखती है, किसी को भी अपने मोहपाश में बांध लेती है।

कैंसर से बड़ा संकल्प

प्रणव प्रियदर्शी

करियर के पहले फेज में अच्छी खासी रफ्तार हासिल करने के बाद आमतौर पर लड़कियों का सामना घर-परिवार और प्रेग्नेंसी-डिलीवरी जैसे स्पीड ब्रेकर से होता ही है। निधि जोसफ के मामले में बाधाएं सामान्य से कहीं ज्यादा मुश्किल और बड़ी साबित हुईं क्योंकि इनमें कैंसर भी शामिल था। तब उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था और सोच रही थीं कि दो-तीन साल के ब्रेक से काम चल जाएगा। लेकिन अचानक थायराइड कैंसर डायग्नोज हुआ और देखते-देखते आठ साल इसकी भेंट चढ़ गए। पहले तो सर्जरी के जरिए थायराइड ग्लैंड निकाला गया, फिर उन्हें रेडियोएक्टिव आयोडिन के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े। इन सबसे उबरने में पांच साल लग गए। तब तक दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। स्वाभाविक ही निधि को लगा कि अब करियर का जो सिरा पूरी तरह छूट चुका है, उसे फिर से पकड़ा जाए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की थी और पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स, IBM और PwC के साथ काम कर चुकी थीं। लेकिन जो लंबा अंतराल आ गया था, उसके बाद नए सिरे से काम शुरू करना था। सो, निधि ने सोचा कि और कुछ नहीं तो पढ़ाने का काम तो मिल जाएगा। यहां काम आई निधि की पहली संतान, उनकी बेटी जो अब तक इतनी समझदार हो चुकी थी कि उन्हें करियर के मामले में सुझाव दे सके। निधि के पुराने सहकर्मियों ने भी मोटिवेट किया। आखिर निधि ने अपना रेज्युमे एक जॉब पोर्टल पर डाल दिया।

निधि जोसफ

आधी दुनिया

टेक्नॉलजी शुरू से उनका शौक थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि इस फील्ड में सारा कुछ बदल चुका था। मसलन उन्होंने SAP के 4.0 वर्जन पर काम किया था पर अब मार्केट में 8.0 वर्जन चल रहा था। लेकिन शौक की वजह से बीमारी के दौरान भी वह टेक्नॉलजी में हो रहे बदलावों पर जहां तक संभव था नजर रखे रही थीं। वह सब काम आया, जब जॉब पोर्टल पर रेज्युमे डालने के दो हफ्ते के अंदर Accenture की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलेंस एनालिस्ट पद के लिए संपर्क किया गया। इंटरव्यू के दौरान रही-सही झिझक भी समाप्त हो गई। उन्होंने पाया कि उनकी समस्याओं पर कंपनी का रवैया काफी पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल है। नतीजतन, आज जहां निधि अपने करियर को रिक्लेम कर चुकी हैं, वहीं कंपनी भी उनके स्किल और एक्सपीरिएंस से लाभान्वित हो रही है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ अच्छी बारिश से उम्मीद

17 अप्रैल का संपादकीय 'मौसम की खुशखबरी' पढ़ा। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। खासकर ग्रामीण भारत के लिए इस बार का मॉनसून खुशहाली ला सकता है। खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, गन्ना, कपास और जूट के उत्पादन बढ़ सकते हैं। अच्छी बारिश से जमीन में नमी बनी रहेगी तो रबी की फसलों के लिए भी यह फायदेमंद रहेगा। अच्छी फसल होने से घरेलू खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। इससे बढ़ती महंगाई पर लगाम लग सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने पर ही समग्र आर्थिक विकास को गति मिल पाएगी।

मोहित शर्मा, ईमेल से

■ ईरान के इरादे

यह पत्र 16 अप्रैल के लेख 'इस्राइल पर ईरानी हमले का क्या होगा अंजाम' से संबंधित है। हाल ही में इस्राइल पर ड्रोन से किए गए ईरान के हमले और उसके बाद ईरानी मंत्री की तरफ से दिए गए आक्रामक बयान ने मध्य-पूर्व में तनाव को एक नए स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि इस्राइल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके लिए नए अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा रहे हैं। अगर इस्राइल ने संयम नहीं बरता तो ईरान कोई खतरनाक कदम उठा सकता है।

सारिका अग्रवाल, ईमेल से

■ बंटवारे की राजनीति

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद पेचीदा होती जा रही है। BSP अध्यक्ष मायावती ने अपनी पहली चुनावी सभा के दौरान सहारनपुर में यह धमाकेदार घोषणा कर दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग राज्य एक बड़ा मुद्दा है। इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों का अलग-अलग नजरिया है। BSP उत्तर प्रदेश को चार भागों में विभाजित कर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कयाम करने की बात करती है। 2011 में मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भी भेजा था। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

केंद्रीय मंत्री ने प्रचार के दौरान चखा स्ट्रीट फूड, UPI से किया भुगतान – खबर
– लगता है चुनाव प्रचार के साथ-साथ डिजिटल इंडिया का भी प्रचार जोरों पर है!

प्रेरणा गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

नक्सलवाद के विष वृक्ष पर प्रहार

भारत में नक्सलवाद की समस्या कोई नई नहीं है। नक्सलवाद देश के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर है। नक्सलवाद का उद्देश्य शासन के विरुद्ध जनयुद्ध की परिकल्पना थी। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में बंदूक की नोंक पर सत्ता हासिल करने की बात करना नक्सलियों की मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाता है। इस नक्सलवाद ने हमें बहुत जख्म दिए हैं। मई 2014 के बाद जब केन्द्र में सत्ता बदली तो निजाम भी बदला। केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए, फिर भी जब नक्सलियों का दांव लगा उन्होंने हमारे जवानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों का खून बहाया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा बलों ने कांकेर जिले में तीन टॉप कमांडरों समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की डीआरजी टीम को इस बार भारी सफलता मिली। हालांकि इस वर्ष माओवादियों के गढ़ बस्तर जिला में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में 80 नक्सली मारे जा चुके हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की सफलता का श्रेय सूझबूझ, बेहतर इनपुट और कुशल रणनीति को जाता है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार यह ऐलान करते आ रहे हैं कि आने वाले 3 वर्षों में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52 प्रतिशत की कमी आई है। इन घटनाओं से मौतों में 70 प्रतिशत की कमी आई है और देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 45 रह गई है, जबकि नक्सल प्रभावित पुलिस थानों की संख्या 493 से घटकर 176 रह गई है लेकिन अभी तक नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ा नहीं जा सका है। नक्सलियों ने बड़ी-बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है।

60 और 70 के दशक में नक्सलवाड़ी आंदोलन के बारे में तीखे तेवरों वाले कवि सुदामा प्रसाद धूमल ने कहा था ''भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है।''' लेकिन नक्सलियों ने जल, जंगल, जमीन का हक आदिवासियों को दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया। आंदोलन अपना रास्ता भटक गया। नक्सली गुट लूट-खसूट करने वाले गिरोह बन गए। नक्सलियों की पूंजी अब जनसमर्थन नहीं बल्कि आतंक और क्रूरता बन गई। राज्य सरकारों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार बहाये जाने से नक्सलियों को जनसमर्थन मिलना बंद हो चुका है।

पाठकों को याद होगा 25 मई, 2013 को इसी सुकमा की झीरम घाटी में 200 नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी की रैली पर हमला कर दिया था जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा सहित 32 लोगों की जान चली गई थी। इस खौफनाक वाकये को 200 से ज्यादा नक्सलियों ने अंजाम दिया था। फिर 2 अप्रैल, 2021 का वो दिन, जब सुरक्षा बलों के 2,000 जवानों ने एक साथ बीजापुर और सुकमा के जंगलों में धावा बोल दिया। नक्सल विरोधी इस बड़े अभियान में भी 22 जवानों को जान गंवानी पड़ी थी। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ की धरती नक्सल नरसंहारों से लाल होती रहती है।

वर्ष 2000 के आसपास नक्सलवाद अपने चरम पर था। तब देश के 200 जिले नक्सल प्रभावित थे। उस वक्त भी नक्सलियों का हेडक्वॉर्टर बस्तर के अबूझमार में हुआ करता था और नक्सलियों ने 700 कि.मी. का गलियारा बना लिया था। वो एक जगह हमला करते और गलियारे के सहारे तुरंत इलाका बदल लेते। तब वो भारत से नेपाल तक नक्सल गलियारा बनाने का ख्वाब देख रहे थे। हालांकि, तब से अब की स्थिति में बहुत अंतर है। आज नक्सली छिटपुट इलाकों में सीमित रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा आदि उनमें से एक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव क्यों नहीं उखड़ रहे?

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सरंचना नक्सलियों को छिपने, साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिहाज से काफी मुफीद है। पहाड़ों से घिरे इस प्रदेश में बड़े चुनौतीपूर्ण पठारी इलाके भी हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे इलाकों में नक्सलियों की तूती बोला करती थी। इस कारण वहां सुरक्षा बलों के कैंप लगाने पड़े लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के बीच भरोसा पैदा करने की रही है। पुलिस-प्रशासन को अच्छे से पता है कि बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक, क्या पुरुष और क्या महिलाएं सभी माओवादियों के लिए काम करते हैं। वो नक्सलियों को सुरक्षा बलों की हर गतिविधि से अवगत करवाते हैं। यह सब नक्सलियों की तरफ से दशकों तक आम लोगों की ब्रेन वॉशिंग किए जाने का नतीजा है।

60 और 70 के दशक में नक्सलवाड़ी आंदोलन के बारे में तीखे तेवरों वाले कवि सुदामा प्रसाद धूमल ने कहा था ''भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है।'' लेकिन नक्सलियों ने जल, जंगल, जमीन का हक आदिवासियों को दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया। आंदोलन अपना रास्ता भटक गया। नक्सली गुट लूट-खसूट करने वाले गिरोह बन गए। नक्सलियों की पूंजी अब जनसमर्थन नहीं बल्कि आतंक और क्रूरता बन गई। राज्य सरकारों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार बहाये जाने से नक्सलियों को जनसमर्थन मिलना बंद हो चुका है। अधिकांश नक्सली समर्पण कर चुके हैं। बचे-खुचे लुटेरे गिरोह अपनी ताकत बटोर कर हिंसा को अंजाम देने की साजिशें रचते रहते हैं। हालत यह है कि अब कई इलाकों में नक्सलवाद अतीत बन चुका है। विकास होने से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के जिस नक्सलवाड़ी जगह से आंदोलन की शुरूआत हुई थी वहां भी इसका कोई नामलेवा नहीं बचा है। नक्सलवाड़ी पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है। जरूरत है नक्सलवाद के विष वृक्ष की जड़ें पूरी तरह से काटने की। उम्मीद है भारत जल्द ही इस विष वृक्ष से मुक्त हो जाएगा।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

अपने-अपने दावे...

"वो विकास –विकास चिल्ला रहे हैं,
और भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं,
पर अतंर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के आंकड़े तो कुछ ओर ही दर्शा रहे हैं,
और मुझ नासमझ कलमकार को भी लाखों डिग्रीधारक
युवा बेरोजगार नजर आ रहे हैं...।।"

गीता पाढा

पाकिस्तान को डूबने से बचाना हमारी ज़िम्मेवारी नहीं हो सकती

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

भारत और पाकिस्तान के बीच ठहरे पानी में उनके विदेश मंत्री इसहाक डार ने पत्थर उछाल दिया है। क़रीब पांच वर्ष के बाद उन्होंने भारत के साथ व्यापार सम्बंध बहाल करने की इच्छा जताई है। लंदन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनके देश का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ फिर कारोबार शुरू करना चाहता है। और उनका कहना था कि, "हम भारत के साथ व्यापार के मामले को गंभीरता से देखेंगे"। स्मरण रहे कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल नहीं होती यह रिश्ते भी बहाल नहीं होंगे। कहा गया कि संबंध सुधारने की ज़िम्मेवारी भारत की है। भारत के साथ व्यापार रुक गया। भारत तो बदला नहीं पर अचानक पाकिस्तान का सुर बदल गया है। जिसे 'हाई हार्स' कहा जाता है उससे वह उतरने के संकेत दे रहें हैं। समझ तो वह बहुत पहले गए थे पर अब उच्च स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है कि भारत के साथ संबंध बेहतर किए बिना गति नहीं है। निश्चित तौर पर उनकी हालत ख़राब होगी तब ही कड़वा घूंट पीकर भारत से व्यापार की इच्छा व्यक्त की जा रही है। इसलिए धारा 370 पर कदम उल्टाने वाली शर्तें ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। वैसे भी कश्मीर शांत है और वह जानते हैं कि न केवल यह सरकार, बल्कि भारत की कोई भी भावी सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं करेगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ व्यापार चल रहा है पर यह समुद्री या हवाई रास्ते से है। दुबई या सिंगापुर जैसी जगहों से हमारा माल पाकिस्तान पहुंच रहा है। ज़मीनी रास्ता अफ़ग़ानिस्तान के लिए खुला है पर हम पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों को माल नहीं भेज सकते। इसके लिए अब ईरान की चाहबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे कच्चे माल पर पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग निर्भर करता है जो अब अपने महंगे उत्पाद के कारण भारत, बंगलादेश और वियतनाम जैसे देशों द्वारा तैयार किए गए माल के आगे टिक नहीं रहा। उन्हें हमारी चीनी भी चाहिए जो सस्ती है। पाकिस्तान के वित्तमंत्री कह चुके हैं कि, "पाकिस्तान में कपास की मांग है। कपास की कम पैदावार से कपड़ा उद्योग प्रभावित हुआ है और दूसरे देशों की तुलना में भारत से चीनी सस्ती है"। लेकिन पाकिस्तान की समस्या कपास या चीनी की कमी से भी बहुत विशाल है। सीधी सी बात है कि देश दिवालिया होने के कगार पर है। जिसे जेल में बंद इमरान खान ने 'भीख का कटोरा' कहा था, को लेकर उनके हर प्रधानमंत्री को विभिन्न राजधानियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या आईएमएफ़ जैसी संस्थाओं के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है।

एशियन डिवेलप्मैंट बैंक के अनुसार 2023-24 में पाकिस्तान की विकास दर 1.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। देश बुरे क़र्ज़ में है और महंगाई की दर 25 प्रतिशत है। विदेशी मुद्रा का रिसर्व न के बराबर है। देश में भारी असंतोष है। इसीलिए इसहाक डार का कहना है कि भूगोल की मजबूरी कहती है कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू किया जाए। पाकिस्तान में एक राय यह भी है जो चीन या अमेरिका पर निर्भरता कम करने की वकालत करती है। विकल्प भारत है। इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि, "पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापार सम्बंध क़ायम करना नीति में महत्वपूर्ण शिफ्ट है। वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार और चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं... उनकी अर्थव्यवस्था लाईफ़ सपोर्ट पर है और वह एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मिलने तक धक्के खा रहे हैं"। विश्व बैंक कह चुका है कि अगर प्रतिबंध हटा लिए जाएें तो दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार 2 अरब डॉलर से बढ़ कर 37 अरब डॉलर हो सकता है।

पर क्या आपसी व्यापार शुरू होगा? अतीत में भी सम्बंध ख़राब होते रहे पर व्यापार चलता रहा। अब सम्बंध बहुत बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान में अभी भी एक राय है जो भारत के साथ सम्बंध सुधारने के खिलाफ है। इसहाक डार की भी आलोचना हो रही है कि उन्होंने ऐसी की बात क्यों कही है। विशेषज्ञ मुशर्रफ ज़ैदी का कहना है, "विदेश मंत्री डार भारत के साथ व्यापार की बात करते हैं। पाकिस्तान के एलीट वर्ग की आदत है कि वह दोस्ती का हाथ मांगता रहता है जो अस्तित्व में नहीं है"। यह बात आंशिक तौर पर सच है। भारत के हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और वह हाथ झुलस गया। दोस्ती के प्रयास के एवज़ में अटल बिहारी वाजपेयी को कारगिल, मनमोहन सिंह को मुम्बई हमला और नरेन्द्र मोदी को उरी, पठानकोट और पुलवामा के हमले मिले। लेकिन एक बात मुशर्रफ ज़ैदी की ज़रूर सही लगती है,इस वक्त भारत में पाकिस्तान के साथ सम्बंध सामान्य करने और व्यापार शुरू करने की बहुत इच्छा नहीं है। 'दोस्ती का हाथ' मौजूद नहीं है। हमारी कोई मजबूरी भी नहीं है। हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार के बहुत फ़ायदे भी नहीं हैं। वहां से ऐसा कोई सामान आयात नहीं जिसके बिना हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा। हां, हमारा इसमें हित ज़रूर है कि पाकिस्तान से अफ़ग़ानिस्तान और केन्द्रीय एशियाई गणराज्यों के लिए ज़मीनी रास्ता खुल जाए। पंजाब में आपसी व्यापार को लेकर एक वर्ग में उत्साह ज़रूर है। दोनों देशों के बीच व्यापार से बहुत लोगों को यहां रोज़गार मिलता था। 2019 से पहले रोज़ाना 200 ट्रक यहां से सीमा पार जाते थे। अब सिर्फ़ अफ़ग़ानिस्तान से माल आता है जिससे उनका धंधा चलता है जो ड्राई फ्रूट और मसाले का व्यापार करते हैं।

दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन का कहना है कि, "बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण भारत को पाक के साथ व्यापार में कम फ़ायदा है...मुझे उम्मीद नहीं कि भारत चुनाव के बाद व्यापार शुरू करेगा...जब तक पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से जुड़ी चिन्ताओं पर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, भारत बातचीत नहीं करेगा"। "हक़ीक़त है कि पाकिस्तान को आज भारत की ज़रूरत भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत अधिक है", यह इकनॉमिक टाइम्स का कहना है। हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत है और हम उन विकासशील देशों के लिए बाज़ार खोलने के बहुत इच्छुक नहीं जिनका सस्ता माल हमारे उद्योगपतियों के लिए चुनौती बन सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था उनसे 10 गुना बढ़ी है। दोनों में कैसी ग़ैर बराबरी है वह कारों की बिक्री से पता चलता है। पिछला साल नवम्बर में पाकिस्तान में केवल 5000 कारें बिकी थी जबकि भारत में 3.6 लाख कारें इसी महीने बिकी थी। पाकिस्तान के कमजोर विकास के कारण यह फ़ासला बढ़ता जाएगा। एक समय ज़रूर था जब यहाँ पाकिस्तान के साथ सम्बंध बेहतर करने कि लिए लॉबी थी। यह लोग वाघा सीमा पर जा कर मोमबत्तियां जलाते थे। पाकिस्तान की अपनी लगातार बेवक़ूफ़ियों के कारण वह जज्बाती लम्हा गुज़र चुका है। ऐसा लगता है कि सारे देश ने सामूहिक तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तान के बिना रह सकते हैं।

हाल ही में जब विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि किस देश को वह सबसे बड़ी चुनौती समझते हैं तो उनका बेबाक़ जवाब था, 'पाकिस्तान'। इसका अर्थ है कि अविश्वास ख़त्म नहीं हुआ। हमें यह ज़रूर फ़ायदा होगा कि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और पाकिस्तान चीन की गोद में बैठना बंद कर देगा। यह भी सकारात्मक है कि 2021 से नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी बंद है। लेकिन उन्हें जिम्मेवार बनाना हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। इमरान खान के समय 2021 में भी उन्होंने भारत से आयात करने वाली कपास और चीनी पर लगाया एकतरफ़ा प्रतिबंध वापिस ले लिया था पर अगले ही दिन उनकी कैबिनेट ने निर्णय पलट दिया क्योंकि कट्टरपंथियों ने विरोध किया था जबकि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा पक्ष में थें। अभी तक पाकिस्तान के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला इसलिए मालूम नहीं कि वह क्या चाहतें हैं। वह सब कुछ पलट सकतें हैं। विशेषज्ञ सी.राजा मोहन ने दिलचस्प टिप्पणी की है, "भारत के साथ व्यापार की बात है पर पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि सही करने की राजनीति वहाँ काफ़ी मुश्किल है"।

पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ सम्बंध कड़वे हो चुके हैं। वास्तव में भारत के साथ उनके सम्बन्ध पड़ोसी इस्लामी देशों से बेहतर है। कम से कम सीमा शांत है। वह जानते हैं कि वह एक कोने में फंस चुके हैं। अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है कि वह सभ्य पड़ोसी की तरह रहें पर आंतरिक राजनीति ऐसी है कि वह सही कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। नवाज़ शरीफ़, शहबाज़ शरीफ़, आसिफ़ ज़रदारी सब समय समय पर भारत के साथ व्यापार शुरू करने की वकालत कर चुकें है पर राजनीति हावी हो जाती है। शरीफ़ बंधुओं की पार्टी पीएमएनएल का विशेष तौर पर समृद्ध और औद्योगिक वर्ग में आधार हैं जिन्हें सदैव भारत के साथ व्यापार में अपना हित नज़र आता हैपर इतिहास बताता है कि उनकी सरकारें कट्टरपंथियों के आगे समर्पण करने में भी देर नहीं लगाती। पर यह उनकी समस्या ।हमें वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। अभी तो चुनाव हो रहे हैं पर उनके बाद भी जब तक पाकिस्तान बंदा नहीं बनता और आतंक का अपना नल बंद नहीं करता, हमें व्यापार शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। आपसी सम्बन्ध उनकी सनक या शरारत पर निर्भर नहीं होने चाहिए। वह स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। न ही उन्हें डूबने से बचाना हमारी ज़िम्मेवारी हो सकती है।

क्या है सिख की असल परिभाषा?

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

सन् 1699 में जब गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सिख पंथ की सिरजना की तो उन्होंने सिख के लिए जो मापदण्ड तय किये थे आज शायद बहुत कम सिख ऐसे होंगे जो उन पर पूरा उतरते हों अन्यथा ज्यादातर को तो सिखों की मर्यादा तक की जानकारी सही से नहीं होगी। गुरु गोबिन्द सिंह जी के द्वारा तैयार खालसा केवल सिर पर दस्तार सजाने, सिर और मुंह पर दाड़ी रखने से नहीं बनता। गुरु जी ने साफ कहा था ''रहत प्यारी मुझको, सिख प्यार ना ही'' भाव जो वेशभूषा से भले ही सिख दिखता हो पर अगर वह सिखी के मापदण्ड को पूरा नहीं करता, रहत मर्यादा का पालन नहीं करता तो वह सिख कहलाने के लायक ही नहीं है। सिख में सबसे पहले निम्रता, त्याग, बलिदान, दूसरों का मददगार, दूसरों के धन दौलत पर निगाह ना रखने वाला, अमृतपान करके नितनेम की बाणियों का पाठ करने वाला, पराई स्त्री को मां-बहन-बेटी की नजर से देखने का नजरिया होना चाहिए जो शायद मुट्ठी भर सिखों में ही हो सकता हैं। यहां तक कि बहुत से जत्थेदार, धर्म गुरु, ग्रन्थी, प्रचारक, सेवादार भी ऐसे दिख जायेंगे जो इन पर पूरी तरह से स्वयं ही नहीं चलते तो वह दूसरों को क्या ही शिक्षा देते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि इसलिए ही इनके द्वारा दी गई शिक्षा का शायद असर भी आम सिख पर नहीं होता। बहुत से ऐसे कीर्तनीए हैं जो खुलकर गुरबाणी बेचने की बात करते हैं। जब से धर्म में राजनीति हावी हुई है तब से सिखी का पैमाना दिन-प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। राजनीतिक लोगों को केवल अपनी राजनीति से मतलब होता है फिर भले ही धार्मिक कार्यों में कोई भी चूक हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई

जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि किसी राजनीतिक पार्टी के लोग गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे तो उनके ज्यादातर साथी बिना सिर ढके ही दिखाई दिये और उनके साथ एक सिख जो शायद उस गुरुद्वारा साहिब का कोई पदाधिकारी होगा या फिर राजनीतिक पार्टी का नुमाईंदा, उसने उन्हें मर्यादा समझाकर सिर ढकने को भी नहीं कहा। आज जब गुरुद्वारों में शादी ब्याह या उससे पहले होने वाले कार्यक्रम होते हैं और उनमें सिख युवा या महिला केशों की बेअदबी किये हुए होते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा का कहना है कि 325 साल तो इसी तरह से बीत चुके हैं पर अगर हर सिख एक संकल्प कर ले कि आने वाले 25 साल बाद जब खालसा पंथ का 350वां स्थापना दिवस मनाएं तो उस समय वह पूर्ण गुरसिख बनकर मनाएं, उससे पहले अपने अन्दर की खामियों को समाप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गुरुद्वारा साहिब की कमेटियों में प्रबन्ध की बागडोर बिना किसी लोभ-लालच के उन्हें सौंपी जानी चाहिए जो वाक्य में ही इसके हकदार हों और सिखी के मापदण्ड को पूरा करते हों। जब प्रबन्धक सिख रहत मर्यादा का पालन करते होंगे तो भूलकर भी जत्थेदार, ग्रन्थी, सेवादार, प्रचारक की नियुक्ति में चूक नहीं कर सकते और जब सभी धार्मिक लोग सेवा भावना के साथ सिख रहत मर्यादा का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी को निभायेंगे तो सिखी स्वयं ही प्रफुलित होती दिखेगी। समाजसेवी दविन्दरपाल सिंह पप्पू का मानना है कि आज सिखी की जो दुर्दशा हो रही है उसे देखकर बहुत दुख होता है। इसके लिए सभी को मिलकर अरदास करनी चाहिए कि परमात्मा हमें आपसी प्यार बख्शे और हम मतभेद भुलाकर, प्रेम भाव के साथ गुरु साहिबान के दिखाए रास्ते पर चल सकें।

सिख के लिए दस्तार का महत्व

किसी भी सिख के सिर पर सजी दस्तार उसके लिए शरीर के अभिन्न अंग का स्थान रखती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख सजाते समय केशों की संभाल हेतु सिर पर पगड़ी बांधना अनिवार्य किया। हालांकि उस समय मुगल हकूमत का शासन था और किसी भी व्यक्ति को सिर पर कपड़ा रखने की सख्त मनाही हुआ करती थी। पगड़ी केवल राजा महाराजा ही पहना करते। गुरु साहिब ने इसी के चलते हर सिख को पगड़ी बांधकर राजा-महाराजा की तरह शान से जीने की प्रेरणा दी। सिखों के लिए पगड़ी का विशेष महत्व है और यह सिख के लिए स्वाभिमान का प्रतीक

भी है। किसी शायर ने भी कहा है कि ''टोपी भले ही सोने की क्यों ना हो पगड़ी के साथ कोई मुकाबला नहीं'' हो सकता। मगर आज हालात यह बन चुके हैं कि ज्यादातर सिखों के बच्चे सिर पर पगड़ी के स्थान पर टोपियां पहनने लगे हैं और कुछ एक तो वह भी नहीं पहनकर नंगे सिर ही बाजारों में घूमते दिख जायेंगे और कुछ तो और भी दो कदम आगे चलकर आफिस, शादी ब्याह में भी ऐसे ही जाने लगे हैं। अब इसमें कमी माता पिता की कही जाएं या फिर धर्म के ठेकेदारों की जो बच्चों को दस्तार का महत्व ही नहीं समझा पाए। कुछ एक संस्थाएं हैं जो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए समय-समय पर बच्चों में दस्तार के प्रति जागरुकता लाने हेतु कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्हीं में से एक है सिख यूथ फाउंडेशन। संस्था के मुखी हरनीक सिंह व उनकी टीम के द्वारा बच्चों को रोजाना शाम को गुरुद्वारा राजौरी गार्डन में पंजाबी सिखलाई से लेकर, कीर्तन, गुरमत आदि की क्लासें दी जाती हैं और माह में एक बार दस्तार सिखलाई की भी क्लास होती है। इसके पीछे कमेटी के अध्यक्ष हरमनजीत सिंह, महासचिव मनजीत सिंह खन्ना का भी भरपूर सहयोग है जिनके कारण यह संभव हो पाया है। अगर सिख यूथ फाउंडेशन की तरह हर सिंह सभा गुरुद्वारा में इस तरह की क्लासें बच्चों को दी जाएं तो निश्चित तौर पर बच्चों में दस्तार के प्रति जागरुकता आएगी और जब उन्हें दस्तार का महत्व पता चल जायेगा तो वह भूलकर भी दस्तार के स्थान पर टोपी नहीं पहन सकते।

भागसर के खुले भाग्य

राजस्थान के श्री गंगानगर के पास एक छोटा सा गांव है भागसर। पूरे गांव में एक ही सिख परिवार का निवास है और उनके द्वारा ही गांव में गुरुद्वारा सुशोभित कर गुरु महाराज का प्रकाश किया जाता है। इस परिवार के अलावा पूरे गांव में कोई भी पगड़ीधारी दिखाई ही नहीं देता। बीते दिनों सनातन धर्म से सिख धर्म में प्रवेश कर गुरु तेग बहादुर जी और सिखी का प्रचार देश ही नहीं यूरोप के देशों में भी करने वाली अनुराधा कौर खालसा जब इस गांव में पहुंची और गुरु तेग बहादुर जी और साहिबजादों की लासानी शहादत की दास्तान जब गांव वासियों को बताई तो उनके प्रचार से प्रभावित होकर 82 के करीब लोग जिनमें महिलाओं की गिनती अधिक थी स्वयं आगे आकर अमृतपान करने को तैयार हो गई। इतना ही नहीं इसकी वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो भिवानी के भी कुछ गैर सिख परिवार सिख सजने को तैयार हो गये हैं। अब सवाल यह बनता है कि जो काम अनुराधा कौर खालसा बिना किसी संसाधन या कमेटी के कर सकती हैं तो करोड़ों रुपये धर्म प्रचार पर खर्च करने वाली कमेटियां आज तक क्यों नहीं कर पाई या यह कहा जाए कि उनका वास्तव में इस ओर ध्यान हीं नहीं है। देश के अनेक शहरों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने बकायदा प्रचार के लिए सैन्टर बनाकर प्रचारक नियुक्ति किये हुए हैं, जिन्हें लाखों रुपये बकायदा तनख्वाह दी जाती है। फिर भी ऐसे परिणाम क्यों नहीं निकलकर आए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है पर जो भी हो अनुराधा कौर खालसा की बदौलत ही सही भागसर गांव के भाग्य खुल गये और वह परिवार जो सिखी से पूरी तरह अंजान थे आज पूर्ण सिख मर्यादा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो संस्थाएं वाक्य में ही सिखी का प्रचार करने की सोच रखती हैं उन्हें इस महिला वकील की मदद लेकर प्रचार को बढ़ाना चाहिए ताकि भागसर वालों की तरह देश के अन्य लोगों के भी भाग्य खुल सकें।

स्वच्छ पर्यावरण, स्थिर जलवायु के लिए मतदान करने का आग्रह

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) विभिन्न पर्यावरण और नागरिक समाज संस्थाओं ने नागरिकों से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले, बीते कुछ वर्षों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का बुधवार को आग्रह किया। सत्तर से अधिक पर्यावरण और नागरिक समाज संस्थाओं ने नागरिकों से स्वच्छ पर्यावरण, स्थिर जलवायु के लिए मतदान करने का आग्रह किया। इन संगठनों में नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स, पीपल फॉर अरावली, यूथ फॉर हिमालय, क्लाइमेट फ्रंट इंडिया, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, एलायंस फॉर रिवर्स इन इंडिया, इंडियन सोशल एक्शन फोरम, यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट (कर्नाटक), आरे कंजर्वेशन ग्रुप, युग्मा कलेक्टिव, सेव पुणे हिल्स (महाराष्ट्र), एनडेंजर्ड हिमालय (हिमाचल प्रदेश), वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन (उत्तराखंड), छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, झारखंड किसान परिषद, जन विकास शक्ति संगठन (बिहार) तथा यूपी लैंड राइट फोरम आदि शामिल हैं। इन संस्थाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, ''देश के नागरिक इस वर्ष के लोकसभा चुनाव में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के भविष्य, विशेषकर युवाओं और आने वाले वर्षों में स्वच्छ वायु और जल सुरक्षा के उनके अधिकार पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश अप्रत्याशित बारिश, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभावों का सामना कर रहा है।'' बयान में नागरिकों से पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे ''जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि या कमी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे, रोजगार सृजन, नागरिकों के अधिकार'' आदि पर विचार करने को कहा। इन संस्थाओं ने कहा कि नवीनतम वैज्ञानिक और पर्यावरण डेटा के आधार पर, भारत 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में 180 देशों में सबसे नीचे है। बयान में कहा गया है, ''भारत बिगड़ती वायु गुणवत्ता, तेजी से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूजल की कमी, सूखती और प्रदूषित नदियों और जल निकायों और हर जगह कचरे के पहाड़ों के साथ सूची में सबसे नीचे है।'' इसमें दावा किया गया है कि देश के प्राचीन जंगलों, नदियों, पहाड़ों और रेगिस्तानों का कोयले के लिए दोहन किया जा रहा है। इन संस्थाओं ने दावा किया कि भारत जबरदस्त जल संकट का सामना कर रहा है। स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय, 'आईक्यू एयर' द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत को तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया था जबकि 2022 में यह आठवें स्थान पर था। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शहर अब भारत में हैं। इन संस्थाओं ने राजनीतिक नेताओं से सभी स्थानीय और राष्ट्रीय विकास कार्यों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय और नागरिक समाज को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ग्राम सभा की सहमति के बिना वन और कृषि भूमि के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हो।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

प्रचार का पहला चरण

अठारहवीं लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रथम चरण वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया है और 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही देश में 18 प्रतिशत मतदान या चुनाव संपन्न हो जाएगा। इतनी ज्यादा सीटों वाला यह सबसे बड़ा चुनावी चरण है और इसमें 10 छोटे-बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। शुक्रवार को तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन मजबूत है, जबकि भाजपा पहली बार सशक्त स्थानीय प्रत्याशियों के दम पर दो-दो हाथ कर रही है। तमिल मतदाता राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को ज्यादा पसंद करते हैं या अन्नाद्रमुक के पक्ष में जाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यहां से भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी? यहां भाजपा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करने वाले तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई (कोयंबटूर) का भाग्य भी कल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा।

देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। शुक्रवार को पहले चरण में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अपनी-अपनी विधानसभाओं के लिए मतदान संपन्न हो जाएगा। उत्तराखंड की सभी पांच सीटों- टिहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल-उधमसिंह नगर और हरिद्वार पर भी प्रचार समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी खास आठ सीटों- पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। इनमें से ज्यादातर सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय है, जहां दो से ज्यादा प्रत्याशी पूरी मजबूती से जीत का दावा कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर भाजपा की मजबूती का इतिहास है, इसलिए विपक्षी दलों को पुरजोर प्रयास करना पड़ रहा है।

देश में 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया है, वहीं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार भी संपन्न हो चुका है।

बिहार में भी औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा में चुनाव प्रचार थम गया है। राजस्थान में भी पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान होने वाला है। लगभग इन सभी क्षेत्रों में पिछली बार कमल खिला था, पर इस बार देखना है कि मतदान किस ओर जाता है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों को मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि 29 नक्सली मारे गए हैं और बस्तर सीट पर मतदान है।

बहरहाल, पहले चरण में जिन नेताओं के भाग्य का फैसला हो जाएगा, उसमें सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। गडकरी का नाम ऐसे मंत्रियों में शुमार रहा है, जिनका काम साफ तौर पर दिखता है। गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जीतेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जैसे कद्दावरों के भी भाग्य का फैसला 19 अप्रैल को हो जाएगा। बहरहाल, चुनाव खर्च की सीमा की वजह से चुनाव प्रचार विशेष रूप से बड़े शहरों में उतना नहीं दिख रहा है, जितना छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, पर चुनाव लड़ने वाले बहुत सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर धन भी खर्च हो रहा है। चुनाव आयोग बेहिसाब धन की बरामदगी कर रहा है, मतलब, एक चुनाव हमारी आंखों के सामने है और उसका एक स्याह पहलू परदे के पीछे जमीन-आसमान एक किए हुए है। बेशक, यह जागरूकता के साथ अपने भविष्य को देखने का समय है। ऐसे प्रत्याशियों का ही चयन होना चाहिए, जो प्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर न छोड़ते हों।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 18 अप्रैल, 1949

अफ्रीकी भारतीयों की चिंता

केपटाउन, १७ अप्रैल। दक्षिण अफ्रीका के सरकारी कमीशन ने, जिसने पिछली जनवरी में अफ्रीकी-भारतीय दंगों की जांच की थी, आज यह चेतावनी दी है कि हो सकता है अफ्रीकी अपना हिसाब चुकता करने के लिए भारतीयों पर एक और आक्रमण कर दें। कमीशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ यूरोपियन थे, जिन्होंने सक्रिय रूप से अफ्रीकियों को भारतीयों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयों के लिए भड़काया, परन्तु कमीशन को संतोष है कि ये यूरोपियन अपवाद रूप में थे। दो दिन के दंगों में १४२ व्यक्ति मारे गए और १०८७ जख्मी हुए थे। कमीशन ने दंगों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें दंगों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि जब तक स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगाह नहीं रखी जाती और सार्वजनिक हिंसा के सभी प्रदर्शन सख्ती के साथ नहीं दबा दिये जाते यह हो सकता है कि अफ्रीकी लोग अपना हिसाब चुकता करने के लिए भारतीयों पर फिर आक्रमण कर दें। रिपोर्ट में कहा गया है कि डरबन पर, जहां जातीय दंगे हुए थे, बराबर निगाह रखने की आवश्यकता है।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अफ्रीकियों और भारतीयों में जो संघर्ष हुआ, वह बहुत आकस्मिक था। उसके लिए अधिकारियों को दोष नहीं दिया जा सकता। इस संघर्ष के कई कारण हैं, जिनमें मकान की समस्या एक है। डरबन के छोर पर बसे गंदी झोंपड़ियों वाले क्षेत्र किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। परन्तु इसके लिए डरबन कारपोरेशन को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरा कारण बड़ी संख्या में अफ्रीकी पुरुषों का कम्पाउंडों में रहना बताया गया है। इन लोगों ने दंगों में बहुत भाग लिया। कमीशन ने कहा है कि अफ्रीकियों के मस्तिष्क पर सबसे बुरा प्रभाव इस तथ्य का पड़ा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रति विदेशी पत्रों में बड़ा आक्रमणात्मक रुख है। गलत जानकारी रखने वाले आलोचक पार्थक्य और जातीय मताधिकार की नीति के विरुद्ध जल्दी में अफ्रीकियों की हिमायत को दौड़ पड़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के समाचार पत्र इन विकारों को दोहराते हैं और सब ओर से अफ्रीकियों के मस्तिष्क में यही आवाज आती है कि उसे शिकायतें हैं। ऐसी स्थिति में वह शांत कैसे रहे?

सत्ता संग्राम में सितारों का सिलसिला

राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

हिंदी पट्टी के मतदाताओं का अनुभव स्टारडम वाले जन-प्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, जबकि दक्षिण भारत में सितारे ईमानदारी से सेवा करते दिखते हैं।

चुनावी राजनीति जनसंपर्क से जब रोड शो बन जाए, तो तरह-तरह के सितारों, यानी सेलिब्रिटीज की दरकार होगी ही। दशकों पुराने निष्ठावान नेताओं को पीछे छोड़कर ये सितारे टिकट की बाजी मार ले जाते हैं। इनके स्टारडम का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता है और ये चुनाव जीतकर संसद-विधानसभा में पहुंच जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी अपवाद नहीं है, बल्कि हो सकता है कि इस बार चुनावी रण में सितारों की संख्या और भी ज्यादा हो जाए। भारत का संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, पर वैसा करने वालों से यह अपेक्षा अनुचित तो नहीं कि वह जनता और उसकी समस्याओं को समझते हुए राजनीति को गंभीरता से लें। बेशक सुनील दत्त सरीखे कुछ सितारे राजनीति में भी मिसाल साबित हुए, पर ज्यादातर हिंदी क्षेत्र के सितारे इसे भी चमक-दमक का ही खेल मान लेते हैं।

ताजा उदाहरण मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल का है। चुनाव प्रचार में एक पत्रकार ने जब उनसे क्षेत्र के मुद्दों की बाबत सवाल पूछा, तो बोले, पहले चुनाव हो जाए, फिर लोगों से बात करके समझेंगे। वैसे, वह मेरठ के ही मूल निवासी हैं। वह अच्छे नेता या अपवाद साबित हो सकते हैं, पर हिंदी पट्टी के मतदाताओं का अनुभव स्टारडम वाले जन-प्रतिनिधियों के साथ अच्छा नहीं रहा है। यही कारण है कि अक्सर अगले चुनाव में राजनीतिक दलों को अपने सितारों का विकल्प ढूंढ़ना पड़ जाता है। जैसे, इस बार पंजाब की गुरदासपुर सीट पर सनी देओल का ढूंढ़ना पड़ा या इसके पहले उनके पिता धर्मेंद्र का बीकानेर में ढूंढ़ना पड़ा था। दोनों के ही क्षेत्र में 'गुमशुदा सांसद' के पोस्टर लगने की नौबत आ गई थी। वैसे इसी परिवार की सदस्य हेमा मालिनी मथुरा से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। गिनती के लिहाज से तो शत्रुघ्न सिन्हा भी पीछे नहीं, मगर भाजपा से शुरू कर कांग्रेस से होते हुए वह तृणमूल कांग्रेस में पहुंच गए हैं। राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए

दलबदल का सहारा लेने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अकेले नहीं हैं। दिल्ली से फिर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी समाजवादी पार्टी से शुरुआत की थी। राज बब्बर भी सपा से ही कांग्रेस में आए।

भारत में राजनीति और सितारों के रिश्ते की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जा सकती है, जब पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। दरअसल राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की श्रेणी है ही ऐसे नामचीन लोगों के लिए, जिन्होंने अपने पेशेवर क्षेत्र में देश और समाज के लिए विशिष्ट योगदान दिया है, पर बाद के दशकों में लोकप्रियता भुनाने की सोच ऐसी हावी हुई कि मौके तलाशे जाने लगे। इस तलाश में विचारधारा या छवि भी बाधक नहीं बनी। मसलन, जिस *रामायण* सीरियल के राम अरुण गोविल अब चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीरियल में सीता और रावण की भूमिका निभाने वाले दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी को भी भाजपा 1991 में गुजरात से लोकसभा भेज चुकी है। भाजपा ने *महाभारत* सीरियल के कृष्ण नीतीश भारद्वाज को भी संसद भेजा था, पर इनमें से कोई भी अपनी खास राजनीतिक पहचान और समर्थक वर्ग नहीं बना पाया।

दरअसल, यही सवाल सितारों और उन्हें राजनीति में लाने वाले दलों को कठघरे में खड़ा करता है और यह धारणा बनती है कि दोनों ही लोकप्रियता को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को छलते हैं। अपने-अपने क्षेत्र में इन सितारों ने जो सफलता हासिल की है, उससे इनके बड़ी संख्या में प्रशंसक बन ही जाते हैं, जो प्रशंसक इनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं, वे चुनाव लड़ने पर इनके लिए वोट न करें, यह कैसे संभव है? मगर एक बार जीत गए, तो ज्यादातर सितारे चुनाव क्षेत्र के लिए भी ईद के चांद बन जाते हैं। आपको याद होगा कि हैदराबाद के मूल निवासी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़वाया। जीत भी गए, पर उन्होंने लोगों के लिए क्या किया? पिछली बार दिल्ली से सांसद चुने गए गौतम गंभीर को यह एहसास करने में पांच साल लग गए कि वह क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। इतना ही समय गोविंदा को लग गया था, पर वह फिर भी दौड़ में आने को बेताब हैं। पहले पंजाब से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव हार चुके हंसराज हंस को 2019 में दिल्ली से टिकट दिया गया, तो इस बार पंजाब भेजना पड़ गया।

विडंबना यह है कि ऐसे तमाम सितारों का संसद-विधानसभाओं में भी प्रदर्शन प्रायः निराशाजनक रहता है। 17 वीं लोकसभा के कामकाज के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज्यादातर सितारे उपस्थिति से लेकर प्रश्न पूछने और चर्चा में भाग लेने तक हर कसौटी पर फिसड्डी ही साबित हुए। शत्रुघ्न सिन्हा और सनी देओल के डॉयलॉग उनके किरदार से भी ज्यादा लोकप्रिय हुए, पर 17वीं लोकसभा में इन दोनों ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। सनी देओल की तो उपस्थिति भी मात्र 18 प्रतिशत रही। मानो लोकसभा में भी गेस्ट एपीयरेंस दे रहे हों। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं, पर उनका राजनीतिक अनुभव बेहद निराशाजनक रहा। अपने मित्र राजीव गांधी की मदद के लिए 1984 में इलाहाबाद से चुनाव लड़कर हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को हराने वाले अमिताभ को संसद और राजनीति, दोनों से हटना पड़ा। बेशक उनकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी से पांचवीं बार राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। वैसे, सितारों या कलाकारों की सही जगह राज्यसभा ही है।

बहरहाल, हिंदी क्षेत्र में सितारों की वैसी चमक नहीं दिखी है, जैसी दक्षिण भारत में दिखती रही है। दक्षिण में कम से कम तीन सितारे अलग राजनीतिक दल बनाकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। हिंदी पट्टी में बस एक अभिनेता देव आनंद ने राजनीतिक दल का गठन किया था, जो चल न पाया। दक्षिण में पहले अभिनेता एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और फिर उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अभिनेत्री जयललिता तो छह बार मुख्यमंत्री रहीं। आंध्र प्रदेश में भी अभिनेता नंदमुरी तारक रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनाई और तीन बार मुख्यमंत्री बने।

दरअसल, राजनीति में आने वाले सितारों को एमजीआर, एनटीआर और जयललिता से सीखना चाहिए, जो लोकप्रियता भुनाने के लिए पैराशूट प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में कूदने के बजाय अपने समर्थकों और उनके सरोकारों से हमेशा हर स्तर पर जुड़े रहे। इसीलिए वे न सिर्फ जीवनकाल में, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

लोकतंत्र की राह पर अभी बहुत आगे जाएगा अपना देश

अश्वनी कुमार | अधिवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री

यहां स्कैन करें

भारत की स्वतंत्रता के 77 वर्षों में देश की अनेक उपलब्धियां प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर देती हैं। जिस देश में 22 प्रमुख भाषाएं और 19,500 से अधिक उप-भाषाएं हों; जहां अनेक धर्मों का श्रद्धा के साथ पालन होता हो और विभिन्न जातियों का सहस्तित्व हो, ऐसे राष्ट्र को एकजुट रखना अपने आप में अनूठी उपलब्धि है। भारत विश्व में विविधता में एकता की गौरवमयी बेमिसाल पहचान है। विशेषज्ञों के अनुसार, 2035 में भारत का विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना तय है। भारत विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है। अंतरिक्ष में चांद को छूने और विश्व में 'वैक्सीन' का सबसे बड़ा उत्पादक होने का गौरव भी देश को प्राप्त है। 2004 के बाद 40 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर देश के मध्यम वर्ग में शामिल करना, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेष प्राप्ति है।

हालांकि, जहां राष्ट्र की इन प्राप्तियों पर सभी को गर्व है, वहीं हृदय में कुछ पीड़ा की अनुभूति भी है। स्वतंत्रता के 77 वर्ष उपरांत भी लाचारी, दरिद्रता, शोषण, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता और विघटनकारी राजनीति की सच्चाई जग-जाहिर है। सांविधानिक मर्यादाओं का हनन, प्रतिशोध व घृणा से दूषित सार्वजनिक संवाद और धर्म व जात-पात पर आधारित देश को विभाजित करने वाली प्रवृतियां चिंताजनक हैं। अधिकांश राजनेताओं में विवेक का अभाव, व्यक्तिगत शत्रुता को जन्म देने वाली राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, उद्योगपतियों के काले-सफेद चंदे पर निर्भर चुनाव प्रक्रिया, चारों ओर धन का प्रलोभन, अमीर का अहंकार, निर्धन का दुत्कार, सत्ता का पूजन, असहायों के प्रति असंवेदनशीलता, किसी उत्कृष्ट लोकतंत्र का दर्शन तो नहीं हो सकते। जिस तरह अभद्र टिप्पणियों एवं अप्रमाणित आरोपों द्वारा हर दिन नेताओं व अन्य लोगों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सिद्धांतहीन गठबंधन को केवल सत्ता प्राप्ति के लिए उचित ठहराया जा रहा है, उससे हमारी सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

सिद्धांतहीन गठबंधनों को सत्ता के लिए उचित ठहराया जा रहा है, हमारी सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है।

ऐसा सामाजिक वातावरण, जिसमें कर्म, फर्ज और त्याग की भावना को भौतिक लाभ एवं नुकसान के तराजू में तौला जाए, किसी सभ्य समाज और गरिमामय चलन का दर्शन तो नहीं है। क्यों प्रेमियों के जज्बात की पवित्रता और औचित्य का 'सर्टिफिकेट' और उनकी निजता का मानवीय अधिकार तंत्र का मोहताज है? क्यों लोकशक्ति अनेक मौकों पर आमजन के सम्मान को सुनिश्चित रखने में विफल हो जाती है? क्यों नीची राहें हैं ऊंचाइयों की? जिस देश में अभी भी अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित रहकर दरिद्रता के बोझ से दबकर अपनी बेबसी की नुमाइश के लिए मजबूर हों, वह देश बापू के सपनों का भारत नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी की इस संवेदनशील पीड़ा की अभिव्यक्ति को सलाम करता हूं- *टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी,/ अंतर को चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी।*

ऐसे प्रश्नों का मकसद किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल को दोषी ठहराना नहीं है। सवाल, सत्य और अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने का है, ताकि इन त्रुटियों और चुनौतियों से जूझा जा सके। लोकतांत्रिक मर्यादा का तकाजा है कि जनादेश का आदर हो, चाहे वह किसी भी दल या गठबंधन के पक्ष में हो और निष्पक्ष चुनावों द्वारा चुनी हुई सरकारें सभी का प्रतिनिधित्व करें और सर्वस्व के हित में समर्पित हों। आम जनता की अपेक्षा है कि भविष्य में बनने वाली केंद्र व राज्य सरकारें सभी के लिए और कल्याणकारी सिद्ध हों। देशवासियों की इस परख पर हमारे राजनेता पूरा उतरेंगे या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भारतीय लोकतंत्र एवं हमारी कल्पना के न्यायसंगत राष्ट्र का भविष्य तय करेगा।

इतिहास गवाह है कि अंततः आदर्शवाद व आशावाद की विजय निश्चित है। प्रगतिशील भारत निराशाजनक नहीं हो सकता। वह सुनहरी सुबह जिसका इंतजार है, जल्द आएगी और हम सब मिलकर उस सुबह को लाएंगे। रामधारी सिंह 'दिनकर' की इस रचना से लेख को समाप्त कर रहा हूं- *हो तिमिर कितना भी गहरा,/ हो रोशनी पर लाख पहरा,/ सूर्य को उगना पड़ेगा,/ फूल को खिलना पड़ेगा।*

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बड़ा बनिए और बड़ा बनाइए

रामजी अपने पिता के वरदान-स्वरूप जंगल जा रहे थे। उन्हें वनवासी होने का वरदान दिया गया था। कैकेयी ने मांगा था, रामजी को 14 वर्षों का वनवास होगा और भरत को राजा बनाया जाएगा। राम वनवासी वेश धारण करके वन की ओर निकल गए। उस पूरी वन-यात्रा में, पिता-आज्ञा के पालन की यात्रा में रामजी ने संपूर्ण मानवता को लाभ पहुंचाया।

यात्राओं का एक विशेष स्वरूप होता है। जैसे, वनस्पति वैज्ञानिकों की यात्रा, खनिज वालों की यात्रा, राजनेताओं की यात्रा। राजनेता यात्रा करता है, तो अपने वोट बैंक को मजबूत करता है। खनिज पदार्थों का अन्वेषण करने वाले यह पता लगाते हैं कि कहां-कहां खनिज तत्व हैं। रामजी भी वनवास यात्रा पर निकले, तो वहां उन्होंने केवल अपने वनवासी स्वरूप को ही नहीं बनाए रखा, बल्कि संपूर्ण संसार को वनवासी होने की प्रेरणा भी वह दे सके। रामभाव में आने की प्रेरणा दे सके। वनवासी होने का अभिप्राय है, भौतिक जीवन से संन्यासी जीवन की ओर बढ़ना। बालों को जटा बना लिया, शैंपू-साबुन की जरूरत नहीं। पैरों में जूते की जरूरत नहीं। कोई श्रृंगार नहीं, कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं; वृक्ष के नीचे रहना, गांव में भी नहीं जाना है। ऋषियों के बीच रहना, अच्छी संगत में रहना है, वनवासी जातियों की परंपराओं से जुड़ना है। उन्होंने 14 वर्षों के वनवास काल में संपूर्ण संसार को वनवासी जीवन का आदर्श दिया।

केवट वाला प्रसंग आप सबको सुनाना चाहता हूं। रामजी केवट के पास गए कि मुझे नदी पार जाना है। केवट ने कहा कि पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। केवट को वनवासी से क्या लेना-देना? उसका काम तो नाव चलाना और अपनी मजदूरी लेना है। अब रामजी से अच्छा ग्राहक कौन मिलेगा? अगर अभी नगद भुगतान नहीं होगा, तो उधारी ही लिखवा लेता। उसको क्या कहा जाएगा कि जो रोज कमाता है, रोज खाता है। जिसका जीवन रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अर्जन और भोग का माध्यम है। वह कौन-सा प्रयास था, कौन-सी बात थी कि केवट ने चरण धोने की बात कही? उसमें ऐसा परिवर्तन हुआ रामजी को देखकर, रामजी को छूकर,

रामजी भी वनवास यात्रा पर निकले, तो वहां उन्होंने केवल अपने वनवासी स्वरूप को ही नहीं बनाए रखा, बल्कि संपूर्ण संसार को वनवासी होने की प्रेरणा भी वह दे सके।

उनसे बातें करके कि जब रामजी मजदूरी देने लगे, तो उसने कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।

एक व्यक्ति अपने पिता की आज्ञा से राजा होते-होते जंगल जा रहा है। जंगल जाते-जाते भी छोटे से छोटे कर्म और छोटी से छोटी सोच, छोटी शिक्षा वालों को भी रामभाव में लाने के प्रयास में जुटा है। जब रामजी केवट को मजदूरी दे रहे हैं, तो उत्तर सुनिए, *नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुःख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी। अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीन दयाल अनुग्रह तोरें।*

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

पोप फ्रांसिस | धर्मगुरु

अपनी प्रार्थनाओं में हमें उन लाखों बच्चों की दारुण पुकार को जरूर शामिल करना चाहिए, जिन्हें त्याग दिया गया है, जो हाशिये पर हैं या जिनको स्वास्थ्य देखभाल व स्कूली शिक्षा तक मयस्सर नहीं!

संहिता की धज्जियां उड़ा रहे राजनेता

देश में साफ-सुथरा चुनाव कराने के लिए दशकों पहले निर्वाचन आयोग ने एक आदर्श आचार संहिता बनाई थी। आम चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही यह संहिता देश भर में लागू हो जाती है। विधानसभा चुनाव के मामले में संबंधित राज्य में ऐसा होता है। इस संहिता के मुताबिक, इसके लगने के बाद न तो किसी तरह की सरकारी घोषणाएं की जा सकती हैं और न कोई शिलान्यास या उद्घाटन किया जा सकता है। सरकारें बगैर आयोग की अनुमति के अधिकारियों के तबादले तक नहीं कर सकतीं। सरकारी गाड़ी, बंगले और विमान का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रत्याशी के लिए रैली या जुलूस निकालने से पहले स्थानीय पुलिस की अनुमति जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकता और न ही इनके ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है, जिनसे सामाजिक तनाव पैदा हो। इसी तरह, किसी के मकान पर बगैर अनुमति नारे लिखने या झंडे लगाने की मनाही है। वोटरों को शराब या पैसे का वितरण प्रतिबंधित है। और भी बहुत कुछ है।

ये सारे प्रावधान वाकई काफी अच्छे हैं और अगर इनको जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए, तो हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दुनिया भर के लिए उदाहरण बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर वास्तव में हो क्या रहा है? जिस आयोग पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी है। उस पर ही तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। एक समय था कि आचार संहिता लगने के बाद चुनावी सर्वे पर पूर्णतः रोक लग जाती थी। आज फर्जी सर्वे के जरिये वोटरों को गुमराह करने का काम धड़ल्ले से हो रहा है और आयोग इसके खिलाफ न अदालत की शरण ले रहा है और न ही खुद अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर पा रहा है। कई नेता और प्रत्याशी तो खुलेआम भगवान की तस्वीरें लेकर वोट मांग रहे हैं, और आयोग मूकदर्शक बना हुआ है।

चुनाव आयोग को वैसी ही सख्ती दिखानी होगी, जैसी कभी टीएन शेषन, जेएम लिंगदोह और टीएस कृष्णमूर्ति के समय उसने दिखाई थी। उसी दौर में हमने देखा-सुना कि नफरती भाषण के लिए बाल ठाकरे से वर्षों तक मतदान का अधिकार छीन लिया गया। उप-प्रधानमंत्री आडवाणी को जिला कलेक्टर ने रात 10 बजे के बाद सभा को संबोधित करने से विनम्रतापूर्वक रोक दिया था। पर आज किसी पार्टी को आयोग का कोई डर नहीं। आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं।

मेघना राय, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
आदर्श आचार संहिता

चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय

आदर्श आचार संहिता का मकसद है, भारतीय लोकतंत्र में सभी दलों को समान अवसर मुहैया कराना। इसीलिए सत्ताधारी लोगों के लिए इस समय चुनाव प्रचार के वास्ते सरकारी साधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। आयोग की सख्ती के कारण ही इस बार भी सभी नेता निजी साधनों का उपयोग करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बल्कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार अब तक आपत्तिजनक बयान या नफरती बोल भी कम ही सुनने को मिले हैं और जैसे ही इस किस्म की शिकायत मिली, आयोग ने त्वरित कार्रवाई की। चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की जांच हो या पार्टी के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के चुनाव प्रचार पर 48 घंटों के लिए रोक लगाने का मामला या फिर केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता शोभा करंदलाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कूच बिहार के दौरे पर रोक लगाने की बात, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर काफी गंभीर है, और पुख्ता सबूत मिलने पर वह कार्रवाई से पीछे नहीं हट रहा। हां, जिस शिकायत के बारे में उसे ऐसा लगता है कि यह बहुत गंभीर आरोप नहीं, उसमें वह आरोपी को हिदायत देकर छोड़ देता है। यह आम बात है कि चुनाव के समय कई शिकायतें महज राजनीतिक आरोप होती हैं।

कुछ विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव आयोग ईडी, सीबीआई आदि की कार्रवाई पर भी रोक लगा दे, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया है कि वह आपराधिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग का यह तर्क बिल्कुल सही है। आखिर ये जांच एजेंसियां किसी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करतीं, बल्कि वे तो आर्थिक या सिविल अपराधों से जुड़े मामलों की जांच कर रही हैं। ऐसी जांच से लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित नहीं होती, क्योंकि वे तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपना कार्य कर रही हैं। इसलिए उन पर दबाव बनाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और प्रतिष्ठा को लेकर हमारा चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। और ऐसा टीएन शेषन के बाद से ही देखने को मिला है। इसलिए उस पर अनावश्यक तंज-तीर बरसाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई नेता आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो पुख्ता सबूत के साथ आयोग के संज्ञान में लाने का काम करना चाहिए। कुछ लोग इसमें बेजा अदालत को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं।

विकास शर्मा, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

आत्मा की जागृति में ही जीवन की सार्थकता है

समान संहिता की जमीन

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस संहिता को स्वीकार किया, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर सहमति बनेगी। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए यह अवश्य कहा था कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका यह आशय कदापि न था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा की जाएगी। सच यह है कि संविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रीय सत्ता ने समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। उलटे जब भी किसी दल और यहां तक कि उच्चतर न्यायपालिका ने इसकी आवश्यकता जताई तो वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया गया। यह काम अब भी किया जा रहा है। बीते दिनों ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं। इस संहिता का विरोध संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के अनदेखी भी है। आखिर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार आदि के कानून एक जैसे हों?

समान नागरिक संहिता का निर्माण भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है। चूंकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को पूरे कर चुकी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे। घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के निर्माण की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतीय समाज की आवश्यकता भी, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे, लोगों में यह आवश्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारतवासी एक जैसे कानून से संचालित हैं। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही, पंथ-मजहब की विभाजनकारी राजनीति पर भी लगाम लगाएगी। समान नागरिक संहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर झूठ के सहारे वैसा दुष्प्रचार न होने पाए, जैसा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया गया।

पुलिस के लिए चुनौती

पंजाब में एक बार फिर धार्मिक संगठन के नेता की हत्या के मामले में पाकिस्तान के आतंकी माड्यूल का हाथ सामने आने से पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। इससे पहले भी टारगेट किलिंग की कई घटनाएं राज्य में हो चुकी हैं। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी, जालंधर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जगदीश गगनेजा, फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या सहित कई और वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। अब नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दुकान में घुसकर हत्या चिंतित करने वाली है। यह हत्याकांड इसलिए और गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव के लिए गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। राज्य में पहली जून को मतदान होना है। अभी लगभग डेढ़ माह का समय है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को यह देखना होगा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से माहौल खराब करने की साजिश कामयाब न होने पाए। विहिप पदाधिकारी की हत्या में किस किस का हाथ है, इसका पता शीघ्र लगाया जाना चाहिए। आखिर हत्या करवाने वालों का मकसद क्या है, इसके बारे में गहन जांच होनी चाहिए और यह यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। चूंकि पाकिस्तान सहित कुछ और देशों में छिपे असामाजिक तत्व सीमा पार से पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रचते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। विदेश में छिपे वांछित आतंकवादियों एवं गैंगस्टरों को भारत लाने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जानी चाहिए। जब तक भारत लाकर देश के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक आतंकियों एवं गैंगस्टरों का दुस्साहस बढ़ता ही जाएगा।

नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष की हत्या में पाकिस्तान के आतंकी माड्यूल का हाथ सामने आना अत्यंत गभीर मामला है

राहुल गांधी के सपनों का भारत

बलबीर पुंज

राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की जो बात कह रहे हैं वह तो देश को पीछे ले जाने वाली है

लोकसभा चुनाव की गहमागहमी चरम पर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे मुखर आलोचक बनकर उभरे हैं। मोदी का विरोध उनकी पार्टी और व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इसकी झलक उनके कुछ हालिया बयानों और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से मिल जाती है। बीते दिनों तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि 'हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे से पता लगाएंगे कि देश का धन किसके और कौन से वर्ग के हाथ में है, जो आपका हक बनता है, वह हम आपको देने का काम करेंगे।' इसके जरिये राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की बात कह रहे हैं। यह नीति कोई नई नहीं है। वास्तव में यह राहुल का मौलिक राजनीतिक-वैचारिक चिंतन भी नहीं। वह उस उधार के दर्शन का प्रतिबिंब है, जिसे 1969-71 में उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वामपंथियों से राजनीतिक समझौते के अंतर्गत आउटसोर्स किया था। उस समय के भारत में भुखमरी और महंगाई के साथ टेलीफोन, सीमेंट, इस्पात, कार-स्कूटर से लेकर दूध-चीनी, तेल-अनाज आदि खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी और उसके लिए लगने वाली लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखती थीं। गरीबी हटाने और समानता लाने हेतु देश में 97.7 प्रतिशत तक आयकर था। इस मार्क्स-लेनिन-स्टालिन प्रेरित समाजवादी व्यवस्था से देश में कालाधन, भ्रष्टाचार, गरीबी और कपट कई गुना बढ़ गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि 1991 में देश को अपनी देनदारियों को पूरा करने हेतु विदेशी बैंकों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। इस अभिशाप रूपी वाम-विचारधारा से तब भारत ही ग्रस्त नहीं था। चीन में माओ (1949-76) और कंबोडिया में पोल पाट का शासनकाल (1975-79) भी इसी चिंतन का भयावह परिणाम देख चुका है। वहां भी सामाजिक-आर्थिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निजी संपत्ति-स्वामित्व और धन-संपदा को समाप्त कर दिया था। ऐसे अव्यावहारिक उपायों से न केवल मानवाधिकारों का भीषण हनन हुआ, अपितु करोड़ों लोगों की मौत तक हो गई।

आज चीन इसीलिए चमक रहा है, क्योंकि चीनी सत्ता अधिष्ठान समय को भांपते हुए अपनी विशुद्ध वाम-नीतियों को दशकों पहले तिलांजलि दे चुका है। वर्तमान भारत भी पिछली सदी के अंतिम दशकों तक जारी नीतियों से उपजी लचर स्थिति से बाहर निकलकर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कालबाह्य वामपंथी जुमले अब भारतीय जनमानस को आकर्षित नहीं करते। आज का युवा आकांक्षावान है। वह समृद्धि और आर्थिक विकास को लांछित नहीं, अपितु अपनाना चाहता है। इस आमूलचूल परिवर्तन में नीतिगत सुधारों के साथ भारतीय उद्यम क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे एक समय पनपने नहीं दिया गया।

करीब 50 वर्ष पहले जिन अपशब्दों से वामपंथी-पश्चिमी समूह टाटा-बिरला जैसे औद्योगिक समूहों को निशाने पर रखते थे, वही अब अंबानी-अदाणी समूह के लिए उपयोग होते हैं। राहुल गांधी भारतीय औद्योगिक घरानों को तो कोसते है, परंतु विदेशी कंपनियों के खिलाफ वैसी मुखरता नहीं दिखाते। कोरोना काल में स्वदेशी कोविड टीके के बजाय विदेशी वैक्सीन पर राहुल का अधिक विश्वास इसका प्रमाण है। इसका कारण क्या है? क्या राहुल औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं?

राहुल गांधी भारत को राष्ट्र के बजाय 'राज्यों का संघ' बता चुके हैं। यह विचार उन्हीं विदेशी विचारधाराओं के अनुरूप है, जिसमें देश के मूल सनातन दर्शन, संस्कृति, पहचान और इतिहास के प्रति हीन-भावना और भारत को 'राष्ट्र' नहीं मानने का चिंतन है। जब राहुल के सहयोगी दल द्रमुक के नेताओं ने खुलकर 'सनातन को मिटाने' का आह्वान किया, तब वह न केवल चुप रहे, अपितु उनकी पार्टी के कार्ति चिदंबरम और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे इसका समर्थन करते नजर आए। राहुल को भारत की पहचान श्रीराम के जन्मभूमि मंदिर जाना भी स्वीकार नहीं। उनके लिए बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिकता के पर्याय हैं, परंतु वह 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरित तत्वों के खिलाफ अक्सर मौन रहते हैं। इसी प्रकार उनके 'जितनी आबादी, उतना हक' सरीखे विचार में राष्ट्रीय पहचान 'भारतीयता' गौण होकर जाति प्रमुख हो जाती है। इससे हिंदू समाज में जाति विभाजन की खाई और गहरी होगी। यह राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होगा।

इधर राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर जिस संविधान के बदलने-खत्म करने का

अवधेश राजपूत

खौफ दिखा रहे हैं, उसकी पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि भारतीय संविधान में सौ से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस ने ही किए हैं। राहुल गांधी ने 2013 में अपनी सरकार के एक अध्यादेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था। असल में राहुल 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं कि केवल उन्हें ही कोई भी विचार रखने और अपने अनुकूल 'लोक' (जनमानस) और 'तंत्र' (मीडिया-न्यायालय सहित) चलाने का 'दैवीय अधिकार' है। अब राहुल को मोदी का विकल्प बनना, उनसे वैचारिक-राजनीतिक रूप से अलग दिखना है। इस होड़ में वह जो वादे और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भारत कैसा होगा? क्या लोकलुभावन नीतियों के नाम पर सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज की वापसी होगी, जिसमें अतीत के दौर की तरह रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी के साथ कालाबाजारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार चरम पर था? क्या उनके विचारों पर चलने वाली सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी या उस स्थिति में पहुंचा देगी, जब देश की आर्थिकी तबाह हो गई थी? क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में बदहाली का कारण इसी प्रकार की राजनीति नहीं रही? इस पर विचार करते हैं कि अगले पांच वर्षों में भारत की तस्वीर कैसी होगी? क्या वह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप बनेगी, जिसमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप स्थापित करने का लक्ष्य है या फिर वैसी जिसका तानाबाना राहुल गांधी बुन रहे हैं? इसका उत्तर मतदाताओं के विवेक पर निर्भर है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे हैं

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच बढ़े। फाइल

लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आइआइएम-अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आइआइटी-मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है। जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है। इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है।

क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजरायल ने भी यह दिखा दिया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है।

अनुसंधान एवं विकास ही बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई। सवाल यह उठता है कि शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू नवप्रवर्तन क्यों पैदा करता है? शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य देशों ने दिया। जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 प्रतिशत है और विश्व औसत 1.8 प्रतिशत से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है।

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे। इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सांसारिक सुख

विकास के दो पथ हैं-बाहरी और आंतरिक। आज बाहरी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक सोच ने इसे अकल्पनीय गति दी है। विकास की हर दौड़ में वह आगे बढ़ता जा रहा है। आज बाह्य विकास इतना हुआ है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना की आनन-फानन में अवगति हो जाती है, लेकिन स्वयं के भीतर घटित होने वाली घटना का कुछ अता-पता भी नहीं है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। बाहर तो उजाला फैलता जा रहा है और भीतर गहन अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अंधकार को हटाए बिना उजाला कैसे मिल सकता है? उजाले के बिना सुख, शांति और तृप्ति कहां है?

मनुष्य की जिस ऊर्जा का उपयोग अंधकार को हटाने के लिए होना चाहिए था, वह निरर्थक कार्यों में बह रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग चेतना के रूपांतरण के लिए होना चाहिए था, वह बाहरी संचालन में खप रही है, क्योंकि आज आदमी केवल देह की परिधि में ही जी रहा है। वह संसार के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। उसकी समग्र दृष्टि बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस बाह्य दौड़ को ही वह पूर्णता की कसौटी समझ रहा है। वह इस सच्चाई को भूल रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो सुखानुभूति वह कर रहा है, उसे केवल मृगतृष्णा ही कहा जा सकता है। मनुष्य को सुखाभास की अनुभूति से स्वयं को ऊपर उठाकर आनंद एवं तृप्ति की अनुभूति में प्रविष्ट होना है।

आनंद आत्मा का स्वभाव है और सुख-दुख शरीर का स्वभाव है। इसलिए निजानंद में प्रवेश करना अपेक्षित है। स्वयं के भीतर डुबकी लगाकर ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसने सर्वस्व पा लिया। सांसारिक सुखों की मृगमरीचिका से बाहर निकलकर अपने ही अंतस की गहराई में उतर जाना श्रेयस्कर है।

ललित गर्ग

सर्वोपरि हो बच्चों की सुरक्षा

डा. मोनिका शर्मा

बच्चों के घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की यात्रा से जुड़ी लापरवाही देश के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती है

पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई स्कूल बस दुर्घटना ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। जानलेवा लापरवाही को सामने रखती यह दुर्घटना हर स्तर पर बरती गई असावधानी का परिणाम है। एक निजी स्कूल की उस बस में हादसे के समय करीब 40 बच्चे सवार थे। सबसे भयावह पक्ष तो यह है कि स्कूल बस का चालक नशे में था। बच्चों और स्थानीय लोगों के अनुसार चालक नशे में अनियंत्रित गति से बस चला रहा था। साथ ही वाहन रखरखाव से जुड़े कागजातों में भी उस बस के दुरुस्त न होने की बातें सामने आई हैं। ऐसे में मासूमों का जीवन छीनने और देशभर के अभिभावकों को भय के घेरे में लाने वाला यह दर्दनाक हादसा कई सवाल उठाता है।

दुखद है कि कुछ ही दिनों में ऐसे हादसे भुला दिए जाते हैं। न तो स्कूली वाहनों के रखरखाव की स्थिति को गंभीरता से लिया जाता है और न चालकों के प्रशिक्षण को। यही वजह है कि बच्चों का अनमोल जीवन पहली बार ऐसी लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ा है। बच्चों के घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की यात्रा से जुड़ी लापरवाही देश के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती है। कई मोर्चों पर असावधानी बरतने के उदाहरण पहले भी सामने आए हैं। अपने बच्चों को खो देने वाले परिवार कभी न खत्म होने वाली पीड़ा के भंवर में फंस जाते हैं। महेंद्रगढ़ में हुए इस हादसे में तो एक परिवार ने अपने दो बच्चों को खोया है। सवाल यह है कि क्यों बिना किसी गलती के इन अभिभावकों को जीवन भर के लिए इस दुख का दंश मिला है? चिंतनीय यह भी है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद कई बच्चे अपनी शारीरिक चोट से नहीं उबर पाते और सदा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। साथ ही ऐसे हादसे उस समय वाहन में सवार बच्चों के मनोविज्ञान पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। बालमन को भय और अनिश्चितता के घेरे में ले आते हैं।

कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहां बच्चों का स्कूली सफर कई तरह के खतरों से भरा है। कहीं छोटे वाहन जैसे आटो और वैन में एक निश्चित संख्या से ज्यादा बच्चे सवार होते हैं तो कहीं स्कूलों की बड़ी बसों के चालक सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हुए दिख जाते हैं। यहां तक कि रफ्तार से जुड़े नियम-कानून का पालन भी नहीं किया जाता। इसके चलते न केवल बच्चों की जान जोखिम में रहती है, बल्कि परिजनों को भी नौनिहालों के साथ किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। ध्यातव्य है कि ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार की गई है। जरूरी है कि हर स्तर पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इन नियमों का पालन किया जाए। अभिभावक भी जागरूक होकर स्कूल बसों की सुरक्षा की पड़ताल करते रहें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अपने-अपने राम

प्रवीन लखेड़ा का आलेख 'जन-जन तक पहुंचे श्रीराम का संदेश' सचमुच में विचारणीय है। वर्तमान भारत की स्वतंत्रता के अमृतकाल की सांप्रतिक पीढ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे अपने जीवनकाल में अयोध्या में सदियों बाद भगवान राम के मंदिर की सुखबर ने आह्लादित किया है। अब इस पीढ़ी का दायित्व है कि रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए वह अपने-अपने मर्यादित राम का अनुसरण करे और अपने दायित्वों का इस प्रकार निर्वहन करे कि उनमें स्वार्थ की कोई झलक न हो। कोई भी समाज अथवा राष्ट्र उसके व्यक्तियों के प्रयासों से ही श्रेष्ठ बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रत्येक आचरण हमें संजीवनी देता है। उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़कर और उसे जीवन में उतारकर ही हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। ऐसा भारत जिसमें कोई ऊंच-नीच न हो, समाज में कोई कलह न हो, समस्याओं की नहीं अपितु समाधान की बात हो, केवल अधिकारों की नहीं, अपितु कर्तव्यों की आवाज उभरे। ऐसा भारत जिसमें कोई भूखा न सोए, लोग सदाचार के बल पर आगे आएं, प्रकृति से कोई खिलवाड़ न हो। ऐसा भारत जहां हर ओर खुशहाली हो, एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो, हर वर्ग केवल राष्ट्रोत्थान की बात करे। ऐसा भारत जिसमें हर बच्चा सुशिक्षित हो, सुसंस्कारित हो, आबाल-वृद्ध सभी अपने-अपने दायित्वों को समझें और पुरजोर उनका निर्वहन करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम हमारी आस्था-विश्वास को प्रबल करते हैं। हमारे संस्कारों को नई ऊर्जा देते हैं। वह जातीय गौरव, ऊंच-नीच को ठुकराते हैं। राम हमें कर्तव्य-पालन का अनूठा पाठ पढ़ाते हैं। राम तो जीवन के हर पक्ष में समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनके आदर्शों का अनुकरण ही उनका सही रीति से वंदन हैं, अभिनंदन है। उनके आदर्श और उनकी मर्यादाओं के पाठ हर क्रंदन का समाधान हैं। धन्य हैं हम कि रघुराज विराजे हैं 'सुखधाम'। प्रभु श्रीराम की प्रीति सभी पर बनी रहे।

yograj62@gmail.com

मेलबाक्स

कोर्ट की फटकार

ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर याचिकाकर्ता को झिड़कते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बैलेट पेपर वाले बहुत चुनाव देखे हैं। तब कैसे बूथ लूट लिए जाते थे। छोटे-छोटे देश बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं, पर भारत में जहां 97 करोड़ मतदाता हैं, वहां भले ही 70 करोड़ से अधिक वोट न पड़ें, बैलेट पेपर तो 97 करोड़ ही छपवाने पड़ेंगे। लाखों बैलेट बाक्स की आवश्यकता होगी। उनको लाने ले जाने की व्यवस्था बहुत ही कठिन होगी। मतगणना में ईवीएम की तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा। ईवीएम को काम में लाने के पहले सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया जाता है कि उसमें पहले से कोई वोट नहीं है। पोलिंग समाप्त होने पर सभी उपस्थित प्रतिनिधि ईवीएम के सील हो जाने पर हस्ताक्षर करते हैं और मतगणना प्रारंभ होने पर सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम की सील टूटी न हो और उस पर पूर्व के हस्ताक्षर मौजूद हों। किसी भी ईवीएम को इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाता है। कुछ बूथ के वोटों का मिलान वीवीपैट से किया जाता है। अतः ईवीएम पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

नकारात्मक चुनाव प्रचार

कांग्रेस के एक-से-एक बड़े नेता को उसके अपने ही शीर्ष नेतृत्व की राजनीति-रणनीति समझ में नहीं आ रही है। मोदी विरोध की अति तीव्रता ने उनके प्रचार अभियान को नकारात्मक बना दिया है। अब वह धमकी देने पर आमादा हैं। भारत में कभी ऐसी राजनीतिक संस्कृति नहीं रही है। राहुल गांधी शायद यह सोचने में नाकाम हैं कि जनता पर उनकी इस बात का कैसा प्रभाव पड़ेगा? किसी के लगातार चुनाव जीतने से लोकतंत्र और संविधान को आघात पहुंचाने वाला नहीं है। देश का राजनीतिक इतिहास लंबा रहा है। ऐसे किसी दुस्साहस का जवाब देना मतदाताओं को आता है। लिहाजा नकारात्मक चुनाव प्रचार से परहेज करे कांग्रेस।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) गुरुवार, 18 अप्रैल, 2024 : चैत्र शुक्ल - 10 वि. 2081

आत्मा की जागृति में ही जीवन की सार्थकता है

समान संहिता की जमीन

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस संहिता को स्वीकार किया, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर सहमति बनेगी। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए यह अवश्य कहा था कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका यह आशय कदापि न था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा की जाएगी। सच यह है कि संविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रीय सत्ता ने समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। उलटे जब भी किसी दल और यहां तक कि उच्चतर न्यायपालिका ने इसकी आवश्यकता जताई तो वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया गया। यह काम अब भी किया जा रहा है। बीते दिनों ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं। इस संहिता का विरोध संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के अनदेखी भी है। आखिर इसमें क्या समस्या है यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार आदि के कानून एक जैसे हों? समान नागरिक संहिता का निर्माण भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है। चूंकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को पूरे कर चुकी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे। घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के निर्माण की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतीय समाज की आवश्यकता भी, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित अलग-अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरे, लोगों में यह आवश्यक संदेश नहीं जा रहा है कि हम सब भारतवासी एक जैसे कानून से संचालित हैं। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही, पंथ-मजहब की विभाजनकारी राजनीति पर भी लगाम लगाएगी। समान नागरिक संहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर झूठ के सहारे वैसा दुष्प्रचार न होने पाए, जैसा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया गया।

हादसों से सबक लें लोग

आए दिन हो रहे हादसों से भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। जानबूझकर यातायात नियमों का उल्लंघन करना चिंताजनक है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो नियमों की अनदेखी कर खुद की जान तो खतरे में डालते ही हैं, उनके कारण दूसरों की भी जान चली जाती है। नियमों का अगर पालन किया गया होता तो पटना के रामलखन पथ में हादसे में सात लोगों की मौत नहीं हुई होती। इस हादसे की वजह ओवरलोड और तेज गति बताई गई। कहने की जरूरत नहीं कि नियमों का पालन करने से हादसों को नियंत्रित किया जा सकता है। वाहन चालकों को यह समझना होगा कि नियमों का अनुपालन नहीं करना कितना खतरनाक हो सकता है। सड़कों पर वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचना होगा। ओवरटेक करने के प्रयास में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। क्षमता से अधिक यात्रियों को वाहनों पर लादने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगानी होगी। पुलिस प्रशासन को इसके लिए नियमित अभियान चलाना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण भी हादसों के कारण बनते हैं। सड़कों पर ढाबे के निकट ट्रकों की कतार लगी रहती है। रात के समय अक्सर इनसे टकराकर दुर्घटनाएं होती हैं। इनपर भी कड़ाई की जरूरत है। कुछ इलाकों में ब्लैक स्पाट चिह्नित किए गए थे। अकेले मुजफ्फरपुर में 54 ब्लैक स्पाट हैं, लेकिन इन जगहों पर कोई संकेतक नहीं है। कुछ तीखे मोड़ पर साइनबोर्ड लगाए गए थे, लेकिन अब ये नहीं दिखते। इसकी अनदेखी घातक सिद्ध होगी। शहरों में बाइक सवार दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। जिम्मेदार अधिकारियों को सख्ती बढ़ानी होगी। कुछ ही दिनों पहले परिवहन विभाग ने यातायात से जुड़े अधिकारियों को गाड़ियों की जांच के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस दिए थे, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से आनलाइन जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है।

आए दिन हो रहे हादसों से सबक लेने की जरूरत है। लोग अपने वाहन नियंत्रित तरीके से चलाएं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या चुनावी बांड से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की मांग सही है?

आज का सवाल
क्या रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई से अन्य नेता सबक लेंगे?

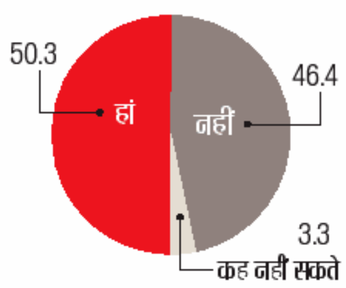

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राहुल गांधी के सपनों का भारत

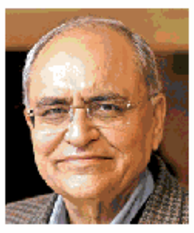

बलबीर पुंज

राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की जो बात कह रहे हैं वह तो देश को पीछे ले जाने वाली है

लोकसभा चुनाव की गहमागहमी चरम पर है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे मुखर आलोचक बनकर उभरे हैं। मोदी का विरोध उनकी पार्टी और व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल कैसा भारत बनाना चाहते हैं? इसकी झलक उनके कुछ हालिया बयानों और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से मिल जाती है। बीते दिनों तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि 'हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे से पता लगाएंगे कि देश का धन किसके और कौन से वर्ग के हाथ में है, जो आपका हक बनता है, वह हम आपको देने का काम करेंगे।' इसके जरिये राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर उसके पुनर्वितरण की बात कह रहे हैं। यह नीति कोई नई नहीं है। वास्तव में यह राहुल का मौलिक राजनीतिक-वैचारिक चिंतन भी नहीं। वह उस उधार के दर्शन का प्रतिबिंब है, जिसे 1969-71 में उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वामपंथियों से राजनीतिक समझौते के अंतर्गत आउटसोर्स किया था। उस समय के भारत में भुखमरी और महंगाई के साथ टेलीफोन, सीमेंट, इस्पात, कार-स्कूटर से लेकर दूध-चीनी, तेल-अनाज आदि खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी और उसके लिए लगने वाली लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखती थीं। गरीबी हटाने और समानता लाने हेतु देश में 97.7 प्रतिशत तक आयकर था। इस मार्क्स-लेनिन-स्टालिन प्रेरित समाजवादी व्यवस्था से देश में कालाधन, भ्रष्टाचार, गरीबी और कपट कई गुना बढ़ गया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि 1991 में देश को अपनी देनदारियों को पूरा करने हेतु विदेशी बैंकों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। इस अभिशाप रूपी वाम-विचारधारा से तब भारत ही ग्रस्त नहीं था। चीन में माओ (1949-76) और कंबोडिया में पोल पाट का शासनकाल (1975-79) भी इसी चिंतन का भयावह परिणाम देख चुका है। वहां भी सामाजिक-आर्थिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निजी संपत्ति-स्वामित्व और धन-संपदा को समाप्त कर दिया था। ऐसे अव्यावहारिक उपायों से न केवल मानवाधिकारों का भीषण हनन हुआ, अपितु करोड़ों लोगों की मौत तक हो गई।

आज चीन इसीलिए चमक रहा है, क्योंकि चीनी सत्ता अधिष्ठान समय को भांपते हुए अपनी विशुद्ध वाम-नीतियों को दशकों पहले तिलांजलि दे चुका है। वर्तमान भारत भी पिछली सदी के अंतिम दशकों तक जारी नीतियों से उपजी लचर स्थिति से बाहर निकलकर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कालबाह्य वामपंथी जुमले अब भारतीय जनमानस को आकर्षित नहीं करते। आज का युवा आकांक्षावान है। वह समृद्धि और आर्थिक विकास को लांछित नहीं, अपितु अपनाना चाहता है। इस आमूलचूल परिवर्तन में नीतिगत सुधारों के साथ भारतीय उद्यम क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे एक समय पनपने नहीं दिया गया।

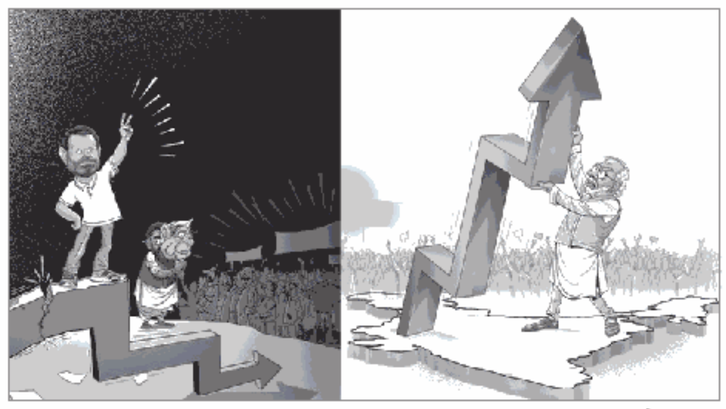

अवधेश राजपूत

करीब 50 वर्ष पहले जिन अपशब्दों से वामपंथी-पश्चिमी समूह टाटा-बिरला जैसे औद्योगिक समूहों को निशाने पर रखते थे, वही अब अंबानी-अदाणी समूह के लिए उपयोग होते हैं। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी भारतीय औद्योगिक घरानों को तो कोसते है, परंतु विदेशी कंपनियों के खिलाफ वैसी मुखरता नहीं दिखाते। भीषण कोरोना काल में स्वदेशी कोविड टीके के बजाय विदेशी वैक्सीन पर राहुल का अधिक विश्वास इसका एक प्रमाण है। इसका कारण क्या है? क्या राहुल औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं?

राहुल गांधी भारत को राष्ट्र के बजाय 'राज्यों का संघ' बता चुके हैं। यह विचार उन्हीं विदेशी विचारधाराओं के अनुरूप है, जिसमें देश के मूल सनातन दर्शन, संस्कृति, पहचान और इतिहास के प्रति हीन-भावना और भारत को 'राष्ट्र' नहीं मानने का चिंतन है। जब राहुल के सहयोगी दल द्रमुक के नेताओं ने खुलकर 'सनातन को मिटाने' का आह्वान किया, तब वह न केवल चुप रहे, अपितु उनकी पार्टी के कार्ति चिदंबरम और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे इसका समर्थन करते नजर आए। राहुल को भारत की पहचान श्रीराम के जन्मभूमि मंदिर जाना भी स्वीकार नहीं। उनके लिए बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिकता के पर्याय हैं, परंतु वह 'काफिर-कुफ्र' अवधारणा से प्रेरित तत्वों के खिलाफ अक्सर मौन रहते हैं। इसी प्रकार उनके 'जितनी आबादी, उतना हक' सरीखे विचार में राष्ट्रीय पहचान 'भारतीयता' गौण होकर जाति प्रमुख हो जाती है। इससे हिंदू समाज में जाति विभाजन की खाई और गहरी होगी। यह राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होगा।

इधर राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर जिस संविधान के बदलने-खत्म करने का खौफ दिखा रहे हैं, उसकी पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि भारतीय संविधान में सौ से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस ने ही किए हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राहुल गांधी ने 2013 में अपनी सरकार के एक अध्यादेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था। असल में राहुल 'विशेषाधिकार की भावना' से ग्रस्त हैं कि केवल उन्हें ही कोई भी विचार रखने और अपने अनुकूल 'लोक' (जनमानस) और 'तंत्र' (मीडिया-न्यायालय सहित) चलाने का 'दैवीय अधिकार' है। अब राहुल को मोदी का विकल्प बनना, उनसे वैचारिक-राजनीतिक रूप से अलग दिखना है। इस होड़ में वह जो वादे और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भारत कैसा होगा? क्या लोकलुभावन नीतियों के नाम पर सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज की वापसी होगी, जिसमें अतीत के दौर की तरह रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी के साथ कालाबाजारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार चरम पर था? क्या उनके विचारों पर चलने वाली सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी या उस स्थिति में पहुंचा देगी, जब देश की आर्थिकी तबाह हो गई थी? क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में बदहाली का कारण इसी प्रकार की राजनीति नहीं रही? इस पर विचार करते हैं कि अगले पांच वर्षों में भारत की तस्वीर कैसी होगी? क्या वह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप बनेगी, जिसमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप स्थापित करने का लक्ष्य है या फिर वैसी जिसका तानाबाना राहुल गांधी बुन रहे हैं? इसका उत्तर मतदाताओं के विवेक पर निर्भर है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि की तुलना में हम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च नहीं कर रहे हैं

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच बढ़े ● फाइल

लंदन की उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 59 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान दिया गया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आइआइएम-अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह आइआइटी-मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है। जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से रहा है। 1969 में स्थापना के वर्ष से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मकता और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है। इसीलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौकरशाह देने का श्रेय भी जेएनयू को है।

क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इस अवधि में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं। मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज हमने अनुसंधान एवं विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य देशों ने दिया। जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6 प्रतिशत है और विश्व औसत 1.8 प्रतिशत से काफी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40 प्रतिशत से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उबरने के लिए नवीन पहल कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं। इन नए प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना समय की मांग है।

उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाएं, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे। इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां, एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सांसारिक सुख

विकास के दो पथ हैं-बाहरी और आंतरिक। आज बाहरी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक सोच ने विकास की रफ्तार को अकल्पनीय गति दी है। विकास की हर दौड़ में वह आगे बढ़ता जा रहा है। आज बाह्य विकास इतना हुआ है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना की आनन-फानन में अवगति हो जाती है, लेकिन स्वयं के भीतर घटित होने वाली घटना का कुछ अता-पता भी नहीं है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। बाहर तो उजाला फैलता जा रहा है और भीतर गहन अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अंधकार को हटाए बिना उजाला कैसे मिल सकता है? उजाले के बिना सुख, शांति और तृप्ति कहां है?

मनुष्य की जिस ऊर्जा का उपयोग अंधकार को हटाने के लिए होना चाहिए था, वह निरर्थक कार्यों में बह रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग चेतना के रूपांतरण एवं ऊर्ध्वारोहण के लिए होना चाहिए था, वह बाहरी संचालन में खप रही है, क्योंकि आज आदमी केवल देह की परिधि में ही जी रहा है। वह संसार के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। उसकी समग्र दृष्टि बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस बाह्य दौड़ को ही वह पूर्णता की कसौटी समझ रहा है। वह इस सच्चाई को भूल रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो सुखानुभूति वह कर रहा है, उसे केवल सुखाभास या मृगतृष्णा ही कहा जा सकता है। मनुष्य को सुखाभास की अनुभूति से स्वयं को ऊपर उठाकर आनंद एवं तृप्ति की अनुभूति में प्रविष्ट होना है।

आनंद आत्मा का स्वभाव है और सुख-दुख शरीर का स्वभाव है। इसलिए निजानंद में प्रवेश करना अपेक्षित है। स्वयं के भीतर डुबकी लगाकर ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसने सर्वस्व पा लिया। सांसारिक सुखों की मृगमरीचिका से बाहर निकलकर अपने ही अंतस की गहराई में उतर जाना श्रेयस्कर है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अपने-अपने राम

प्रवीन लखेड़ा का आलेख 'जन-जन तक पहुंचे श्रीराम का संदेश' सचमुच में विचारणीय है। वर्तमान भारत की स्वतंत्रता के अमृतकाल की सांप्रतिक पीढ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे अपने जीवनकाल में अयोध्या में सदियों बाद भगवान राम के मंदिर की सुखबर ने आह्लादित किया है। अब इस पीढ़ी का दायित्व है कि रामराज्य के सपने को साकार करने के लिए वह अपने-अपने मर्यादित राम का अनुसरण करे और अपने दायित्वों का इस प्रकार निर्वहन करे कि उनमें स्वार्थ की कोई झलक न हो। कोई भी समाज अथवा राष्ट्र उसके व्यक्तियों के प्रयासों से ही श्रेष्ठ बनता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रत्येक आचरण हमें संजीवनी देता है। उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़कर और उसे जीवन में उतारकर ही हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। ऐसा भारत जिसमें कोई ऊंच-नीच न हो, समाज में कोई कलह न हो, समस्याओं की नहीं अपितु समाधान की बात हो, केवल अधिकारों की नहीं, अपितु कर्तव्यों की आवाज उभरे। ऐसा भारत जिसमें कोई भूखा न सोए, लोग सदाचार के बल पर आगे आएं, प्रकृति से कोई खिलवाड़ न हो। ऐसा भारत जहां हर ओर खुशहाली हो, एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो, हर वर्ग केवल राष्ट्रोत्थान की बात करे। ऐसा भारत जिसमें हर बच्चा सुशिक्षित हो, सुसंस्कारित हो, आबाल-वृद्ध सभी अपने-अपने दायित्वों को समझें और पुरजोर उनका निर्वहन करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम हमारी आस्था-विश्वास को प्रबल करते हैं। हमारे संस्कारों को नई ऊर्जा देते हैं। वह जातीय गौरव, ऊंच-नीच को ठुकराते हैं। राम हमें कर्तव्य-पालन का अनूठा पाठ पढ़ाते हैं। राम तो जीवन के हर पक्ष में समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनके आदर्शों का अनुकरण ही उनका सही रीति से वंदन हैं, अभिनंदन है। उनके आदर्श और उनकी मर्यादाओं के पाठ हर क्रंदन का समाधान हैं। धन्य हैं हम कि रघुराज विराजे हैं 'सुखधाम'। प्रभु श्रीराम की प्रीति सभी पर बनी रहे।

yograj62@gmail.com

नैतिक मूल्यों का पतन

शंकर शरण द्वारा लिखित आलेख 'दल बदल कानून की दुर्गति' पढ़ा । आज राजनीति अपने उद्देश्य से भटक चुकी है। एक दौर में राजनीति का उद्देश्य जन सेवा और देशभक्ति था, लेकिन आज की राजनीति का उद्देश्य पद और धन की प्राप्ति बन चुका है। प्रारंभ में सभी राजनीतिक दलों के नीति व सिद्धांत थे, लेकिन आज सभी राजनीतिक दल अपने सिद्धांत को तिलांजलि देकर सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। समाज में नैतिक मूल्यों के पतन का असर सभी संस्थाओं पर पड़ रहा है। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक दल बदल की समस्या नहीं थी, क्योंकि उन दिनों सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों पर अडिग रहते थे, एवं नेताओं का उद्देश्य पद और धन की प्राप्ति नहीं थी। जब समाज में नैतिकता का पतन होता रहेगा, तब कोई भी कानून इसे सुधार नहीं सकता। दल बदल की समस्या एक नासूर बन चुकी है, केवल कानून के द्वारा इस नहीं रोका जा सकता है। दल बदल की समस्या को रोकने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन उस कानून के बावजूद भी दलबदल की समस्या कायम है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

कोर्ट की फटकार उचित

संपादकीय आलेख ईवीएम पर संदेह (17 अप्रैल) पढ़ा। ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर याचिका कर्ता के वकील को झिड़कते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपने जीवन के छठे दशक में हूं और मैंने बैलेट पेपर वाले बहुत चुनाव देखे हैं। तब कैसे बूथ लूट लिए जाते थे, गुंडे बैलेट पेपर छीन कर फटाफट स्टैंप लगा कर डिब्बे में डालते थे। आप की याददाश्त कमजोर हो सकती है, पर मुझे सब बखूबी याद है। छोटे छोटे देश बैलेट पेपर से चुनाव करा सकते हैं, परंतु भारत जैसे देश में जहां 97 करोड़ मतदाता हैं, वहां भले ही 70 करोड़ से अधिक वोट न पड़ें, बैलेट पेपर तो 97 करोड़ ही छपवाने पड़ेंगे। करोड़ों बैलेट बाक्सेज की आवश्यकता होगी। उनको लाने व ले जाने की व्यवस्था बहुत ही कठिन होगी। मतगणना में ईवीएम की तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा। आप देश को क्यों 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं? ईवीएम को काम में लाने के पहले सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया जाता है कि उसमें पहले से कोई वोट नहीं है। मतदान समाप्त होने पर सभी उपस्थित प्रतिनिधि, ईवीएम के सील हो जाने पर हस्ताक्षर करते हैं और मतगणना प्रारंभ होने पर सुनिश्चित किया जाता है कि ईवीएम की सील टूटी न हो और उस पर पूर्व के हस्ताक्षर मौजूद हों। किसी भी ईवीएम को इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाता है। प्रत्येक लोकसभा के पांच विधान सभा क्षेत्रों के वोटों का मिलान वीवीपैट से किया जाता है।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादिवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

पोस्ट

हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्रीराम का सूर्यतिलक का दृश्य देख सके।

मि. सिन्हा@MrSinha_

दूसरे की जाति से घृणा करना और उन्हें बेवजह नीचा दिखाना ही असली जातिवाद है। कौन किस जाति में पैदा होगा, यह हमारे हाथ में नहीं तो फिर क्यों किसी से जाति या धर्म की वजह से नफरत करें?

रोहिणी@RohiniGhavari11

भारत की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवा में मुस्लिम वर्ग के 51 अभ्यर्थी चुने गए। जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं को ऐसे समान अवसर उपलब्ध नहीं। उलटे वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और जबरन मतांतरण कराया जाता है। इसके बावजूद वामपंथी इस्लामिस्ट तबके की दृष्टि में भारत असहिष्णु है।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नंबर दो हो गई हैं। सुनीता जी का स्थान पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया से भी ऊपर है। फिर अन्य सांसदों का नीचे रहना स्वाभाविक है। अरविंद जी तो राजनीति बदलने आए थे। रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

जनपथ

करके बालक राम का किरणों से अभिषेक,
सूर्य देव भी धन्य हैं दृश्य अवध का देख।
दृश्य अवध का देख हो रहे जन-जन विह्वल,
क्योंकी सदियों बाद देख पाए हम यह पल।
पूरे साल हजार रहे हैं हम डर-डरके,
मत लौटाना काल वही फिर गलती करके!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 7

****

किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। -सर्वपल्ली राधाकृष्णन

ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के पूर्ण मिलान की मांग को लेकर शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण की शुरुआत से ऐन पहले जो टिप्पणियां की हैं, वे सभी आशंकाओं पर विराम लगा देने वाली हैं। इन टिप्पणियों के बाद अनावश्यक चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप समाप्त हो जाने चाहिए।

अब बहस खत्म हो

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की पर्चियों के पूर्ण मिलान की मांग के संदर्भ में, शीर्ष अदालत की पीठ ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण की शुरुआत से ऐन पहले जो टिप्पणियां की हैं, वे महत्वपूर्ण होने के साथ सभी आशंकाओं पर विराम लगाने वाली भी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से ईवीएम में हेरफेर से जुड़ी आशंकाएं जताई जाती रही हैं, जिनके समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने कई कदम भी उठाए हैं, जिनमें वीवीपैट व्यवस्था और इसमें लाए गए सुधार भी शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर जिसे वोट दिया गया है, उसका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है। ईवीएम में लगे शीशे की स्क्रीन पर यह पर्ची कुछ सेकंड तक दिखती है। यह पूरी व्यवस्था दरअसल इसलिए की गई है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर ही प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से किन्हीं पांच ईवीएम और वीवीपैट में पड़े वोटों की जांच की जाती है। गैर-सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए या तो पूरे चुनाव मतपत्रों के जरिये हों या फिर ईवीएम में पड़े वोटों व वीवीपैट की पर्चियों का सौ फीसदी मिलान किया जाए। अदालत ने भी कहा है कि करीब 97 करोड़ मतदाताओं वाले भारत में ऐसी मांग अव्यावहारिक है, तो इसकी वजह स्पष्ट है। एक तो इससे चुनावों के नतीजों की घोषणा में विलंब होगा और दूसरे, इससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे गलतियों की आशंका बढ़ेगी। याचिकाकर्ता पूर्ण पारदर्शिता और मतदाताओं के भरोसे की बात कर रहे हैं, जो जायज भी है, लेकिन इनके नाम पर बूथ कैप्चरिंग वाले दौर की ओर तो लौटा नहीं जा सकता, जिसका स्मरण शीर्ष अदालत ने भी कराया है, और जिससे अब भी देश के कुछ राज्य पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके हैं। तथ्य यह है कि वीवीपैट व्यवस्था में अब तक किसी बड़ी गड़बड़ी के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी अगर कोई संशय है, तो संकीर्ण अंतर से जीत मिलने वाली सीटों में पुनर्गणना के नमूने को बढ़ाने या पुनः मतगणना का आग्रह तो समझ आता है, पर इस तरह ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों में सौ-फीसदी मिलान की मांग अतिशयोक्ति ही है, जो संपूर्ण व्यवस्था में भरोसे की कमी को दिखाती है। मामले में अंतिम फैसला कुछ भी हो, उम्मीद है कि शीर्ष अदालत की इन टिप्पणियों के बाद अनावश्यक चर्चाएं और आरोप-प्रत्यारोप समाप्त हो सकेंगे।

चुनावों में चुनौती बन रहा चीन

चीन मतदाताओं को सबसे ज्यादा किस चीज से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान कराने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मतभेद पैदा हो सकें। आशंका है कि वह भारत में लोकसभा चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है।

हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकी और राजनीति का जुड़ाव तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत के लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य चुनावों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का दुरुपयोग कर सकता है। यह लेख इस मुद्दे के बहुआयामी आयामों को रेखांकित करता है और तकनीकी, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक निहितार्थों की खोज करता है। ताइवान के अनुभवों के जरिये इसकी भी पड़ताल की गई है कि इनसे निपटने में सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशांत माली

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा बनाई गई राजनीतिक सामग्री वितरित करेगा, जो 'इन हाई-प्रोफाइल चुनावों में उसके हितों को लाभ पहुंचा सकता है', क्योंकि एआई से तेजी से मीम्स, वीडियो और ऑडियो सामग्रियां बन रही हैं। कंपनी ने जून, 2023 से चीन और उत्तर कोरिया में 'कुछ उल्लेखनीय साइबर रुझान देखे हैं, जो न केवल अपने परिचित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक जटिल प्रभावी तकनीकों का उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं।' माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीनी साइबर हमलावरों ने तीन लक्ष्य क्षेत्रों को चुना है- दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के देश, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके क्षेत्रीय विरोधी और अमेरिकी रक्षा औद्योगिक आधार। चीनी अभियान एआई-जेनरेटेड या एआई-समर्थित सामग्री को परिष्कृत करना जारी रखते हैं। इन अभियानों के पीछे के खिलाड़ियों ने एआई-जनरेटेड मीडिया को बढ़ाने की इच्छा दर्शाई है, जो उनके रणनीतिक आख्यानों को लाभ पहुंचाता है, साथ ही वे वीडियो, मीम्स और ऑडियो सामग्री भी बनाते हैं।

चीन, मतदाताओं को सबसे ज्यादा किस चीज से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान कराने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मतभेद पैदा हो सकें। वह संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को भी अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य लक्ष्यों और गुप्तचर जानकारी संग्रह को वित्तपोषित करने और आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरंसी लूट और आपूर्ति शृंखला को बाधित करने वाले हमलों को बढ़ा दिया है। इसने अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए एआई का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है।

सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने चीन द्वारा एआई का इस्तेमाल कर भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में चुनावों को बाधित करने की आशंका से संबंधित जो चेतावनी जारी की है, वह चिंताजनक है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के अनुसार, चीन आगामी प्रमुख चुनावों में विशेष रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एआई द्वारा बनाई गई सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर (एमटीएसी) की रिपोर्ट इस आसन्न खतरे को रेखांकित करती है कि 'इस साल दुनिया भर में होने वाले प्रमुख चुनावों को देखते हुए, खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में, चीन अपने हितों को लाभ पहुंचाने के लिए एआई जनरेटेड सामग्री बनाएगा और उसका प्रचार करेगा।'

माइक्रोसॉफ्ट की चेतावनी ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चीन के कथित ट्रायल रन की खबरों के बाद आई है, जहां उसने जनवरी में एआई द्वारा बनाई सामग्री के जरिये दुष्प्रचार का प्रयास किया था। रिपोर्ट में स्टॉर्म 1376 नामक एक बीजिंग समर्थित समूह का उल्लेख है, जिसे स्पैमोफ्लाज या ड्रैगनब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो ताइवानी चुनाव के दौरान अत्यधिक सक्रिय था। यह राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामले का अध्ययन करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तकनीकी हस्तक्षेप की क्षमता को रेखांकित करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाई गई सामग्री जनमत को प्रभावित करने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठा सकती है। माइक्रो टार्गेटिंग और भावनात्मक संदेश जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर, एआई एल्गोरिदम इको चैंबर्स बना सकता है, जो मौजूदा विश्वासों को मजबूत करता है और समाज को ध्रुवीकृत करता है। इसके अलावा, 'डीपफेक' तकनीक का उदय सूचना के पारंपरिक स्रोतों में विश्वास को कम करते हुए, तथ्य और कल्पना के बीच की बारीक रेखा को धुंधला कर एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।

सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एआई सामग्री के दुरुपयोग को रोकने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, इंटरनेट की सीमाहीन प्रकृति क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों को जटिल बनाती है, जिससे दुर्भावनापूर्ण लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार बिना किसी दंड के काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी नवाचार की तीव्र गति विनियामक प्रयासों से आगे निकल जाती है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए उभरते खतरों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, एआइ सामग्री निर्माण और प्रसार का विकेंद्रीकृत स्वरूप पारंपरिक प्रवर्तन रणनीतियों में बाधा डालता है, जिसके लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

डिजिटल युग में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन द्वारा एआई-जनरेटेड सामग्री के संभावित उपयोग से प्रौद्योगिकी और राजनीति के बीच जटिलता स्पष्ट होती है। ताइवान जैसे अन्य देशों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि तकनीकी हस्तक्षेप दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को मजबूत विनियामक ढांचा विकसित करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और चुनावों की सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करेगी और नागरिकों का अपने राजनीतिक संस्थानों पर भरोसा कम हो सकता है।

-लेखक साइबर कानून विशेषज्ञ और बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

महर्षि अरविंद

शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहां भक्ति-भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है।

अंतर्ज्ञान की शक्ति से परमात्मा के दर्शन

संसार के समस्त पदार्थों में जो 'सत्य' पाया गया, वह समस्त हमारे भीतर आ जाए, और हमारा शरीर भी उसी से भर उठे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा अंतर्ज्ञान पहले मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। पर यदि वह इसी स्थान पर बना रहे, तो जब तक हम ऊपर रहेंगे, तभी तक वह काम देगा। जैसे ही हम नीचे के स्तर पर आए, उसका संबंध टूट जाएगा। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने समाधि पर इतना जोर दिया था। इस उपाय से वे इस ज्ञान शक्ति को मनोमय क्षेत्र में ले आते थे। वहीं पर सूक्ष्म इंद्रियों की सृष्टि होती है। ये सूक्ष्म इंद्रियां बाहर की इंद्रियों की सहायता के बिना भी दर्शन, स्पर्शन करने में समर्थ होती हैं। जब तक शरीर का रूपांतर नहीं होगा (इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर और सुख का स्वरूप बदल जाएगा), तब तक हमें अपनी विजय पूर्ण और सारयुक्त नहीं समझनी चाहिए। पर ऐसा होने पर शरीर की कार्य-शक्ति में अंतर आ जाएगा। तब शरीर अमृतमय हो जाएगा, रोग और बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सब इंद्रियां सृष्टि के गूढ़ और वास्तविक तत्व को ग्रहण करने लगेंगी। यह अंतरंग ज्ञान की शक्ति मानव इंद्रियों को प्राप्त हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। वैदिक युग के ऋषि समस्त चैतन्य और ज्ञान-शक्ति को सार रूप करके उद्दीप्त करते थे। उस समय वैज्ञानिक यंत्र तो थे नहीं। इसलिए ज्ञानी जन भीतरी ज्ञान के जरिये ही सृष्टि के रहस्यों का पता लगाते थे। ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने गायें चराते-चराते ही अनंत प्रकृति के स्वरूप को समझ लिया था। उनको पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि से ज्ञान मिला था। यही सनातन ज्ञान पथ है और यही ज्ञान की मुक्त प्रणाली है। पर आजकल की वैज्ञानिक धारणा के अनुसार, अनुभव के साथ पदार्थ का मिलान करना ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हम जो कुछ देखते-सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना ही ज्ञान हम सत्य मानते हैं, उसके सिवाय और कुछ हम नहीं जानते, न मानते हैं। पर अब विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ नवीन विचारक मान रहे हैं कि अंतर्ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहां भक्ति-भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है। यह सत्य है कि भक्ति होने से भगवान का कार्य करने में शक्ति का अभाव नहीं रहेगा, पर इससे ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त न होने से वृहत सृष्टि में प्रवेश असंभव है। ज्ञान द्वारा ही भगवान के अनंत स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। अनंत विचित्रताओं-भेदों में ऐक्यता स्थापित किए बिना हमें क्षुद्र सृष्टि में रहना पड़ेगा और ऐसी क्षुद्रता भगवान की इच्छा के विरुद्ध होती है। इसलिए सबको वृहत होना चाहिए और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान का ही अनुगामी समता का भाव है और समता ही वृहत सृष्टि का बीज मंत्र है। सिर्फ कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान का प्रकाश सृष्टि का सर्वोच्च अंग है।

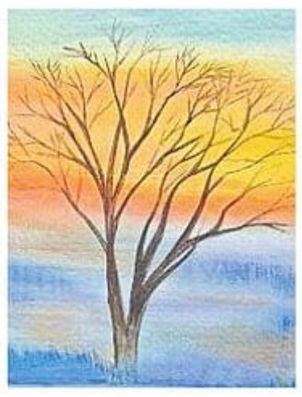

बिना ज्ञान कुछ नहीं...

सूत्र

सबको वृहत होना चाहिए और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान का ही अनुगामी समता का भाव है और समता ही वृहत सृष्टि का बीज मंत्र है। सिर्फ कर्म ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान का प्रकाश सृष्टि का सर्वोच्च अंग है। जब शक्ति और भक्ति के सम्मिश्रण से ज्ञान रूप धारण करेगा, तभी समस्त सृष्टि सार्थक होगी।

दूसरा पहलू

अफ्रीकी महाद्वीप ने अपने यहां मौजूद कार्बन से कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है।

दुनिया में कार्बन को संतुलित करता अफ्रीका

एक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले एक दशक में अफ्रीकी महाद्वीप ने अपने यहां मौजूद कार्बन से कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा जमा कार्बन की कुल मात्रा एक तंत्र के भीतर कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा से अधिक हो जाती है, तो इसे कार्बन सिंक कहा जाता है। लेकिन जैसे-जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए बदला जा रहा है, कार्बन भंडारण क्षमता कम हो रही है और उत्सर्जन दर बढ़ रही है।

योलैंडी अर्न्स्ट

जब लोग जमीन का उपयोग खेती या दूसरे कामों के लिए करने लगते हैं, तो आग से उत्सर्जन भले कम हो जाता है, पर शाकाहारी जीवों से मीथेन का उत्सर्जन बढ़ जाता है।

हम अफ्रीकी महाद्वीप में उत्सर्जित होने वाली और अवशोषित की जा रही कुल ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा का पता लगाना चाहते थे। इससे हम यह समझ पाए कि कैसे यह महाद्वीप वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर रहा है। इस अध्ययन का लक्ष्य महाद्वीपों (या बड़े देशों) और बड़े क्षेत्रों के लिए एक उन्नत ग्रीनहाउस बजट तैयार करना है। ऐसी जानकारी नीति निर्माण के लिए बहुत महत्व रखती है। यदि वैज्ञानिकों, भूमि प्रबंधकों और एनजीओ को यह पता हो किन गतिविधियों से ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, तो वे इसे कम करने के लिए सरकारों और नीति निर्माताओं के साथ काम कर सकते हैं।

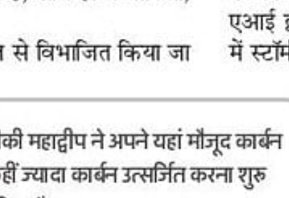

अफ्रीका में कार्बन खींचने की प्रक्रियाएं, प्राकृतिक उत्सर्जन और मानवजनित उत्सर्जन के मुकाबले ज्यादा थीं। यह महाद्वीप कार्बन सिंक था।

अफ्रीका के मामले में हमारा आकलन है कि जब लोग जमीन का उपयोग खेती या दूसरे कामों के लिए करने लगते हैं, तो आग से उत्सर्जन भले कम हो जाता है, पर शाकाहारी जीवों से मीथेन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी हैं, जो कार्बन और ग्रीनहाउस गैसों को जमीन की सतह की ओर वापस खींचती हैं।

अफ्रीका का पिछला कार्बन बजट (1985 से 2009) बताता है कि अफ्रीका में कार्बन खींचने की प्रक्रियाएं, प्राकृतिक उत्सर्जन और मानवजनित उत्सर्जन के मुकाबले ज्यादा थीं। यह महाद्वीप कार्बन सिंक था, भले ही यह मानवजनित ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा था, पर अफ्रीका पूरे विश्व को जलवायु सेवा प्रदान कर रहा था। अफ्रीकी भूमि की कार्बन शोषण क्षमता लगभग 0.8 गीगाटन कार्बन सालाना है, जो दुनिया की कुल कार्बन शोषण का लगभग 20 प्रतिशत है। इसकी कार्बन शोषण क्षमता में कमी नहीं हुई है। अफ्रीका को कार्बन तटस्थ बनाने के लिए तरीके खोजना एक बड़ी चुनौती है। कार्बन-तटस्थ ऊर्जा स्रोतों में निवेश और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी से इसकी शुरुआत की जा सकेगी। *(द कन्वर्सेशन)*

-साथ में सैली आर्किबैल्ड

आंकड़े

शीर्ष नाशपाती उत्पादक

वैश्विक स्तर पर नाशपाती के उत्पादन में कोस्टारिका अव्वल है, जबकि हमारा देश शीर्ष सात उत्पादकों में शामिल है।

कोस्टारिका	10.26%
इंडोनेशिया	10.08%
फिलीपीन	9.98%
ब्राजील	8.09%
चीन	6.63%

स्रोत : FAO

जिंदगी में हमें बहुत-सी चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें लालच में न फंसकर सही राह चुननी चाहिए।

दिव्य पुष्प

अंतर्यात्रा
संकलित

एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास एक तालाब था। एक दिन जब वह पानी लेने गया, तो उसने तालाब में एक अद्भुत पुष्प देखा। उसने अपनी पत्नी को भी बुलाकर दिखाया। उन दोनों ने सोचा कि अगर यह पुष्प राजा को दे दिया जाए, तो वह इनाम देगा।

वह पुष्प लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसने पूछा कि यह पुष्प लेकर कहां जा रहे हो? उसने बताया कि मैं राजा के पास जा रहा हूं। इसे राजा को भेंट करके उनसे इनाम लूंगा। व्यापारी ने कहा कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब व्यापारी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को मना कर दिया।

राजा ने जब वह दिव्य पुष्प देखा, तो अचंभित हो गए। राजा 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार था। तभी उसके मन में एक अजीब-सी चेतना आई। वह राजा को पुष्प न देकर सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए कहा, मैं समझ गया हूं कि आपकी शरण में आने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 23 मार्च, 1993

बम की धमकी से संसद की कार्यवाही में बाधा

संसद और हाईकोर्ट में बम की अफवाह

बम विस्फोट की धमकी के चलते आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आनन-फानन में स्थगित कर दी गई। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी बम की अफवाह से तीन घंटे कामकाज ठप रहा।

हवाइयां उड़ातीं हवाई टिकट की कीमतें

बड़ी संख्या में विमानों का परिचालन रद्द होने से हवाई टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी जरुरतमंद यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है।

सतीश सिंह

विमानन

भारत की इंडिगो एयरलाइन 1.47 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी विमानन कंपनी बन गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, यात्रियों की संख्या के हिसाब से भारत के विमानन क्षेत्र में इंडिगो एयरलाइन की 60.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि दूसरे स्थान पर एयर इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत है।

विगत छह महीनों में इंडिगो एयरलाइन के शेयर में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि पिछले एक साल में इसके शेयरों ने निवेशकों को 102.55 प्रतिशत का प्रतिफल (रिटर्न) दिया है। पिछले महीने इसके शेयर ने निवेशकों को 18.25 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है। इस साल एक जनवरी से अब तक इसके शेयर ने निवेशकों को 27.78 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है।

इंडिगो एयरलाइन ने दो फरवरी, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा की थी, जिसके अनुसार इंडिगो का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 110.7 प्रतिशत बढ़कर 2,998 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में इसने 1,422.6 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तिमाही में भी इंडिगो ने 188.9 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। विगत पांच वर्षों में पहली बार किसी भारतीय विमानन कंपनी ने किसी भी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया है, क्योंकि दूसरी तिमाही विमानन उद्योग के लिए कमजोर मांग वाला सीजन माना जाता है।

इंडिगो का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बनना निश्चित रूप से हर्ष एवं गौरव का विषय हो सकता है। यह शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि इसके शेयर में निवेश करके निवेशकों ने काफी कमाई की है, लेकिन यह जरूरतमंद यात्रियों के लिए खुशी की बात कतई नहीं हो सकती है। मौज-मस्ती के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयर टिकट की कीमत ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन किसी बीमार का इलाज के लिए सफर करने या नौकरी में योगदान देने, जरूरी मीटिंग में शामिल होने, आदि के लिए यात्रा करने वालों के लिए लगातार एयर टिकट की कीमत में इजाफा परेशानी का कारण बन गया है।

यात्रा वेबसाइट इक्सिगो के विश्लेषण से पता चला है कि एक से सात मार्च की तुलना में एक से सात अप्रैल की अवधि में कुछ हवाई मार्गों पर किराया 39 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इस अवधि में दिल्ली से बंगलूरू के बीच के उड़ानों के लिए एक तरफ का किराया 39 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जबकि दिल्ली से श्रीनगर के हवाई किराये में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइन के पास 320 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है, जो हर दिन 1,900 से ज्यादा फेरे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शहरों में लगाते हैं। वर्ष 2024 में 150 नए विमानों को घरेलू उड़ान हेतु बेड़े में जोड़ा गया है। फिर भी यह घरेलू मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। घरेलू यात्रियों की संख्या में वर्ष दर वर्ष के आधार पर 24 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। 2023 में घरेलू यात्रियों की संख्या 15.2 करोड़ से अधिक हो गई है।

विमानन उद्योग मांग के अनुरूप क्षमता बढ़ाने में कई चुनौतियों से जूझ रहा है। घरेलू मार्गों पर भी बड़े विमानों का उपयोग हो रहा है। बावजूद इसके, मांग और आपूर्ति के बीच खाई बनी हुई है। इंडिगो को छोड़ दूसरी एयरलाइंस की उड़ानें गाहे-बगाहे रद्द होने और यात्री मांग में मजबूती के कारण हवाई किराये में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। गर्मियों में घरेलू उड़ानों में यात्रियों को टिकट के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। सभी एयरलाइंस के टिकटों की कीमत आसमान छू रही है। गर्मी की छुट्टियों में इसमें बढ़ोतरी का अंदेशा है। हालांकि, 18 से 24 महीने पहले भारत में एयर टिकट की कीमत काफी सस्ती थी।

एयर टिकट की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है। वैसे, विमानन मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संसदीय स्थायी समिति ने भी छुट्टियों और त्योहारों के दौरान एयर टिकट की कीमत वृद्धि पर रोक लगाने पर जोर दिया है। बावजूद इसके, एयर टिकट की कीमत में कमी के आसार नहीं हैं, क्योंकि आज बड़ी संख्या में विमान जमीन पर खड़े हैं और परिचालनगत समस्याओं की वजह से विमानों का परिचालन भी रद्द हो रहा है।

edit@amarujala.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

फौरी कार्रवाई से नहीं थमेंगे नेताओं के बिगड़े बोल

बिगड़े बोल का दोषी मानते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी एवं सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी को अपमानजनक मानते हुए आयोग ने सुरजेवाला के खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया है। लेकिन क्या इस एक्शन को सचमुच सख्त कहा जाना चाहिए? क्या आपत्तिजनक बयानबाजी और खास तौर से महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के लिए इतनी ही सजा काफी है? ये सवाल इसलिए भी कि चुनावों को हम लोकतंत्र का उत्सव कहते आए हैं और ऐसे बयान उत्सव में खलल डालने वाले साबित होते हैं।

सुरजेवाला को हरियाणा की एक चुनावी सभा में हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसा नहीं है कि सुरजेवाला व कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस गलती का अहसास नहीं हुआ होगा। लेकिन पहले बयानबाजी कर बाद में लीपापोती करने में जुटना नेताओं का शगल होता जा रहा है। ज्यादा विवाद उठने लगे तो ऐसे बयानवीर यह कहकर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि उनके बयान को तोड़मरोड़कर दिखाया गया है। सोशल मीडिया के दौर में जब हर हाथ में कैमरायुक्त मोबाइल रहने लगा है चुनावी सभाओं में कोई बयान सार्वजनिक हुए बिना रह ही नहीं सकता। बात केवल सुरजेवाला की ही नहीं है, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व हिमाचल प्रदेश में मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर ऐसी ही अपमानजनक टिप्पणियां सामने आई थीं। चुनाव आयोग के संज्ञान में यह सब भी सामने आया था लेकिन बयान देने वालों को चेतावनी पत्र देकर ही छोड़ दिया गया। सुरजेवाला को लेकर आयोग के आदेश के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के इस दौर में आयोग ने किसी नेता को प्रचार से रोकने जैसा फैसला पहली बार किया है। अड़तालीस घंटे की रोक अवधि पूरी होने के बाद सुरजेवाला फिर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आगामी दिनों में वे अपना बर्ताव संयत रखेंगे।

दरअसल, इस तरह के प्रकरणों में आचार संहिता से ज्यादा नेताओं की आचरण संहिता की जरूरत रहती है। महिला हो या पुरुष, किसी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल आगे आकर पहल करें। आयोग से पहले खुद अपने ऐसे नेताओं पर सख्ती करे, जिनके विवादास्पद बयान चुनावी माहौल में जहर घोलने का काम करते हैं।

लोकसभा चुनाव 2024

41 से 60 साल तक के 578 प्रत्याशी

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 363 प्रत्याशी 25 से 40 वर्ष, 578 प्रत्याशी 41 से 60 वर्ष, 249 प्रत्याशी 61 से 80 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक आयु के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

167 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर मामले

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1198 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 250 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक और 167 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

चुनावी चटकारा

बड़े बोल.... हम रचने जा रहे इतिहास

मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने छिंदवाड़ा सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। इसलिए यहां दोनों पक्षों ने प्रचार अभियान में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दूसरे को घेरने के आरोप-प्रत्यारोप से माहौल गरमा रहा है। यहां हर रोज नए मुद्दे सामने लाने में दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में भाजपा के बड़े नेता का यहां रोड शो हुआ। भाजपा नेताओं ने इसे सौभाग्य बताया तो कांग्रेस नेताओं ने इसे दुर्भाग्य बताना शुरू कर दिया। दोनों दलों का नेतृत्व कर रहे नेता कार्यकर्ताओं से रोज फीडबैक ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता यही फीडबैक दे रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा में वे इतिहास रचने जा रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता जीत को लेकर बड़े बोल बोलने में कतई पीछे नहीं है। ऐसे में दोनों दलों के आलाकमान भी यह मान रहे हैं कि उनकी पार्टी की ही जीतेगी।

राग सियासी

थैला भर-भर नोट हैं,
महंगे गिफ्ट शराब।
लोकतंत्र भौंचक भयो,
आयो समय खराब।।
आयो समय खराब,
वोट के बदले रिश्वत।
देगा कौन जवाब,
गई गर मत की इज्जत।।
हे! नेता महराज,
निकालो मन से मैला।
छोड़ो ओछे काज,
फेंक रिश्वत का थैला।।

-राम नरेश गौतम

असम

दस विधानसभा सीटों वाली लोकसभा में पांच पर भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को लगाना होगा जोर

बागान में फिर खिले फूल, हाथ नहीं आ रही चाय

डिब्रूगढ़ से
आनंद मणि त्रिपाठी

चाय...वह पेय है कि तबीयत से बनाई जाए तो जुबान मीठी कर दे और बदजुबानी पर चढ़ जाए तो पूरी राजनीति ही साफ कर दे। कांग्रेस पार्टी से बेहतर चाय और चायवाले का असर कौन जानता है? जिसने असम के चाय बागान से कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। देश की सबसे महंगी चाय का उत्पादन करने वाले डिब्रूगढ़ जिले के हवाईअड्डे पर जब उतरकर शहर की तरफ आप बढ़ते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हरे-भरे चाय के बागान अपनी बांहें खोले आपका स्वागत करते दिखाई देते हैं। चायपत्तियों की खुशबू मिजाज को तरबतर कर देती है। राजनीतिक मिजाज की बात करें तो कुछ खास माहौल नहीं दिखाई देता है। एक दो जगहों पर भाजपा का प्रचार वाहन दिखता है, बाकी कुछेक जगहों पर पार्टी के पोस्टर और बैनर।

डिब्रूगढ़, सोनितपुर और लखीमपुर चाय बागान में करीने से कटी चाय की पत्तियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि यहां राजनीति भी एकसार हो चुकी है। हालांकि जोरहाट के बागान में कहीं-कहीं पत्तियों के रंग में थोड़ा परिवर्तन दिखता है लेकिन कुछ पत्तियों का यह परिवर्तन यहां चाय की फसल पर असर नहीं डालता नहीं दिख रहा है। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे की तरह ही राजनीति में भी एक ही दिखाई देता है।

जोरहाट : यहां चाय पर शोध, 17 बार युद्ध में हारे थे मुगल: सबसे महंगी चाय भले ही डिब्रूगढ़ में बनी हो लेकिन चाय की राजधानी जोरहाट को ही कहा जाता है। यहां सिर्फ चाय पैदा ही नहीं होती है बल्कि यहां किस्में भी तैयार होती हैं। विश्व प्रसिद्ध चाय अनुसंधान संस्थान यानी टोकलाई का प्रायोगिक केंद्र यहीं पर है। इस बार यह राजनीति का टेस्टिंग सेंटर बन गया है। कांग्रेस ने यहां गौरव गोगोई को चुनाव में उतारा है तो वहीं भाजपा ने तपन गोगोई को। दोनों एक ही समाज से आते हैं। ऐसे में वर्ग राजनीति का मामला तो यहां बराबर है लेकिन 10 विधानसभा सीटों वाली लोकसभा में 10 में से पांच सीटों पर भाजपा का कब्जा है और दो पर उसकी सहयोगी असम गण परिषद का। ऐसे में गौरव गोगोई को इस सीट को कांग्रेस से जोड़ने के लिए काफी जोर लगाना होगा। अहोम राजवंश की समृद्ध विरासत को संजोए सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाला यह इलाका कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा और सत्रह बार युद्ध में उन्हें हराया। राजनीति के लिहाज से कहें तो यह सीट कइयों का मुगालता भी दूर कर देती है। गौरव कलियाबोर से चुनाव लड़ा करते थे लेकिन परिसीमन के बाद उसका गणित ऐसा बदला कि उन्हें जोरहाट आना पड़ा। गौरव गोगोई कहते हैं कि इस समय उनका ध्यान अर्जुन की तरह इसी सीट पर है। तपन गोगोई कहते हैं कि यहां हमने लोगों को जोड़ा है तो ऐसे में हमें चुनाव लड़ने में जोर कम आ रहा है। वैष्णव पंथ को मानने वाले इस क्षेत्र में शैव संप्रदाय का 200 साल से अधिक पुराना शैव मंदिर है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग भूमि के गर्भ में है। इसे सिबसागर यानी शिव भगवान का समुद्र कहा जाता है। अब देखना यह है कि राजनीति के सागर से किसका जहाज किनारे लगता है।

लखीमपुर: यहां कांग्रेस को कमजोर कर रही सीपीआइ और तृणमूल: क्षेत्र में यह एकमात्र लोकसभा है जहां धान का वर्चस्व है। यह इलाका ऐसा है कि न तो यहां धान में खाद डालने की जरूरत होती है और न ही बहुत मेहनत की। राजनीति भी यहां कुछ इसी तरह की है। एक बार यहां फसल रोप दी तो फिर फुरसत है। पहले कांग्रेस ने करीब छह दशक तक राज किया। अब एक दशक से भाजपा की फसल यहां लहलहा रही है। यहां भूगोल से एमए कर रही उमीका कहती हैं कि लखीम शब्द लक्ष्मी से निकला है और यहां धान को लक्ष्मी मानते हैं। पुर का मतलब है परिपूर्ण। यहां कभी भी कोई कमी नहीं होती है। सभी यहां अच्छे से रहते हैं। राजनीति में भी बहुत ज्यादा हडबड़ी नहीं है। भाजपा के अशोक सिंघल कहते हैं कि इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत काम किया है। कोई मुकाबले में नहीं है। प्रब्रदान बरुआ को यहां से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। यह वही क्षेत्र है जहां से सर्वानंद सोनवाल पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। यहां कांग्रेस की तरफ से उदय शंकर हजारिका चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल और सीपीआइ ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये यहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं।

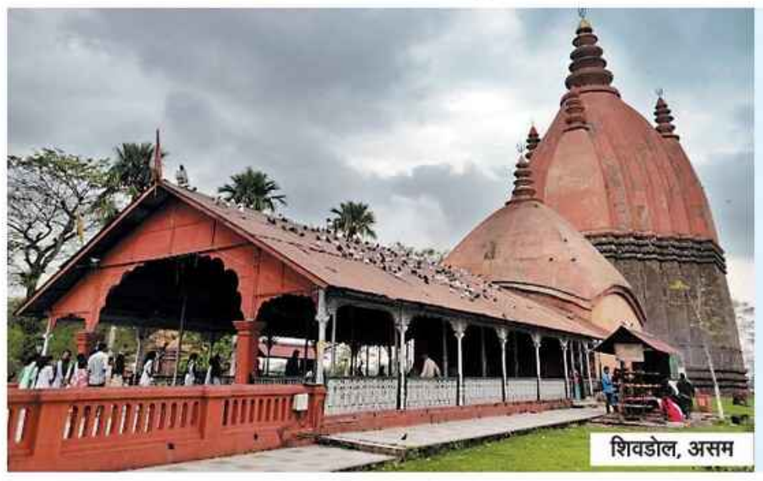
शिवडोल, असम

काजीरंगा : एक ही सींग, एक ही नीति

काजीरंगा देश ही नहीं दुनिया में अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजनीति भी यहां इसी तरह से दिखाई दे रही है। परिसीमन के बाद काजीरंगा लोकसभा की नई सीट तैयार हुई है। परिसीमन से पहले कांग्रेस और वामदल का यहां पूरी तरह कब्जा रहा। 2014 में यहां बदलाव हुआ। यहां की राजनीति में भी चाय बागान का ही वर्चस्व है। ऐसे में भाजपा ने चाय बागान ट्राइब से आने वाले कमाख्या प्रसाद तासा को उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी विधायक रोसलिना तिर्के को उतारा है। कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है।

डिब्रूगढ़ : आप ने ठोकी ताल, त्रिकोणीय हुआ संघर्ष

असम की राजनीति में डिब्रूगढ़ की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि देश में यह एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां चार सांसद (रामेश्वर तेली, सर्वानंद सोनवाल, पवित्र मरग़ीहता और रंजन गोगोई) है। तीन राज्यसभा और एक लोकसभा। इसके अलावा इसी क्षेत्र से पीएम मोदी ने अपने मंत्री मंडल में दो केंद्रीय मंत्री रखे हैं। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल को उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया है। वह असम जातीय परिषद के लुरिन ज्योति गोगोई को समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी ने मनोज धनवार को मैदान में उतारा है।

सोनितपुर : परिसीमन ने बदल दी चुनाव की चौसर

बाणासुर की धरती पर आपका स्वागत है। जी, हां कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम करने वाली राजकुमारी उषा की जन्मस्थली। अनिरुद्ध और उषा के प्रेम के कारण यहां हुए युद्ध से खून के शहर यानी शोणितपुर के रूप में पहचान मिली। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इस इलाके की राजनीति में कहीं भी कोई रक्त चरित्र नहीं दिखता। इस सीट की चौसर परिसीमन के बाद बदल गई है। हालांकि इस सीट पर बदलाव ज्यादा नहीं है। इसके कारण भाजपा यहां बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा ने यहां से रंजीत दत्ता को चुनाव मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने प्रेम लाल गुंजू को लेकिन यहां भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से होने जा रही है। राजू देवरी को बीपीएफ ने चुनाव में उतारा है।

उत्तराखंड | अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आए एक जाजम पर

दूसरे मुद्दों पर भारी नजर आ रहा राष्ट्रवाद, रैलियों और सभाओं में भाजपा आगे

उत्तराखंड सैन्य सेवा में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। इसलिए भी यहां राष्ट्रवाद का मुद्दा जनता को ज्यादा प्रभावित करता है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है जो अल्मोड़ा जिले का हिस्सा है।

नैनीताल से
अभिषेक श्रीवास्तव

चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी।

हल्द्वानी की सभा में यूपी सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी।

14 वीं सदी की राजुला-मालूशाही की प्रेमकथा और अपने प्राकृतिक अप्रतिम सौंदर्य के लिए ख्यात कुमाऊं के पहाड़ एक दशक से अलग ही कहानी कह रहे हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस अंचल में अब लोगों के बीच सिर्फ भाजपा और मोदी की ही चर्चा है। कुमाऊंनी में बात करते हुए लोग समस्याएं तो गिनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर देशहित को सर्वोपरि रख देते हैं। गढ़वाल के बाद जब मैं नैनीताल जिले के आखिरी रेलवे स्टेशन काठगोदाम पहुंचा तो ठंडी हवा के झोंके एक अलग अहसास कराने लगे।

कुमाऊं की सियासत को समझना था तो पहले मैं नैनीताल, फिर वहां से आसपास के क्षेत्रों में गया। दरअसल, नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की सीमा यूपी के मुरादाबाद, बरेली और रामपुर जिले को छूती है। कभी यह सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी के लिए जानी जाती थी। भवाली में एक चाय की दुकान पर मिले मोहन चंद भट्ट ने तिवारी को याद करते हुए कहा कि समय के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कभी यही पहाड़ उसका बेस वोट बैंक होता था, लेकिन आज सिर्फ मोदी और राष्ट्रवाद की चर्चा होती है। नैनीताल में डीएसबी ग्राउंड के पास पहुंचे तो वहां क्रिकेट मैच के साथ ही पास में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वहां मुलाकात मदन रौतेला से मुलाकात हुई। परिवार के साथ नैनी झील देखने आए मदन ने कहा कि बेरोजगारी यहां की बड़ी समस्या है। धामी सरकार अच्छा काम कर रही है।

दरअसल, कुमाऊं का चुनावी समीकरण उलझा हुआ है। यहां कांग्रेस एकजुट होने का अहसास दिलाने के लिए सामूहिक प्रचार पर जोर दे रही है। जो नेता कभी एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे, वही एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। कुमाऊं में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस से कई कदम आगे है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की सभाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस की बात करें तो यहां सिर्फ प्रियंका गांधी की सभा हुई है।

अल्मोड़ा सीट पर 2009 के चुनाव में जब कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने भाजपा के अजय टम्टा को हराया था तब वे फूट-फूट कर रोए थे। उसके बाद 2014 में अजय टम्टा ने हरीश रावत के खास प्रदीप टम्टा को पटखनी दी। इस बार फिर दोनों आमने-सामने हैं।

गढ़वाल(पौड़ी) सीट का एक विधानसभा क्षेत्र कुमाऊं में भी आता है। यह एक मात्र सीट है जहां मतदाता सीधे तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की चर्चा करते हैं। कारण साफ है। पौड़ी जिले के गंगा-भोगपुर के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हुई हत्या ने काफी तूल पकड़ा था। यह घटनाक्रम इस चुनाव में प्रमुख मुद्दों में शामिल है। 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी से 3,02,669 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है।

यह है नैनीताल सीट का इतिहास

यहां पहले कांग्रेस के बाबा जीतते थे, पिछले दो चुनाव से भाजपा का कब्जा है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर सीट में नैनीताल जिले के पांच और ऊधमसिंह नगर के नौ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2014 के चुनाव से ही यहां भाजपा का कब्जा है। 2019 में बीजेपी ने अजय भट्ट को टिकट दिया। भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरा दिया। कांग्रेसी दिग्गज हरीश रावत को हराने के कारण अजय भट्ट को मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार भी भाजपा ने भट्ट को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी के कोर टीम के सदस्य प्रकाश जोशी को टिकट दिया है।

तमिलनाडु | अन्नाद्रमुक के बिखराव पर टिकी अन्नामलाई की उम्मीदें

पश्चिमी घाट की तलहटी में राज्य की द्रविड़ राजनीति की दीवार को भेदने की कोशिश

सवाल यह है कि पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित कोयम्बटूर में क्या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के.अन्नामलाई द्रविड़ दीवार भेद पाएंगे? द्रमुक उम्मीदवार गणपति पी.राजकुमार और अन्नाद्रमुक पार्टी के सिंगई जी. रामचंद्रन से कड़ा मुकाबला है।

कोयम्बटूर से
राजीव मिश्रा

प्रचार अभियान के दौरान के.अन्नामलाई।

गणपति पी.राजकुमार का जनसंपर्क अभियान।

तमिलनाडु में चुनावी शोर थमने से एक दिन पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के.अन्नामलाई कोयम्बटूर से लगभग 32 किलोमीटर दूर पल्लडम विधानसभा क्षेत्र में सुबह 6.30 बजे प्रचार के लिए निकले। अपराह्न करीब 3 बजे तक लगभग 25 गांवों तक जनसंपर्क चलता रहा। उनकी खासियत यह है कि पूरे होमवर्क के साथ गांवों में गए। वहां की स्थानीय समस्याओं को गिनाया और समाधान का वादा भी किया। केंद्र सरकार की उस गांव में पहुंचने वाली विभिन्न परियोजनाओं (जैसे-रक्षा कॉरिडोर आदि) का जिक्र कर उसके लाभ के बारे में भी लोगों को बताया। उनके भाषण एक जैसे नहीं होते। पर, ग्रामीण इलाकों में भीड़ और प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा को अभी लंबा सफर तय करना है। जब शहर के करीब पहुंचते हैं तो दृश्य बदलने लगते हैं।

पुराने ढर्रे पर चलेंगे या देखेंगे भविष्य: कोयम्बटूर कलेक्टर ऑफिस में एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अपने करियर में पहली बार किसी उम्मीदवार को कोयम्बटूर के लिए घोषणापत्र जारी करते देखा है। यहां ड्रग्स की तस्करी, शराब पीने की बढ़ती लत, नागरिक सुविधाओं का अभाव और बेरोजगार जैसी समस्याएं हैं। जो भविष्य की ओर देख रहे हैं, वे बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे। समाज का एक बड़ा तबका चुनावी प्रलोभन की राजनीति से ऊब गया है। लेकिन, ग्रामीण इलाकों में जड़ें इसकी जड़ें अब भी काफी गहरी हैं। द्रमुक पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर तमिलनाडु सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों से पूछते हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक के तीन मंत्री यहां लगातार कैम्प कर रहे हैं। के.अन्नामलाई उन पर पैसे देने का आरोप लगाते हैं। सिंघम उपनाम से मशहूर पूर्व आइपीएस अधिकारी चुनाव जीतने पर खनन माफिया को सबक सिखाने की बात भी करते हैं। उनका यह अंदाज 30 साल की वसंता को पसंद है। वह के.अन्नामलाई की पुलिसिया छवि और भाषणों से प्रभावित हैं, लेकिन बुजुर्ग रजातिअम्मा कहती हैं कि अन्नाद्रमुक के कमजोर होने के बाद वह फैसला नहीं कर पा रही हैं कि किसे वोट दिया जाए।

प्रवासी भी निभाएंगे अहम भूमिका: कोयम्बटूर में प्रवासी उत्तर भारतीयों की अच्छी तादाद है और भाजपा को इन पर काफी भरोसा है। दक्षिण का मैनचेस्टर कहे जाने वाले इस शहर में लगभग 30 हजार एमएसएमइ हैं और इनके कई मुद्दे हैं। यहां जीएसटी चुनावों में एक मुद्दा बन गया है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आधारभूत नागरिक सुविधाओं की कमी और कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावी मुकाबले को लेकर द्रमुक समर्थक दावा करते हैं कि टक्कर अन्नाद्रमुक से है। लेकिन अन्नाद्रमुक समर्थक कहते हैं कि मुकाबला भाजपा से है। भाजपा की संभावनाएं अन्ना द्रमुक मतदाताओं के रुख पर काफी हद तक निर्भर है।

गठबंधन की अहमियत का अब लग रहा पता

कोयम्बटूर लोकसभा कोंगू क्षेत्र में आता है जो अन्नाद्रमुक का पारंपरिक गढ़ रहा है। पिछली बार यहां से सीपीआइ के पीआर नटराजन चुनाव जीते लेकिन उनके खिलाफ असंतोष को देखते हुए गठबंधन में दमुक उम्मीदवार को उतारा गया। कार्ति कहते हैं कि अगर भाजपा का गठबंधन अन्नाद्रमुक के साथ होता तो बात अलग होती। दरअसल तमिलनाडु में यह बात हर जगह सुनाई दे रही है। कई लोगों ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव भाजपा अगर अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन में लड़े तो बेहतर होगा। आगे क्या होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी तो दोनों दल अलग-अलग लड़ रहे हैं।

आज का सवाल

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

जल संरक्षण सभी जिम्मेदारी

हम अपने दैनिक जीवन में पानी का सही तरह से उपयोग करें। पानी को सुरक्षित रखने की दिशा में उपाय करें। पानी सभी के लिए आवश्यक है, तो इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सभी की है।

-उमराव सिंह वर्मा, बेमेतरा, छत्तीसगढ़

सजा का हो प्रावधान

जल की बर्बादी पर सजा का प्रावधान हो। बरामदों, वाहनों इत्यादि की धुलाई की जगह पोछा लगाकर कर काम चलाएं। टपकता नल तुरंत ठीक कराएं। बारिश के पानी को व्यर्थ न जाने दिया जाए।

-डॉ. कविता माथुर, जयपुर

वर्षा जल को व्यर्थ न बहने दें

जनता को वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बरसात के पानी को इकट्ठा करने लिए घरों में टांके या कुंड बनाने चाहिए। सरकार को इसके लिए लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए।

-अजीतसिंह सिसोदिया, खारा, बीकानेर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'जल संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/zj73gf

चिंतन

प्रलय को आमंत्रित करना है प्रकृति से छेड़छाड़

लगातार बढ़ रही आबादी और आधुनिक जीवनशैली ने इंसान की जरूरतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव प्रकृति से न केवल छेड़छाड़ कर रहा है, बल्कि उसे तहस नहस करने पर आमादा है। अपनी महत्वाकांक्षा में मानव इतना मगन हो गया है कि उसने प्रकृति की परवाह करना ही छोड़ दिया है। वनों का निरंतर काटा जाना और कंक्रीट के जंगलों का विस्तार, पहाड़ों का सीना चीरना हो या फिर रेगिस्तान में महल बनाना इसी के सबूत हैं। वन भूमि के कटाव को रोकते हैं और बाढ़ की संभावना को कम करते हैं। अब समय-असमय अनेक नदियों में बाढ़ आती है, इसका कारण यही है कि हमने अपने वनों को नष्ट कर दिया है तो नदियों का पानी भी अनियंत्रित हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व के लिए काल बनी हुई है। इसका कारण भी मनुष्य द्वारा बनाए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसे हैं, जो वायुमंडल में एकत्रित होकर वायुमंडल के ताप को बढ़ा देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर निरंतर पिघलते जा रहे हैं। पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। शहरों में हरियाली कम होती जा रही है। वायुमंडल अस्वच्छ हो रहा है। समुद्र में असमय तूफान आ रहे हैं। इसका कारण भी यही है कि समुद्री जीव भी निरंतर कम होते जा रहे हैं, जो समुद्र के पर्यावरण को संतुलित करके रखते हैं। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा में उन जीवों का या तो शिकार कर रहा है या फिर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों द्वारा उन जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। प्रकृति से खिलवाड़ में एक नया शब्द जुड़ा है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग मौसम संशोधन तकनीक है, जो कुछ प्रकार के सबफ्रीजिंग बादलों में छोटे बर्फ के नाभिकों को शामिल करके बारिश या बर्फ पैदा करने की बादल की क्षमता में सुधार करती है। ये नाभिक बर्फ के टुकड़े बनने के लिए आधार प्रदान करते हैं। क्लाउड सीडिंग होने के बाद, नवगठित बर्फ के टुकड़े तेजी से बढ़ते हैं और बादलों से वापस पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, जिससे स्नोपैक और स्ट्रीमफ्लो बढ़ जाता है और बरसात हो जाती है। कुछ सालों में रेगिस्तान वाले इलाकों में इस तकनीक से बरसात करवाई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात पृथ्वी पर सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक में स्थित है। यह देश बारिश को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करने में आगे है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था की पानी की मांग को पूरा करना है, जो पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में विविधता ला रही है। यूएई ने 2002 में अपना क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया। इसमें खास अवधि के दौरान बादलों की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जब इनमें अतिरिक्त वर्षा की संभावना सबसे अधिक होती है। हाल ही में सीडिंग के लिए विमानों को अल-एन हवाई अड्डे से भेजा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात और उसके आस-पास के रेगिस्तानी इलाकों में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने भयावह स्थिति बना दी। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में शुमार दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हालत यह हुई कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया। शहर के हाईवे पर गाड़ियां पानी में फंस गईं और शॉपिंग माल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक पानी घुस गया। यूएई से पहले ओमान के अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और बताया था कि देश में पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हालात ऐसे हो गए कि आसपास के देश भी बाढ़ की चपेट में आ गए। मौसम वैज्ञानिक इसे प्रकृति से ऐसी छेड़छाड़ को धरती के लिए विनाशकारी बता रहे हैं। अभी भी हालात बिगड़े नहीं हैं, लेकिन अगर यूं ही चलता रहा तो हमें प्रलय के लिए तैयार रहना होगा।

सुखद
रविशंकर

अर्थव्यवस्था को अच्छे मानसून से मिलेगी गति

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस साल भारत में 'सामान्य से ज्यादा' मानसून रहने की संभावना जताई है। अल नीना प्रभाव के चलते इस साल देश में मानसून अच्छा रहेगा। अगस्त-सितंबर में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। दरअसल अर्थशास्त्री और नीति निर्माता भी मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और कामना करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अच्छी बारिश हो। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यदि सही होती है तो ये देश की अर्थव्यवस्था से लेकर खेती-किसानी के लिए रामबाण हो सकती है। कहा जा रहा है कि मानसून सामान्य रहा तो फसलों की पैदावार अच्छी होगी जो महंगाई को नीचे लाने का काम करेगी। इससे ग्रामीण मांग में भी सुधार आएगा जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करेगी। अच्छी बारिश का असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ता है, जिससे कुछ खास खाद्य पदार्थों के दाम घट सकते हैं। चावल, बाजरा, रागी, अरहर, मूंगफली, कपास, मक्का, सोयाबीन आदि खरीफ फसलें हैं और इनका उत्पादन अधिकतर अच्छे मानसून पर निर्भर करता है। एक अनुमान के मुताबिक मानसून पर 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और कम से कम 50 प्रतिशत कृषि को पानी वर्षा के जरिए ही हासिल होता है। लगभग 800 मिलियन लोग गांवों में निवास करते हैं और वे कृषि पर ही निर्भर हैं, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 14 है। अगर मानसून असफल रहता है तो देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सामान्य से ऊपर मानसून रहने पर कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रामीण बाज़ारों में उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलता है। अच्छी बारिश से उद्योग जगत में भी बहार आती है। खेत से लेकर खाने की टेबल तक एक बड़ी चेन जुड़ी होती है। ऐसे में कमजोर मानसून पूरी वैल्यू चेन को बिगाड़ सकता है। जब वर्ष 2024 में एक अच्छा मानसून संभावित है, तब सरकार को, किसानों को मुस्कराहट देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभप्रद बनाने के लिए रणनीतिक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माना जा रहा है कि चार महीने की मानसूनी बारिश अर्थव्यवस्था के लिए मरहम साबित हो सकती है। देश की आधे से ज्यादा फसलें इसी मानसूनी बारिश से लहलहाती हैं। फसलों की पैदावार से खाने-पीने की चीजों के दाम तय होते हैं। पैदावार बढ़िया रही तो खाद्य पदार्थों की कीमतें कम रहेंगी। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। मानसूनी बारिश से खरीफ फसलों को लाभ होता है। साथ ही रबी सीजन यानी सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए भी मिट्टी को नमी मिल जाती है। बढ़िया बारिश से देश के जलाशयों में पानी भरता है, जिससे किसानों को खेती के लिए पानी मिल पाता है इतना ही नहीं आरबीआई ब्याज दरें तय करते समय मानसून के प्रदर्शन, खाद्य उत्पादन और महंगाई दर पर ध्यान देता है, इसलिए अच्छे मानसून से ब्याज दरों में भी गिरावट आती है और कर्ज सस्ता होता है। अच्छे मानसून से किसानों की फसल अच्छी होने से क्रयशक्ति बढ़ेगी और उनके बाजारों की तरफ जाने वाले कदम बाजारों की चमक बढ़ाएंगे। वर्तमान समय मे अगर बात करे तो देश के किसानों को खेती करना काफी महंगा पड़ रहा है। बीज, खाद और डीजल के दामों मे तेजी के बाद किसानों के लिए खेती करना बड़ा मुश्किल कर दिया है। किसानों का मानना है कि अब खेती से लागत भी निकलना असंभव सा हो रहा है। ऐसे में खराब मानसून से हालात और जटिल हो सकते हैं। कम पैदावार से अनाज, फल-सब्जी और दूध जैसी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे मानसून के कारण जलाशय लबालब भर जाते हैं जो हाइड्रोपावर तथा सिंचाई के लिए अहम हैं। साफ है, जिस तरह मानसून देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है उसी तरह कॉरपोरेट कंपनियों से लेकर आम कंज्यूमर तक हर किसी की पर्सनल इनकम और सेविंग्स पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। यकीनन देश कीअर्थव्यवस्थाके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सुकून भरा परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है। मॉनसून तो रूरल इकॉनोमी की रीढ़ ही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

नारे जिन्होंने बदल दिया सियासत का भूगोल

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

इन दिनों देश में आम चुनाव की सरगर्मियां तेज है तथा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी नारों का शोर है। देश में चाहे चुनाव हो या कोई आंदोलन सभी में नारों की भूमिका अहम मानी जाती है। जनमानस में नारों का व्यापक असर आजादी के संघर्ष से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत के चुनावी राजनीति में रहा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक नारे वन लाइनर पंचलाइन होते हैं जो मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं जो लोगों को काफी समय तक याद रहते हैं। वहीं नारे धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बंटे हुए लोगों को एकसाथ लाने का कारगर जरिया भी है। नारों के इतिहास पर गौर करें तो देश के आजादी आंदोलन में महात्मा गांधी से लेकर पहली पंक्ति के नेताओं ने जनता को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए अनेक नारे दिए जो आज भी इतिहास में अमिट हैं। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 'करो या मरो' का नारा दिया तो पं. जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' और ' आराम हराम है ' का उद्घोष किया। इसी आंदोलन में शहीद भगतसिंह ने ' इंकलाब जिंदाबाद ' का आवाज बुलंद किया तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 'जय हिंद' और ' तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ' नारे ने लाखों देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का जज्बा भर दिया। इसी संघर्ष के दौर में बाल गंगाधर तिलक ने 'स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार इसे मैं लेकर रहूंगा' का प्रण कर देशवासियों के मन में आजादी के प्रति प्रतिज्ञा का भाव जागृत कर दिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने 1928 में ब्रिटिश हुकूमत के साइमन कमीशन के खिलाफ मुंबई में 'साइमन गो बैक' का ऐलान कर सेनानियों में जोश भर दिया।

देश की आजादी के बाद राजनीतिक दलों के लिए नारे चुनावी वैतरणी पार करने का सशक्त माध्यम बन गया। देश के चुनावी राजनीति पर नजर डालें तो कोई भी चुनाव बगैर नारों के संपन्न नहीं हुआ बल्कि वर्तमान सोशल मीडिया के दौर में नारों को और भी ज्यादा विस्तार मिला है। मुल्क के सियासी इतिहास पर गौर करें तो कुछ नारों का जूनून लोगों के सर पर चढ़कर इतना बोला कि इसके चलते जनता ने सत्ता और नेता दोनों बदल दिया। पचास के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 'हिंदी-चीनी भाई-भाई ' का नारा दिया जो भारत के लिए विश्वासघाती साबित हुआ। साल 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने'खरो रुपयो चांदी को, राज महात्मा गांधी को ' नारा दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ' देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है ' नारा दिया था। साल 1965 में भारत -पाक युद्ध के दौरान जब देश में खाद्यान्न की कमी हो गई तब पूर्व प्रधानमंत्री स्व लालबहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का आव्हान किया जिसने न केवल देश का मनोबल बढ़ाया बल्कि अगले चुनाव में कांग्रेस को जीत भी दिलाया। साल 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने इसी में शब्द जोड़ते हुए ' जय जवान,जय किसान,जय विज्ञान ' नारा दिया। साठ के दशक में प्रसिद्ध गांधीवादी और समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने नारा दिया ' समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ ' इस नारे की प्रतिध्वनि आज इक्कीसवीं सदी में सुनाई पड़ रही है जब कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर पिछड़ों की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 1971 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया जिसने उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 352 सीटों के साथ भारी जीत दिलाया। इसी कार्यकाल में सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ 'संपूर्ण क्रांति ' का आगाज हुआ जिसकी परिणति 1975 के आपातकाल के रूप में हुई। इस क्रांति की ही उपज 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' जैसे नारे रहे हैं। जेपी आंदोलन के बाद देश में अनेक गैर राजनीतिक जन आंदोलन हुए जिसे नारों ने ही जन-जन तक पहुंचाया था। लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 2011 में अन्ना हजारे के अगुवाई में हुए आंदोलन को 'मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना...' , और 'अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है ' जैसे नारों के लिए याद किया जाएगा। इस आंदोलन के बाद 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और निर्ममता के विरोध में हुए 'निर्भया आंदोलन ' की आवाज को ' निर्भया अमर रहे....' और भारत माता की जय जैसे नारों ने सात समंदर पार पहुंचा दिया। गौरतलब है कि उक्त दोनों आंदोलनों ने तब के सत्ता की चूलें हिला दी।

अब सियासी नारों की ओर लौटें तो आपातकाल के दौरान ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने 'इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया ' नारा देकर नारों को व्यक्तिवादी बना दिया जो सिलसिला आज भी जारी है। इमरजेंसी के बाद जेपी की अगुवाई में 'जनता मोर्चा' का गठन हुआ जिसने 1977 के आम चुनाव में 'इंदिरा हटाओ, देश बचाओ' का नारा बुलंद कर पहली बार दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को रुखसत कर दिया। इसी दौर में 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' और 'अंधकार में एक प्रकाश, देश का नेता जयप्रकाश ' जैसे नारों को जनता ने हाथों - हाथ लिया।

कांग्रेस ने इस चुनाव में ' जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा ' तथा इंदिरा गांधी के भुवनेश्वर में दिए गए अंतिम भाषण ' मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरे खून का एक- एक कतरा इस देश के लिए अर्पित है' को ही इलेक्शन कैंपेन के मुख्य धुरी में रखा। इस चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय मिली लेकिन अगले चुनाव के ठीक पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता वीपी सिंह ने राजीव सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने के बाद पूरे देश में वीपी सिंह का स्वागत ' राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है ' के नारे से किया गया। इस नारे ने 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया लेकिन वीपी सिंह की अगुवाई वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और अपनों के ही बोझ तले गिर गई। अलबत्ता इस दौर में ही बाद देश में मंडल और कमंडल की राजनीति का उदय हुआ लेकिन 1991 के मध्यावधि चुनाव में दोनों मुद्दे कुछ खास नहीं कर पाई और कांग्रेस की एक बार फिर वापसी हुई। इस चुनाव अभियान के दौरान ही एक आत्मघाती हमले में भारत ने इक्कीसवीं सदी के स्वप्नदृष्टा राजीव गांधी को खो दिया। इसके बाद कांग्रेस ने 'राजीव तेरा ये बलिदान, याद रखेगा हिंदुस्तान' दिया।

इस चुनाव के बाद देश की सियासत मंदिर और मस्जिद की दिशा में मुड़ गई और फिजां में 'जय श्रीराम', 'सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे' और 'बच्चा-बच्चा राम का, रामजन्म भूमि के काम का' जैसे नारों ने धार्मिक वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ा दिया। 1996 के आमचुनाव में 'सबको देखा बारी-बारी, अबकी बार अटल बिहारी' नारे का भी आगाज हुआ। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ' इंडिया शाइनिंग ' नारा दिया लेकिन यह फ्लॉप साबित हुआ और भाजपा के हाथ से सत्ता छीन गई। 2014 के आम चुनाव आते-आते चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका निर्णायक बन चुकी थी। भाजपा ने अपने प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को बढ़त दिलाने के लिए इस मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया।आम चुनाव में भाजपा के 'अच्छे दिन आएंगे', 'बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार' जैसे नारे मतदाताओं के सर चढ़कर बोला तो कांग्रेस ने इसके मुकाबले में ' हर हाथ शक्ति,हर हाथ तरक्की' और 'कट्टर सोच नहीं, युवा जोश ' जैसे नारों को आगे बढ़ाया। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सोशल मीडिया में 'मैं भी चौकीदार ' अभियान को आगे बढ़ाया तो चुनाव में ' मोदी है तो मुमकिन है ' और 'अबकी बार फिर मोदी सरकार ' पंचलाइन को चुनावी हथियार बनाया। कांग्रेस के 'चौकीदार ही चोर है', ' मोदी हटाओ, देश बचाओ ' और 'अब होगा न्याय ' जैसे नारे लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही और मोदी सरकार फिर सत्ता में लौटी। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस ने 'परिवर्तन' नरवा,गरवा,घुरूवा अऊ बारी, ऐला बचाना हे संगवारी ' और ' गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ' जैसे नारों ने राज्य के पंद्रह साल पुरानी भाजपा सरकार को सत्ता से रुखसत कर दिया। राज्य की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली और 2023 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के दिए 'बदलबो-बदलबो ऐ दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलबो' नारे ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर भाजपा के हाथों राज्य की कमान सौंप दी। इस आम चुनाव में भाजपा ने ' तीसरी बार मोदी सरकार, अबकी बार चार सौ पार' जैसे नारे दिए हैं तो कांग्रेस ने ' हाथ बदलेगा हालात ....' का नारा देकर मोदी की गारंटी पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि देश के 97 करोड़ मतदाता आखिरकार किस नारे पर ऐतबार करते हैं ? अलबत्ता नारे महज चंद शब्द ही नहीं होते हैं बल्कि इन शब्दों में राजनीतिक भूगोल बदलने की भी ताकत होती है लिहाजा हर चुनाव में नारों का जोर और शोर रहेगा।

करेंगे दान तो बनेंगे समृद्ध और खुशहाल!

संकलित
दर्शन

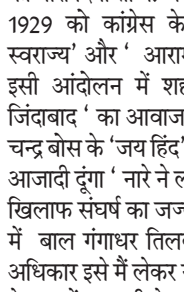

एक विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य से त्याग की अपेक्षा स्वाभाविक है। वास्तव में मानव का पूर्ण विकास ही त्याग द्वारा संभव है। जो दूसरे के लिए जितना अधिक त्याग कर सकता है, वह उतना ही महान समझा जाता है।राजा हरिश्चंद्र को हम आज भी उनके त्याग के लिए ही तो स्मरण करते हैं। महर्षि दधीचि ने तो एक विराट लक्ष्य के लिए अपनी देह का ही त्याग कर दिया था। वास्तव में हमारे समृद्ध इतिहास में कई विभूतियां तो केवल अपनी त्याग भावना के लिए ही विख्यात हुई हैं। त्याग की भावना का विकास करने के लिए सभी धर्मों में दान की महिमा बताई गई है। कहा जाता है धन का दान करने से धन शुद्ध होता है। आवश्यक नहीं है कि मात्र धनी व्यक्ति ही दान करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। दान की भावना जाग्रत होने पर आप पाएंगे कि आपके पास भी एक अक्षय भंडार है। मात्र धनदान या अन्नदान ही दान नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति धनहीन हो, परंतु उसके पास एक स्वस्थ एवं निरोग शरीर हो। क्या ऐसे लोगों के लिए श्रमदान विकल्प नहीं है? उनके आसपास कितने अशक्त लोग मिल जाएंगे, जिनकी वे अपनी शारीरिक ऊर्जा से सेवा कर सकते हैं। किसी के कार्य में हाथ बंटा लेना भी श्रमदान है। विद्यादान या ज्ञानदान को तो उत्तम में सवरेत्तम माना गया है। किसी निर्धन बच्चे को निःशुल्क पढ़ा देना भी तो दान ही है। आप किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त की सहायता कर सकते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, धन और भाव सब उपकरण हैं।

अनुकरण अच्छा, अंधानुकरण नहीं

संकलित
प्रेरणा

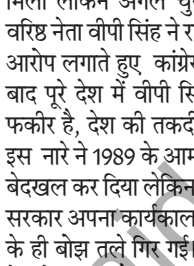

एक गाँव में दो युवक रहते थे। दोनों में बड़ी मैत्री थी। जहाँ जाते साथ-साथ जाते। एक बार दोनों एक धनी व्यक्ति के साथ उसकी ससुराल गए। किसी धनी व्यक्ति के साथ रहने का यह पहला अवसर था, सो वे अपने धनी मित्र की प्रत्येक गतिविधि ध्यान से देखते रहे। गरमियों के दिन थे। रात में उक्त युवक के लिए शयन की व्यवस्था खुले स्थान पर की गई। पर्याप्त शीतलता बनी रहे इसके लिए वहाँ चारों तरफ जल छिड़का गया और रात को ओढ़ने के लिए बहुत ही हलकी मखमली चादर दी गई। अन्य दोनों युवकों ने इतना ही जाना कि इस तरह का रहन-सहन बड़प्पन की बात है। कुछ दिन बाद उन्हें भी अपनी-अपनी ससुराल जाने का अवसर मिला पर वे दिन गरमी के न होकर शीत के थे। नकल तो नकल ही है। दोनों ने अपना बड़प्पन जताने के लिए बिस्तर खुले आकाश के नीचे लगवाया, लोगों के लाख मना करने पर भी उन्होंने बिस्तर के आस-पास पानी भी छिड़कवाया और ओढ़ने के लिए कुल एक-एक चादर वह भी हलकी ली। रात को पाला पड़ गया सो दोनों को निमोनियाँ हो गया । चिकित्सा कराई गई तब कठिनाई से जान बची। इतनी कथा सुनाने के बाद गुरुजी ने शिष्य को समझाया–' तात ! उचित और अनुचित का विचार किए बिना जो औरों का अनुकरण करता है वह मूर्ख ऐसे ही संकट में पड़ता है जैसे वह दोनों युवक।' !

अंतर्मन

आज की पाती

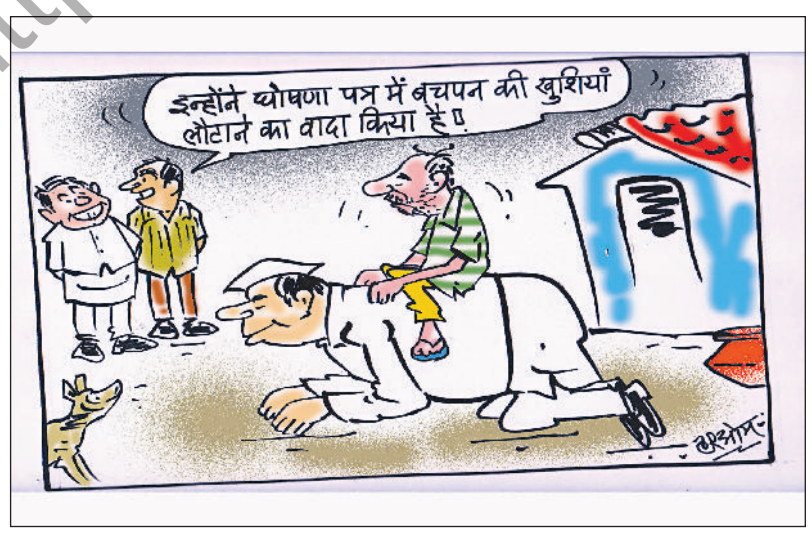

भगवान राम जी के आदर्श अपनाएं

हम भगवान श्री राम जी का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाते हैं। जब-जब भी सृष्टि पर पाप बढ़ा है, असुरों के अत्याचार से प्राणी जाति संकट में आई है और सत्य, इनसानियत का पतन होने लगा है, तब-तब भगवान धरती पर किसी न किसी रूप में आए हैं। कभी राम बनके, तो कभी कृष्ण के रूप में। भगवान श्री राम जी ने सृष्टि को रावण के जुल्मों और अत्याचारों से मुक्त करवाया था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस के अहंकारवश किए जा रहे गलत कामों से। जब धरती पर रावण के अत्याचार बढ़ने लगे, रावण साधु-संतों को परेशान करने लगा, तब भगवान विष्णु जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम जी के रूप में अवतार लिया था। राम नवमी का उत्सव हमें भगवान राम जी के आदर्श अपनाने की प्रेरणा देता है।

– संजय शर्मा, बिलासपुर

करंट अफेयर

ईरान पर कार्रवाई करने का निर्णय ले रहा इजराइल

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने बुधवार को कहा कि सप्ताहांत में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल 'कार्रवाई करने का निर्णय ले रहा है'। इस बीच, ईरान ने चेतावनी दी कि उसके क्षेत्र में किसी छोटे से हमले का भी कठोर जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने ईरान के अभूतपूर्व हमले का जवाब देने का संकल्प लिया है लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी। गाजा में जारी युद्ध के चलते महीनों की अशांति के बाद नए घटनाक्रम से क्षेत्र में और अधिक अशांति की आशंका उत्पन्न हो गई है। ईरान के हमले को नाकाम करने में मदद करने वाले इजराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका तथा ब्रिटेन हालात और खराब न होने देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने वार्षिक सैन्य परेड को संबोधित करते हुए इजराइल को किसी भी जवाबी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी। संभवतः इजराइल की जवाबी कार्रवाई के डर से इस सैन्य परेड का टेलीविजन पर प्रसारण नहीं किया गया। ईरान की आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी ने रईसी के हवाले से कहा कि शनिवार का हमला एक सीमित हमला था, और अगर ईरान बड़ा हमला करना चाहता तो इजराइल में कुछ भी नहीं बचता।

ऑफ बीट

हमें विलुप्त विशाल कंगारू की तीन नई प्रजातियां मिलीं

लाखों वर्षों से, विशाल जानवर या मेगाफ़ौना उन जगहों पर घूमते रहे हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी हैं। इनमें कई आधुनिक जानवरों के बहुत बड़े संस्करण थे। उदाहरण के लिए, मेगालानिया (वारानस प्रिस्कस) नामक चार मीटर का गोआना था, जो संभवतः अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता था। यह जानवर लगभग 40,000 साल पहले लाल कंगारू और खारे पानी के मगरमच्छ जैसे अवशेषों को छोड़कर लगभग सभी अन्य मेगाफौना के साथ गायब हो गया था। अब लुप्त हो चुकी कंगारू प्रजातियों में से कुछ काफी विशाल थीं। छोटे मुंह वाला कंगारू प्रोकोप्टोडोन गोलिया तीन मीटर तक लंबा था और इसका वजन 250 किलोग्राम से अधिक रहा होगा। विलुप्त कंगारूओं की एक और प्रजाति थी, प्रोटेमनोडोन, जिनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक नए अध्ययन में, मैं और मेरे सहकर्मी इन लुप्त हो चुके मार्सुपियल्स की तीन नई प्रजातियों का वर्णन करते हैं – और इस बात पर कुछ प्रकाश डालते हैं कि वे कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। 150 साल की पहेली प्रोटेमनोडोन की पहली प्रजाति का वर्णन 1874 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी रिचर्ड ओवेन द्वारा किया गया था।

ट्रेंड

पीछे नहीं हटूंगा

सूडान के भविष्य के लिए सभी सूडानी लोगों के योगदान, भागीदारी और दूरदर्शिता की आवश्यकता है। मैं बंदूकों को शांत करने और शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए सूडानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के अपने आह्वान में पीछे नहीं हटूंगा।

-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

एक और मिशन पूरा

डब्ल्यूएचओ और साझेदारों ने उत्तरी गाजा के लिए एक और मिशन पूरा किया। अपनी वर्तमान क्षमता का आकलन करने के लिए फिलिस्तीनी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी मेडिकल प्वाइंट, अल-शिफा अस्पताल और इंडोनेशियाई अस्पताल पहुंचे।

-डॉ टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

शक्ति को व्यर्थ न जाने दें

18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को इस मौलिक अधिकार और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह यह तय कर सके कि अगले पांच वर्षों तक राष्ट्र को कौन आगे ले जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निहित इस शक्ति को व्यर्थ न जाने दें या नोटा को चुनें।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

आप्रवासन के पक्ष में

केवल 3 वर्षों में 36 राज्यों की जनसंख्या से अधिक! मैं खुद एक आप्रवासी होने के नाते कानूनी आप्रवासन के पक्ष में हूं, लेकिन अमेरिका में अवैध रूप से लाखों लोगों को प्रवेश की अनुमति देना पागलपन है।

-एलोन मस्क, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid